मासिक पत्रिका | जुलाई 2026

PRGI NO. RJHIN/26/A2336

सम्यक् करेंट अफेयर्स

▶ अंतरराष्ट्रीय ▶ राष्ट्रीय ▶ राजस्थान

वर्ष 01, अंक 03, जुलाई 2026, मूल्य 100/- प्रति, वार्षिक शुल्क 1000/-, पृष्ठ संख्या 124

Samyak
An Institute For Civil Services

सम्यक् मार्गदर्शन
सर्वश्रेष्ठ परिणाम

RAS

PRELIMS | **PRE CUM MAINS**
PRELIMS GOLD | **FOUNDATION**

3 दिवसीय नि:शुल्क कक्षा के साथ

बैच प्रारम्भ

ऑफलाइन व LIVE FROM CLASSROOM

SEPARATE BATCHES FOR
ENGLISH MEDIUM | हिंदी माध्यम

COURSE FEATURES

- विषय विशेषज्ञों द्वारा क्लासेज
- लाइव एवं रिकॉर्डेड क्लासेज
- पर्सनल मेंटरशिप
- प्रिंटेड बुकलेट्स
- टेस्ट सीरीज
- ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन कोर्स नि:शुल्क

DOWNLOAD THE APP NOW
GET IT ON Google Play
Download on the App Store

NEAR RIDDHI-SIDDHI, JAIPUR **9875170111**

-:: अनुक्रमणिका ::-

अध्याय	पृष्ठ संख्या
◆ मासिक सारांश	7
◆ राजस्थान परिदृश्य	11
◆ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य	34
◆ राष्ट्रीय परिदृश्य	41
◆ आर्थिक परिदृश्य	57
◆ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	61
◆ खेल परिदृश्य	70
◆ पुरस्कार एवं सम्मान	76
◆ निर्वाचन एवं नियुक्ति	81
◆ सम्मेलन/बैठक/मेला/ महोत्सव/प्रदर्शनी	85
◆ अभियान/युद्धाभ्यास	93
◆ महत्वपूर्ण दिवस	94
◆ **विशेष लेख** : राजस्थान मे वन्य जीव और जैव विविधता	97
◆ **विशेष लेख :** राजस्थान सरकार की प्रमुख नीतियाँ	111
◆ करेंट अफेयर्स- जुलाई 2026 अंक वस्तुनिष्ठ टेस्ट	122

स्वत्वाधिकारी सम्यक एड्यूटेक,

प्रकाशक एवं सम्पादक वैष्णवी भारद्वाज द्वारा SP-21, गंगाराम नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर (राजस्थान)-302018 से प्रकाशित एवं महारानी प्रिन्टर्स, प्लॉट नं. 17, माँ वैष्णो देवी नगर, कालवाड़ रोड, जयपुर, राजस्थान-302012 से मुद्रित।

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर शहर, राजस्थान होगा।)

Gmail id - currentaffairs@samyakias.com

मो. 9460480423 | इस अंक का मूल्य : 100 | वार्षिक सदस्यता शुल्क : 1000

इस अंक मे प्रकाशित किसी भी सामग्री अथवा चित्र के लिए संपादक की सहमति होना आवश्यक नहीं है। इस पत्रिका मे प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापति किए गए हैं। यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया है तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक, उससे किसी व्यक्ति विशेष को पहुंची क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

संपादकीय

संकल्प से सिद्धि तक: सफलता का वास्तविक पथ

“उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्।”
श्रीमद्भगवद्गीता (6.5)

अर्थात् मनुष्य को अपने पुरुषार्थ से स्वयं अपना उत्थान करना चाहिए, निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। आज के प्रत्येक प्रतियोगी विद्यार्थी के लिए इससे बड़ा जीवन मंत्र शायद ही कोई हो।

वर्तमान युग तीव्र परिवर्तन का युग है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल क्रांति और बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा ने अवसरों के नए द्वार खोले हैं, वहीं चुनौतियों का दायरा भी व्यापक किया है। ऐसे समय में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी केवल एक नौकरी प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि स्वयं को एक सक्षम, संवेदनशील और उत्तरदायी नागरिक के रूप में गढ़ने की साधना है।

गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है-
“कर्म प्रधान विश्व करि राखा।
जो जस करइ सो तस फल चाखा ॥”

यह चौपाई हमें स्मरण कराती है कि सफलता का आधार भाग्य नहीं, बल्कि सतत कर्म, अनुशासन और धैर्य है। इसलिए प्रत्येक दिन ईमानदार से किया गया प्रयास, भविष्य की सबसे बड़ी पूँजी है।

वास्तविक सफलता केवल अंतिम चयन में नहीं, बल्कि उस निरंतर आत्म-विकास में निहित है, जो हमें प्रतिदिन कल से बेहतर बनाता है। यदि आपने आज कोई नया विचार सीखा, किसी कमजोरी पर विजय पाई, या कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहे, तो समझिए कि आपने सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा लिया।

आज आवश्यकता केवल अधिक पढ़ने की नहीं बल्कि गहराई से समझने तार्किक चिंतन विकसित करने और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना को आत्मसात करने की है। क्योंकि एक भावी प्रशासक, शिक्षक, वैज्ञानिक या नीति-निर्माता के निर्णय लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं।

आइए, हम अपनी तैयारी को केवल परीक्षा तक सीमित न रखें, बल्कि उसे राष्ट्र निर्माण के व्यापक उद्देश्य से जोड़ें। कठिनाइयों को अवसर में बदलते हुए, संकल्प, पुरुषार्थ और सकारात्मक दृष्टि के साथ आगे बढ़ें। जब लक्ष्य केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा बन जाता है, तब सफलता स्वयं आपके चरण चूमती है।

संपादक

Samyak
An Institute For Civil Services

निबन्ध प्रतियोगिता

निबन्ध का विषय-

1. डिजिटल गवर्नेंस : सुशासन का माध्यम या डिजिटल विभाजन की नई चुनौती?
2. गिग इकोनोमी : युवाओं के लिए अवसर या चुनौती ?

निबन्ध प्रतियोगिता के लिए आवश्यक शर्तें और निर्देश-

- निबन्ध लेखन पूरी तरह मौलिक होना चाहिए, नकल या एआई द्वारा जनरेटेड सामग्री मान्य नहीं होगी।
- निर्धारित शब्द सीमा का पालन करें- 600 शब्द (लगभग)
- निबन्ध में व्याकरण, वर्तनी और विराम चिह्नों की शुद्धता पर ध्यान रखें।
- निबन्ध में केवल प्रमाणित और सटीक आंकड़ों या ऐतिहासिक तथ्यों का ही उपयोग करें।
- निबन्ध को निर्धारित अंतिम तिथि और समय से पहले ही जमा करें। (31 मई, 2026)
- निबन्ध केवल निम्न माध्यम से प्रेषित किये जा सकते हैं-

  1. Whatsapp- 9875170111
  2. Mail- samyakcurrentaffairs@samyakias.com
  3. स्थानीय पता- Samyak- An Institute For Civil Services, Near Riddhi-Siddhi, Jaipur

- निबन्ध के साथ प्रतियोगी अपना पासपोर्ट साइज का फोटो, आधिकारिक नाम और पता अवश्य भेजें।

पुरस्कार-

- प्रतियोगिता में प्रथम तीन स्थान पाने वाले प्रतिभागियों के फोटो को अगले माह की समसमायिकी पत्रिका में स्थान दिया जायेगा और संबंधित माह का अंक उनके निर्धारित पते पर भेजा जायेगा।

“भाषाई विविधता:- भारत की एकता का सूत्र या क्षेत्रीय अस्मिता का संघर्ष?”

निबन्ध प्रतियोगिता- जून, 2026 (सर्वश्रेष्ठ निबन्ध)

नाम - तमन्ना व्यास
पता- खेड़ा ब्राह्मण, (डीग-भरतपुर)

“कोस-कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी।”

भारतीय समाज की यह प्राचीन लोकोक्ति हमारी भाषाई विविधता का अत्यंत सजीव और यथार्थ चित्रण करती है। भारत मात्र एक भौगोलिक खण्ड ही नहीं, अपितु यह बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक चेतना से स्पंदित एक जीवंत राष्ट्र है। संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज बाईस आधिकारिक भाषाओं और लोक-व्यवहार में पल्लवित हो रही सैकड़ों मातृभाषाओं के परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न अत्यंत ज्वलंत है कि- क्या यह विविधता राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोती है, या यह केवल संकीर्ण क्षेत्रीय अस्मिता और राजनीतिक संघर्ष का साधन मात्र है?

वस्तुतः एक सूक्ष्म और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण से यह पूर्णतः स्पष्ट होता है कि हमारी भाषाई विविधता अलगाव का कारण नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक परिपक्वता का सबसे सुदृढ़ आधार स्तम्भ है।

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य- ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भारत में भाषा कभी भी सांस्कृतिक विभाजन या वैमनस्य की रेखा नहीं रही। प्राचीन काल से ही संस्कृत और तमिल जैसी उत्कृष्ट शास्त्रीय भाषाओं के समानांतर पालि, प्राकृत और अपभ्रंश जैसी लोकभाषाओं ने ‘सह-अस्तित्व’ का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया है। मध्यकाल में भक्तिकालीन संतों- दक्षिण में आलवार व नयनार, उत्तर में कबीर व तुलसीदास तथा पूर्व में शंकरदेव ने अपनी स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से ही सम्पूर्ण भारत को एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सूत्र में पिरोया था। भाषाएं भले ही अलग थीं, परंतु उनके भीतर प्रवाहित होने वाली राष्ट्रीय चेतना पूर्णतः एक थीं।

सामाजिक और आर्थिक प्रभाव- समाज के हाशिए पर खड़े वर्गों के लिए उनकी मातृभाषा केवल संवाद का साधन ही नहीं, बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक पहचान का मुख्य आधार है। जब शिक्षा, रोजगार और न्याय-प्रणाली क्षेत्रीय भाषाओं में सुलभ नहीं होती, तो एक बड़ा ग्रामीण और आदिवासी वर्ग स्वतः ही विकास की मुख्यधारा से कट जाता है। इसके विपरीत, भाषाई विविधता का संरक्षण स्थानीय कौशल, पारंपरिक आजीविका और लोक-साहित्य को जीवित रखता है। यह सूक्ष्म अर्थव्यवस्थाओं को बल प्रदान कर समाज का यथार्थ और समावेशी विकास सुनिश्चित करता है।

प्रशासनिक एवं राजनीतिक पहलू- प्रशासनिक स्तर पर, स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन (फ़ज़ल अली आयोग) एक साहसिक कदम था यद्यपि 1960 के दशक में हुए भाषा-विरोधी आंदोलनों ने देश में अलगाववाद की आशंकाएँ बढ़ाईं, परन्तु भारतीय शासन प्रणाली ने अत्यंत दूरदर्शिता का परिचय दिया। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण और ‘त्रि-भाषा सूत्र’ का निर्माण इसी समन्वयवादी सोच के परिणाम हैं। वर्तमान में ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020’ द्वारा प्राथमिक स्तर की शिक्षा को मातृभाषा में देने का निर्णय भाषाई समानता की दिशा में एक अत्यंत व्यावहारिक प्रशासनिक कदम है।

समस्याएँ और चुनौतियाँ- इन सकारात्मक प्रयासों के बावजूद कुछ गंभीर चुनौतियाँ विद्यमान हैं। जब भी संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए किसी एक भाषा को ‘थोपने’ का प्रयास किया जाता है, या क्षेत्रीय भाषाओं की प्रशासनिक उपेक्षा होती है, तब भाषाई उन्माद और अस्मिता का आक्रामक संघर्ष जन्म लेता है। इसके अतिरिक्त, वैश्वीकरण के दौर में अंग्रेजी का बढ़ता एकाधिकार और कई देशज बोलियों का तेजी से विलुप्त होना हमारी सांस्कृतिक धरोहर के समक्ष एक गंभीर संकट है। यथार्थ में यह संघर्ष भाषा का नहीं, अपितु विकास के समान अवसरों के छिन जाने के भय का है।

उपसंहार- निष्कर्षतः एक भावी प्रशासक के दृष्टिकोण से यह समझना अनिवार्य है कि भाषाई विविधता भारत के लिए कोई समस्या नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी और जीवंत शक्ति है। जिस प्रकार एक उपवन की सुंदरता उसमें खिले विविध रंगो के पुष्पों से होती है, उसी प्रकार राष्ट्र की अखंडता विभिन्न भाषाओं के माधुर्य से समृद्ध होती है। हमारी प्राथमिकता किसी लोकभाषा का दमन करना नहीं, अपितु आधुनिक तकनीकी (जैसे-’भाषिणी ऐप’) के माध्यम से भारतीय भाषाओं के मध्य निर्बाध अनुवाद और संवाद स्थापित करना होनी चाहिए। यदि हम भाषाई सहिष्णुता के इस दर्शन को आत्मसात करें, तो महाकवि सुब्रह्मण्यम भारती का यह कथन अवश्य चरितार्थ होगा कि “हमारी भाषाएँ अठारह हैं, परंतु हमारा चिंतन एक है,” जो क्षेत्रीय अस्मिताओं का पूर्ण सम्मान करते हुए भारत की अखण्ड एकता का शाश्वत सूत्र सिद्ध होगा।

मासिक सारांश

- राजस्थान सरकार ने राजस्थान समान नागरिक संहिता, 2026 के विधेयक का प्रारूप तैयार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है?- **रंजना प्रकाश देसाई**
- राजस्थान और हरियाणा सरकार के मध्य यमुना जल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किस तिथि को हुए?- **29 जून, 2026**
- पीएम सूर्यघर योजना में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर कितने पुरस्कार प्राप्त हुए है?- **छह पुरस्कार**
- हाल ही में पीएम-कुसम योजना के कम्पोनेंट-सी के तहत प्रदेश के 553 ऊर्जादाताओं के लिए भारत सरकार ने कितने रूपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता की मंजूर प्रदान की है?- **531 करोड़ रूपए**
- राजस्थान से राज्यसभा चुनाव-2026 के लिए निर्वाचित प्रत्याशी है- **अलका सिंह, सतीश पूनिया, नीरज डांगी**
- 16 जून, 2026 को कितने जिलों में 'नागरिक सुरक्षा कोर' का गठन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है?- **8 नवगठित जिलों में**
- देश का पहला एग्री पीवी प्लांट कहां स्थापित हुआ है?- **कुंदनपुरा गांव (बस्सी-तूंगा)**
- भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण तथा उर्वरक विभाग द्वारा राजस्थान के कौनसे जिलों में 'फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल्स' को एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया है?- **सिरोही और राजसमंद**
- 29 जून, 2026 को जयपुर स्थित बिड़ला ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का कौनसा संस्करण आयोजित किया गया?- **30वां**
- राज्य के कौनसे जिला पुलिस प्रशासन द्वारा पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को संकट की घड़ी में त्वरित आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए एक अभिनव कल्याणकारी योजना अक्षय फंड की शुरुआत की है?- **सवाई माधोपुर**
- दुनिया का पहला आरटीआई लिविंग म्यूजियम कहां बनाये जाने की घोषणा की गयी है?- **ब्यावर में**
- राजस्थान की पहली मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली का शुभारंभ कहां किया गया है?- **दौलतपुरा टोल प्लाजा**
- 1 जून, 2026 को आयोजित राज्य की सीजीडी संस्थाओं की बैठक में राज्य में कितने एलपीजी फ्री जोन चिन्हित किए गए हैं?- **132**
- देश में आभा आईडी बनाने में राज्य को कौनसा स्थान प्राप्त हुआ है?- **दूसरा**
- मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (इंडिया) द्वारा किसे वैश्विक सम्मान प्रदान किया गया?- **राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को**
- केंद्र सरकार से पीएम श्री योजना में सत्र 2026-27 के लिए राजस्थान की पीएम श्री स्कूलों के लिए को कितना बजट आवंटित किया है?- **226.38 करोड़ का**
- नारी चौपाल-नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम प्रदेश में किसी तिथि को आयोजित हुआ?- **10 जून, 2026 को**
- अमृत सेवा अभियान किसके द्वारा चलाया गया था?- **जयपुर नगर निगम**
- प्रदेश में आमजन को राज्य सरकार की विभिन्न जन-कल्याणकारी एवं फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर-2026 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है?- **12 जून से 15 जुलाई, 2026 तक**
- राज्य में लम्पी स्किन डिजीज राज्य स्तरीय टीकाकरण अभियान का कौनसा चरण प्रारम्भ हुआ है?- **द्वितीय चरण**
- यह राजस्थान पुलिस की एएनटीएफ शाखा द्वारा कौनसा प्रोजेक्ट चलाया गया है?- **प्रोजेक्ट लक्ष्मण रेखा**
- टैक्सकॉन-2026 शिखर का आयोजन कहां किया गया?- **राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर**
- हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग में नवीन सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है- **संतोष आनंद और दीपक कुमार शर्मा**
- राजस्थान की किस प्रसिद्ध मांड गायिका का निधन हुआ है?- **गवरी देवी**
- राजस्थान सरकार ने राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड, अजमेर में किसे सदस्य नियुक्त किया है?- **योगेश शर्मा**
- उदयपुर की पहली महिला फाइटर पायलट बनने वाली युवती कौन है?- **ख़ुशी गंभीर**

- राज्य के किस क्षेत्र में 59 हेक्टेयर भूमि को डिफेंस एवं एयरोस्पेस पार्क के लिए रिजर्व किया गया है?- **उदयपुर खुर्द क्षेत्र-**
- एशियन ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन्स का अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है?- **डॉ. वी.डी. सिन्हा**
- सार्जेंट सुरेंद्र कुमार राज्य के किस जिले के निवासी थे?- **झुंझुनूं**
- नई दिल्ली में राजस्थान का प्रमुख आवासीय आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है?- **श्री रोहित कुमार**
- कृषक उपहार योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय लॉटरी का प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है?- **श्रीमती विद्या देवी**
- राज्य स्तरीय जूनियर पुरुष हॉकी के 16वें संस्करण का विजेता कौनसा जिला रहा है?- **जयपुर**
- पश्चिम क्षेत्र सांस्कृति केन्द्र की शाषी परिषद की बैठक कहां आयोजित हुई?- **गोवा में**
- हाल ही में राज्य सरकार ने माउंट आबू का नाम परिवर्तित करके क्या रखा है?- **आबूराज**
- राजस्थान बैडमिटन संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है?- **गजेंद्र सिंह शेखावत को**
- जी7 शिखर सम्मेलन-2026 की मेजबानी किस देश ने की है?- **फ्रांस**
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को किस देश के द्वारा 'गार्जियन ऑफ द ब्ल्यू हॉरिजन' से सम्मानित किया गया?- **सेशेल्स**
- संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है?- **खलीलुर रहमान को**
- स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की वार्षिक रिपोर्ट 'SIPRI ईयरबुक 2026' के अनुसार वर्ष 2021-25 की अवधि के दौरान वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे सबसे बड़ा प्रमुख हथियारों का आयातक कौनसा देश रहा है?- **भारत (प्रथम- यूक्रेन)**
- ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत कौनसे स्थान पर है?- **127वें स्थान**
- चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट-2026 किसके द्वारा जारी की गयी थी?- **यूनिसेफ**
- कौनसा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां और पहला मध्य एशियाई सदस्य बना है?- **उज्बेकिस्तान**
- मलेशिया की सरकार ने कितनी वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगा दी है?- **16 वर्ष से कम उम्र के**
- किस देश के एक प्रांत ने प्रस्ताव पारित कर पेड़ों को 'जीवित प्राणी' के रूप में मान्यता दी है?- **कनाडा**
- दुनिया का सबसे पुराना उल्कापिंड गड्ढा/क्रेटर कहां खोजा गया है?- **पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में**
- केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने किस तिथि को महा जल परियोजना का शुभारंभ किया है?- **1 जून, 2026**
- अरावली की परिभाषा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में हाई-पावर कमेटी गठित की गयी है?- **कंचन देवी**
- केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 28 जून, 2026 को कहां से पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया?- **गांधीनगर, गुजरात**
- 20वां सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया गया?- **29 जून, 2026**
- प्रियदर्शिनी मुफ्त बस यात्रा योजना किस राज्य की है?- **केरल**
- झारखंड के कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है?- **ग्यारह**
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को मंजूरी दी है?**- सात**
- भारत ने किस देश के साथ मिलकर 'क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी' की शुरुआत की है?- **ब्रिटेन**
- देश का पहला 85 प्रतिशत एथेनॉल मिक्स E85 फ्यूल कहां लॉन्च किया गया है?- **दिल्ली में**
- कौनसा राज्य वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली को ई-कोर्ट से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बन गया है?- **केरलम**
- केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जून, 2026 को कहां से राष्ट्रव्यापी 'खेत बचाओ अभियान' का शुभारंभ किया है?- **रायसेन (मध्यप्रदेश)**
- किस मंत्रालय ने 3 जून, 2026 को 'नवाचार मंत्र' नामक राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ किया है?- **कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय**
- जय प्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है, यह कहां है?- **बलिया, उत्तर प्रदेश।**

- केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 5 जून, 2026 को कहां पर देश के सातवें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया?- **जम्मू में**
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून, 2026 को पश्चिम बंगाल के हुगली से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की कौनसी किस्त जारी की है?- **23वीं**
- 25 जून, 2026 को कहां से हब-एंड-स्पोक मॉडल के तहत भारत की पहली 'ईज़ी कनेक्ट' उड़ान का शुभारंभ किया गया है?- **वाराणसी से**
- वर्ष 2025 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार कौनसा देश बना है?- **भारत**
- राज्यसभा के लिए हुए निर्वाचन में 27 सीटों में से कितनी सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं?- **24 सीटों पर**
- भारत के किस शहर में अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के नाम पर सड़क का नामकरण किया गया है?- **हैदराबाद में**
- देश के किस राज्य ने अपना स्वदेशी AI मॉडल लॉन्च किया है?- **महाराष्ट्र**
- आईआईटी-बॉम्बे अपना पहला विदेशी सब-कैंपस कहां पर खोलेगा?- **न्यूयॉर्क (अमेरिका) में**
- भारत और ओमान के मध्य भारत और ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) कब से लागू हुआ?- **1 जून, 2026**
- सात्विक इंडेक्स किसके द्वारा लॉंच किया गया है?- **बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई)**
- हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर कोयला-से-अमोनियम नाइट्रेट परियोजना की आधारशिला रखी है?- **ओडिशा में**
- डीआरडीओ ने स्वदेशी नेत्र-विमानस्थ प्रारंभिक चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली का अंतिम परिचालन स्वीकृति (एफओसी) प्रमाणपत्र किसे औपचारिक रूप से सौंप दिया है?- **भारतीय वायुसेना को**
- भारतीय सेना ने कहां पर स्वदेशी टैक्टिकल लोइटरिंग म्यूनिशन 'दिव्यास्त्र MK-1' का सफल परीक्षण किया?- **जोधपुर में**
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 21 जून, 2026 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारतीय नौसेना के प्रथम पंक्ति के कौनसे अत्याधुनिक जहाजों को कमीशन किया है?- **आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय**
- नासा और लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित सुपरसोनिक विमान है?- **X-59 विमान**
- एडवांस क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस प्रयोगशालाएं कहां स्थापित होगी?- **एमएनआईटी जयपुर**
- केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 20 जून, 2026 को कितनी निश्चित खुराक संयोजनों (एफडीसी) के निर्माण, बिक्री और उनके मानवीय उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है?- **16 एफडीसी**
- किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने पीने के पानी में आर्सेनिक की तेजी से पहचान के लिए 'आर्सेनसेफ' नामक एक पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है?- **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भुवनेश्वर**
- रिलायंस इंडस्ट्रीज और मेटा के मध्य कहां पर डेटा सेंटर के निर्माण के लिए समझौता हुआ है?- **जामनगर (गुजरात) में**
- भारत के किस राज्य में शिगेला संक्रमण के सौ से अधिक मामले सामने आये है?- **केरल में**
- भारत के पहले 3डी प्रिंटेड कृत्रिम रीफ मॉड्यूल्स को भारत के किस तट के पास समुद्र में स्थापित किया जाएगा?- **रामनाथपुरम तट**
- 'RTX Spark' नाम की नई एआई चिप किसके द्वारा लॉंच की गयी है?- **एनवीडिया**
- आईसीसी महिला टी20 विश्व कप-2026 का कौनसा संस्करण आयोजित हो रहा है?- **10वां**
- वनडे वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन-कौनसे देश करेंगे?- **दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया**
- पुरुष हॉकी अंडर-18 एशिया कप 2026 की क्रमश: विजेता और उप-विजेता टीम रही है?- **भारत व जापान**
- FIH हॉकी विमेंस नेशंस कप-2025-26 की उपविजेता टीम कौनसी है?- **न्यूजीलैंड**
- एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 22वां संस्करण कहां आयोजित किया गया?- **हांगकांग, चीन**
- राष्ट्रीय अंतरराज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप-2026 का आयोजन कहां किया गया?- **भुवनेश्वर, ओड़िशा**
- फीफा वर्ल्ड कप-2026 में कितनी टीम हिस्सा ले रही है?- **48 टीम**
- उलानबतोर ओपन-2026 कुश्ती टूर्नामेंट में भारत कुल कितने पदक अपने नाम किये है?- **कुल 16 पदक**

- विश्व योगासन चैंपियनशिप-2026 का मैस्कॉट क्या था?- **वीर द लॉयन**
- टाइम मैगजीन द्वार जारी खेल जगत के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय खिलाड़ी ने जगह बनाई है?- **स्मृति मंधाना**
- राष्ट्रमंडल खेल-2026 का शेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है?- **रोहित राजपाल**
- भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में तैनात किस व्यक्तित्व को वर्ष 2025 के लिए यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?- **मेजर अभिलाषा बराक को**
- किस अमरीकी-भारतीय मूल के सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी को मिश्रित फर्मियन की खोज के लिए वुल्फ प्राइज से सम्मानित किया गया है?- **प्रो. जैनेंद्र के. जैन**
- इंडियन एथलेटिक्स अवॉर्ड्स 2025 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट के रूप में किसे चुना गया है?- **नीरज चोपड़ा**
- यूएन के खाद्य एवं कृषि संगठन ने 'सॉयल फार्मर हीरो' सम्मान से किसे नवाजा है?- **वल्लुवन को**
- इंटरनेशनल आइपी हॉल ऑफ फेम-2026 में किसे शामिल किया गया है?- **प्रतिभा एम. सिंह**
- फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है?- **विवेक अग्रवाल को**
- विश्व बैंक मुख्यालय में भारत का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है?- **नीलकंठ मिश्रा**
- मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है?- **डॉ. सैबल चट्टोपाध्याय**
- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का नया मिलिट्री एडवाइजर किसे नियुक्त किया गया है?- **लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को**
- भारत सरकार ने किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक नियुक्त किया है?- **महेश दीक्षित**
- भारत के किस विधिवेत्ता को अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून ट्रिब्यूनल का जज चुना गया है?- **बिमल एन. पटेल**
- भारत के किस सुप्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ का निधन हुआ है?- **डॉ. सुभाष कश्यप**
- हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता का निधन हुआ है?- **जसपाल राणा**
- 13वां ब्रिक्स शहरीकरण मंच का विषय क्या था?- **जनता के लिए शहर: समावेशी और सुदृढ़ शहरी भविष्य के लिए ब्रिक्स सहयोग**
- उत्तर पूर्वी परिषद के 73वां पूर्ण सत्र का कहां आयोजन किया गया?- **शिलांग में**
- नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक का विषय क्या था?- विकसित भारत@2047 के लिए समावेशी मानव विकास
- ब्रिक्स इंदौर डिक्लेरेशन का मूल केंद्र है- कि**सान**
- राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया?- **श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर**
- बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास 'खान क्वेस्ट' का आयोजन कहां हुआ?- **मंगोलिया**
- विश्व पर्यावरण दिवस 2026 का विषय क्या था?- **प्रकृति से प्रेरित। जलवायु के लिये। हमारे भविष्य के लिये।**
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस किस तिथि को आयोजित किया जाता है?- **27 जून**

राजस्थान परिदृश्य

यमुना जल परियोजना समझौता

- हाल ही में राजस्थान और हरियाणा सरकार के मध्य यमुना जल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए है।
- समझौता हस्ताक्षरित तिथि- 29 जून, 2026
- समझौता स्थल- नई दिल्ली

समझौते के दौरान उपस्थिति गणमान्य-

1. श्री अमित शाह (केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री)
2. श्री सी.आर. पाटिल (केंद्रीय जल शक्ति मंत्री)
3. श्री भजनलाल शर्मा (राजस्थान के मुख्यमंत्री)
4. नायब सिंह सैनी (हरियाणा के मुख्यमंत्री)

समझौता के सन्दर्भ में प्रमुख तथ्य-

- यह समझौता मूलतः वर्ष 1994 के 'अपर यमुना रिवर बोर्ड' के तहत सह-बेसिन राज्यों के बीच हुए जल आवंटन समझौते को लागू करता है। इस समझौता के तहत राजस्थान का हिस्सा 10.4% तय किया गया था।
- परियोजना की लागत- ₹34,102 करोड़ (अनुमानित लागत)
- जल की मात्रा- 577 मिलियन क्यूबिक मीटर
- जल का स्रोत- हथिनीकुंड बैराज, हरियाणा
- भूमिगत पाइपलाइन नेटवर्क- हथिनीकुंड बैराज से हांसियावास जलाशय (चूरू) तक पानी पहुँचाने के लिए लगभग 295.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन का निर्माण।
- क्रियान्वयन एजेंसी- राजस्थान-हरियाणा यमुना वाटर प्रोजेक्ट स्पेशल पर्पज व्हीकल

राजस्थान को होने वाले मुख्य लाभ-

- शेखावाटी अंचल को दीर्घकालिक पेयजल सुरक्षा मिलेगी।
- भूजल पुनर्भरण के माध्यम से लगातार गिरते भूजल स्तर को सुधारने में मदद मिलेगी।

राजस्थान समान नागरिक संहिता, 2026 विधेयक-

- हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजस्थान समान नागरिक संहिता, 2026 के विधेयक का प्रारूप तैयार करने हेतु समिति का गठन किया है।
- **समिति की संरचना-**

पद	नाम	विशेषज्ञ
अध्यक्ष	श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई	सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय
सदस्य	श्री शत्रुघ्न सिंह	सेवानिवृत्त आई.ए.एस.
सदस्य	श्री बसंत सिंह छाबा	अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय
सदस्य	श्री रामस्वरूप अग्रवाल	महानिदेशक प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, श्रीगंगानगर
सदस्य	डॉ. शुचि चौहान	विषय विशेषज्ञ
सदस्य सचिव	अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)	गृह विभाग, राजस्थान सरकार

समिति द्वारा समान नागरिक संहिता के विधेयक के प्रारूप को समावेशी और पारदर्शी बनाने के लिए संभाग स्तर पर जन-संवाद को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

समान नागरिक संहिता के लिए संवैधानिक प्रावधान

- भारत के संविधान के भाग-4 में वर्णित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद-44 राज्य को भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का निर्देश देता है।

समान नागरिक संहिता के मुख्य प्रावधान और उद्देश्य-

- वर्तमान में विवाह, तलाक, संपत्ति, गोद लेने और भरण-पोषण जैसे मामलों में अलग-अलग पर्सनल लॉ लागू हैं। यूसीसी लागू होने से निम्नलिखित बड़े बदलाव होंगे-
  - विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण करना होगा।
  - बहुविवाह पर पूर्ण रोक लगेगी।
  - लिव-इन में रहने वाले जोड़ों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित किया जाएगा।
  - पैतृक संपत्ति में बेटा और बेटी दोनों को समान अधिकार प्राप्त होंगे।
  - लैंगिक समानता सुनिश्चित होगी।

पांचना बाँध

- हाल ही में पांचना बांध पानी के बटवारें को लेकर उपजे विवाद के कारण सुर्ख़ियों में है।
- इस बाँध के एक ओर कमांड एरिया के 35 गांवों के किसान नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग कर रहे हैं जबकि दूसरी ओर बांध क्षेत्र से जुड़े 39 गांवों के लोग नहरों में पानी छोड़े जाने का विरोध कर रहे हैं। यह मांगे वर्तमान में विरोध का कारण बन गयी है।
- इससे पूर्व राजस्थान हाई कोर्ट ने दो बार नहरों में पानी छोड़ने के आदेश दे चुका है हालांकि इन आदेशों की पालना नहीं की गयी।

पांचना बाँध

- अवस्थित- गुड़ला गांव, करौली
- संबंधित नदियाँ- भद्रावती, बरखेड़ा, अटा, माची और भैंसावट
- पांचना नाम- यह बांध पांच नदियों के संगम पर स्थित है, इसलिए इसे पांचना कहा जाता है।
- पूर्वी राजस्थान में साल 1972 में आई भीषण बाढ़ के बाद इस क्षेत्र में जल प्रबंधन की आवश्यकता महसूस की गई थी जिसके बाद पांचना बांध परियोजना को मंज़ूरी मिली।
- इस बांध का निर्माण कार्य वर्ष 1978-79 में शुरू होकर 2004-05 में पूर्ण हुआ था।
- यह राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है।
- इस परियोजना का कुल कमांड एरिया लगभग 9,985 हेक्टेयर है।

राजस्थान में शहरी अवसंरचना विकास और अर्बन चैलेंज फंड-

- हाल ही में जयपुर के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में 28 जून, 2026 को राजस्थान के स्वायत्त शासन विभाग और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (हुडको) के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए है।
- इस समझौता के तहत केंद्र सरकार के अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से राज्य के शहरी निकायों में आगामी 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे का समावेशी विकास किया जाएगा।
- इसके तहत राज्य में लगभग ₹15,800 करोड़ की परियोजनाएं प्रस्तावित हैं।
- **वित्तीय अंशदान-** अर्बन चैलेंज फंड एक प्रतिस्पर्धी वित्तपोषण व्यवस्था है। इसके तहत कुल परियोजना लागत का विभाजन निम्न प्रकार है-

हितधारक	अंशदान प्रतिशत	राजस्थान के संदर्भ में राशि
केंद्र सरकार (UCF के माध्यम से)	25%	लगभग ₹3,950 करोड़
राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय	25%	लगभग ₹3,950 करोड़
वित्तीय संस्थान/हुडको (HUDCO)	50%	लगभग ₹7,900 करोड़
कुल प्रस्तावित लागत (राजस्थान)	100%	लगभग ₹15,800 करोड़

पीएम सूर्यघर योजना में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर मिले 6 पुरस्कार

- हाल ही में केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पीएम सूर्यघर योजना के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दिल्ली में आयोजित समारोह में राजस्थान को विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कुल 6 पुरस्कार प्राप्त किए हैं।
- राजस्थान की ओर से ऊर्जा सचिव एवं राजस्थान डिस्कॉम्स की चेयरमैन सुश्री आरती डोगरा ने चार अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कार ग्रहण किए।

प्रमुख पुरस्कार एवं श्रेणियां-

- राज्य श्रेणी- '90 लाख से 1.50 करोड़ विद्युत उपभोक्ता' वाले राज्यों के अंतर्गत, मई माह के दौरान रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों के सर्वाधिक आवेदन, इंस्टॉलेशन, निरीक्षण तथा वेंडर्स के रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में राजस्थान को द्वितीय पुरस्कार मिला।
- जिला श्रेणी- सर्वाधिक इंस्टॉलेशन वाले देश के 10 सर्वश्रेष्ठ जिलों की कैटेगरी में जयपुर को 7वें स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया।
- वेंडर श्रेणी- मई माह के दौरान उत्तर क्षेत्र के राज्यों में सर्वाधिक रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन की कैटेगरी में 'मिलन सौर ऊर्जा केंद्र' को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

पीएम सूर्यघर योजना-

- लॉन्च- फरवरी, 2024 को
- उद्देश्य- देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर उन्हें मुफ्त बिजली प्रदान करना।
- लक्ष्य- मार्च 2027 तक 1 करोड़ सोलर इंस्टॉलेशन स्थापित करना

सब्सिडी और वित्तीय सहायता-

औसत मासिक बिजली खपत (यूनिट)	उपयुक्त रूफटॉप सोलर प्लांट क्षमता	मिलने वाली सब्सिडी सहायता
0 से 150 यूनिट	1 से 2 किलोवाट	₹30,000/- से ₹60,000/-
150 से 300 यूनिट	2 से 3 किलोवाट	₹60,000/- से ₹78,000/-
300 यूनिट से अधिक	3 किलोवाट से ऊपर	अधिकतम ₹78,000/-

- योजना के तहत देश के प्रत्येक जिले में एक "मॉडल सोलर विलेज" विकसित करने का प्रावधान है ताकि ग्रामीण समुदायों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

योजना के दूरगामी प्रभाव और लाभ-

- घरेलू बचत और अतिरिक्त आय का सृजन।
- सौर क्षमता में वृद्धि होगी।
- पर्यावरणीय लाभ प्राप्त होंगे।
- अतिरिक्त रोजगार सृजन होगा।

'हरियालो राजस्थान' और 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान का शुभारंभ-

- हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 5 जून, 2026 (विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर) विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में बरगद का पौधा लगाकर 'हरियालो राजस्थान-2026' और 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान का शुभारंभ किया।
- **Note-** वर्ष 2026-27 के राज्य बजट में राज्य में 10 करोड़ पौधे लगाने एवं संरक्षण का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में आयोजित किया गया था।

हरियालो राजस्थान मिशन-

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'एक पेड़ माँ के नाम' से प्रेरित मिशन।
- प्रारम्भ- 7 अगस्त 2024
- स्थान- जाहोता, जयपुर से
- संबंधित विभाग- वन विभाग, राजस्थान सरकार
- लक्ष्य- 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाना

भीम एवं भोपालसागर बांध आधुनिकीकरण परियोजना-

- हाल ही में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और भीम विधायक हरिसिंह रावत ने राजसमंद जिले में स्थित भीम बांध और भोपालसागर बांध तथा उनकी नहर प्रणालियों के मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्यों का शिलान्यास किया है।
- यह कार्य मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है। इस संपूर्ण परियोजना के लिए 8 करोड़ 70 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है तथा परियोजना का कार्य 24 अप्रैल, 2027 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
- **ऐतिहासिक सन्दर्भ-**
  - भीम बांध- इसका निर्माण वर्ष 1950 में किया गया था।
  - भोपालसागर बांध- इसका निर्माण वर्ष 1956 में किया गया था।
  - अवस्थिति- यह दोनों बांध राजसमंद जिला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।

बिजली निगमों में कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए लागू होगी एकीकृत ईआरपी प्रणाली-

- हाल ही में राजस्थान के ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने बिजली निगमों में कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए एकीकृत एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ERP) प्रणाली और एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने की बात कही हैं।
- इस एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म को विकसित करने की संभावनाओं को अमल में लाने की जिम्मेदारी ऊर्जा विकास एवं आईटी सर्विसेज निगम लिमिटेड को प्रदान की गई है।
- इस सिंगल प्लेटफॉर्म (ईआरपी) के तहत मानव संसाधन, वित्त, लेखा, खरीद तथा परिसंपत्तियों के प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों को एक साथ लाया जाएगा।
- इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया त्वरित और सुगम होगी, प्रशासनिक कार्यों में मितव्ययता और पारदर्शिता आएगी और उपभोक्ता सेवाओं (बिलिंग, शिकायत निवारण आदि) की ट्रैकिंग आसान होगी।

एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) सिस्टम-

- यह बिजनेस मैनेजमेंट का भाग और सिस्टम है। यह किसी संगठन के विभिन्न विभागों (वित्त, मानव संसाधन, विनिर्माण, और आपूर्ति श्रृंखला) को एक केंद्रीय मंच पर जोड़ता है जिससे प्रक्रियाओं को स्वचालित और सुव्यवस्थित करके कंपनी की दक्षता और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार हो पाता है।

प्रदेश के 553 ऊर्जादाताओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता मंजूर-

- हाल ही में पीएम-कुसम योजना के कम्पोनेंट-सी के तहत प्रदेश के 553 ऊर्जादाताओं के लिए भारत सरकार ने 531 करोड़ रूपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) की मंजूर प्रदान की है।
- इस राशि का भुगतान अजमेर एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा ऊर्जादाताओं के बैंक खातों में किया जाएगा। इसके अन्तर्गत 429 मेगावाट के संयंत्र लगाने वाले जोधपुर विद्युत वितरण निगम के 432 ऊर्जादाताओं को 379.41 करोड़ रूपए तथा 169 मेगावाट क्षमता के प्लांट लगाने वाले अजमेर डिस्कॉम के 121 सौर ऊर्जा उत्पादकों के लिए 151.21 करोड़ रूपए की सहायता मिलेगी।
- प्रदेश में कम्पोनेंट-सी के अन्तर्गत 3371 मेगावाट क्षमता की 1312 परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं। इनमें जोधपुर डिस्कॉम में 2647 मेगावाट, अजमेर डिस्कॉम में 373 मेगावाट तथा जयपुर डिस्कॉम में 352 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं।
- राजस्थान कम्पोनेंट-सी में देश में तीसरे स्थान पर है।

प्रधानमंत्री कुसुम योजना (किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं महाउत्थान अभियान)-

- शुरुआत- मार्च, 2019
- केन्द्र का मंत्रालय- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
- राजस्थान का विभाग- RRECL (Rajasthan Renewable Renewable Energy Limited) (राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड) ऊर्जा विभाग के अंतर्गत एजेंसी।

कुसुम योजना के 3 घटक-

- घटक A- ग्रिड से जुड़े 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना।
- घटक B- 7.5 HP क्षमता तक के स्वतंत्र सौर कृषि पंपों की स्थापना।
- घटक C- ग्रिड से जुड़े 7.5 HP क्षमता तक के मौजूदा कृषि पंपों का सौर ऊर्जा से संचालन।

दिल्ली-गुरुग्राम-रेवाड़ी-एसएनबी-बहरोड़ आरआरटीएस कॉरिडोर-

- दिल्ली-गुरुग्राम-रेवाड़ी-एसएनबी-बहरोड़ आरआरटीएस कॉरिडोर (रीजनल रेपिड ट्रांजिट सिस्टम—आरआरटीएस) के प्रथम चरण को बहरोड़ तक बनाया जा रहा है।

परियोजना के मुख्य तथ्य-

- कुल लंबाई- लगभग 130 किलोमीटर
- कुल स्टेशन- 19 स्टेशन
- राजस्थान में स्टेशन- 3 स्टेशन
  - शाहजहाँपुर
  - नीमराना
  - बहरोड़
- बावल से राजस्थान सीमा तक का खण्ड- इस खण्ड की परियोजना लागत का 50 प्रतिशत भाग हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- राजस्थान सीमा से बहरोड़ तक का खण्ड- इस खण्ड की 100 प्रतिशत (सम्पूर्ण) लागत राजक स्थान सरकार एवं उसकी संबद्ध संस्थाओं द्वारा वहन की जाएगी।

राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत 800 वरिष्ठजनों को 75 लाख रुपये के सहायक उपकरण वितरित-

- हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत राज्य एवं एलिम्को के सहयोग से चित्तौड़गढ़ में 800 वरिष्ठ नागरिकों को 75 लाख रुपये मूल्य के सहायक उपकरण वितरित किए गये।

राष्ट्रीय वयोश्री योजना

- योजना का प्रारम्भ- अप्रैल, 2017 को आंध्र प्रदेश से
- नोडल मंत्रालय- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
- कार्यान्वयन एजेंसी- भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO)
- यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- इसके लिए आवश्यक बजटीय राशि 'वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष' से आवंटित की जाती है।

योजना का उद्देश्य-

- शारीरिक अक्षमता को दूर करना
- आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों को दूसरों पर आश्रित रहने के बजाय स्वयं के कार्यों को स्वतंत्र रूप से करने के योग्य बनाना।

राष्ट्रीय राजमार्ग-62 के फोरलेन निर्माण कार्य को स्वीकृति-

- हाल ही में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नागौर-बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग-62 के फोरलेन निर्माण कार्य को स्वीकृति प्रदान की है।
- इस राष्ट्रीय राजमार्ग को लगभग 1359.33 करोड़ रुपये की लागत से बीओटी (टोल) मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इससे पश्चिमी राजस्थान की कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलने के साथ ही निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

प्रदेश में खनिज के मलबों से निकालें जायेंगे क्रिटिकल मिनरल्स-

- हाल ही में प्रदेश में पिंक मार्बल और हरे मार्बल के मलबों के ढेर (अपशिष्ट) के अध्ययन में क्रिटिकल मिनरल्स (निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम और गैलियम) की गुणवत्तापूर्ण मात्रा के सकारात्मक संकेत मिले हैं।
- इन मलबों के ढेर में क्रिटिकल मिनरल्स की मात्रा पृथ्वी की ऊपरी परत में मिलने वाली सामान्य मात्रा से 25 से 40 गुना अधिक है।
- इसके लिए खान विभाग के RSMET और IIT (ISM) धनबाद के बीच एक एमओयू हुआ है, जिसके तहत खनिज कचरे से बेशकीमती खनिज निकालने का अध्ययन किया जायेगा।
- इसके शुरुआती चरण में 78 डम्प्स की पहचान कर 10-10 के क्लस्टर बनाए गए हैं।
- राज्य में अपशिष्ट से प्राप्त इन मिनरल्स से रक्षा, ग्रीन एनर्जी, एयरोस्पेस और एयरोनॉटिकल उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा के साथ-साथ सामरिक और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत मिलेगी।

क्रिटिकल मिनरल्स-

- यह मिनरल्स किसी देश के आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपरिहार्य होते हैं, लेकिन इनकी आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान का जोखिम बहुत अधिक होता है।
- **Note-** हाल ही में सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में रेयर अर्थ मिनरल्स और हेवी रेयर अर्थ मिनरल्स के बड़े डिपॉजिट्स मिले हैं, जिनके ब्लॉक्स की नीलामी केंद्र सरकार द्वारा शुरू भी कर दी गई है।

राजस्थान (लवण क्षेत्रों में भूखंड आवटंन) संशोधन नियम, 2026 जारी

- हाल ही में राजस्थान सरकार ने नमक उद्योग को बढावा देने के लिए वतर्मान में प्रचलित नियमों में संशोधन कर राजस्थान (लवण क्षेत्रों में भूखंड आवटंन) संशोधन नियम, 2026 जारी किए हैं।

संशोधित नियम-

- नमक उद्योग के लिए भूखंड आवंटन ई-ऑक्शन के माध्यम से किया जाएगा।
- नमक इकाइयों के वर्गीकरण संबंधी प्रावधान को सम्मिलित किया गया है।
- जिन जिलो में नमक उत्पादन हेतु लवणीय भूमि उपलब्ध है, उनमें सर्वे सीमांकन और भूखंडो के मापन के बाद आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी।
- इसके अलावा 300 नामक उत्पादन इकाइयाँ जो नवीनीकरण से वचिंत थी, उनकों 6 माह की छूट प्रदान की जायेगी। इससे लीज नवीनीकरण के साथ-साथ राज्य सरकार को राजस्व में भी लाभ मिलेगा।

राज्यसभा निर्वाचन-2026-

- राजस्थान से राज्यसभा चुनाव-2026 के लिए तीन प्रत्याशियों को निर्वाचित घोषित किया गया है। राजस्थान से राज्यसभा के लिए तीनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए है।

निर्वाचित सदस्य-

1. डॉ. अलका सिंह- भारतीय जनता पार्टी
2. डॉ. सतीश पूनिया- भारतीय जनता पार्टी
3. श्री नीरज डांगी- इण्डियन नेशनल कांग्रेस

वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य-

क्र.	नाम	दल
1 .	श्री नीरज डांगी	इण्डियन नेशनल कांग्रेस (कांग्रेस)
2 .	डॉ. सतीश पूनिया	भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)
3 .	डॉ. अलका सिंह	भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)
4 .	श्री घनश्याम तिवारी	भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)
5 .	श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला	इण्डियन नेशनल कांग्रेस (कांग्रेस)
6 .	श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक	इण्डियन नेशनल कांग्रेस (कांग्रेस)
7 .	श्री प्रमोद कुमार	इण्डियन नेशनल कांग्रेस (कांग्रेस)
8 .	श्री चुन्नीलाल गरासिया	भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)
9 .	श्री मदन राठौर	भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)
10 .	श्रीमती सोनिया गांधी	इण्डियन नेशनल कांग्रेस (कांग्रेस)

नवगठित जिलों में होगा 'नागरिक सुरक्षा कोर' का गठन-

- हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 16 जून, 2026 को 8 नवगठित जिलों में 'नागरिक सुरक्षा कोर' का गठन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की। यह स्वीकृति वर्ष 2025-26 की बजट घोषणा के क्रम में हुई है।
- नागरिक सुरक्षा कोर नवगठित जिलों में आपदा प्रबंधन, नागरिक सुरक्षा तथा आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा सहायक होगी है।
- Note- आठ नवगठित जिलों (बालोतरा, डीडवाना-कुचामन, फलौदी, सलूम्बर, खैरथल-तिजारा, डीग, कोटपूतली-बहरोड़ एवं ब्यावर)

राज्य में एनआईए मामलों के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना को मंजूरी-

- हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 16 जून, 2026 को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) मामलों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायालय की स्थापना करने की स्वीकृति प्रदान की है।
- इस विशेष न्यायालय की स्थापना से राज्य में न्यायिक प्रक्रिया अधिक सुदृढ़ और प्रभावी होगी तथा मामलों के त्वरित निस्तारण में सहायता मिलेगी।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए)-

- स्थापना- इसकी स्थापना 26/11 मुंबई हमलों के मद्देनजर राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत की गयी थी।
- यह एक केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है।

कुंदनपुरा गांव में स्थापित हुआ देश का पहला एग्री पीवी प्लांट-

- हाल ही में जयपुर जिले के कुंदनपुरा गांव (बस्सी-तूंगा) में देश का पहला एग्री पीवी प्लांट स्थापित हुआ है।
- यह एग्री पीवी प्लांट इंडियन काउन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकॉनोमिक रिलेशंस (आईसीआरआईईआर) ने कोटक महिन्द्रा बैंक के वित्तीय सहयोग से पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्थापित किया है।
- यह प्लांट पूर्व में स्थापित कुसुम प्लांट के सोलर पैनल की ऊंचाई बढ़ाकर स्थापित किया गया है।

एग्री पीवी प्लांट-

- यह आधुनिक तकनीक है जिसमें सोलर पैनलों को 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर लगवाया जाता है तथा उसके बाद सोलर पैनलों के नीचे कृषि कार्य किया जाता है।

अक्षय फंड-

- सवाई माधोपुर जिला पुलिस द्वारा पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को संकट की घड़ी में त्वरित आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए एक अभिनव कल्याणकारी योजना अक्षय फंडकी शुरुआत की गई है।
- **'अक्षय फंड' की कार्यप्रणाली एवं विशेषताएं-**
  - फंड का गठन (स्वैच्छिक अंशदान)- जिले के सभी पुलिस कार्मिकों के एक दिन के वेतन के स्वैच्छिक अंशदान से इस फंड का निर्माण किया जा रहा है।
  - अनुमानित प्रारंभिक कोष- इस स्वैच्छिक अंशदान से कोष में लगभग ₹16 लाख एकत्रित होने का अनुमान है।
  - तत्काल आर्थिक सहायता- ड्यूटी के दौरान या सेवाकाल में किसी भी पुलिसकर्मी के आकस्मिक निधन की स्थिति में, उनके शोकाकुल परिजनों को ₹3 लाख की आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी।

एग्रीस्टेक एवं फर्टिलाइजर सेल्स फ्रेमवर्क-

- हाल ही में भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण तथा उर्वरक विभाग द्वारा राजस्थान के सिरोही और राजसमंद जिलों में (प्रथम चरण) 25 जून, 2026 से 'फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल्स' को एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया है।

उद्देश्य-

- उर्वरकों पर दी जाने वाली भारी सरकारी सब्सिडी का लाभ केवल वास्तविक और पात्र किसानों तक पहुंचाना।
- अनुदानित उर्वरकों के गैर-कृषि कार्यों (औद्योगिक उपयोग) में डायवर्जन, कालाबाजारी और जमाखोरी को पूरी तरह रोकना।
- डिजिटल माध्यम से उर्वरकों की उपलब्धता, स्टॉक प्रबंधन और वितरण की रीयल-टाइम निगरानी सुनिश्चित करना।

नई वितरण कार्यप्रणाली-

1. टोकन बुकिंग- ऑनलाइन या ई-मित्र माध्यम
2. टोकन जनरेशन एवं वैधता- 48 घंटे की समय-सीमा
3. उर्वरक प्राप्ति का उठाव- नजदीकी डीलर से

30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह-2026

- 29 जून, 2026 को जयपुर स्थित बिड़ला ऑडिटोरियम में 30वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
- इस सम्मान समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में जनसहभागिता और सामाजिक योगदान को सम्मानित करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया।
- इस समारोह में 276 से अधिक भामाशाहों, प्रेरकों एवं एनआरआई (NRI) दानदाताओं को सम्मानित किया गया।
- इन भामाशाहों द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण (जैसे- नए भवन निर्माण, अतिरिक्त निर्माण, भूमि दान व भौतिक संसाधन) के लिए कुल 318 करोड़ रुपए का सहयोग दिया गया।

पुरस्कार-

सम्मान/श्रेणी	संख्या	विवरण/विशेष नोट
शिक्षा विभूषण	49 भामाशाह	उत्कृष्ट एवं वृहद वित्तीय सहयोग हेतु
शिक्षा भूषण	105 भामाशाह	उल्लेखनीय भौतिक व आर्थिक सहयोग हेतु
प्रेरक सम्मान	99 प्रेरक	दानदाताओं को प्रेरित करने वाले व्यक्तित्व
एनआरआई (NRI) दानदाता	23 दानदाता	कुल सम्मानित सूची में शामिल प्रवासी भारतीय

ओकुहेपा के लिए डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी सम्मानित -

- हाल ही में मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद के अंतर्गत संचालित साहित्य अकादमी ने वर्ष 2024 के अखिल भारतीय एवं प्रादेशिक कृति पुरस्कारों की घोषणा की है।
- अखिल भारतीय प्रोफेसर विष्णुकांत शास्त्री पुरस्कार आईएएस अधिकारी एवं साहित्यकार डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी को उनके हिन्दी यात्रा-वृत्तांत 'ओकुहेपा' के लिए प्रदान किया जाएगा।

डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी-

- o यह आईएएस अधिकारी एवं साहित्यकार है।
- o यह मूल रूप से राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से हैं।
- o उनकी अन्य प्रमुख साहित्यिक कृतियों में राजस्थानी कहानी संग्रह 'भरखमा' और 'रणखार' भी प्रमुख प्रसिद्ध कृति हैं।

आरटीआई लिविंग म्यूजियम-

- प्रदेश के ब्यावर जिले में ढाई करोड़ की लागत से दुनिया का पहला आरटीआई लिविंग म्यूजियम बनाये जाने की घोषणा की गयी है।
- इस म्यूजियम के लिए नरबद खेड़ा, केसरपुरा क्षेत्र में एक एकड़ जमीन चिह्नित की गई है। म्यूजियम का निर्माण और संचालन स्कूल फॉर डेमोक्रेसी (लोकतंत्र की पाठशाला) संस्था की ओर से किया जायेगा।
- इस संग्रहालय को पारंपरिक म्यूजियम से अलग एक लिविंग म्यूजियम (जीवंत संग्रहालय) के रूप में विकसित किया जायेगा जिसमें वर्ष 1996 के ब्यावर धरने और जनआंदोलन से जुड़े दुर्लभ दस्तावेज रखे जायेंगे।
- प्रदेश के ब्यावर जिले से ही आरटीआई के लिए आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसके बाद जयपुर और अन्य जगह पर आंदोलन किया गया।

राज्य में 132 एलपीजी फ्री जोन चिन्हित-

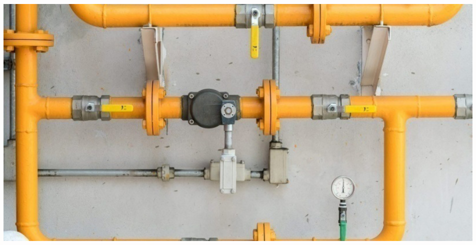

- हाल ही में मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास के निर्देशन में 1 जून, 2026 को आयोजित राज्य की सीजीडी संस्थाओं की बैठक में राज्य में 132 एलपीजी फ्री जोन चिन्हित किए गए हैं।
- राज्य में चिन्हित इन एलपीजी फ्री जोन क्षेत्रों में भविष्य में केवल पाइपलाइन (DPNG) से गैस सप्लाई होगी और सिलेंडरों की जरूरत नहीं रहेगी।
- इसके अलावा सरकार ने जून के अंत तक 43 हजार परिवारों को पाइपलाइन से घरेलू गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर मुख्यमंत्री की प्रमुख घोषणा

27 जून, 2026 को कॉन्स्टीट्यूशनल क्लब, जयपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर मुख्यमंत्री ने प्रमुख घोषणाएँ की है जो निम्न है-

हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पाद

- हस्तशिल्पियों, बुनकरों और सूक्ष्म उद्यमों के उत्पादों के लिए पहले चरण में पुष्कर, नाथद्वारा, जैसलमेर और अलवर में हाटों का विकास एवं संचालन किया जाएगा।
- पंच गौरव योजना में चिन्हित प्रजातियों और वनस्पति संबंधी प्रसंस्करण इकाइयों को 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट' (ODOP) योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाएगी।

रिप्स और निवेश नियमों में बदलाव

- रिप्स में एमएसएमई के लिए कैपिटल सब्सिडी की अवधि 10 वर्ष से घटाकर 7 वर्ष की गई।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर क्षेत्र-**
  - o रिप्स-2024 में न्यूनतम निवेश की सीमा को घटाकर 15 करोड़ रुपये किया गया है।
  - o भारत सरकार की ईसीएमएस (ECMS) योजना के तहत आने वाली परियोजनाओं को अब 3 चरणों के बजाय 5 चरणों में निवेश की अनुमति होगी।
  - o कौशल भत्ता- इस क्षेत्र में कौशल और प्रशिक्षण के लिए महिला एवं दिव्यांग कार्मिकों का अधिकतम भत्ता 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।

स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन

- o राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड- इस फंड के माध्यम से इस वर्ष 25 नए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

- **अन्य-**
  - o राजस्थान औद्योगिक विकास नीति और ओडीओपी कॉफी टेबल बुक का विमोचन।
  - o रैम्प (RAMP - राइजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस) पोर्टल का शुभारंभ।

दौलतपुरा टोल प्लाजा पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली शुभारंभ-

- हाल ही में एनएचएआई ने एनएच-48 के दिल्ली-जयपुर खंड पर स्थित दौलतपुरा टोल प्लाजा पर राजस्थान की पहली मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली का शुभारंभ किया है।
- इस टोल प्लाजा पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन और फास्ट टैग जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करके, वाहनों को बिना रुके निर्बाध टोल संग्रह की सुविधा प्रदान होगी।
- इससे यात्रा के समय में कमी, राजमार्ग पर भीड़ कम, ईंधन दक्षता में सुधार, वाहनों के उत्सर्जन में कमी और टोल संचालन में मानवीय हस्तक्षेप कम होगा।

मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF)-

- एक आधुनिक टोलिंग प्रणाली है, जिसमें वाहनों को टोल प्लाजा पर बिना रुके, सामान्य गति से गुजरने की अनुमति मिलती है।

प्रदेश में नया बिल्डिंग बायलाज लागू-

- हाल ही में राज्य सरकार ने राजस्थान में नए मॉडल बिल्डिंग बायलॉज के लिए नियम लागू किये है तथा शहरों में बहुमंजिला इमारतों की ऊंचाई (70 मीटर) पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है।
- हाईराइज बिल्डिंग की ऊंचाई (70 मीटर) का यह प्रतिबंध हटाने का फैसला उन इमारतों पर लागू होगा जिनमें फायर फाइटिंग सिस्टम उपलब्ध होगा।
- वर्ष 2020 से राजस्थान में सबसे ऊंची फायर लेडर की ऊंचाई के आधार पर अधिकतम 70 मीटर ऊंचे भवन निर्माण की अनुमति का प्रावधान लागू किया गया था।
- नए मॉडल बिल्डिंग बायलॉज में अब 'इंडियन स्टैंडर्ड कोड' को लागू किया गया है जबकि पहले 'नेशनल बिल्डिंग कोड' प्रभावी थे।

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के नवीन प्रतीक चिन्ह (लोगो) का अनावरण-

RREC
Powering a Green Future

- हाल ही में ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने 19 जून, 2026 को राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के नए प्रतीक चिन्ह (लोगो) का अनावरण किया।
- यह प्रतीक चिन्ह स्वच्छ, हरित एवं सतत् ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान की उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है।

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम-

- गठन- अगस्त, 2002 में
- इसका गठन राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी और राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड को मिलाकर किया गया था।
- पंजीकृत- कंपनी अधिनियम 1956 के तहत
- यह राज्य में गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए राज्य नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है।

जयपुर डिस्कॉम ने शुरू किया निःशुल्क स्मार्ट आईओटी डिवाइस प्रोजेक्ट-

- हाल ही में जयपुर डिस्कॉम ने 20 जून, 2026 को प्रौद्योगिकी कंपनी फ्लॉक एनर्जी के सहयोग से जयपुर में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के एयर कंडीशनर पर निःशुल्क स्मार्ट आईओटी डिवाइस लगाने का प्रोजेक्ट शुरू किया है।
- यह प्रोजेक्ट फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वैशालीनगर, मानसरोवर एवं मालवीय नगर में करीब 2 हजार विद्युत उपभोक्ताओं के घरों में लागू किया जा रहा है।
- यह पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान विद्युत नियामक प्राधिकरण के डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी एवं डिमांड साइड मैनेजमेंट विनियम-2026 के अन्तर्गत प्रारंभ किया गया है।
- यह जयपुर डिस्कॉम की ग्रिड सुरक्षा एवं बिजली बचत की दिशा में अनूठी पहल है।
- इस तकनीक के माध्यम से पीक ऑवर्स में बिजली का अत्यधिक उपभोग करने वाले घरेलू उपकरणों, विशेष रूप से एयर कंडीशनरों की बिजली खपत को स्वचालित रूप से नियंत्रित किया जा सकेगा।
- इससे करीब 2000 विद्युत उपभोक्ताओं के एसी के उपयोग को एडीआर तकनीक से जोड़कर बिजली की खपत में 1 मेगावाट तक की कमी लाई जा सकेगी।

पैमाना रिपोर्ट

- हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी 'पैमाना रिपोर्ट' के अनुसार राजस्थान में ₹2.72 लाख करोड़ से अधिक की कुल 81 परियोजनाएं संचालित हो रही हैं।

संचालित प्रमुख परियोजना

पेट्रोलियम और रिफाइनरी

- राजस्थान रिफाइनरी परियोजना (बाड़मेर, पचपदरा)- यह प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसकी कुल लागत ₹79,459 करोड़ है।
- पेट्रोकेमिकल निकासी एवं विपणन टर्मिनल (बाड़मेर)- HPCL द्वारा ₹461 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। इसे दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

ऊर्जा क्षेत्र-

- राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ₹75,000 करोड़ से अधिक की 19 परियोजनाएं चल रही हैं।

रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर (उत्तर-पश्चिम रेलवे)-

- रेलवे सेक्टर में कुल ₹1,64,998 करोड़ की 23 परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें ₹1,55,524 करोड़ के 10 बहुराज्यीय प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं।

सड़क एवं राजमार्ग विकास-

- सड़क परिवहन मंत्रालय और NHAI के जरिए प्रदेश में ₹18,000 करोड़ की 28 परियोजनाएं चल रही हैं।

नागरिक उड्डयन (हवाई अड्डे)-

- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा ₹2,874 करोड़ की लागत से 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं चलाई जा रही हैं-
  1. कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा
  2. उदयपुर हवाई अड्डा (एकीकृत टर्मिनल)
  3. जोधपुर हवाई अड्डा (नया घरेलू पैसेंजर टर्मिनल)

राजस्थान में ग्रामीण सड़क नेटवर्क होगा मजबूत:-79 ग्रामीण सड़कों की मंजूरी

- हाल ही में राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 की बजट घोषणा को क्रियान्विति करते हुए प्रदेश में 79 ग्रामीण सड़क निर्माण कार्यों को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है।
- सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जारी स्वीकृतियों के तहत पाँच विधानसभा क्षेत्रों में कुल 151.75 किलोमीटर लंबाई की सड़कों (अनुमानित लागत 68.30 करोड़ रुपये) के निर्माण एवं विकास कार्य किए जाएंगे।

विधानसभा क्षेत्र-

- झालावाड़ जिले के झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र में
- झुनझुनू जिले के नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में
- जोधपुर जिले के भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में
- अलवर जिले के राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में
- ब्यावर जिले के जैतारण विधानसभा क्षेत्र में

रीको ने कार्यस्थल पर खेल सुविधाएं विकसित करने के लिए 12 भूखंड आवंटित किए-

- हाल ही में रीको द्वारा 1 जून, 2026 को औद्योगिक क्षेत्रों में खेल सुविधाओं को विकसित करने के लिए 10 जिलों में 12 भूखंड आवंटित तथा 'प्लग एंड प्ले' बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 3 भूखंडों का आवंटन किया है।
- इन आवंटित भूखंडों का कुल क्षेत्रफल करीब 9 एकड़ है, जिससे करीब रीको को 228 लाख रूपए का वार्षिक किराया प्राप्त होगा।
- इन भूखंडों का आवंटन 15 वर्षों के लिए, तत्पश्चात 10 वर्षों का विस्तार भी नियमानुसार दिया जा सकेगा।

खेल सुविधाएं- कुल 12 भूखंड-

क्र.सं.	जिला	आवंटित औद्योगिक क्षेत्र
1	जयपुर	सीतापुरा फेज-तृतीय
2	जयपुर	अपैरल पार्क
3	जयपुर	बगरू (छितरौली)
4	कोटा	इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र
5	जोधपुर	बोरानाडा
6	सिरोही	आबू रोड (अर्बुदा)
7	खैरथल-तिजारा	भिवाड़ी (कारोली)
8	झुंझुनू	झुंझुनू-द्वितीय
9	अजमेर	किशनगढ़
10	पाली	पाली फेज-IV
11	सवाई माधोपुर	खेरड़ा
12	सीकर	रींगस विस्तार

'प्लग एंड प्ले' सुविधाएं- कुल 03 भूखंड-

1. जयपुर- सीतापुरा फेज-तृतीय
2. जोधपुर- बोरानाडा स्थित एग्रो फूड पार्क
3. कोटा- एग्रो फूड पार्क (रानपुर)

आभा आईडी बनाने में राज्य को दूसरा स्थान प्राप्त-

- राजस्थान ने 7 करोड़ 19 लाख से अधिक आभा आईडी बनाकर देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। सर्वाधिक आभा आईडी बनाने में उत्तरप्रदेश शीर्ष स्थान पर है।
- वर्ष 2026 में देश भर में कुल आभा खातों की संख्या 90 करोड़ के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर चुकी है।

'आभा' (Ayushman Bharat Health Account)

- यह एक विशिष्ट डिजिटल स्वास्थ्य पहचान है, जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का एक प्रमुख आधार स्तंभ है।
- इसके तहत प्रत्येक पंजीकृत नागरिक की 14 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या बनती है, जो रोगी की मेडिकल हिस्ट्री का आधार होती है।

'सहकार से समृद्धि' अभियान और डोर-स्टेप बैंकिंग का विस्तार-

- राज्य में संचालित 'सहकार से समृद्धि' अभियान के तहत राज्य की ग्रामीण आबादी को घर तक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए फिनटेक आधारित डोर-स्टेप बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया जायेगा।
- इस अभियान के अंतर्गत ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स) एवं प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों को बैंक मित्र बनाकर माइक्रो एटीएम उपलब्ध कराए जा रहे हैं जो नाबार्ड (NABARD) की वित्तीय सहायता से संचालित हो रही है।
- वर्तमान में लगभग 2,700 पैक्स तथा बैंक मित्र के रूप में कार्यरत 557 प्राथमिक डेयरी समितियों को माइक्रो एटीएम दिए जा चुके हैं।

आगामी लक्ष्य-

- 30 सितम्बर, 2026 तक- 5 हजार सहकारी समितियों को बैंक मित्र बनाकर माइक्रो एटीएम उपलब्ध कराने का लक्ष्य।
- 31 मार्च 2027 तक- सभी सक्रिय 12 हजार प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को बैंक मित्र बनाकर माइक्रो एटीएम उपलब्ध कराने का लक्ष्य।

पैक्स (PACS) का गठन-

- राज्य में 9 हजार 500 से अधिक ग्राम पंचायतों में पैक्स का गठन किया जा चुका है। राज्य सरकार का लक्ष्य प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पैक्स स्थापित करना है।

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत संचालित होंगी 1150 इलेक्ट्रिक बसें-

- प्रदेश में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गठित राज्य स्तरीय संचालन समिति की द्वितीय बैठक 4 जून. 2026 को मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
- प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना योजना के अंतर्गत राजस्थान के 8 शहरों को कुल 1150 इलेक्ट्रिक बसें आवंटित की गई हैं, जिनका ट्रायल पूरा हो चुका है।

प्रदेश में शहर-वार ई-बसों का आवंटन-

क्र.सं.	शहर का नाम	आवंटित ई-बसों की संख्या
1.	जयपुर	450
2.	जोधपुर	125
3.	बीकानेर	125
4.	अजमेर	100
5.	अलवर	100
6.	कोटा	100
7.	उदयपुर	50
8.	सीकर	50
9.	भीलवाड़ा	50

- Note- हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 20 जून, 2026 को प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत जेसीटीएसएल की 29 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसों और भीलवाड़ा में 18 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया।

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना

- केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी- 16 अगस्त, 2023
- संबंधित मंत्रालय- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
- वित्तीय परिव्यय- ₹57,613 करोड़

उद्देश्य

- सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करना
- ई-मोबिलिटी को बढ़ावा
- अर्बन मोबिलिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास

इंडिया स्टोनमार्ट 2028-रीको, सिडोस और लघु उद्योग भारती के मध्य त्रि-पक्षीय एमओयू-

- हाल ही में इंडिया स्टोनेमार्ट 2028 के आयोजन के लिए 16 जून, 2026 को रीको, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स (सिडोस) और लघु उद्योग भारती के मध्य त्रि-पक्षीय एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है।
- इससे इंडिया स्टोन मार्ट-2028 का ऐतिहासिक आयोजन होगा और राजस्थान का पत्थर पूरी दुनिया में पहुंचेगा।

इंडिया स्टोनमार्ट-2028

- संस्करण- 14वां संस्करण
- आयोजन तिथि- 17-20 फरवरी, 2028
- इसके लिए 11 देशों में रोड शो आयोजित किए जाएंगे।

मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (इंडिया) द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को वैश्विक सम्मान प्रदान किया गया-

- हाल ही में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा राज्य स्तर पर अब तक का सर्वश्रेष्ठ और ऐतिहासिक विद्युत उत्पादन करने की उपलब्धि को मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (इंडिया) द्वारा रिकॉर्ड श्रेणी में दर्ज किया गया है।
- इसके लिए 25 जून, 2026 को जयपुर स्थित 'विद्युत भवन' में वैश्विक सम्मान पत्र प्रदान किया गया।

ऐतिहासिक रिकॉर्ड-

- रिकॉर्ड तिथि- 2 जून, 2026 को।
- सर्वोच्च उत्पादन- अब तक का उच्चतम 7,171 मेगावाट विद्युत उत्पादन।
- कुल क्षमता व इकाइयाँ- कुल 7,580 मेगावाट क्षमता की सभी 23 थर्मल इकाइयों के माध्यम से।
- क्षमता उपयोग- 94.60 प्रतिशत यूटिलाइजेशन के साथ यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन।

हनुमानगढ़ में पोटाश एवं हैलाइट ब्लॉकों की सफल नीलामी-

- केन्द्रीय खान मंत्रालय ने हाल ही में राजस्थान में दो पोटाश एवं हैलाइट ब्लॉकों की सफल नीलामी पूर्ण की है।

ब्लॉक अधिगृहित कम्पनी-

- o हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड- जंडावाली सतीपुरा अमलगमेटेड पोटाश एवं हैलाइट ब्लॉक
- o ऑयल इंडिया लिमिटेड- जोड़कियां, सतीपुरा, खुंजा अमलगमेलटेड पोटाश एवं हैलाइट ब्लॉक

- यह भारत में पहली बार किसी पोटाश ब्लॉक की नीलामी हुई है।
- भारत अधिकांश पोटाश विदेशों से आयात करता रहा है।

प्रदेश के पीएम श्री स्कूलों को पहली बार सर्वाधिक बजट-

- केंद्र सरकार से पीएम श्री योजना में सत्र 2026-27 के लिए राजस्थान की पीएम श्री स्कूलों के लिए को 226.38 करोड़ का बजट आवंटित किया है।
- इस बजट में आवर्ती मद में 215.72 करोड़ रुपए और अनावर्ती मद में 10.66 करोड़ रुपए शामिल हैं।
- इस राशि से राज्य के 649 पीएम श्री विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं विकसित की जायेगी हो सकेंगी।

महोत्सव/सम्मेलन/ बैठक/ अभियान/आपरेशन

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 की समीक्षा बैठक-

- हाल ही में मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में 2 जून, 2026 को स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी।
- इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के शहरों को स्वच्छ, आधुनिक और वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन आधारित मॉडल के रूप में विकसित करना था।
- मिशन के तहत जयपुर में संचालित 1000 TPD (टन प्रतिदिन) क्षमता के 'वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट' के सन्दर्भ में समीक्षा और स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियों को पुख्ता करने के निर्देश प्रदान किये गये।
- वर्त्तमान में प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अंतर्गत 4804.94 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत हैं। वर्तमान में 27 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र संचालित हैं।

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी

- शुरुआत- 2 अक्टूबर, 2014
- नोडल मंत्रालय- आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
- योजना प्रकार- केंद्र प्रायोजित योजना

उद्देश्य-

- शहरी भारत को ओडीएफ एवं कचरा मुक्त बनाना।
- 100% वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।
- व्यवहार परिवर्तन एवं जनभागीदारी को बढ़ावा।
- चक्रीय अर्थव्यस्था एवं वेस्ट टू वेल्थ विकसित करना।
- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 1.0 (2014–2019)
- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 (2021–2026)
- वित्तीय परिव्यय- लगभग ₹1.41 लाख करोड़

आईएफएमएस 3.0 वेबिनार-

- हाल ही में राज्य के मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने सचिवालय से आयोजित आईएफएमएस 3.0 वेबिनार में निर्देश प्रदान किये।

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आई. एफ. एम. एस)-राजस्थान

- यह राजस्थान सरकार के लिए एक व्यापक डिजिटल मंच है जो वित्तीय उत्कृष्टता के लिए एकीकृत समाधान है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का आधुनिकीकरण करना है।
- यह प्रणाली बजट, व्यय प्रबंधन, राजस्व संग्रह और लेखांकन जैसे विभिन्न वित्तीय कार्यों को एक एकीकृत डिजिटल मंच में एकीकृत करती है, जिससे सरकारी वित्तीय कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

नारी चौपाल-नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम-

- यह कार्यक्रम 10 जून, 2026 को प्रदेश में सभी जिला और ब्लॉक स्तर पर आयोजित हुआ।
- इस कार्यक्रम में बाल विवाह रोकथाम, साइबर सुरक्षा, एनीमिया रोकथाम, लिंगानुपात सुधार, सर्वाइकल कैंसर और बालिकाओं को इसकी वैक्सीन देकर बचाव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी प्रदान की गयी।

अमृत सेवा अभियान-

- यह जयपुर नगर निगम द्वारा निर्जला एकादशी के अवसर पर 25 जून, 2026 को चलाया गया मिशन है।
- इस अभियान का उद्देश्य भीषण गर्मी के बीच आमजन को राहत पहुंचाने तथा सेवा एवं जनकल्याण की भावना को सशक्त करना था।

ऑपरेशन जमुहार-

- यह राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा 5 राज्यों में चलाया गया मादक पदार्थ विरोधी ऑपरेशन था।
- इस ऑपरेशन के तहत मणिपुर से राजस्थान लाइ जा रही लगभग 4.5 करोड़ की अवैध अफीम की खेप को पकड़ा गया।
- इस ऑपरेशन का नामकरण (ज-मु-हा-र) पाँच राज्यों के शुरुआती अक्षरों को मिलाकर किया गया-
  - ज- जम्मू (जहां मुख्य सूत्रधार बैठा था)
  - म- मणिपुर (जहां से नशे की खेप चली)
  - उ- उत्तर प्रदेश (ट्रांजिट पॉइंट - लखनऊ)
  - हा- हरियाणा (जहां माल को दबोचा गया)
  - र- राजस्थान (जहां नशे की सप्लाई होनी थी)

ग्रामीण सेवा शिविर-2026-

- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन को राज्य सरकार की विभिन्न जन-कल्याणकारी एवं फ्लैगशिप योजनाओं का सीधा लाभ पहुँचाने के लिए ग्रामीण सेवा शिविर-2026 का आयोजन किया गया।

ग्रामीण सेवा शिविर-2026-

- अवधि- 12 जून से 15 जुलाई, 2026 तक
- नोडल विभाग- राजस्व विभाग
- इस शिविर के दौरान जारी होने वाले सभी दस्तावेजों और प्रमाण-पत्रों पर "ग्रामीण सेवा शिविर-2026" की विशेष मोहर लगाई गयी।
- प्रमुख शासन सचिव (राजस्व) के निर्देशन में शिविर की प्रभावी समीक्षा के लिए राज्य स्तर पर एक समन्वय प्रकोष्ठ का गठन किया गया था।
- शिविर में आने वाले प्रत्येक नागरिक का कार्य उसी दिन पूर्ण करने का प्रयास किया गया। इस शिविर के तहत राजस्व विभाग के अलावा 21 अन्य महत्वपूर्ण विभागों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

- प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आमजन को शिविरों के माध्यम से एक ही स्थान पर त्वरित और पारदर्शी समाधान उपलब्ध कराने के लिए शहरी सेवा शिविर-2026 का आयोजन किया गया।

शहरी सेवा शिविर-2026

- अवधि- 12 जून से 15 जुलाई, 2026 तक
- नोडल विभाग- नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग
- आयोजन स्थल- नगर निगम / नगर परिषद / नगर पालिका में आयोजित

शिविर में प्रदान की गयी सेवाएं

- पट्टा एवं भूमि संबंधी सेवाएं, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना
- पेंशन एवं जनकल्याणकारी योजनाएं
- जलापूर्ति एवं सीवरेज संबंधी समाधान, स्वच्छता, सफाई एवं कचरा प्रबंधन
- स्ट्रीट लाइट समस्या का निवारण, सड़क, नाली एवं सार्वजनिक स्थलों का सुधार
- आवारा पशु नियंत्रण एवं समाधान, भवन अनुमति, मानचित्र स्वीकृति एवं अन्य सेवाएं

> हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 25 जून, 2026 को लोकतंत्र सेनानियों की मासिक पेंशन 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये तथा मासिक चिकित्सा सहायता 4 हजार रुपये से बढ़ाकर 5 हजार रुपये करने की घोषणा की है।

ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन (एनसीईजी)

- संस्करण- 29वां
- विषय- विकसित भारत 2047: एआई एनेबल्ड, डेटा ड्रिवेन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेन्स
- आयोजन तिथि- 1-2 जुलाई, 2026
- आयोजन स्थल- राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी), जयपुर
- आयोजक- प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राजस्थान सरकार
- नॉलेज पार्टनर- नैस्कॉम एवं एमएनआईटी, जयपुर
- उद्घाटन- मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा
- उद्देश्य- ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना, सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदर्शित करना और सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए भारत में डिजिटल शासन के नवीनतम पहलुओं पर विचार-विमर्श करना।

लम्पी स्किन डिजीज राज्य स्तरीय टीकाकरण अभियान-

- चरण- द्वितीय
- लाँच तिथि- 24 जून, 2026
- स्थल- श्री तिजारती सर्राफान चैम्बर गौशाला, ब्यावर
- इस अभियान का शुभारम्भ राजस्थान के पशुपालन, डेयरी एवं गोपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत द्वारा किया गया।
- इस अभियान के अंतर्गत होमोलॉगस रांची स्ट्रेन लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का उपयोग किया जा रहा है। यह लम्पी रोग के लिए विशेष रूप से तैयार की गई वैक्सीन है।

"खिलौना बैंक" एवं "प्रवेशोत्सव एवं पौधारोपण" कार्यक्रम-

- आयोजन स्थल- प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्र
- आयोजन तिथि-24 जून से 1 जुलाई, 2026
- उद्देश्य- आंगनबाड़ी केंद्र पर 3-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शाला पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराना।
- इस कार्यक्रम में जनसहभागिता से खिलौने जुटाकर बच्चों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा दिया जायेगा। जिन बच्चों के लिए खिलौने अब उपयोगी नहीं रहे, आंगनबाड़ी के छोटे बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास हेतु उनसे खिलौने एकत्रित किए जाएंगे।
- प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर 10-20 सुरक्षित खिलौने एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया है।

क्षितिज कार्यक्रम-

- आयोजन तिथि- 27 जून, 2026
- आयोजन स्थल- बिड़ला सभागार, जयपुर
- आयोजक- द इन्टीट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा

राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान-

- आयोजन तिथि- 28 जून से 30 जून, 2026
- इसके तहत प्रदेश के 1.04 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गयी।
- अभियान के प्रथम दिन 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को बूथ पर दवा पिलाई गयी तथा अगले 2 दिन पर घर-घर जाकर टीमों के द्वारा बच्चों को खुराक पिलाई गयी।

पल्स पोलियो अभियान के सन्दर्भ में स्मरणीय तथ्य-

- भारत में वर्ष 1995 में पल्स पोलियो अभियान के शुरूआत की गई। 27 मार्च, 2014 को भारत को पल्स पोलियो मुक्त प्रमाण पत्र मिल चुका है।
- वर्ष 2026 में अभी तक पाकिस्तान में 3, अफगानिस्तान मे 4 पोलियो पाए गए हैं। जनवरी, 2011 के पश्चात गत 15 वर्षों में भारत में कोई भी पोलियो का नया केस नहीं पाया गया है।

प्रोजेक्ट लक्ष्मण रेखा-

- यह राजस्थान पुलिस की एएनटीएफ शाखा द्वारा चलाया गया है।
- यह नशामुक्त राजस्थान अभियान के तहत संचालित किया गया है।
- इसके तहत प्रदेश के शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन, शिक्षकों और विद्यार्थियों को 'नशा विरोधी योद्धा' बनाया जायेगा और संस्थानों के आसपास 500 मीटर क्षेत्र को नशामुक्त क्षेत्र के रूप में विकसित किया जायेगा।

'समृद्धि' पायलट प्रोजेक्ट-

- बीसलपुर बांध में कमांड एरिया एरिया आधुनिकीकरण के तहत 'समृद्धि' पायलट प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा।
- इसके तहत किसानों को नहरों से आगे खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए प्रेशराइज्ड पाइपलाइन नेटवर्क विकसित किया जाएगा।
- यह प्रोजेक्ट/परियोजना 'मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डवलपमेंट' (एम-कैड) योजना के तहत संचालित की जा रही है।
- इसमें देशभर में चयनित 32 पायलट परियोजनाओं में राजस्थान से बीसलपुर परियोजना को शामिल किया गया है।

टैक्सकॉन-2026 शिखर-

- आयोजन तिथि- 26 जून, 2026
- आयोजन स्थल- राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर
- आयोजक- टैक्स कंसल्टेंट एसोसिएशन
- उद्देश्य- कर कानूनों में हुए नवीनतम बदलावों की जानकारी देकर टैक्स प्रोफेशनल्स की जिज्ञासाओं और व्यावहारिक चुनौतियों का समाधान करना।

स्पोर्ट्सकॉन - 2026

- यह जयपुर में आयोजित दो दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव था जिसमें 250 से अधिक युवा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
- इस आयोजन में खेल, नीति-निर्माण, खेल प्रशासन, रणनीति और मीडिया से जुड़े समसामयिक विषयों पर गहन चर्चा एवं विचार-विमर्श किया गया।

चर्चित योजना/व्यक्ति/स्थान/अन्य

आरपीएससी में दो नये सदस्यों की नियुक्ति-

- हाल ही में राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने राजस्थान लोक सेवा आयोग में प्रो. (डा.) संतोष आनंद और डा. दीपक कुमार शर्मा को सदस्य पद पर नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं।
- इनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने से छह वर्ष तक के लिए अथवा 62 वर्ष आयु तक के लिए (जो भी पहले हो) होगी।

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)

- स्थापना- 22 दिसम्बर, 1949
- राजस्थान लोक सेवा आयोग में 1 अध्यक्ष एवं 10 सदस्य के पद स्वीकृत है।
- अध्यक्ष व सदस्य के पद संवैधानिक पद होते है।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को आयोग कार्यालय में सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।

वर्तमान में आयोग में अध्यक्ष और सदस्य-

- अध्यक्ष (कार्यवाहक)- श्री केसरी सिंह राठौर
- सदस्य-
  - श्री बाबू लाल कटारा – निलंबित
  - श्री केसरी सिंह राठौर
  - श्री कैलाश चंद मीना
  - प्रो. अयूब खान
  - डॉ. सुशील कुमार बिस्सु
  - श्री हेमंत प्रियदर्शी
  - डॉ. अशोक कुमार कलवार
  - प्रो. दीपक कुमार शर्मा
  - प्रो. (डा.) संतोष आनंद

हनुमान सिंह राठौड़-

- हाल ही में राज्य सरकार ने हनुमान सिंह राठौड़ को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है।
- इनका कार्यकाल कार्यभार संभालने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए होगा। यह वरिष्ठ शिक्षाविद और अजमेर जिले के निवासी है।

आर.डी. बाहेती-

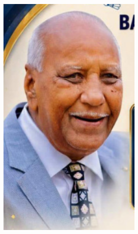

- यह समाजसेवी, श्री माहेश्वरी समाज जयपुर के पूर्व अध्यक्ष और 'हास्य सम्राट' के नाम से प्रसिद्ध थे, इनका हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्होंने वर्ष 1970 में देश के पहले 'हास्य क्लब' की स्थापना की थी। इन्होंने वर्ष 1975 में सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध उत्तर भारत का पहला सामूहिक विवाह आयोजित करवाया तथा राजस्थान स्वास्थ्य योग परिषद की स्थापना की।

मांड गायिका गवरी देवी का निधन-

- राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका गवरी देवी का 11 जून, 2026 को 98 वर्ष की उम्र में पाली में निधन हो गया।
- गवरी देवी भैरवी युक्त मांड गायिकी के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध थीं।

गवरी देवी के चर्चित गीत-

1. केसरिया बालम पधारो
2. बागा चालो केसरिया
3. ढोला मारे देश में निपजे तीन रत्न
4. अब घरे आओ गोरी साहिबा
5. आई आई सावणिया री तीज
6. मोर बोले रे मलजी

गवरी देवी के चर्चित भजन-

1. मैं तो लियो सांवरिया
2. मस्ताना रे मस्ती में
3. पुनागर माताजी री लाल

मांड गायन

- यह राजस्थान की लोक गायन शैली है।
- इसका उद्भव जैसलमेर क्षेत्र में माना जाता है, जिसे प्राचीन काल में मांड क्षेत्र कहा जाता था।
- यह शृंगार प्रधान गायन शैली है, जिसका प्रयोग राजस्थानी लोकगीतों में किया जाता है।
- पुराने समय में मांड गायन राजाओं और रजवाड़ों के दरबारों में प्रस्तुत किया जाता था।

योगेश शर्मा-

- राजस्थान न्यायिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और जिला जज है।
- इनको हाल ही में राज्य सरकार ने राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड, अजमेर में सदस्य नियुक्त किया है।
- इससे पूर्व वे विशिष्ट शासन सचिव (विधि) के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

उषा प्रियदर्शी-

- इनको हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
- इनका जन्म 12 अगस्त, 1972 को राजस्थान में हुआ था।
- उषा प्रियदर्शी पूर्व मंत्री डॉ. रोहिताश शर्मा की पुत्री हैं।

ख़ुशी गंभीर-

- यह 23 वर्षीय उदयपुर निवासी युवती है। इन्होंने उदयपुर की पहली महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव हासिल किया है।

अब्दुल गफूर आजाद-

- यह बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के हीरो थे जिनका 85 वर्ष की आयु में झालावाड़ जिले के असनावर कस्बे में निधन हो गया।
- इनको 'फौजी अब्बा' उपनाम से भी जाना जाता था। वे भारतीय सेना की एएससी (एमटी) इकाई में थे और वर्ष 1971 की जंग के दौरान सिलीगुड़ी क्षेत्र में तैनात थे।

विनीता शर्मा-

- यह जयपुर निवासी कथक नृत्यांगना है। इनको दूरदर्शन प्रसार भारती की ओर से भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक में बी-ग्रेड प्रदान किया गया है। उन्हें यह ग्रेड 'नृत्य परीक्षण-फलदक श्रेणी' में दिया गया है।

उदयपुर खुर्द क्षेत्र-

- यह क्षेत्र किशनगढ़ तहसील(अजमेर जिला) में स्थित है।
- इस क्षेत्र में 59 हेक्टेयर भूमि को डिफेंस एवं एयरोस्पेस पार्क के लिए रिजर्व किया गया है। यहां लगने वाली मेन्यूफेक्चरिंग यूनिट में स्नाइपर राइफल का निर्माण किया जाएगा।

अजुनी तिवाड़ी-

- यह जयपुर की की निवासी है। इन्होंने दून यूनिवर्सिटी में आयोजित 'राष्ट्रीय युवा संसद 2026' में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है।

प्रोफेसर मनोज पंडित

- यह राजस्थान विश्वविधालय के पूर्व प्रोफेसर व महाराजा कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल है। इनको विश्व के शीर्ष भूवैज्ञानिकों की वैश्विक सूची में जगह डी गयी है।

डॉ. हेमंत भाई गोयल-

- यह डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट है। इन्होंने 27 वर्षों तक बिना किसी सरकारी अनुदान के दिव्यांग अधिकारों के लिए निस्वार्थ संघर्ष करने पर 'लाइफटाइम ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट एंड डिसेबिलिटी राइट्स एक्सीलेंस अवार्ड' से नवाजा गया है।

डॉ. स्वरूपानन्द-

- यह जयपुर के होम्योपैथिक विशेषज्ञ है। इनको नेपाल में अंतरराष्ट्रीय आयुष कॉन्क्लेव 4.0 में 'आयुष लीजेंडरी अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया।

डॉ. वी.डी. सिन्हा-

- इनकों को एशियन ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन्स का अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया है।
- यह गौरव हासिल करने वाले डॉ. सिन्हा भारत के पहले न्यूरो सर्जन है।
- यह जयपुर के वरिष्ठ न्यूरोसर्जन और सवाईमानसिंह मेडिकल कॉलेज के पूर्व न्यूरोसर्जरी विभागाध्यक्ष है।

सार्जेंट सुरेंद्र कुमार-

- ये झुंझनूं के मेहरादासी गांव के निवासी थे। इनको भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से शहीद का दर्जा दिया है।
- यह भारतीय वायुसेना की जम्मू-कश्मीर के उधमपुर स्थित 39 विंग में मेडिकल असिस्टेंट सार्जेंट के पद पर तैनात थे जिन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान देश की सेवा करते हुए देश के लिए शहादत दी।

अनिमेष पाटनी-

- यह राजस्थान के बारां जिले के निवासी है जो वायुसेना में ग्रुप कैप्टन है। इनको ऑपरेशन सिंदूर में असाधारण शौर्य के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। उनकी यूनिट ने पाकिस्तान वायुसेना के विमान को मार गिराया था।

खेमाराम कुमावत-

- यह पांचोटा गांव, नावां उपखंड (डीडवाना-कुचामन जिला) के निवासी थे, जो भारतीय वायुसेना में अग्निवीर थे।
- यह हाल ही में असम के जोरहाट में भारतीय वायु सेना के एएन-32 विमान हादसे में शहीद हो गये।

श्री रोहित कुमार-

- यह भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1997 बैच के अधिकारी है जिनको हाल ही में नई दिल्ली में राजस्थान का प्रमुख आवासीय आयुक्त नियुक्त किया गया है।
- श्री रोहित कुमार इससे पूर्व केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर थे और नीति आयोग में अतिरिक्त सचिव के पद पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे थे।
- रोहित कुमार नई दिल्ली में राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के साथ-साथ राज्य से संबंधित मामलों के प्रभावी संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

ऑपरेशन स्माइल

- राजस्थान पुलिस अकादमी में 'ऑपरेशन स्माइल' के तहत कार्यशाला आयोजित हुई। यह ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों और कल्याण को सुनिश्चित किये जाने वाला ऑपरेशन या पहल है।

जयपुर फुट-

- हाल ही में भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (बीएमवीएसएस) ने श्रीलंका में जयपुर फुट के दो स्थायी केंद्र स्थापित किए हैं। यह केंद्र श्रीलंका के कोलंबो और जाफना में संचालित होंगे।
- Note- हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी पोर्ट-ऑफ-स्पेन में भी जयपुर फुट का नया केंद्र खुला है।

कृषक उपहार योजना के राज्य स्तरीय लॉटरी विजेताओं के नाम घोषित

- कृषि विभाग ने 15 जून, 2026 को पंत कृषि भवन में आयोजित बैठक में कृषक उपहार योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय लॉटरी विजेताओं के नामों की घोषणा की है।

लॉटरी विजेता किसान-

  - o प्रथम पुरस्कार- श्रीमती विद्या देवी, कृषि उपज मंडी समिति श्री_ विजयनगर (2.50 लाख रुपये)
  - o द्वितीय पुरस्कार- श्री हंसराज, रायसिंहनगर मंडी समिति (1.50 लाख रुपये)
  - o तृतीय पुरस्कार- श्री सुखराम, कृषि उपज मंडी समिति मेड़ता सिटी (1 लाख रुपये)
- इस पुरस्कार राशि का भुगतान संबंधित मंडी समितियों द्वारा किया जाएगा।

कृषक उपहार योजना

- नोडल विभाग-कृषि विपणन निदेशालय
- जब कोई किसान अपनी कृषि उपज मंडी में बेचता है, तो प्रत्येक ₹10,000 की विक्रय पर्ची पर ई-नाम सॉफ्टवेयर द्वारा एक उपहार कूपन नंबर जारी किया जाता है।
- इस योजना के तहत लाभार्थियों को₹10,000 से लेकर ₹2.5 लाख तकके पुरस्कार/सहायता राशि दी जाती है।

सुर्ख़ियों में-राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना

- हाल ही में राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना की तीसरी उच्चाधिकार समिति की बैठक 18 जून, 2026 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
- इस बैठक में परियोजना के विभिन्न घटकों की विस्तृत समीक्षा कर वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्य योजना प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना-

- कार्यान्वयन एजेंसी- राजस्थान वन विभाग, राजस्थान सरकार
- प्रोजेक्ट फ़ंडिंग एजेंसी- एजेंस फ्रैन्साइज़ डे डेवलपमेंट (एएफडी)
- परियोजना की अवधि- 8 वर्ष
- परियोजना की कुल लागत- 1693.91 करोड़ रुपये (एएफडी- 1185.29 करोड़ रुपये, राज्य सरकार- 508.62 करोड़ रुपये)
- परियोजना का दायरा- पूर्वी राजस्थान के 13 जिले (अलवर, बारां, भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाईमाधोपुर और टोंक)
- उद्देश्य- परियोजना क्षेत्र में वन और वन्यजीव संसाधनों का संरक्षण करना है।

सुर्ख़ियों में-वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना

- हाल ही में 'सोमनाथ स्वाभिमान महापर्व' के अंतर्गत राजस्थान सरकार की 'वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना' के तहत राज्य के 1,008 वरिष्ठ नागरिक श्रद्धालुओं ने जून,2026 में श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए।
- सोमनाथ स्वाभिमान महापर्व-इस पर्व का आयोजन सोमनाथ मंदिर के आधुनिक पुनर्निर्माण के 75वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है।

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-

- प्रारंभ- वर्ष 2013 से रेल द्वारा तथा वर्ष 2016 से रेल एवं हवाई यात्रा द्वारा
- योजना का उद्देश्य- राजस्थान के मूल निवासी वरिष्ठ नागरिकों को देश में या देश के बाहर स्थित तीर्थ स्थानों की यात्रा सुलभ कराने हेतु राजकीय सुविधा एवं सहायता प्रदान करना।

योजना में लाभार्थियो विभागीय सीमा-

- रेलमार्ग से- 50000 वरिष्ठजन
- वायुयान मार्ग से- 6000 वरिष्ठजन
- तीर्थ स्थानों की सूची-
- रेल द्वारा 15 स्थान
- हवाई जहाज द्वारा- पशुपतिनाथ (काठमांडू), नेपाल

पात्रता-

- लाभार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।
- लाभार्थी 60 वर्ष से अधिक आयु का हो।
- आवेदक स्वयं एवं जीवनसाथी आयकरदाता न हो।

चर्चा में- अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना'

- **चर्चा में क्यों?**- राजस्थान सरकार द्वारा वागड़ क्षेत्र में कृषि व्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए'अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना'पर कार्य किया जा रहा है।
- **परियोजना के सन्दर्भ में मुख्य तथ्य-**
  - o कुल अनुमानित लागत-लगभग 2,500 करोड़ रुपए।
  - o लाभान्वित क्षेत्र-बांसवाड़ा जिले की 3 विधानसभा क्षेत्र (बांसवाड़ा, बागीदौरा एवं कुशलगढ़) की 6 तहसीलें।
  - o सिंचाई क्षमता-42 हजार हेक्टेयरकृषि भूमि कोलिफ्ट सिंचाई प्रक्णालीसे पानी मिलेगा।
  - o लाभान्वित आबादी-लगभग3.5 लाख आबादीप्रत्यक्ष एवं अप्र- त्यक्ष रूप से।
  - o नहर एवं सुरंग की लंबाई-मुख्य नहर की कुल लंबाई102 किलोए- मीटरहै। इसमें 22.50 किलोमीटरलंबाई में सुरंगें/कट एंड कवर संरचनाएं, एक्वाडक्ट और नदी को पार करते हुए साइफन हैं।

सुर्ख़ियों में- सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना-

- हाल ही में मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना की बैठक आयोजित की गई।
- योजना का प्रारम्भ- अप्रैल, 2021
- वर्तमान संशोधित रूप- मई, 2023
- योजना अवधि- आगामी 5 वर्ष की अवधितक (वर्ष 2028)
- प्रशासनिक/नोडल विभाग-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

योजना का उद्देश्य

- राज्य में वंचित, बेसहारा और असहाय वर्गों के कल्याण हेतु काम करने वालेगैर-लाभकारी संगठनों (NGOs), ट्रस्टों और स्वैच्छिक संस्थाओंकी सक्रिय भागीदारी बढ़ाना। इन संस्थाओं को बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए वित्तीय संबल, करों में रियायतें और प्रशासनिक छूट प्रदान करना।

योजना के अंतर्गत पात्रता (Eligible Beneficiaries)

- कार्यरत अलाभकारी संस्था का न्यूनतम 03 वर्ष पूर्व पंजीकृत होना आवश्यक। अलाभकारी संस्था की स्थापना में न्यूनतम रूपए 50 लाख का पूंजीगत निवेश अथवा न्यूनतम 25 लाभार्थियों हेतु संचालन।

लक्षित वर्ग-

- बच्चे (अनाथ, निराश्रित, बाल श्रमिक)
- महिलाएं (परित्यक्ता, पीड़ित, बेसहारा)
- दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक (वृद्धजन)
- बेघर व्यक्ति, भिखारी और निर्धन वर्ग, ट्रांसजेंडर
- नशामुक्त होने वाले व्यक्ति, एचआईवी/एड्स प्रभावित व्यक्ति

- योजना के तहत गतिविधियां-संस्थागत देखरेख, डे-केयर सेंटर, वृद्धाश्रम, अनाथालय, नारी निकेतन, व्यावसायिक शिक्षा व कौशल प्रशिक्षण केंद्र, ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी, ओपन शेल्टर, चाइल्ड हेल्पलाइन और नशामुक्ति व पुनर्वास केंद्रों का संचालन करना।

योजना के तहत संस्थान को मिलने वाले लाभ और रियायतें-

श्रेणी	देय लाभ/छूट
भूमि एवं भवन नियमन	▪ भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में 100% छूट। नियमन शुल्कऔर विकास शुल्क में 100% छूट।स्थानीय निकायों द्वारा भवन मानचित्र अनुमोदन शुल्क में 100% छूट।
राजस्व एवं पंजीकरण	▪ आवंटित या क्रय की जाने वाली भूमि/भवन की लीज डीड, सेल डीडपर 100% स्टाम्प ड्यूटीकी छूट। ▪ पंजीकरण शुल्क में 100% छूट। किसी निजी व्यक्ति या संस्था द्वारा इन कल्याणकारी कार्यों के लिए अचल संपत्ति दान करने पर भी स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन शुल्क मुक्त।
कर में राहत	▪ संस्था द्वारा कल्याणकारी कार्यों हेतु क्रय की जाने वाली गैर-उपभोज्य वस्तुओं, उपकरणों और पूंजीगत सामग्री परराज्य वस्तु एवं सेवा कर का 100% पुनर्भरण।
वित्तीय व अन्य प्रोत्साहन	▪ संस्था के नाम पंजीकृत अधिकृत वाहनों परमोटर व्हीकल टैक्स से पूर्ण मुक्ति। ▪ इन कार्यों के लिए लिए गए ऋण पर 6% की सीमा तक ब्याज अनुदान का पुनर्भरण (अधिकतम 3 वर्ष हेतु)।

वरुण सागर झील-

- सुर्ख़ियों में- 27 जून, 2026 को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी एवं जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने वरुण सागर झील के डीसिल्टिंग कार्य का शुभारम्भ किया।
- डीसिल्टिंग से झील की जलधारण क्षमता बढ़ेगी, भराव क्षेत्र का विस्तार होगा तथा अतिक्रमण हटाकर झील को उसका मूल स्वरूप प्रदान किया जाएगा।
- **वरुण सागर झील-**
  - अवस्थित- अजमेर ज़िले में
  - यह कृत्रिम झील है।
  - निर्माण- फॉय के निर्देशन में वर्ष 1891-1892 में
  - परियोजना- बाढ़ और अकाल राहत परियोजना के तहत।
- **Note-** पहले वरुण सागर झील का नाम फॉयसागर झील था जिसे बाद में परिवर्तित कर दिया गया।

Samyak
An Institute For Civil Services

क्लास 12th के बाद

IAS & RAS

ग्रेजुएशन के साथ 2 & 3 वर्षीय कोर्स

OFFLINE & LIVE FROM CLASSROOM

बैच प्रारम्भ

COURSE FEATURES

- विषय विशेषज्ञों द्वारा क्लासेज
- प्रिंटेड बुकलेट्स
- पर्सनल मेंटरशिप
- टेस्ट सीरीज
- लाइब्रेरी सुविधा

FREE 03 DAYS DEMO CLASSES

SAMYAK IAS, NEAR RIDDHI-SIDDHI, JAIPUR

9875170111

खेल/खेल व्यक्तित्व

राजस्थान सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप-2026

- आयोजन तिथि- 30-31 मई, 2026
- आयोजन स्थल- सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर
- आयोजक- राजस्थान एथलेटिक एसोसिएशन द्वारा

पुरुष वर्ग की राजस्थान की चैम्पियन एथलीट:-

स्पर्धा	विजेता	जिला
200 मी.	धर्मवीर	टोंक
400 मी.	राकेश	पाली
800 मी.	शकील	स. माधोपुर
5000 मी.	गंभीर	जैसलमेर
10,000 मी.	मानव	जयपुर
400 मी. बाधा	शक्ति	जैसलमेर
3000 मी. स्टी.	अतुल	चूरू
20 किमी वॉक	अमित	कोटा
हाई जम्प	रामनरेश	श्रीगंगानगर
पॉल वॉल्ट	रामरतन	श्रीगंगानगर
लॉन्ग जम्प	प्रदीप	श्रीगंगानगर
ट्रिपल जम्प	युवराज	अजमेर
शॉटपुट	रामचन्द्र	राजसमंद
हैमर थ्रो	प्रवीण	स. माधोपुर
जैवलिन थ्रो	यशवीर	कोटा
डेकेथलॉन	यमनदीप	टोंक

महिला वर्ग की राजस्थान की चैम्पियन एथलीट:-

स्पर्धा	विजेता	जिला
200 मी.	रिशिता	जयपुर
400 मी.	गीता	श्रीगंगानगर
800 मी.	कमला	जोधपुर
1500 मी.	रीना	भरतपुर
5000 मी.	चतरू	बाड़मेर
10,000 मी.	लतिका	अलवर
100 मी. बाधा	गीता	जोधपुर
400 मी. बाध	गीता	जोधपुर
3000 मी. स्टी.	पारू	जोधपुर
20 किमी वॉक	कमला	नागौर
हाई जम्प	सारिका	अजमेर
पोल वॉल्ट	चुकी	नागौर
लांग जम्प	मुमुल	कोटा
ट्रिपल जम्प	रिंकू	जयपुर
शॉटपुट	कचनार	जयपुर
डिस्कस थ्रो	निकिता	जयपुर
हैमर थ्रो	कुलविन्दर	श्रीगंगानगर
जैवलिन थ्रो	संजना	झालावाड़
हेप्टाथलोन	नीता	जोधपुर

75वीं सीनियर राज्य तैराकी चैंपियनशिप-

- आयोजन स्थल- सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर
- आयोजक-राजस्थान तैराकी संघ

शीर्ष प्रदर्शनकर्ता

महिला वर्ग (संयुक्त ओवरऑल चैंपियन):

- योग्या सिंह (भीलवाड़ा)- 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक
- दक्षिणा जोशी (टोंक)- 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक
- रतिका खाटा (धौलपुर)- 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक

पुरुष वर्ग (ओवरऑल चैंपियन)-

- मोहम्मद अनस (भीलवाड़ा)- पुरुष वर्ग में शीर्ष स्थान, 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक

राज्य स्तरीय जूनियर पुरुष हॉकी-

- संस्करण- 16वीं
- आयोजन स्थल- पाली जिला
- समापन तिथि- 7 जून, 2026 को, चार दिवसीय प्रतियोगिता
- आयोजक- हॉकी पाली
- फाइनल मुकाबला-जयपुर और अलवर की टीमों के बीच
- विजेता-जयपुर (3-1 से जीत), उपविजेता-अलवर
- तीसरे स्थान के लिए खेले गए मैच में हनुमानगढ़ ने भीलवाड़ा को पराजित किया।
- भागीदार टीम- 23 टीम

पुरस्कार राशि-

- विजेता- जयपुर को, 51 हजार रुपए का नकद पुरस्कार
- उपविजेता- अलवर को, 21 हजार रुपए का नकद पुरस्कार
- तीसरा स्थान- हनुमानगढ़ को, 11 हजार रुपए का नकद पुरस्कार

विष्णु प्रजापत और शुभम कुमावत-

- यह जयपुर स्थित भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय के छात्र है।
- इनका वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता-2026 के लिए टीम इंडिया में चयन हुआ है।
- विष्णु प्रजापत 'रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी' और शुभम कुमावत 'आईटी एंड नेटवर्किंग स्किल्स' में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
- वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता-2026 चीन के शंघाई में आयोजित होगी।

ओजस्विनी सारस्वत-

- यह जयपुर निवासी युवा गोल्फ खिलाड़ी है। इन्होंने हाल ही में सिपुत्रा जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप (इंडोनेशिया में आयोजित) में 'बेस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर' श्रेणी में रनर-अप स्थान हासिल किया है।

राजेन्द्र भास्कर-

- यह जयपुर (राजस्थान) निवासी, ट्रायएथलीट है। इन्होंने फ्रांस के टूर्स मेट्रोपोल लॉयर वैली में आयोजित प्रतिष्ठित आयरनमैन प्रतियोगिता को 10 घंटे 6 मिनट 31 सेकंड में पूरा कर खिताब हासिल किया है।

पी. कृष्ण कुमार-

- यह राजस्थान के पूर्व क्रिकेटर है। इनको इंडिया-ए की महिला क्रिकेट टीम का बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया है।

लवमीत कटारिया-

- यह जयपुर के निवासी और अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी है। इनकों भारतीय वॉलीबॉल अंडर-18 टीम का चयन करने वाली भारतीय चयन कमेटी में शामिल किया गया है।

जय मूंदड़ा-

- यह मूलत: टोंक, राजस्थान के निवासी है, जिन्होंने आयरलैंड की नागरिकता प्राप्त करली है। यह भारत-आयरलैंड टी-20 क्रिकेट सीरीज में आयरलैंड की ओर से खेलेंगे।

दिव्यांशी

- यह राजस्थान की वुशू खिलाड़ी है।
- इनका चयन भारतीय वुशू टीम में हुआ है।

देवांशी शर्मा-

- यह राजस्थान पुलिस में कॉन्स्टेबल पद पर कार्यरत है। इन्होंने हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप में सीनियर-बी हैंड बैलेंस (इंडिविजुअल) वर्ग में स्वर्ण पदक जीतता है।

सविता पुनिया-

- सविता पूनिया जिनको हॉकी की 'ग्रेट वॉल'कहा जाता है, को 23 जून, 2026 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इनका जन्म जुलाई, 1990 में हनुमानगढ़ (राजस्थान) जिले के झांसल गाँव में हुआ था।

विविध तथ्य

- संवाद पहल/कार्यक्रम- यह जयपुर विकास प्राधिकरण की पहल है। इस पहल के द्वारा जेडीए द्वारा आयोजित बैठकों में संबंधित आवेदकों और हितधारकों को बुलाकर उनकी आपत्तियों, समस्याओं और सुझावों को आमने-सामने सुनकर हाथों-हाथ निस्तारण किया गया।
- स्कूल-शाला संवाद- यह शाला दर्पण पोर्टल का भाग है जहां कक्षा 1 से 12 तक के लिए विविध और गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।
- वर्ष 2025-26 के दौरान "एक जिला-एक कृषि उपज" योजना के अंतर्गत 50 हजार से अधिक किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया हैतथा "एक जिला-एक वनस्पति प्रजाति" योजना के तहत 85 लाख पौधों का वितरण किया गया है।
- हाल ही में पाली जिले के तख्तगढ़ में पशुपालन एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने राजकीय बहुउदेशीय पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस चिकित्सालय भवन का निर्माण डेढ़ करोड़ रुपए की लागत से करवाया जाएगा।
- हाल ही में राज्य में राज्यसभा के द्विवार्षिक निर्वाचन की प्रक्रिया 1 जून से आरम्भ हुई। राज्यसभा के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन 8 जून तक तथा नाम निर्देशन को 11 जून तक हुए।
- प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत योजना प्रारम्भ होने के बाद मई, 2026 में प्रदेश में रिकॉर्ड 26,632 रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। यह प्रदेश में किसी भी एक माह में हुए अब तक का सर्वाधिक रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन है।
- हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2 जून, 2026 को कोटा जिले में 4.5 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित अत्याधुनिक इंडोर खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया।
- हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण राज्यमंत्री श्री राम नाथ ठाकुर ने 3 जून, 2026 को अलवर जिले में किया खेत बचाओ अभियान का शुभारम्भ किया।
- वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान-2026 के तहत जयपुर जिले ने पूरे प्रदेश में सर्वाधिक सक्रियता दिखाते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है।
- प्रदेश में भारत टैक्सी का 4 जून, 2026 से जयपुर में ट्रायल शुरू हुआ है। यह भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा समर्थित देश का पहला सरकारी और सहकारी राइड-हेलिंग ऐप है।
- हाल ही में अलवर सांसद खेल उत्सव 2025-26 के अंतर्गत "समर कैंप 2026" (महिला वर्ग)का आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल, कोटपूतली-बहरोड़ में शुभारंभ हुआ।

- हाल ही में डॉ. प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में 12 जून, 2026 को स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल की 22वीं बैठक आयोजित हुई।
- राजस्थान स्टेट माइंस एवं मिनरल्स (आरएसएमएम) में आर एण्ड डी प्रकोष्ठ का गठन किया जा रहा है ताकि खनन क्षेत्र में शोध को बढ़ावा दिया जा सके और देश दुनिया में आ रही नवीनतम तकनीक को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उपयोग की संभावनाएं तलाशी जा सके।
- पश्चिम क्षेत्र सांस्कृति केन्द्रकीशाषी परिषद की बैठक 13 जून, 2026 को गोवा में आयोजित हुई।
- हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सेवा समिति एवं पाली सेवा मंडल के संयुक्त तत्वावधान में वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्थापित किए गए वरिष्ठ नागरिक डे-केयर सेंटर का उद्घाटन किया।
- विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम 1 जुलाई, 2026 से देश में लागू होगा।
- हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने 16 जून, 2026 को अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी विभाग का शुभारंभ किया।
- हाल ही में राज्य सरकार ने 16 जून, 2026 को बालोतरा के पचपदरा व शेरगढ़ के ग्राम नवातला एवं देवीगढ़ में 207.63 वर्ग किमी में रेयर अर्थ एलिमेंट्स खनिज के ब्लॉक की नीलामी में मैसर्स सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट को एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की स्वीकृति दी है।
- हाल ही में राज्य सरकार ने 18 करोड़ 86 लाख रुपये की लागत से कृषि उपज मण्डी समिति सोजत सिटी (पाली), पलसाना एवं श्रीमाधोपुर (सीकर), अनाज मण्डी (बीकानेर), मेड़ता सिटी (नागौर) तथा दूदू (जयपुर) के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने को मंजूरी प्रदान की है।
- हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2026 के उपलक्ष्य में राजस्थान विधानसभा परिसर स्थित कर्तव्य द्वार पर 19 जून, 2026 को सामूहिक योग कार्यक्रम 'योगोत्सव' का आयोजन किया गया।
- हाल ही में महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा 19 जून, 2026 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर में स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र अवसंरचना पहल हेतु सीएसआर भागीदारी कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- हाल ही में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 22वीं बैठक 19 जून, 2026 को शिमला (हिमाचल प्रदेश) में आयोजित हुई। इस बैठक में राज्य के मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।
- हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 19 जून, 2026 को बिड़ला ऑडिटोरियम (जयपुर) में आयोजित कार्यक्रम में ओएनडीसी डिजिदुकान एप का शुभारंभ किया।
- हाल ही में राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध संस्थान द्वारा 20 जून, 2026 को 'स्वच्छ सहकार समृद्ध सहकार' थीम पर स्वच्छता मैराथन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वच्छता एवं सहकारिता के प्रति जन-जागरूकता को बढ़ावा देना तथा इन मूल्यों को व्यवहार में अपनाने के लिए प्रेरित करना था।
- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 20 जून, 2026 को पश्चिम बंगाल से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की है। इस 23वीं किस्त का लाभ राजस्थान के 66 लाख से अधिक किसानों को प्राप्त हुआ है।
- हाल ही में राज्य सरकार ने माउंट आबू का नाम परिवर्तित करके 'आबूराज' कर दिया है।
- हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार द्वारा 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस राज्यस्तरीय समारोह आबूराज, सिरोही जिले में आयोजित किया गया।
- हाल ही में केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 21 जून, 2026 को खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस रेल सेवा का शुभारंभ किया तथा मेगा कोचिंग टर्मिनल खातीपुरा एवं रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया।
- हाल ही में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव तथा वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने 21 जून, 2026 को अलवर में नटनी के बाड़ा से जयसमंद बांध नहर पक्कीकरण कार्य एवं भाखेडा एनीकट का उद्घाटन किया।
- हाल ही में राज्य में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 22 जून, 2026 को इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) 2.0 परियोजना के क्रियान्वयन के लिए गठित समिति की बैठक आयोजित हुई।
- हाल ही में राजस्थान सरकार, रीको एवं इन्वेस्ट इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में जयपुर में 24 जून, 2026 को "रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता" विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- हाल ही में श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) में आयोजित राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में राजस्थान की उपलब्धियों को सराहा गया है।
- राजस्थान में सड़क निर्माण परियोजनाओं को गति देने के लिए बिटूमिन (डामर) का प्रावधिक मूल्य मासिक आधार पर जारी किया जाएगा। इससे सड़क निर्माण कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी।
- केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 28 जून, 2026 को राजस्थान के अलवर में "बाघों का पुनर्वास अवसर और चुनौतियां" विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया।
- 20वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस आर्थिक एवं सांख्यिकी दिवस सांख्यिकी विभाग द्वारा कॉन्स्टीट्यूशनल क्लब, जयपुर में मनाया गया। इस वर्ष सांख्यिकी दिवस की थीम 'अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनेस्ट्रेटिव डेटा' रही।

2. अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

जी-7 शिखर सम्मेलन-2026-

- संस्करण- 52वां संस्करण
- विषय- नई साझेदारियों का निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को पुनर्जीवित करना।
- आयोजन तिथि- 15-17 जून, 2026
- आयोजन स्थल-एवियन, फ्रांस
- मेजबान देश- राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन की अध्यक्षता में फ्रांस
- विशेष अतिथि देश- भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात
- जी-7 शिखर सम्मेलन कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका सहित जी7 सदस्य देशों के नेताओं के लिए प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक अंतरराष्ट्रीय मंच है।
- परिणाम-
  - फ्रांस की पहल पर कैंसर अनुसंधान, डेटा साझाकरण और मृत्यु दर कम करने को मुख्य एजेंडा बनाया गया।
  - दुर्लभ खनिजों के लिए किसी बाहरी देश पर निर्भरता को 2030 तक 60% से नीचेलाने का लक्ष्य।
  - टेक कंपनियोंके साथ मिलकर बच्चों के लिए चैटबॉट की भाषा सुधारने और प्लेटफॉर्म्स को सुरक्षित बनाने पर सहमति।

G7 समूह-

- यह एक अनौपचारिक समूह है।
- स्थापना- वर्ष 1975 में
- मुख्यालय- स्थायी मुख्यालय का अभाव
- यह समूह स्थापना के समय छह औद्योगिक देशों (फ्राँस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका) का समूह था।
- वर्ष 1976 में कनाडा के शामिल होने से यह G7, वर्ष 1998 में रूस के शामिल होने से यह G8 बना।
- Note- वर्ष 2014 में रूस को इस समूह से निष्कासित कर दिया गया था और यह वापस G7 बन गया।
- उद्देश्य- यह समूह वैश्विक स्तर पर आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यापार और ऊर्जा नीति समन्वय के को बनाये रखना।
- G-7 देश विश्व की लगभग 10% जनसंख्या वैश्विक नाममात्र GDP का लगभग 43% रखते हैं।

म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

- हाल ही में म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग ने 30 मई से 3 जून, 2026 के मध्य भारत का आधिकारिक दौरा किया।
- म्यांमार भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' और 'एक्ट ईस्ट' नीतियों के संगम पर स्थित एकमात्र आसियान देश है।
- **यात्रा के परिणाम-**
  - म्यांमार के छात्रों के लिए मेकांग गंगा आईसीसीआर छात्रवृत्ति की संख्या 2026 से 36 से बढ़ाकर 100 करने की घोषणा की गयी।
  - द्विपक्षीय व्यापार, सीमा पार निवेश, और दोनों देशों के निजी क्षेत्रों के बीच वाणिज्यिक सहयोग बढ़ाने के लिए आने वाली बाधाओं को दूर करने और नए अवसरों को तलाशने की प्रतिबद्धता जताई गई। म्यांमार ने भारत से स्वच्छ ऊर्जा नवाचार, ऊर्जा दक्षता प्रणालियाँ, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण, ग्रिड सुदृढ़ीकरण तकनीकी सहयोग और अनुसंधान को अपनाने की बात कही है।
  - भारत-म्यांमार की साझा सीमा पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों ने प्रतिबद्धता जताई।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सेशेल्स की राजकीय यात्रा-

- भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 27 से 29 जून, 2026 तक सेशेल्स की अपनी राजकीय यात्रा पर रहे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी से आधिकारिक वार्ता की।

यात्रा के दौरान सेशेल्स की सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को 'गार्जियन ऑफ द ब्ल्यू हॉरिजन' से भी सम्मानित किया।

भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता-

- सेशेल्स सरकार को एकफास्ट पेट्रोल वेसल दिया गया।
- सेशेल्स रक्षा बल को 10 उपयोगिता वाहन और 5 लेजर रेडियल क्लास नौकाएं प्रदान की गई।
- सेशेल्स सरकार को 6 एम्बुलेंस, चावल और बुनियादी ढांचे के लिए सीमेंट की आपूर्ति की गई।

महत्वपूर्ण घोषणाएँ-

- सेशेल्स मेंव्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा केंद्र के निर्माण के लिए वर्चुअल भूमि-पूजन।
- सेशेल्स केडोर्नियर विमान को आधुनिकग्लास कॉकपिट तकनीक के साथ अपग्रेड किया गया।
- सेशेल्स को आधिकारिक तौर पर भारत समर्थितआपदा-प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल किया गया।

हस्ताक्षरित/नवीनीकृत समझौते-

क्षेत्र	समझौता	रणनीतिक उद्देश्य
वित्तीय सहयोग	अम्ब्रेला लाइन ऑफ क्रेडिट समझौता (एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया और सेशेल्स सरकार)	सेशेल्स में प्राथमिक बुनियादी ढांचे और विकास पहलों (विशेष आर्थिक पैकेज के तहत) को आगे बढ़ाना।
डिजिटल भुगतान	NPCIइंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और सेशेल्स के केंद्रीय बैंक के बीच समझौता।	सेशेल्स में UPI डिजिटल भुगतान अवसंरचनाकी तैनाती और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा	HLLलाइफकेयर लिमिटेड और सेशेल्स स्वास्थ्य मंत्रालय के बीचजनऔषधि योजनाके तहत समझौता।	भारत से सेशेल्स को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं एवं चिकित्सा आपूर्ति का निर्यात करना।
कानूनी ढांचा	भारत और सेशेल्स के बीचप्रत्यर्पण संधि	सीमा पार और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने तथा भगोड़ों के प्रत्यर्पण हेतु कानूनी सहयोग मजबूत करना।
कृषि अनुसंधान	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदऔर सेशेल्स के कृषि विभाग के बीच कार्य योजना (2026-2031)।	कृषि अनुसंधान, शिक्षा, संयुक्त प्रशिक्षण और तकनीकी अध्ययन में सहयोग बढ़ाना।

लाओस के उप-प्रधानमंत्री का भारत दौरा-

- हाल ही में लाओ जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य (लाओस) के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंगसावन फोमविहाने ने 1 से 3 जून, 2026 के मध्य भारत का आधिकारिक दौरा किया। यह उनकी पहली भारत यात्रा थी, जो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में थी।

यात्रा के परिणाम-

- 10वीं 'भारत-लाओस संयुक्त आयोग' की बैठक का आयोजन हुआ। दोनों पक्षों ने बौद्ध धर्म और रामायण की साझा सांस्कृतिक विरासत पर के लिए आपस में सहमति प्रकट की।
- लाओस ने 'इंडिया-लाओस बिजनेस फोरम' में भारतीय व्यापारियों को निवेश और व्यापार के अवसर तलाशने के लिए आमंत्रित किया।
- भारत ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में लाओस को तकनीकी सहायता और अनुभव साझा करने की पेशकश की है।

खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष-

- हाल ही में बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है।
- खलीलुर रहमान ने सत्र के अध्यक्ष के चुनाव में साइप्रस के विशेष दूत एंड्रियास एस. काकौरिस को हराया। रहमान को 190 वैध मतों में से उन्हें 99 और काकौरिस को 91 वोट मिले।

संयुक्त राष्ट्र महासभा

- स्थापना- वर्ष 1945 में
- मुख्यालय- न्यूयॉर्क (USA)
- सदस्य- 193 देश
- यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख नीति-निर्धारण निकाय है।
- इसमें सभी सदस्य देशों के पास एक मत होता है।
- इसका सत्र प्रतिवर्ष सितंबर में आयोजित होता है।
- अध्यक्ष पद- अध्यक्ष पद पांच भौगोलिक समूहों (अफ्रीकी, एशियाई, पूर्वी यूरोपीय, लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन, पश्चिमी यूरोपीय और अन्य) के बीच वार्षिक रूप से बारी-बारी से प्रदान किया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए अस्थायी सदस्यों का चुनाव-

- 3 जून 2026 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों चुनाव में पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, जिम्बाब्वे और त्रिनिदाद-टोबैगो नए अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। इनका कार्यकाल वर्ष 2027-2028 के लिए होगा। इस परिषद में किर्गिस्तान पहली बार पहुंचा है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना और अस्थायी सीटें-

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल पन्द्रह सदस्य होते हैं।
- स्थायी सदस्य- पाँच स्थायी सदस्य (चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका)

अस्थायी सदस्य-

- दस अस्थायी सदस्य, ये दो साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं।
- आधे सदस्यों या पाँच सीटों का चुनाव हर साल किया जाता है।
- सीटों का वितरण- 10 अस्थायी सीटें भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर बांटी गई हैं-
  - अफ्रीका- 3 सीटें
  - एशिया-प्रशांत- 2 सीटें
  - लैटिन अमेरिका और कैरेबियन- 2 सीटें
  - पूर्वी यूरोप- 1 सीट
  - पश्चिमी यूरोप व अन्य- 2 सीटें
- **भारत एवं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद-**
  - भारत यू.एन.एस.सी. का स्थायी सदस्य नहीं है।
  - भारत को अभी तक कुल आठ बार यू.एन.एस.सी. का अस्थायी सदस्य चुना गया है।

ब्रिटेन की विदेश मंत्री यवेट कूपर का दो दिवसीय भारत दौरा-

- हाल ही में ब्रिटेन की विदेश मंत्री यवेट कूपर ने 3-4 जून, 2026 को भारत का आधिकारिक दौरा किया। ब्रिटेन की विदेश सचिव के रूप में यह उनका भारत का पहला दौरा था।

यात्रा के परिणाम

- भारत की नई शिक्षा नीति के तहत यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल बेंगलुरु में अपना नया कैंपस स्थापित करेगी।
- आईआईटी धनबाद में कैम्ब्रिज के सहयोग से महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति के लिए वेधशाला स्थापित होगी।
- समुद्री व्यापार और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 'रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' लॉन्च हुआ।
- द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने पर सहमति बनी।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित उपयोग और अंतरराष्ट्रीय मानक तय करने के लिए मिलकर काम करेंगे।

वेनेजुएला गणराज्य के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा

- हाल ही में वेनेजुएला गणराज्य की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज गोमेज़ ने 3 से 7 जून, 2026 तक भारत की आधिकारिक यात्रा की।
- इससे पहले रोड्रिगेज विदेश मंत्री और उपराष्ट्रपति के रूप में भी कई बार भारत आ चुकी हैं। यह रोड्रिगेज का भारत का छठा दौरा है।

यात्रा के परिणाम-

- वैश्विक तनाव के बीच दोनों देशों में दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी पर सहमति बनी।
- ऊर्जा क्षेत्र में भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों के मौजूदा निवेश की समीक्षा।
- फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य, ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी जैसे नए क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाने पर चर्चा।

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ईयर-बुक-2026

- स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी वार्षिक 'SIPRI ईयरबुक 2026' जारी की है। इस रिपोर्ट में वैश्विक शस्त्रागार, सैन्य खर्च, परमाणु हथियारों की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के बदलते परिदृश्य को उल्लेखित किया गया है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- वैश्विक-
  - वैश्विक स्तर पर परमाणु संपन्न देशों के पास अनुमानित **12,187 परमाणु युद्धशीर्ष** हैं, जिनमें से लगभग 9,745 सैन्य स्टॉकपाइल में संभावित उपयोग के लिए तैयार हैं।
  - कुल परमाणु हथियारों का लगभग **86% हिस्सा अकेले अमेरिका और रूस** के पास है।
  - मार्च 2025 में लिथुआनिया 'कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन्स' (मानवीय हथियार नियंत्रण संधि) से हटने वाला पहला देश बना।
- भारत-
  - भारत वर्ष 2025 में 92.1 बिलिय नडॉलर के साथ दुनिया का 5वाँ सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है।
  - वर्ष 2021-25 की अवधि के दौरान भारत वैश्विक स्तर पर यूक्रेन के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रमुख हथियारों का आयातक रहा।
  - जनवरी 2026 तक भारत का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर 190 युद्ध शीर्ष तक पहुंच गया है।

ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026

- संस्करण- 20वां
- जारीकर्ता- इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (आईईपी)
- संकेतक- 23 संकेतक
- शीर्ष स्थान- आइसलैंड
- अंतिम स्थान- रूस/163वां स्थान

दुनिया के टॉप 10 सबसे शांत देश-

रैंकिंग	देश	रैंकिंग	देश
1.	आइसलैंड	6.	ऑस्ट्रिया
2.	न्यूजीलैंड	7.	पुर्तगाल
3.	स्विट्जरलैंड	8.	सिंगापुर
4.	स्लोवेनिया	9.	फिनलैंड
5.	आयरलैंड	10.	जापान

दक्षिण एशिया के देशों की रैंकिंग-

रैंकिंग	देश
16	भूटान
67	श्रीलंका
111	नेपाल
117	बांग्लादेश
127	भारत
152	पाकिस्तान
157	अफगानिस्तान

भारत

- इस सूचकांक में भारत को 127वां स्थान (स्कोर-2.409) प्राप्त हुआ।
- जबकि भारत गत वर्ष 115वें स्थान पर था।
- भारत की रैंकिंग में गिरावट का मुख्य कारण पाकिस्तान और म्यांमार के साथ बढ़ते तनाव के साथ-साथ मणिपुर में जारी जातीय हिंसा बताया गया है।

चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट-2026-

- जारीकर्ता- यूनिसेफ

रिपोर्ट के निष्कर्ष-

- दुनिया का लगभग हर बच्चा जलवायु खतरे के दायरे में है।
- 110 करोड़ बच्चे कम से कम 3 जलवायु खतरे झेल रहे है।
- 40 लाख से अधिक बच्चे 6 जलवायु खतरों के दायरे में है।
- 29.6 करोड़ बच्चे सूखा, भीषण गर्मी और हीटवेव के संयुक्त खतरे में है।
- 100 करोड़ बच्चे मलेरिया के जोखिम वाले क्षेत्रों में है।
- 33.7 करोड़ बच्चे नदी की बाढ़ के खतरे में है।
- सबसे ज्यादा जोखिम वाले देश- सोमालिया, मेडागास्कर, म्यांमार, कंबोडिया और पाकिस्तान

उज्बेकिस्तान न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना-

- हाल ही में उज्बेकिस्तान न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां और पहला मध्य एशियाई सदस्य बना है।

न्यू डेवलपमेंट बैंक-

- स्थापना- वर्ष 2015
- संस्थापक- BRICS सदस्य
- मुख्यालय- शंघाई (चीन)
- उद्देश्य- बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजनाओं का वित्त पोषण।
- प्रत्येक सदस्य देश को एक वोट देने का अधिकार है और किसी भी देश के पास वीटो पावर नहीं है।

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग-2027

- वैश्विक स्तर पर शीर्ष पाँच यूनिवर्सिटी-

संस्था	वैश्विक रैंकिंग	समग्र प्राप्तांक
मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी)	1	100
इंपीरियल कॉलेज लंदन	2	99.2
स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय	2	99.2
ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय	4	98.6
विदेश महाविद्यालय	5	97.4
कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय	6	97.1
कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (कैल्टेक)	7	96.6
ईटीएच ज्यूरिख	8	96.3
यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (यूसीएल)	8	96.3
सिंगापुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (एनयूएस)	10	96.2

शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालय-

संस्था	भारत रैंकिंग	वैश्विक रैंकिंग
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	1	118
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे	2	134
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास	3	170
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर	4	205
भारतीय विज्ञान संस्थान,बेंगलुरु	5	221
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	6	221
दिल्ली विश्वविद्यालय	7	332
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की	8	335
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी	9	349
शूलिनी जैव प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विज्ञान विश्वविद्यालय	10	452

- जारीकर्ता- क्यूएस क्वाक्वेरेली सायमंड्स द्वारा
- यह एक वैश्विक रैंकिंग प्रणाली है।
- यह विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन शैक्षणिक प्रतिष्ठा, अनुसंधान प्रभाव, नियोक्ता प्रतिष्ठा, संकाय-छात्र अनुपात, अंतर्राष्ट्रीयकरण, रोजगार परिणाम और स्थिरता के आधार पर करती है।

वेनेजुएला में भूकंप

- हाल ही में वेनेजुएला में आए भूकम्पों के बाद वेनेजुएला की सरकार ने राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की है।

वेनेजुएला-

- अवस्थित दक्षिणी अमरीका महाद्वीप में
- राजधानी- काराकास
- सरकार- संघीय अध्यक्षीय संवैधानिक गणराज्य
- मुद्रा- वेनेज़ुएला बोलिवर
- राष्ट्रपति- डेल्सी रोड्रिग्ज (कार्यवाहक)
- ईद देश में दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार के साथ-साथ कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट और सोने के विशाल भंडार पाए जाते है।

नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा का भारत दौरा-

- नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा 23-25 जून, 2025 तक भारत की यात्रा पर रही। उनकी भारत की यात्रा यूएन महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य मामलों की विशेष अधिवक्ता के रूप में थी।
- इस यात्रा का उद्देश्य भारत के यूपीआई इकोसिस्टम और वेतन-आधारित वित्तीय ढांचे को समझना था ताकि वेतनभोगी व्यक्तियों की वित्तीय स्थिति में सुधार किया जा सके।

प्रधानमंत्री का फ्रांस का आधिकारिक दौरा-

- हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस का आधिकारिक दौरा किया।
- **यात्रा के परिणाम-**
  - आगामी 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार कोदोगुनाकरने का लक्ष्य
  - फ्रांस के नीस शहर में'भारत इनोवेट्स 2026' के पहले संस्करण का सफल शुभारंभ।
  - वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए'आर्थिक सुरक्षा संवाद'शुरू करने का निर्णय।
  - राफेल विमानों के इंजन हेतु MRO सुविधा और भारत में हैमर मिसाइल निर्माण।
  - एआई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में संयुक्त अनुसंधान के लिए एक'संयुक्त भारत-फ्रांस एआई कार्य समूह'के गठन पर सहमति।

भारत और नेपाल ने सीमा पार धन प्रेषण प्रणाली को प्रारम्भ किया-

- हाल ही में भारत और नेपाल ने 6 जून, 2026 को आधिकारिक तौर पर व्यक्ति-से-व्यक्ति (पी2पी) सीमा-पार धन प्रेषण प्रणाली का शुभारंभ किया है।
- यह नव-संचालित प्रणाली भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) और नेपाल के राष्ट्रीय भुगतान इंटरफेस (एनपीआई) के बीच संबंध स्थापित करती है।
- यह एकीकरण दोनों देशों के नागरिकों को मोबाइल बैंकिंग अनुप्रयोगों और डिजिटल वॉलेट के माध्यम से निर्बाध, वास्तविक समय और सुरक्षित रूप से तत्काल धन हस्तांतरण करने में सक्षम बनाता है।
- **वर्तमान में विश्वभर में यूपीआई की पहुंच-**
  - वर्तमान में यूपीआई नौ देशों (सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, मॉरीशस, नेपाल, भूटान, कतर, श्रीलंका और कंबोडिया) में स्वीकार किया जाता है।
  - इन देशों में भारतीय यात्री अपने परिचित यूपीआई प्लेटफार्मों के माध्यम से आसानी से डिजिटल भुगतान कर सकते हैं।

झांग यिमिंग बने एशिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी-

- ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक टिकटॉक की पैरेंट कंपनी बाइडांस के को-फाउंडर झांग यिमिंग एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं।
- इन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए यह स्थान हासिल किया है। वर्तमान में झांग की संपत्ति 93 बिलियन डॉलर जबकि मुकेश अंबानी की संपत्ति 86 बिलियन डॉलर है।
- वर्तमान में गौतम अदाणी 115 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं।

मलेशिया में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया पर रोक-

- हाल ही में मलेशिया की सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगा दी है।
- मलेशिया ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को अनिवार्य आयु सत्यापन प्रणाली लागू करने के आदेश दिए है।
- मलेशिया सरकार इन नियमों को न मानने वाली कंपनियों पर 24 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है।

विविध तथ्य

- हाल ही में स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान "ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, प्रथम श्रेणी" से सम्मानित किया है।
- हाल ही में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमीसन ग्रीर ने आधिकारिक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए 22-24 जून, 2026 तक नई दिल्ली का दौरा किया। यह दौरा संतुलित, पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) को आगे बढ़ाने के रूप में था।
- हाल ही में भारत और दक्षिण अफ्रीका ने 3 जून, 2026 को भविष्य की प्रौद्योगिकियों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है।
- 1 जून, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया। सम्मेलन बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा सहित सात बिग कैट प्रजातियों और उनके संरक्षण पर केंद्रित था।
- हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने कंबोडिया में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को शुरू करने के लिए एसीएलईडीए बैंक पीएलसी के साथ आधिकारिक तौर पर साझेदारी की।
- हाल ही में ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स को भारत में अपने परिसर स्थापित करने हेतु अनुमोदन पत्र प्रदान किए गए है। ब्रिस्टल और यॉर्क विश्वविद्यालय मुंबई में तथा यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स बेंगलुरु में अपना परिसर स्थापित करेंगे।
- हाल ही में अमेरिका में यूसी बर्कले लॉ कॉलेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के इस्तेमाल प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध के तहत पढ़ाई की रूपरेखा बनाने, ड्राफ्टिंग, क्लास वर्क की एडिटिंग सहित परीक्षा और अनुवाद में एआई का उपयोग रोका गया है।
- अमेरिका का किल स्विच- यह अमेरिका का रणनीतिक तकनीकी और रक्षा तंत्र है। इसके तहत अमेरिका द्वारा बनाये गये सॉफ्टवेअर या एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर तक अपनी पहुंच और नियंत्रण बनाए रखता है। इसके जरिए अमेरिका जरूरत पड़ने पर दूर से ही इन प्रणालियों को निष्क्रिय कर सकता है।
- अमेरिका के बोस्टन के संघीय न्यायाल्य ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा H-1Bवीसा आवेदनों पर 1 लाख डॉलर (करीब 86 लाख रुपए) की फीस को स्ट्राइक डाउन कर दिया है।
- मैकेंजी स्कॉट (जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी) ने वर्ष 2025 में करीब 7 अरब डॉलर दान देकर अमरीका की सबसे बड़ी व्यक्तिगत दानदाता का स्थान हासिल किया है।
- कनाडा के क्यूबेक प्रांत के टेरास-वाद्रेय शहर ने प्रस्ताव पारित कर पेड़ों को 'जीवित प्राणी' के रूप में मान्यता दी है। इसके तहत पेड़ों की सुरक्षा, नए पौधरोपण व लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
- कनाडा सरकार ने संसद में 'सेफ सोशल मीडिया एक्ट' पेश किया है। यह एक्ट 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने को सुनिश्चित करता है।
- इलॉन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बने है। स्पेसएक्स के आईपीओ के बाद उनकी संपत्ति एक लाख करोड़ डॉलर के पार पहुंच गई है।
- ब्रिटेन में सौलह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर बैन लगाया जाने की घोषणा की गयी है।
- अमेरीकी रक्षा विभाग ने 'यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड' का नाम बदलकर वापस 'यूएस पैसिफिक कमांड' कर दिया है। इस बदलाव के तहत नाम से 'इंडो' शब्द हटा दिया गया है।
- संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाने वाला पहला अरब देश बन गया है।
- भारत और जापान ने जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म के नियम लागू करने को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करना और सतत विकास को बढ़ाना है।
- भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा।
- G7 देशों ने डिजिटल तकनीक और स्वच्छ ऊर्जा के लिए जरूरी खनिजों की आपूर्ति सुरक्षित करने के उद्देश्य से 'क्रिटिकल मिनरल्स रेसिलिऐस एंड प्रोडक्शन एलायंस' शुरू किया है।
- ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने लेबर पार्टी के नेता व पीएम पद से इस्तीफे की घोषणा की है।
- यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने पोलैंड का सर्वोच्च राजकीय सम्मान 'ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल' लौटा दिया है।
- पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का सबसे पुराना उल्कापिंड गड्ढा/क्रेटर खोजा गया है। इस क्रेटर का नाम नार्थ पोल डोम है जो करीब 3.024 अरब साल पुराना है।
- श्रीलंका ने चुनावों में अमिट स्याही का इस्तेमाल बंद करने का फैसला किया है।

3. राष्ट्रीय परिदृश्य

सर्वोच्च न्यायालय में पांच नए न्यायाधीश नियुक्त

- हाल ही में केंद्र सरकार ने 1 जून, 2026 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में पांच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है।
- केंद्र सरकार को इन नामों की सिफारिश भारत के मुख्य न्यायाधीक्ष की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने की थी।

नियुक्त न्यायाधीश-

1. श्री न्यायमूर्ति शील नागू (मुख्य न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय)
2. श्री न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर (मुख्य न्यायाधीश, बॉम्बे उच्च न्याय्र यालय)
3. श्री न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा (मुख्य न्यायाधीश, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय)
4. श्री न्यायमूर्ति अरुण पल्ली (मुख्य न्यायाधीश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय)
5. श्रीमती वेंकिता सुब्रमणि मोहना (वरिष्ठ अधिवक्ता)

श्रीमती वेंकिता सुब्रमणि मोहना-

- वेंकिता सुब्रमणि मोहना सीधे वकालत के पेशे से पदोन्नत होकर सुप्रीम कोर्ट की जज बनी हैं।
- वह वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली दूसरी महिला हैं। उनसे पहले जस्टिस इंदु मल्होत्रा सीधे सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला थीं।
- जस्टिस मोहना सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की 12वीं महिला जज भी हैं।
- संविधान का अनुच्छेद 124 (2)-सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाती है।

महा जल मिशन का शुभारम्भ-

- हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह 1 जून, 2026को महा जल परियोजनाका शुभारंभ किया है।
- यह मिशन अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और जल शक्ति मंत्रालय की संयुक्त पहल है जिसपर ₹200 करोड़ का वित्तीय परिव्यय किया जायेगा।
- इस मिशन का उद्देश्यजल संबंधी गंभीर चुनौतियों के समाधान के लिएप्रौद्योगिकी विकास, क्षेत्र सत्यापन और कार्यान्वयन में सहयोग करना है।
- **यह महा जल मिशन 5 रणनीतिक क्षेत्रों पर केंद्रित है-**
  1. जल संसाधन प्रबंधन
  2. पेयजल
  3. जल गुणवत्ता
  4. दक्षता
  5. जलवायु अनुकूलन

अरावली की परिभाषा की जांच के लिए हाई-पावर कमेटी गठित

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की परिभाषा की समीक्षा के लिए कंचन देवी के नेतृत्व में पांच सदस्यीय हाई-पावर कमेटी गठित की है।
- यह हाई-पावर कमेटी अरावली की परिभाषा और इसके सीमांकन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की स्वतंत्र समीक्षा करेगी।

कमेटी के गठन का उद्देश्य-

- 500 मीटर की दूरी के नियम से संरक्षित क्षेत्र कम हो रहा है या नहीं, इसकी जांच करना।
- यह पता लगाना कि क्या इस सीमित सीमांकन की वजह से गैर-अरावली क्षेत्रों में अनियंत्रित खनन को बढ़ावा मिल रहा है।
- 100 मीटर से अधिक ऊंची पहाड़ियां यदि 500 मीटर से अधिक की दूरी पर हैं तो क्या वे एक निरंतर पारिस्थितिकी संरचना का हिस्सा हैं।
- राजस्थान में मौजूद 12,081 पहाड़ियों में से केवल 1,048 पहाड़ियां ही 100 मीटर की ऊंचाई के मानदंड को पूरा करती हैं, इस दावे की वैज्ञानिक और तथ्यात्मक जांच करना।

- यह सुनिश्चित करना कि नई परिभाषा और सीमांकन से अरावली के पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान न पहुंचे।
- यह कमेटी, अपनी विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट 31 अगस्त, 2026 तक सुप्रीम कोर्ट को सुपर्द करेगी।

हाई-पावर कमेटी के सदस्य-

अध्यक्ष-

- कंचन देवी- पदेन अध्यक्ष (महानिदेशक, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद सदस्य)

सदस्य-

- डॉ. सुभाष आशुतोष
- डॉ. राजेंद्र कुमार शर्मा
- बृज मोहन सिंह राठौर
- प्रो. अशोक के. भटनागर
- सदस्य सचिव- भारत सरकार के वन मंत्रालय के निदेशक स्तर का अधिकारी

आमंत्रित सदस्य-

- प्रो. जगदीश कृष्णास्वामी
- प्रो. (डॉ.) लक्ष्मीकांत शर्मा

'समाधान दीदी' चैटबॉट-

- हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने नई दिल्ली में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा भाषिणी के सहयोग से विकसित किए गए सीपीजीआरएएमएस के एआई-सक्षम वॉयस चैटबॉट "समाधान दीदी" का शुभारंभ किया।
- यह चैटबॉटदेश में लोक शिकायत निवारण तंत्र के लोकतंत्रीकरण और नागरिकों के लिए सार्वजनिक सेवाओं के उपयोग की सुगमता को बढ़ावा देगा। इस चैटबॉटमें नागरिक किसी भी प्रकार की शिकायत को अपनी मातृभाषा में बोलकर दर्ज करा सकता हैं
- यह चैटबॉटपूर्णत: सुरक्षित सरकारी अवसंरचना के भीतर विकसित किया गया है जिससे नागरिकों के आंकड़ों की गोपनीयता पूरी तरह सुनिश्चित रहे।

पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट-

- केन्द्रीय गृह मंत्री अमितशाह ने 28 जून, 2026 को गांधीनगर, गुजरात में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया।
- यह ट्रैकर डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण और परिवार कल्याण को मजबूत करेगा।
- यह ट्रैकर पूरे डेटाबेस को एकीकृत कर उसेजन्म-मृत्यु के डेटा के साथ जोड़ेगा तथा हर बच्चे को एक विशिष्ट आईडी और नंबर दिया जाएगा।
- डेटाबेस के एकीकरण से सरकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को स्वतः और समय पर सुनिश्चित किया जा सकेगा।

मेकेदातु बांध का मुद्दा-

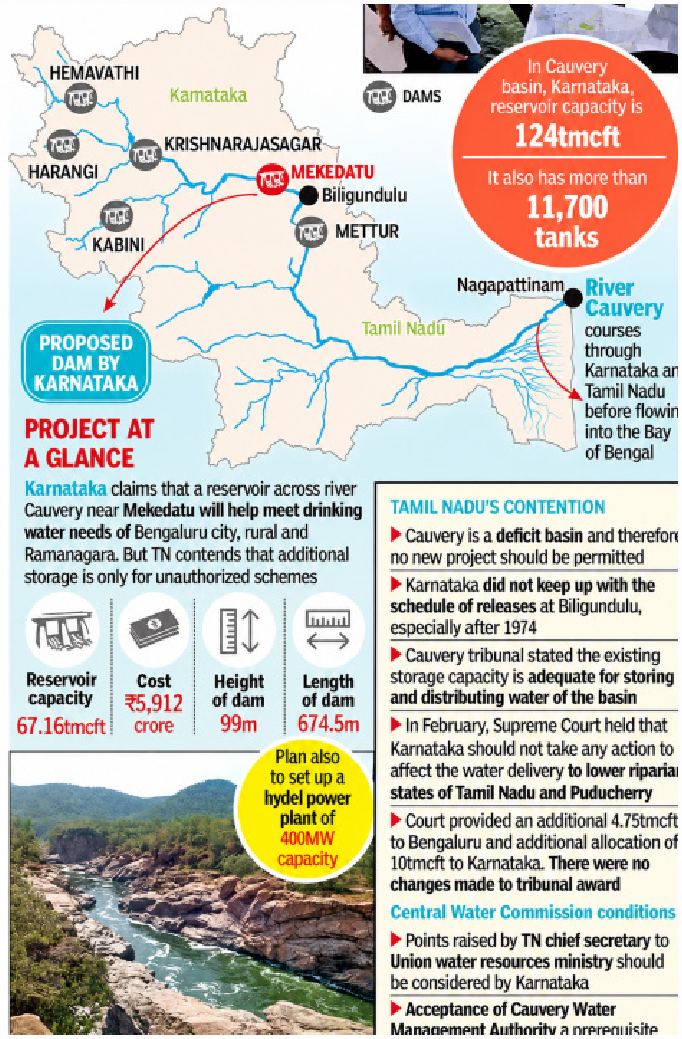

- हाल ही में कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का दशकों पुराना विवाद पुन: चर्चा में आ गया है।
- मेकेदातु कर्नाटक की बहुउद्देशीय (पेयजल और बिजली) परियोजना है। इसके तहत बेंगलुरु साउथ जिले के कनकपुरा के पास कावेरी नदी पर एक 'बैलेंसिंग रिजर्ववायर' बनाने का प्रस्ताव है।
- इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बेंगलुरु महानगर और उसके आसपास के इलाकों के लिए पीने का पानी सुनिश्चित करना है। इससे 400 मेगावाट जल-विद्युत पैदा करने की भी योजना है।
- **तमिलनाडु इस बांध का विरोध क्यों कर रहा है?-**
    - तमिलनाडु राज्य का मानना है कि यदि कर्नाटक ने नदी के ऊपरी हिस्से में यह बांध बना लिया, तो तमिलनाडु में आने वाले पानी के प्रवाह पर कर्नाटक का नियंत्रण हो जाएगा। इससे कावेरी डेल्टा क्षेत्र के लाखों किसानों को सिंचाई का पानी नहीं मिलेगा।

- **विवाद की कानूनी स्थिति?-**
  - o सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर कर्नाटक को कानूनी राहत दी है। अब मामला केंद्र सरकार के पास लंबित है।

कावेरी नदी

- यह दक्षिण भारत की सबसे महत्त्वपूर्ण नदी है जिसे 'दक्षिण भारत की गंगा' कहा जाता है।
- उद्गम- ब्रह्मगिरि श्रेणी, पश्चिमी घाट
- प्रवाह मार्ग- 800 किलोमीटर (लगभग)
- प्रवाह क्षेत्र/राज्य- कर्नाटक और तमिलनाडु
- जल विसर्जन- बंगाल की खाड़ी
- मुख्य सहायक नदियाँ-
  - o बाएँ- हरंगी, हेमावती, शिमशा, अर्कावती
  - o दाएँ- लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, भवानी, नोय्याल, अमए रावती

समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ-

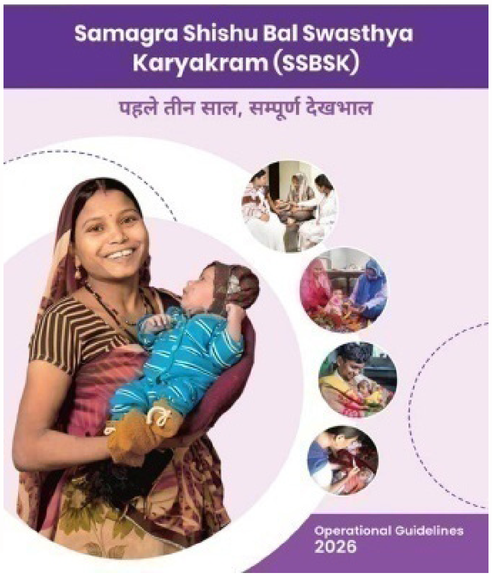

- केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 29 जून, 2026 को समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (एसएसबीएसके) का शुभारंभ किया। इस एकीकृत दृष्टिकोण आधारित कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों की जीवन रक्षा, पोषण, और शुरुआती विकास पर ध्यान देना है।
- यह कार्यक्रम जन्म से लेकर 36 माह (3 वर्ष) तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय-आधारित निरंतर देखभाल सुनिश्चित करने वाला एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है।
- इसके तहत घर पर नवजात शिशु की देखभाल (एचबीएनसी) और घर पर छोटे बच्चों की देखभाल (एचबीवाईसी) कार्यक्रमों को जोड़कर एक समग्र ढाँचा तैयार किया गया है।

एनीमिया मुक्त भारत अभियान के परिचालन संबंधी नवीन दिशा-निर्देश जारी-

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने 29 जून, 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद की 16वीं बैठक में एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत नवीन परिचालन दिशानिर्देश जारी किये है। इसके तहत 'एनीमिया मुक्त भारत' कार्यक्रम को अपग्रेड करके'एनीमिया मुक्त भारत अभियान'के रूप लागू किये जाने की घोषणा की गयी है।
- 'एनीमिया मुक्त भारत' कार्यक्रम में 6 लाभार्थी समूह, 6 हस्तक्षेप और6 संस्थागत तंत्र शामिल थे जबकि 'एनीमिया मुक्त भारत अभियान'में 7x7x7ढांचालागू किया गया है-

घटक	नया घटक/7वाँ घटक	महत्व/उद्देश्य
लाभार्थी समूह	कम जन्म भार वाले शिशु (0-6 महीने)	प्रारंभिक जीवन चरण से ही एनीमिया की रोकथाम करना।
इंटरवेन्शन (उपाय)	"सही खान-पान" का दृष्टिकोण	आयरन-युक्त और विविध आहार के नियमित सेवन को दैनिक आदत बनाना।
संस्थागत तंत्र	डिजिटल ट्रैकिंग समर्थित निगरानी ढांचा	मजबूत डेटा संग्रह, वास्तविक समय निगरानी और मूल्यांकन।

T3 से T4 दृष्टिकोण में परिवर्तन-

पुराना मॉडल- T3	नया मॉडल- T4
Test (जांच)	Test (जांच)
Treat (उपचार)	Treat (उपचार)
Talk (चर्चा/परामर्श)	Talk (चर्चा/परामर्श)
	Track (निगरानी/फॉलो-अप)

- **गंभीर मामलों के लिए नैदानिक हस्तक्षेप-** गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में गंभीर एनीमिया और सामान्य दवाओं से ठीक न होने वाले मामलों के लिए अंतःशिरा आयरन थेरेपी अनिवार्य किया गया है।

एनीमिया-

- एनीमिया में शरीर के रक्त में स्वस्थलाल रक्त कोशिकाएं या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है जिससे अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती।
- **लक्षण-**
  - अत्यधिक थकान और कमजोरी।
  - त्वचा, होठों और नाखूनों का पीलापन।
  - चक्कर आना, सिरदर्द और ठंडे हाथ-पैर।
  - सांस फूलना और धड़कन का अनियमित होना।

सुमन रोडमैप - 2030

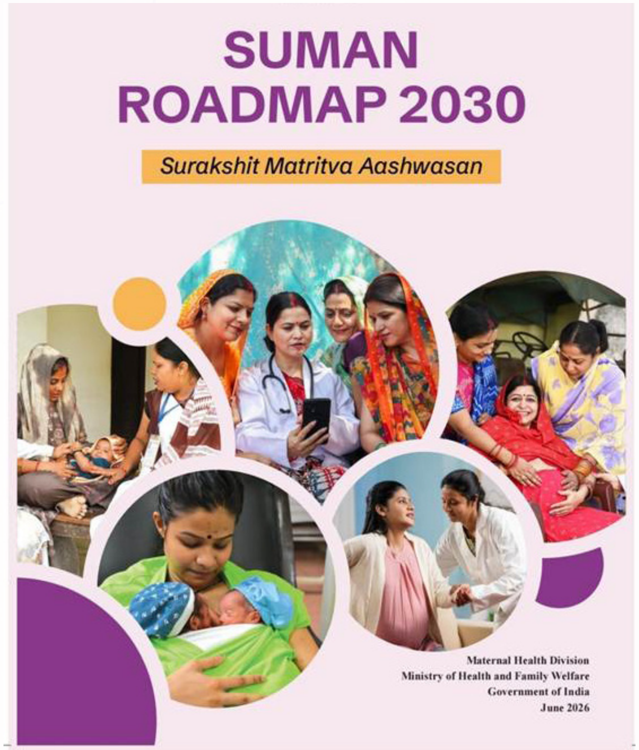

- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने 29 जून, 2026 को सुमन रोडमैप 2030 लॉन्च किया है। यह रोडमैप व्यापक और भविष्योन्मुखी रणनीतिक ढांचा है।
- **इस रोडमैप के निम्न उद्देश्य है-**
  - देशभर में मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य देखभाल में आमूल बदलाव लाना।
  - 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भारत की प्रगति में तेजी लाना।
  - मातृ मृत्यु दर को 2030 तक प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 70 से कम करना।
  - नवजात मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को और नीचे लाना।
  - ऐसी मौतों को पूरी तरह रोकना जिन्हें उचित देखभाल से बचाया जा सके।
- जहाँ मातृ-शिशु मृत्यु दर अधिक है, वहां सुधार लाने के लिए देश के13 राज्यों (राजस्थान, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल) के 130 जिलों को विशेष रूप से लक्षित किया गया है।
- **रोडमैप की प्रमुख विशेषताएँ-** यह रोडमैप RMNCHA+N फ्रेमवर्कपर आधारित है इसके तहत-
  - इसके तहत गर्भवती महिलाओं को जल्दी रजिस्ट्रेशन, पूरी प्रसव-पूर्व देखभाल, उच्च गुणवत्ता की नैदानिक जाँच और प्रसव के बाद अस्पताल में पर्याप्त समय तक रुकने की सुविधा मिलेगी।
  - आशा कार्यकर्ताएँ गर्भावस्था के 8वें और 9वें महीने में खतरे के संकेत पहचानने, पोषण सलाह देने और अस्पताल में प्रसव सुनिश्चित करने के लिए हर दो हफ्ते में घर जाकरजाँच करेंगी।
  - दूरदराज के इलाकों मेंबर्थ वेटिंग होम, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग, ऑब्स्टेट्रिक HDU और ICU बनाए जाएंगे।
  - डिजिटल नवाचारके तहत AI-सक्षम लेबर रूम और 'जननी पोर्टल' से बेहतर निगरानी होगी।
  - 'सुमन पंचायत' और 'मदर्स पिकनिक' जैसी पहलों से समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित होगी।
  - शिकायत निवारण के लिए एक केंद्रीकृत 'सुमन कॉल सेंटर' की स्थापना की जाएगी।
  - जन्म से 36 महीने तक के बच्चों के लिए 'समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (SSBSK)' के तहत घर पर ही निर्बाध देखभाल मिलेगी।

भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दो फैसलों की घोषणा-

- 29 जून, 2026 को सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक में भारतीय फिल्म उद्योग को मजबूत बनाने के लिए दो बड़े फैसले लिए गए।
- इन फैसलों का लक्ष्य मजबूत, आधुनिक और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय फिल्म उद्योग बनाना है, जिससे भारतीय सिनेमा रचनात्मकता, संस्कृति और नवाचार का सशक्त माध्यम बना रहे।
- **अध्ययन समूह का गठन (प्रथम फैसला)-** श्री प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय अध्ययन समूह बनाया गया है। यह समूह निम्न विषयों पर विचार करेगा-
  - भारतीय फिल्मों को वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के उपाय।
  - कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वर्चुअल प्रोडक्शन जैसी नई तकनीकों का सिनेमा पर प्रभाव।
  - फिल्म निर्माण के लिए संस्थागत वित्त और नए वित्तपोषण विकल्पों तक पहुंच।
  - यह समूह तीन महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।
- **मॉडल राज्य सिनेमा नियम (द्वितीय फैसला)-**
  - सिनेमा और थिएटर का नियमन राज्य सूची का विषय है अत: अलग-अलग राज्यों के भिन्न-भिन्न नियमों के कारण खासकर छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में सिनेमा अवसंरचना के विकास में बाधा आती रही है।
  - इसे दूर करने के लिए मंत्रालय ने सभी हितधारकों से बातचीत के बाद मॉडल नियम तैयार किए हैं और उन्हें सभी राज्य सरकारों को भेजा है, ताकि राज्य इन्हें अपनाएं।

20वें सांख्यिकी दिवस के अवसर पर एसडीजी प्रकाशनों का विमोचन-

- 20वें सांख्यिकी दिवस पर 29 जून, 2026 के अवसर पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (एसडीजी) पर चार प्रकाशनों का विमोचन किया है।

1. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स-नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2026-
- o यह रिपोर्ट सतत् विकास लक्ष्यों के राष्ट्रीय संकेतकों से संबंधित नवीनतम उपलब्ध समय-श्रृंखला आँकड़े प्रस्तुत करती है।
- o यह नीति-निर्माताओं, योजनाकारों, शोधकर्ताओं तथा अन्य हितधारकों के लिए भी महत्त्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध कराती है।

2. डेटा स्नैपशॉट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स-नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2026-
- o डेटा स्नैपशॉट ऑन एसडीजी-एनआईएफ प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2026 एसडीजी-एनआईएफ प्रोग्रेस रिपोर्ट से व्युत्पन्न हैंडबुक के रूप में एक प्रकाशन है।

3. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स-नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, 2026 (मेटाडेटा के साथ)-
- o यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स-नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2026 से व्युत्पन्न हैंडबुक के रूप में एक प्रकाशन है, जिसमें सभी राष्ट्रीय एसडीजी संकेतकों के साथ उनका विस्तृत मेटाडेटा भी सम्मिलित है।

4. ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स- इंडियाज़ अचीवमेंट्स अंडर द पीपल डाइमेंशन ऑफ द एसडीजीज़-
- o यह बुलेटिन सतत् विकास हेतु 2030 एजेंडा के पाँच आधारभूत स्तंभों- पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस और पार्टनरशिप्स के अनुरूप तैयार किया गया विषयगत, आँकड़ा-आधारित एसडीजी बुलेटिनों की श्रृंखला का हिस्सा है।

प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे लगातार कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने-

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून, 2026 को भारत के सबसे लंबे लगातार कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए।
- पीएम मोदी ने निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर 4,399 दिनों तक पद पर रहने का पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
- निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का कार्यकाल वर्ष 1952 से शुरू हुआ था क्योंकि इससे पहले वहवर्ष 1947 से 1952 के बीच अंतरिम सरकार के प्रमुख थे।
- हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 14 साल से ज्यादा समय तक पद पर रहीं, लेकिन उनका कार्यकाल लगातार नहीं था।
- नरेंद्र मोदी लगातार तीन बार प्रधानमंत्री बनने वाले पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी हैं।

प्रियदर्शिनी मुफ्त बस यात्रा योजना-

- यह केरल सरकार की योजना है। इस योजना के तहत केरल में महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा का प्रावधान किया गया है।

बढ़ते वैश्विक तापमान के खतरों के मद्देनजर विश्व के शीर्ष 50 सबसे अधिक संवेदनशील शहरों 14 भारतीय शहर-

- जर्नल 'सस्टेनेबल सिटीज एंड सोसाइटी' में प्रकाशित यूनिवर्सिटी आफ आक्सफोर्ड के अध्ययन में भारत में बढ़तेशहरी ताप जोखिमको स्पष्ट रूप से उजागर किया गया है।
- इस शोध मेंदुनिया के 14 भारतीय शहरों को शीर्ष 50 सबसे अधिक संवेदनशील शहरों की सूची में रखा गया हैजो जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक गर्मी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।
- **विश्व के टॉप दस शहर-**

वैश्विक रैंक	शहर
1	अल बशरा, इराक
2	अहमदाबाद, भारत
3	बमाको, माली
4	नागपुर, भारत
5	क्वेजोन सिटी, फिलीपींस
6	बगदाद, इराक
7	मदुरै, भारत
8	फैसलाबाद, पाकिस्तान
9	लागोस, नाइजीरिया
10	हैदराबाद, पाकिस्तान

- **विश्व के टॉप-50 में भारत के शहर-**

वैश्विक रैंक	शहर	वैश्विक रैंक	शहर
2	अहमदाबाद	33	बेंगलूरु
4	नागपुर	35	कोलकाता
7	मदुरै	36	जयपुर
15	भोपाल	41	लखनऊ
20	कानपुर	49	मुंबई
23	पुणे	50	चेन्नई
25	पटना		
31	हैदराबाद		

- इस रैंकिंग में विश्व के टॉप-50 में राजस्थान के जयपुर को 36वें स्थान पर रखा गया है।

झारखंड के पारंपरिक उत्पादों को मिला जीआई टैग-

- झारखंड के ग्यारह पारंपरिक उत्पादों को भौगोलिक संकेतक (जी. आई.) टैग प्रदान किया गया है।
- यह उत्पाद निम्न है-
    1. भोया साड़ी और वस्त्र
    2. कुचाई सिल्क साड़ी
    3. केसरिया कलाकंद
    4. डोकरा शिल्प
    5. तुमका चादर
    6. बरोनी पेंटिंग
    7. मुंडा आभूषण
    8. झारखंड बाँस शिल्प
    9. तसर रेशम एवं साड़ियाँ
    10. जादोपटिया पेंटिंग
    11. पांचो साड़ी एवं वस्त्र
- **अन्य राज्यों के उत्पाद जिनकों भी जी.आई. टैग प्रदान किये गये है-**
    - मांडू (मध्यप्रदेश)- खुरासानी इमली
    - सिवनी (मध्यप्रदेश)- जम्बो सीताफल
    - बुरहानपुर(मध्यप्रदेश)- केला
    - त्रिपुरा- सरिंदा वाद्य यंत्र
- **भौगोलिक संकेतक (जी.आई.) टैग-**
    - यह किसी क्षेत्र के उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, गुणवत्ता और प्रतिष्ठा का आधार या गारंटी है जो बौद्धिक संपदा अधिकार के रूप में है।
    - यह टैग 10 वर्षों के लिए मान्य होता है।

सात बुलेट ट्रेन कॉरिडोरों को मंजूरी-

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सात बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को मंजूरी दी है। नए कॉरिडोर की कुल लंबाई 4,000 किमी होगी और इन पर 16 लाख करोड़ रु. निवेश होगा है।
- इन ट्रेनों की डिजाइन स्पीड 350 किमी/घंटा होगी, लेकिन इनका संचालन 320 किमी/घंटा की रफ्तार से किया जाएगा।
- **कॉरिडोर-**
    1. मुंबई-पुणे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर
    2. चेन्नई-बेंगलुरु बुलेट ट्रेन कॉरिडोर
    3. बेंगलुरु-हैदराबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर
    4. पुणे-हैदराबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर
    5. दिल्ली-लखनऊ बुलेट ट्रेन कॉरिडोर
    6. दिल्ली-वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर
    7. दिल्ली-सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर

देश में 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर-ट्रंक-

- दिग्गज डेटा सेंटर कंपनी एयरट्रंक ने भारतीय बाजार में करीब 3 लाख करोड़ रु. के भारी-भरकम निवेश की घोषणा की है।
- इस निवेश के तहत कंपनी भारत में 5 गीगावाट की विशाल डेटा सेंटर क्षमता विकसित करेगी।
- यह भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था के इतिहास में सबसे बड़े विदेशी निवेश प्रस्तावों में से एक है।

एयरट्रंक-

- यह ऑस्ट्रेलिया की हाइपरस्केल डेटा सेंटर कंपनी है।
- यह एशिया-प्रशांत और मध्य पूर्व क्षेत्र में क्लाउड और बड़े उद्यमों के लिए तकनीकी अवसंरचना विकसित करती है।

वेत्री तमिझगम विजन डॉक्यूमेंट-

- यह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय द्वारा जारी किया गया व्यापक प्रशासनिक विज़न डॉक्यूमेंट है।
- इस विजन डॉक्यूमेंट में 35 विभागों के लिए 436 विज़न स्टेटमेंट शामिल हैं, जिन्हें तिरुक्कुरल से प्रेरित होकर 10 प्रमुख स्तंभों और 54 उप-स्तंभों में बांटा गया है।
- इस विजन डॉक्यूमेंट में शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, किसानों और मछुआरों के कल्याण पर विशेष जोर दिया गया है।
- यह तमिलनाडु के दीर्घकालिक विकास का रोडमैप के रूप में काम करेगा।

क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी (GSCO)-

- हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने 'क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी' (GSCO) की शुरुआत की है।
- इस शुरुआत की घोषणा अक्टूबर, 2025 में भारत-यूके के प्रधानमंत्रियों की द्विपक्षीय बैठक के दौरान की गई थी।
- इस ऑब्जर्वेटरी का उद्देश्य भविष्य की तकनीकों के लिए जरूरी खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
- यह केंद्र स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक कच्चे माल की कमी को दूर करने में मदद करेगा।।
- क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी (GSCO)-
- **यह त्रिपक्षीय संयुक्त पहल है-**
    - नेतृत्व- टेक्समिन
    - भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-धनबाद
    - कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय

दिल्ली पक्षियों की विविधता में दुनिया में दूसरे नंबर पर-

- दिल्ली बर्ड एटलस पक्षियों की विविधता के मामले में दिल्ली दुनिया की दूसरी सबसे समृद्ध राजधानी बन गई है।
- दिल्ली बर्ड एटलस के अनुसार, राजधानी में 471 पक्षी प्रजातियां पाई गई हैं।
- इस सूची में केवल नैरोबी (केन्या की राजधानी और केन्या का सबसे बड़ा शहर) दिल्ली से आगे है।
- यह एटलस दिल्ली वन विभाग और 'बर्ड्स काउंट इंडिया' ने मिलकर तैयार किया है।

E85 फ्यूल-

- केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 5 जून, 2026 को दिल्ली में देश का पहला 85 प्रतिशत एथेनॉल मिक्स E85 फ्यूल लॉन्च किया है।
- यह फ्यूल दिल्ली के इंडियन ऑयल के पूसा रोड आउटलेट पर लॉंच किया गया किया।

E85 - फ्यूल

- यह उच्च-एथिनॉल ईंधन मिश्रण है।
- इसेफ्लेक्स-फ्यूल भी कहा जाता है।
- **घटक-**
  - **85% एथिनॉल-**
    - यह अल्कोहल का घटक है।
    - इसे पौधों (जैसे मक्का, गन्ना, या अनाज) को सड़ाकर बनाया जाता है।
    - इसे बायोफ्यूल भी कहा जाता हैं।
  - **15% गैसोलीन-**
    - यह सामान्य पेट्रोल होता है।
- **फायदे-**
  - यह सामान्य पेट्रोल के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन कम करता है।
  - सामान्य पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग 87-91 होती है, जबकि E85की ऑक्टेन रेटिंग 100 से 105 के बीच होती है। उच्च ऑक्टेन के कारण यह इंजन को अधिक पावर देता है।
  - यह सामान्य पेट्रोल से काफी सस्ता मिलता है।

केरलम ने वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली को ई-कोर्ट से जोड़ा-

- केरलम ने वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली को ई-कोर्ट से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य के वन विभाग ने अपनी हॉक प्रणाली को ई-कोर्ट से जोड़ दिया है।

हॉक (HAWK - Hostile Activity Watch Kernel)-

- यह डिज़िटाइज़्ड और क्लाउड-आधारित वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली है इसे वन विभाग, वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और NTT डेटा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
- इसके जरिए प्रारंभिक अपराध रिपोर्ट दर्ज करने से लेकर अदालती फैसलों और गवाहों की गवाही तक के हर चरण को एक ही केंद्रीकृत डेटाबेस में ट्रैक किया जा सकता है।
- यह प्रणाली फाइलों की भौतिक आवाजाही को कम करती है, जिससे वन्यजीव अपराधों का बिना कागजी कार्रवाई के वास्तविक समय में अभियोजन संभव हो पाता है।

व्योमा इनोवेशन प्रतियोगिता का शुभारंभ-

- हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन ने 2 जून, 2026 को करंट एआई और कल्पा इम्पैक्ट के सहयोग से वीवाईओएमए (व्योमा) इनोवेशन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है।
- यह एक नवाचार पहल है जिसका उद्देश्य ओपन-सोर्स, बहुभाषी, वॉइस-फर्स्ट एआई समाधानों के विकास को बढ़ावा देना है जो ऑफलाइन और कम कनेक्टिविटी वाले वातावरण में काम कर सकते हैं।
- वीवाईओएमए(व्योमा) इनोवेशन प्रतियोगिता, भाषिनी के बहुभाषी एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर और करंट एआई की ओपन-सोर्स तकनीक में विशेषज्ञता को एक साथ लाता है ताकि भाषा की सुलभता, डिजिटल साक्षरता और कनेक्टिविटी से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने वाले व्यावहारिक एआई समाधानों के विकास को प्रोत्साहित किया जा सके।

सुर्ख़ियों में- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के छह वर्ष पूर्ण।

पीएम स्वनिधि योजना

- योजना का प्रारम्भ- 1 जून, 2020
- इस योजना को कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण जिन रेहड़ी-पटरी वालों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई थी, उन्हें दोबारा पैरों पर खड़ा करने के लिए लॉन्च किया गया था।

विभाग या मंत्रालय-

- केंद्र स्तर पर-केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।
- राजस्थान स्तर पर-स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।

उद्देश्य-

- रेहड़ी-पटरी वालों को अपना छोटा व्यवसाय फिर से शुरू करने या बढ़ाने के लिए बिना किसी गारंटी के आसान लोन उपलब्ध कराना।
- स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतानअपनाने के लिए प्रेरित करना और उन्हें इसके लिए तैयार करना।
- छोटे व्यापारियों को ऊंचे ब्याज पर पैसे देने वाले अनौपचारिक स्रोतों से बचाकर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना।

लाभ-

- इस योजना के तहत मिलने वाले लाभों को तीन चरणों में बांटा गया है-
- पहला चरण-शुरुआत में व्यवसाय के लिए ₹10,000 तक का प्रारं-भिक कार्यशील पूंजी ऋण दिया जाता है।
- दूसरा चरण-पहला लोन समय पर या उससे पहले चुकाने पर ₹20,000 तक का दूसरा लोन मिलता है।
- तीसरा चरण-दूसरा लोन भी सही समय पर चुकाने के बाद ₹50,000 तक की तीसरी लोन राशि की पात्रता बनती है।

खेत बचाओ अभियान-

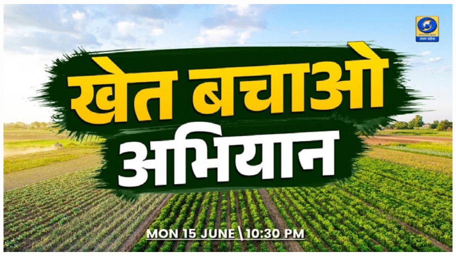

- हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जून, 2026 को रमासिया ग्राम, रायसेन जिले (मध्यप्रदेश) से राष्ट्रव्यापी 'खेत बचाओ अभियान' का शुभारंभ किया।
- यह अभियान 1 जूनसे 30 जून, 2026 तक चलेगा।

उद्देश्य-

- मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना।
- रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग घटाना।
- किसानों को प्राकृतिक तथा वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करना।

आकांक्षा से उपलब्धि तक: उद्यमियों और नवप्रवर्तकों की सफलता की कहानियां-

- यह एक पुस्तिका है जिसका विमोचन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में 3 जून, 2026 को किया।
- इसमें अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों की सफलता और उपलब्धियों में वेंचर कैपिटल फंड और अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन के परिवर्तनकारी प्रभाव की कहानियां संकलित हैं।
- इस पुस्तिका का उद्देश्य सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का प्रसार करना, उद्यमिता कार्यक्रमों में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना और मंत्रालय की प्रमुख पहलों के सकारात्मक परिणामों कोs प्रदर्शित करना है।

सीसीईए ने राजमार्गों के निर्माण के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की-

- हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने 3 जून, 2026 को विभिन्न राजमार्गों के निर्माण और उन्नयन के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है।
- **प्रस्तावीत राजमार्ग (निर्माण और उन्नयन)-**
  1. ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के तहत नए तटीय राजमार्ग का निर्माण।
  2. बिहार में एनएच-31 और एनएच-231 के खगड़िया-पूर्णिया खंड (143.529 किलोमीटर) को बीओटी (टोल) मोड पर 4-लेन मानक में अपग्रेड।

3. मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-347बी के हिवारखेड़ी-रोशनी-आशाब पुर-रुधी खंड (125.01 किमी) की मौजूदा मध्यवर्ती लेन को पक्की शोल्डर मानक वाली 2 लेन में अपग्रेड।
4. देशगांव-जुलवानिया खंड (108.643 किमी) की मौजूदा 2 लेन को 4 लेन में चौड़ा करना।
5. राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)-63 के मौजूदा आर्मूर-जगति) याल-मंचरियाल खंड को हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (एचएम) के तहत चार लेन मानक तक चौड़ा।
6. राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)-563 के जगतियाल-करीमनगर खंड को बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (टोल) [बीओटी (टोल)] के तहत चार लेन मानक तक चौड़ा।

नवाचार मंत्र पहल-

- हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने 3 जून, 2026 को 'नवाचार मंत्र' नामक राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ किया है।
- इस पहल का उद्देश्य कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, शिक्षा प्रौद्योगिकी एवं कौशल विकास, जलवायु एवं स्थिरता, ग्रामीण वाणिज्य और लघु एवं मध्यम उद्यम सशक्तिकरण जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में काम करने वाले नवप्रवर्तकों के लिए सहायता का एक संरचित तंत्र प्रदान करना है।
- नवाचार मंत्र के माध्यम से, नवप्रवर्तकों को नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के दिग्गजों, निवेशकों और संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों तक सीधी पहुंच प्राप्त होगीजिससे वे अपने विचारों को परिष्कृत कर सकेंगे।
- इस पहल का कार्यान्वयन राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कर रहा है।
- इसमें तकनीकी ज्ञान भागीदार के रूप में फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, आईआईटी दिल्ली है।

विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 का शुभारंभ-

- हाल ही में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने 'मेरा युवा भारत (एमवाई भारत)' के तहत विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 का पहले चरण का शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम दो चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा।
- यह एक अग्रणी युवा नेतृत्व वाली पहल है जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर भागीदारी को सुदृढ़ करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और भारत के सीमावर्ती गांवों में सतत विकास को प्रोत्साहित करना है।
- इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कुल 500 'एमवाई भारत' स्वयंसेवकों का चयन किया गया है।
- सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वयंसेवकों को लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के चिन्हित सीमावर्ती गांवों में दो चरणों में तैनात किया जा रहा है।
- प्रथम चरण में 250 स्वयंसेवक 43 गांवों में गहन गतिविधियों में भाग ले रहे हैं, जबकि शेष 250 स्वयंसेवक जून के अंत में 50 गांवों में द्वितीय चरण की गतिविधियों में शामिल होंगे।

जय प्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य रामसर स्थल घोषित-

- हाल ही में जय प्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है। इस अभयारण्य को देश का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है।
- **जय प्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य-**
  - अवस्थित- बलिया, उत्तर प्रदेश
  - यह स्थान साइबेरिया और मध्य एशिया से आने वाले प्रवासी पक्षियों का प्रमुख आश्रय स्थल है।
  - यहाँ पौधों की 221, मछलियों की 66, सरीसृपों की 7 और उभयचरों की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं।
- **रामसर स्थल-**
  - यह स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियां होती हैं। इनका चयन 'रामसर कन्वेंशन' के तहत किया जाता है।
  - रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है।
  - यह अंतरराष्ट्रीय संधि 2 फरवरी, 1971 को ईरान के रामसर शहर में अपनाई गई थी और इसे 21 दिसंबर 1975 को लागू किया गया था।
- **रामसर स्थल के सन्दर्भ में प्रमुख तथ्य-**

विशेषता	विवरण
कुल संख्या (2026 तक)	100
सर्वाधिक स्थलों वाला राज्य	तमिलनाडु
सबसे बड़ा रामसर स्थल	सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम बंगाल
सबसे छोटा रामसर स्थल	रेणुका आर्द्रभूमि, हिमाचल प्रदेश
सबसे पुराने/प्रथम स्थल	चिल्का झील (ओडिशा) और केवला-देव राष्ट्रीय उद्यान

देश के सातवें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारम्भ-

- हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 5 जून, 2026 को जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया।
- यह केंद्र देश का सातवां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र है।
- यह केंद्र जम्मू-कश्मीर, लद्दाख तथा हिमाचल प्रदेश के लिए काम करेगा। यह हिमालयी क्षेत्र के लिए विशेष रूप से तैयार की गई मौसम सेवाएं, आपदा चेतावनी और जलवायु सहायता प्रदान करेगा।

पश्चिम बंगाल में लागू होगी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-

- हाल ही में पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गया है।
- इस योजना के पश्चिम बंगाल में लागू होने के साथ ही यह योजना पूरे देश में लागू हो गई है।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई)

- लॉंच- 23 सितंबर, 2018 को रांची, झारखंड से

योजना के मुख्य लाभ-

- प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹ 5 लाख तक का मुफ्त इलाज (माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर अस्पताल में भर्ती होने के लिए)।
- लाभार्थियों को अस्पताल (सेवा केंद्र) पर कोई नकद भुगतान या कागजी कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- यह दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य10.74 करोड़ से अधिक कमजोर परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों) तक पहुंचना है।
- परिवार के आकार (सदस्यों की संख्या) और उम्र पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- योजना के मुख्य घटक- यह योजना स्वास्थ्य सेवा को दो स्तरों पर सुदृढ़ करती है-

स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (HWC)-

- देशभर में1,50,000 केंद्रबनाए जा रहे हैं जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, मुफ्त दवाएं और जांच सेवाएं प्रदान करेंगे। पहला केंद्र 14 अप्रैल 2018 को बीजापुर, छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया था।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY)-

- यह गरीब और कमजोर परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सीधे बड़े अस्पतालों (द्वितीयक और तृतीयक देखभाल) से जोड़ती है।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के एक दशक पूरा होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोह-

- हाल ही में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) के 10 वर्ष होने के उपलक्ष्य में 9 जून, 2026 को "पीएमएसएमए के 10 वर्ष- देखभाल का एक दशक" विषय के तहत राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ किया गया।
- यह समारोह सुरक्षित गर्भावस्था और स्वस्थ मातृत्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत की प्रमुख पहलों में से एक पीएमएसएमए के सफल कार्यान्वयन के एक दशक की सफलता का प्रतीक है।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA)-

- लॉंच तिथि- 9 जून, 2016
- संबंधित मंत्रालय- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।
- यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में मातृ मृत्यु दर को कम करना है।
- **लक्ष्य-** प्रत्येक माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करना।
- **विशेषताएं-**
  - यह अभियान मुख्य रूप से गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही वाली महिलाओं के लिए है।
  - प्रसव पूर्व जांच सेवाएं ओबीजीवाई विशेषज्ञों या चिकित्सा अधिकारियों द्वारा प्रदान की जाती हैं।
- **प्राप्त होने वाली सुविधा-**
  - स्वास्थ्य जांच (अल्ट्रासाउंड) और दवा (आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट)।
  - उच्च जोखिम वाली गर्भधारण की पहचान और उनका उचित प्रबंधन।
  - जोखिम पहचान के लिए स्टिकर- हरा स्टिकर (सामान्य गर्भावस्था वाली महिला के लिए) और लाल स्टिकर (उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था वाली महिला के लिए)

एनसीसी ने दो नए राज्य निदेशालय स्थापित किए-

- हाल ही में एनसीसी महानिदेशालय मुख्यालय ने आंध्र प्रदेश और झारखंड में स्वतंत्र राज्य निदेशालयों के गठन को मंजूरी दी है।
- इनके गठन के साथ ही भारत में एनसीसी राज्य निदेशालयों की कुल संख्या 17 से बढ़कर 19 हो गई है।
- इसके गठन युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्रीय कैडेट कोर तक पहुंच का विस्तार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते

एनसीसी (National Cadet Corps)-

- स्थापना- वर्ष 1948 में, मुख्यालय- नई दिल्ली
- आदर्श वाक्य-एकता और अनुशासन
- वर्तमान में इसमें 20 लाख से अधिक कैडेट हैं।

किशाऊ बहु-उद्देशीय बांध परियोजनापर संबंधित राज्यों में सहमति बनी-

- हाल ही में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 16 जून, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में 'किशाऊ बहु-उद्देशीय बांध परियोजना' पर संबंधित राज्यों में सहमति बनी है।
- केन्द्रीय गृह मंत्री की पहल पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान किशाऊ बहु-उद्देशीय परियोजना के क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन के लिए सहमत हो गए हैं।
- समझौते के तहत हिमाचल प्रदेश के जल-हिस्से का आवंटन दिल्ली और राजस्थान को किया जाएगा, जिसके बदले में ये राज्य परियोजना के विद्युत घटक में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी की लागत वहन करेंगे।
- किशाऊ बहु-उद्देशीय बांध परियोजना के संबंध में जल घटक के कार्य का 90% केन्द्रीय सहायता के रूप में केंद्र सरकार द्वारा और शेष 10% राशि का वित्तीय भार इन छहराज्यों द्वारा वहन किया जाएगा।
- समझौता होने के बाद किशाऊ परियोजना को अनुमोदन के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

किशाऊ बहु-उद्देशीय बांध परियोजना

- यह यमुना की सहायक टोंस नदी पर उत्तराखंड-हिमाचल सीमा पर प्रस्तावित बहुउद्देशीय बांध है।
- जलविद्युत उत्पादन की क्षमता- 422 मेगावाट
- प्रस्तावित बांध- 236 मीटर ऊंचा
- जल भंडारण क्षमता- 1324 एमसीएम
- सिंचाई सुविधा- 97 हजार हेक्टेयर से अधिक

टोंस नदी-

- यह नदी यमुना की सबसे लंबी हिमालयी सहायक नदी है।
- यह बंदरपूँछ पर्वत समूह से निकलती है।

पीएम-वीबीआरवाई के तहत ₹2,400 करोड़ के प्रोत्साहन राशि का वितरण-

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून, 2026 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) के तहत लगभग ₹2,400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना-

- प्रारम्भ- 1 अगस्त, 2025
- संबंधित विभाग या मंत्रालय-
- केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय
- कार्यान्वयन एजेंसी- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)
- **उद्देश्य-**
  - औपचारिक रोजगारों को बढ़ावा।
  - पहली बार नौकरी पाने वालों को सहायता।
  - रोजगार सृजन में नियोक्ताओं की मदद।
  - विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती प्रदान करना।
- **लाभ-**
  - पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को एक महीने के वेतन के बराबर (अधिकतम ₹15,000 तक) प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
  - पहली किश्त नौकरी के 6 महीने पूरे होने पर सीधे आधार लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है। दूसरी किश्त 12 महीने पूरे होने पर भविष्य की बचत योजना/खाते में जमा की जाती है।
  - EPFO से जुड़ने के कारण युवाओं को भविष्य निधि और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा का स्थायी लाभ मिलता है।
  - अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए₹3,000 प्रति माहतक की वित्तीय सहायता (उनके वेतन स्लैब के आधार पर)।

यूपीएससी के नए कार्यालय का उद्घाटन-

- हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों ने 19 जून, 2026 को नई दिल्ली के तालकटोरा एनेक्स भवन में आयोग के नए कार्यालय का उद्घाटन किया।
- यह नया कार्यालय आयोग की बढ़ती स्थान संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने और इसकी बढ़ती संस्थागत जिम्मेदारियों को देखते हुए इसके प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत करने के लिए स्थापित किया गया है।

संघ लोक सेवा आयोग

- गठन- वर्ष 1926 में (ली आयोग की सिफारिश पर)
- स्वतंत्रता के बाद इस संस्था का संघ लोक सेवा आयोग के रूप में पुनर्गठन किया गया था।
- मुख्यालय- धौलपुर हाउस, नई दिल्ली (वर्ष 1952 में)

पीएम-किसान की 23वीं किस्त जारी-

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून, 2026 को पश्चिम बंगाल के हुगली से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 23वीं किस्त जारी की है।
- इस क़िस्त में ₹18,880 करोड़ से अधिक की राशि जारी की गयी जिसके अंतर्गत 9.44 करोड़ से अधिक किसानों को वित्तीय मदद प्राप्त हुई।
- इस योजना के अंतर्गत अब तक ₹4.46 लाख करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)

- यह केंद्र प्रायोजित योजना है।
- लाँच- 24 फरवरी, 2019
- उद्देश्य- देशभर में कृषि योग्य भूमि वाले भूमिधारक किसान परिवारों को सुनिश्चित आय की सहायता प्रदान करना।
- लाभ- पात्र किसान परिवार को प्रति वर्ष ₹6,000 की वित्तीय मदद (₹2,000 की तीन समान किस्तों में डीबीटी के माध्यम से)
- अब तक देश भर में पात्र किसान परिवारों को 23 किस्तों में ₹4.46 लाख करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है।
- इस योजना का लाभ किसानों को पीएम किसान पोर्टल पर भूमि रिकॉर्ड दर्ज करने पर मिलता है।
- केंद्रीय बजट 2026-27 में पीएम किसान योजना के लिए ₹60,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

दिशा-2.0 का अनुमोदन-

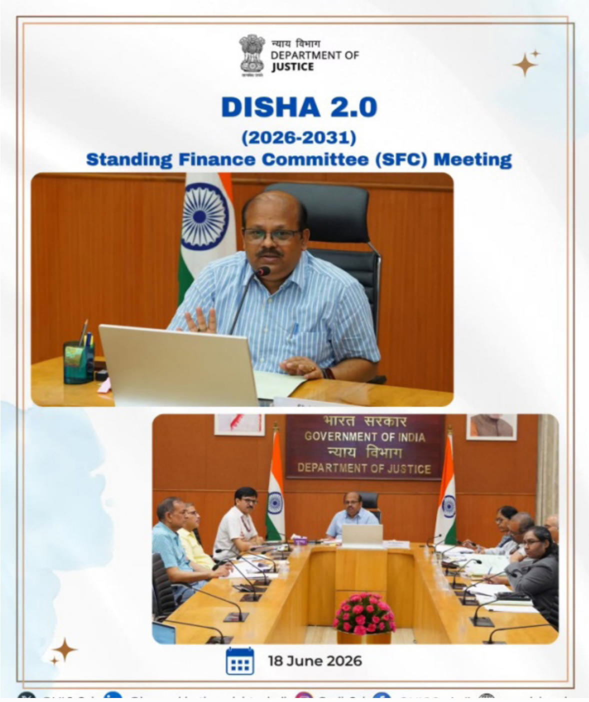

- हाल ही में केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना (दिशा)' को दिशा 2.0 के रूप में पुनर्गठित करने की मंजूरी प्रदान की है।

दिशा 2.0 (Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice - DISHA 2.0)-

- मंत्रालय- केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय
- विभाग-न्याय विभाग
- योजना का स्वरूप- यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना
- वित्तीय परिव्यय- 255 करोड़ रुपये
- योजना अवधि- 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031 तक (5 वर्ष की अवधि - 16वें वित्त आयोगके चक्र के अनुरूप)।
- योजना के घटक- 4 घटक
  1. टेली-लॉ कार्यक्रम
  2. न्याय बंधु-प्रो-बोनो कानूनी सेवाएं
  3. कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम
- दिशा 2.0 सतत विकास लक्ष्य-16 और वर्ष 2047 के विकसित भारत विज़न के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को सीधे तौर पर आगे बढ़ाती है।

एयर सुविधा 2.0 का शुभारंभ-

- हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (डीआईएएल) ने 25 जून, 2026 को एयर सुविधा 2.0 का शुभारंभ किया है।
- यह एक उन्नत संपर्क रहित यात्री स्वास्थ्य स्व-घोषणा पोर्टल है।
- इसका उद्देश्य इबोला रोग के प्रकोप के जवाब में प्रवेश केंद्रों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है।
- एयर सुविधा 2.0 का शुभारंभ डब्ल्यूएचओ द्वारा 17 मई, 2026 को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (आईएचआर) 2005 के अंतर्गत कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा में इबोला/बुंडीबुग्यो वायरस रोग के प्रकोप को अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (पीएचईआईसी) घोषित करने के बाद की गई है।

एमएसएमई दिवस 2026-उद्यमी भारतकार्यक्रम-

- आयोजन तिथि- 27 जून 2026
- आयोजन स्थल- डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली
- आयोजक- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
- अध्यक्षता- उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन
- उद्देश्य-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को सुदृढ़ता प्रदान करना।

- **डिजिटल पोर्टल और पहल का शुभारम्भ-**

क्र. सं.	पोर्टल/पहल का नाम	मुख्य उद्देश्य और विशेषताएँ
1	पीएमईजीपी 2.0 पोर्टल	■ पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और नागरिक-केन्द्रित इकोसिस्टम। ■ 'जन समर्थ पोर्टल' के साथ एकीकृत, जिससे बैंकों के साथ रियल-टाइम में लोन मंज़ूरी और डेटा ट्रांसफर आसान होगा।
2	समाधान 2.0 पोर्टल	■ केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों और CPSEs द्वारा MSMEs के बकाया भुगतान की ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग। ■ हर महीने अनिवार्य ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए समर्पित सुविधा।
3	पीएमएस 2.0 पोर्टल	■ सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSEs) को व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों से जोड़ना। ■ उद्यम रजिस्ट्रेशन से लिंक; आवेदन से लेकर रीइंबर्समेंट (प्रतिपूर्ति) तक की पूरी प्रक्रियाकागज रहित (Paperless)।
4	एमएसएमई ग्लोबल मार्ट 2.0	■ ONDC (ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स) इकोसिस्टम से जुड़ा अगली पीढ़ी का प्लेटफॉर्म। ■ MSMEs को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर व्यापार के नए अवसर देना।
5	एमएसएमई टेस्टिंग पोर्टल	■ देश भर के टेस्टिंग सेंटरों और स्टेशनों का संपूर्ण डिजिटलीकरण। ■ ग्राहक ऑनलाइन सैंपल बुकिंग, पेमेंट, ट्रैकिंग औरडिजिटल टेस्ट रिपोर्ट डाउनलोडकर सकेंगे।
6	एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 6.0	■ MSMEs में नवाचार (Innovation) को बढ़ावा देना। ■ स्वीकृत विचारों के लिए ₹15 लाख तक की वित्तीय सहायताका प्रावधान।

- इनके अलावा ई-बुक का भी विमोचन किया गया जो निम्न है-
  - **कॉफ़ी टेबल बुक-** 'पीएम विश्वकर्मा योजना' के सफल वर्षों के उपलक्ष्य में कारीगरों की प्रेरणादायक और बदलाव लाने वाली कहानियों का संग्रह।
  - **एसआरआई फंड पुस्तक-** 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत उद्यमों के विकास, रोजगार सृजन और महिला उद्यमिता में 'सेल्फ-रिलायंट इंडिया फंड' के योगदान पर आधारित पुस्तक।

भारत की पहली 'ईज़ी कनेक्ट' उड़ान का शुभारंभ

- केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने 25 जून, 2026 को वाराणसी से हब-एंड-स्पोक मॉडल के तहत भारत की पहली 'ईज़ी कनेक्ट' उड़ान का शुभारंभ किया।
- यह भारत को एक वैश्विक विमानन केंद्र में बदलने और टीयर-2 और टीयर-3 शहरों से यात्रियों को निर्बाध अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी प्रदान करने में सहायक होगी।
- इस 'ईज़ी कनेक्ट' सेवा के तहत यात्रियों के अनुभव और परिचालन की प्रक्रिया को बेहद सरल और सुविधायुक्त बनाया गया है।
- इस व्यवस्था के तहत सिंगल पॉइंट चेक-इन, प्रस्थान बिंदु पर ही इमिग्रेशन, नो-हैसल ट्रांजिट आदि को एकीकृत कर दिया जाता है। इस सेवा का संचालनएयर इंडिया द्वारा किया जा रहा है।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान और अधिसूचना के लिए एसओपी जारी की-

- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) ने जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 38 के तहत संकटग्रस्त प्रजातियों की अधिसूचना के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।
- इस एसओपी का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान, मूल्यांकन और अधिसूचना के लिए एक समान, पारदर्शी और वैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ प्रक्रिया को सुगम बनाना है।
- **जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 38-**
  - यह धारा केंद्र सरकार को संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करके किसी भी ऐसी प्रजाति को संकटग्रस्त अधिसूचित करने का अधिकार देती है जो विलुप्त होने की कगार पर है।
  - इसके तहत प्रजातियों के संग्रह को प्रतिबंधित/विनियमित किया जाता है और उनके पुनर्वास के उपाय किए जाते हैं।
  - केंद्र यह शक्ति राज्यों को भी सौंप सकता है।

Note- पर्यावरण मंत्रालय ने अब तक 17 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित 159 पौधों की प्रजातियोंऔर 173 जानवरों की प्रजातियों को संकटग्रस्त घोषित किया है।

सुर्ख़ियों में- डिजिटल इंडिया पहल

- डिजिटल इंडिया पहल के 1 जुलाई, 2026 को ग्यारह वर्ष पूर्ण होंगे।

- **डिजिटल इंडिया पहल- "शक्ति से सशक्तिकरण"**
- लॉंच तिथि- **1 जुलाई, 2015**
- यह दिन 'डिजिटल इंडिया सप्ताह' के रूप में मनाया गया था, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया।

संबंधित विभाग या मंत्रालय- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

- **उद्देश्य- प्रमुख उद्देश्य-**
  - **इंटरनेट की पहुँच बढ़ाना।**
  - **इंटरनेट को सस्ता बनाना।**
  - **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना।**
  - **डिजिटल साक्षरता बढ़ाना।**
  - **डिजिटल विभाजन को पाटना।**
  - **डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन।**

योजना के स्तंभ (नौ स्तंभ)

1. ब्रॉडबैंड हाईवे
2. मोबाइल कनेक्टिविटी
3. सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस
4. ई-गवर्नेंस
5. ई-क्रांति (सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी)
6. सभी के लिए सूचना
7. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण
8. आईटीसे रोजगार
9. अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम

विविध

- केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 26 जून, 2026 को पणजी (गोवा) में नए कैप्टन ऑफ पोर्ट्स टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया।
- हाल ही में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने 1 जून, 2026 को असम के डूमडूमा में परियोजना उदयक का 37वां स्थापना दिवस मनाया गया। परियोजना उदयक बीआरओ की रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश और असम के सुदूर पूर्वी क्षेत्रों में सी_मावर्ती बुनियादी ढांचे, पुलों और सड़कों का निर्माण और रखरखाव करके राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है।
- हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने 1 जून, 2026 को नई दिल्ली में स्वच्छ ग्राम, सुरक्षित जलवायु अभियान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया।
- हाल ही में राष्ट्रपति ने सिक्किम उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है।
- हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 3 जून, 2026 को नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजा-तीय विकास परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।
- भारत के अनुसंधान इको सिस्टम को मजबूत करने करने के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन-एएनआरएफ के सहयोग से डिजिटल पोर्टल लॉंच किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य देश भर के शोधकर्ताओं, छात्रों और नवोन्मेषकों के लिए पेटेंट दाखिल करने में सहायता और शोध पत्र लेखन में सहायता प्रदान करना है।
- हाल ही में मेरा युवा भारत (एमवाई भारत) को **"ऑनलाइन क्विज़ में एक सप्ताह में सबसे अधिक संख्या लोगों के भाग लेने" पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स खिताब से सम्मानित किया गया है।** आधिकारिक मूल्यांकन अवधि के दौरान ऑनलाइन क्विज़ में 390,812 प्रतिभागियों ने भाग लिया था।
- हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 5 जून, 2026 को दमन में नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे पर एक आधुनिक टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया।
- हाल ही में भारत की राष्ट्रपति ने 6 अपर न्यायाधीशों को बम्बई उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया है।

- हाल ही में केन्द्रीय मंत्री श्री जयंत चौधरी ने 6 जून, 2026 को भारत सरकार ने अधिक समावेशी, करुणामय और जन-केंद्रित कार्य वातावरण को बढ़ावा देने की दिशा में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के मुख्यालय के कौशल भवन में कर्मचारियों के बच्चों के लिए 'नई शिशु सदन सुविधा' का उद्घाटन किया।
- हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंडरवाटर आर्कियोलॉजी विंग और डेनमार्क के नेशनल म्यूज़ियम के 'न्योर्ड- सेंटर फ़ॉर मैरीटाइम एंड अंडरवाटर कल्चरल हेरिटेज' ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य 1619 ईस्वी में पुडुचेरी के कराईकल तट के पास दुर्घटनाग्रस्त ऐतिहासिक डेनिश जहाज 'ओरेसंड' के अवशेषों का पता लगाने और उनका दस्तावेजीकरण करने के लिए जलमग्न पुरातात्विक परियोजना शुरू करना है।
- प्रोजेक्ट सुपर 50- यह 19 जून, 2026 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) द्वारा नई दिल्ली में आयोजित सिविल सेवा परीक्षा मार्गदर्शन कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम का विषय "मार्गदर्शन,परामर्श,सशक्तिकरण" था।
- हाल ही में आईआईएम इंदौर ने वैभव सूर्यवंशी के माइंडसेट-मैनेजमेंट पर स्टडी करने की घोषणा की है। इसके तहत आईआईएम इंदौर 'वैभव मॉडल' पर देश की पहली मल्टी-डिसिप्लिनरी स्टडी करेगी।
- हाल ही में जर्मनी ने जर्मन एयरपोर्ट पर भारतीयों के लिए ट्रांजिट वीसा में छूट प्रदान की है।
- सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर घटकर 1.9 हो गई है, जो 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से कम है।
- हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में पानी लीकेज और पानी चोरी को रोकने के लिए रोबोट औरएआई सिस्टम को प्रयोग में लेने की घोषणा की है। इसके लिए 'सोलिनास' नामक स्टार्टअप पानी की पाइपलाइनों के भीतर विशेष रूप से डिजाइन किए गए रोबोट तैनात करेगा।
- भारत वर्ष 2025 में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बन गया है। देश की सौर क्षमता 155 गीगावाट से अधिक पहुंच गई है।
- केंद्र सरकार ने 'इमिग्रेशन और विदेशी नियम- 2025' में संशोधन किया है। नए नियमों के तहत 180 दिन या उससे कम अवधि के वीजा पर भारत आने वाले विदेशी नागरिक अब वीजा समाप्त होने से पहले कभी भी पंजीकरण करा सकेंगे।
- दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए 9,585 करोड़ रुपए की ग्रीन मोबिलिटी योजना को मंजूरी प्रदान की गयी है। इसके तहत पुराने ट्रक और बसें हटाई जाएंगी तथा बीएस-IV या उससे पुराने वाहनों के बदले नए बीएस-VI या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर प्रोत्साहन मिलेगा।
- आईआईटी भुवनेश्वर के वैज्ञानिकों ने नासा के सहयोग से गर्म शहरों की टॉप-20 लिस्ट जारी की है, इसमें राजस्थान का जयपुर शहर को भी गर्म शहर के रूप में रखा गया है।
- ऑयल इंडिया लिमिटेड को अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के पास प्राकृतिक गैस का विशाल बड़ा भंडार मिला। यह भंडार अंडमान निकोबार द्वीपों से 15 किलोमीटर दूर श्री विजय पुरम-3 में मिला है।
- यूएन-हैबिटेट और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने दुनिया के 20 शहरी इलाकों में वर्कला नगर पालिका (केरल) को 'जीरो वेस्ट सिटी' के तौर पर चुना है। वर्कला 20 शहरों में अकेला भारतीय शहर है।
- 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के तहत लाभार्थियों को प्रतिवर्ष चार सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर प्राप्त होंगे।
- भारत सरकार ने बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी को 'टेबल ऑफ प्रेसिडेंस' में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा दिया।
- सीमा सड़क संगठन की परियोजना ब्रह्मांक ने 29 जून, 2026 को अरुणाचल प्रदेश के राणाघाट में अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया।
- केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 29 जून, 2026 को आरोग्य सेतु 2.0 और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अन्य डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया।
- हाल ही में पूर्णिमा विश्वविद्यालय में विद्याभारती के सहयोग से "भारतीय ज्ञान परंपरा-पारंपरिक ज्ञान से आधुनिक शिक्षा, शोध और नवाचार" विषयक पांच दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
- एडेलमैन ट्रस्ट इंडेक्स-2026 **में** भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया। यह इंडेक्स बिजनेस, सरकार, मीडिया और एनजीओ में लोगों के भरोसे के औसत स्तर को दिखाता है। इस इंडेक्स में चीन और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) संयुक्त रूप से पहले पायदान पर है।
- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाली 13.1 किमी लंबी जोजिला सुरंग में 9 जून, 2026 को अंतिम ब्रेकथ्रू हासिल हुआ। 11,578 फीट की ऊंचाई पर बन रही यह दुनिया की सबसे लंबी द्वि-दिशात्मक सड़क सुरंग है।
- भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNRWA को 21 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की। यह भारत के सालाना 50 लाख डॉलर के योगदान की पहली किस्त होगी।
- हाल ही में राज्यसभा के लिए हुए निर्वाचन में 27 सीटों में से 24 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। निर्विरोध चुने गए सदस्यों में 19 एनडीए और 5 कांग्रेस के हैं।
- लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश में 74 नए लैंड पोर्ट बनाने का प्रस्ताव रखा। इनमें तीन लैंड पोर्ट चीन सीमा पर और छह लैंड पोर्ट पाकिस्तान सीमा पर बनाए जायेंगे। वर्तमान में देश में पन्द्रहलैंड पोर्ट हैं।

Samyak
An Institute For Civil Services

सर्वाधिक विश्वसनीय व परिणामोन्मुखी

TEST SERIES

RAS 2026

OFFLINE & ONLINE
EVERY SUNDAY

PRELIMS
21 TEST PAPER
16 TOPICWISE
05 FULL PAPER
TIME: 10:30 AM

PRELIMS GOLD
35 TEST PAPER
MAINS 14 TEST
8 AM - 10 AM
PRE 21 TEST
10:30 AM - 1:30 PM

RPSC पैटर्न पर आधारित
डिटेल्ड मॉडल ANSWER KEY
हिंदी और ENGLISH MEDIUM
PERSONAL MENTORSHIP

H.O: NEAR RIDDHI - SIDDHI, JAIPUR 9875170111

4. आर्थिक परिदृश्य

भारत और ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) प्रभावी-

- हाल ही में भारत और ओमान की तरफ से दोनों पक्षों द्वारा आंतरिक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बादभारत और ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) 1 जून, 2026 से प्रभावी हो गया है।
- इस समझौते पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैथम सईद की उपस्थिति में 18 दिसंबर, 2025 को मस्कट में हस्ताक्षर किए गए थे।
- ओमान खाड़ी क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और अपने उन्नत बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से व्यापक जीसीसी बाजार के लिए एक रणनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।
- वित्त वर्ष 2025-26 में भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 11.18 अरब अमरीकी डॉलर रहा।
- **CEPA की प्रमुख विशेषताएँ-**
  - ओमान भारत के 99.38% निर्यात (मूल्य के हिसाब से) को तत्काल शून्य शुल्क पर प्रवेश दे रहा है, जिसमें ओमान की 98.08% शुल्क प्रक्रियाएं शामिल हैं।
  - भारत ने ओमान से होने वाले 94.81% मूल्य के आयात को कवर करने वाली 77.79% शुल्क प्रक्रियाओं पर रियायत दी है।
  - झींगा, मछली और कटलफिश सहित सभी समुद्री उत्पादों पर लगने वाला 5% तक का आयात शुल्क तत्काल समाप्त कर दिया गया है।
  - रत्नों और आभूषणों पर लगने वाला 5% तक का आयात शुल्क पहले दिन से खत्म।
  - शहद, मसाले, काजू, बासमती चावल, मक्खन, मीठे बिस्कुट और आम को शुल्क-मुक्त पहुंच दी गई है।
  - टीकों और पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन व टेट्रासाइक्लिन जैसी सामग्रियों के लिए बाध्यकारी शून्य-शुल्क पहुंच दी गयी है।
  - ओमान ने 127 सेवा उप-क्षेत्रों में बाजार पहुंच की प्रतिबद्धता की है।
  - ओमान, भारत की निर्यात निरीक्षण परिषद के प्रमाण-पत्रों, NPOP जैविक प्रमाणन और हलाल प्रमाणन प्रणालियों को अनिवार्य रूप से स्वीकार करेगा।

मूगा रेशम के लिए 'सेनेहजोरी मिशन' का शुभारंभ-

- हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2 जून, 2026 को असम में मिशन सेनेहजोरी- असम मूगा सिल्क का शुभारंभ किया। यह एक व्यापक क्लस्टर-आधारित पहल है।
- इसका उद्देश्य असम के अद्वितीय मूगा रेशम क्षेत्र को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी, उच्च मूल्य वाले लक्जरी वस्त्र इकोसिस्टम में परिवर्तित करना है।
- इस मिशन में तीन वर्षों की अवधि में लगभग 396 से 411 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिसमें से 136 से151करोड़ रुपये पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय देगा।
- मिशन में जोरहाट, शिवसागर, लखीमपुर, धेमाजी, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, माजुली और सुआलकुची जैसे प्रमुख रेशम उत्पादक जिलों को शामिल किया गया है।
- मिशन के अंतर्गत वर्ष 2028 तक पाँच आधुनिक रीलिंग इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी, 30 किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे और 8000 से अधिक परिवारों के लिए डिजिटल ट्रेसबिलिटी तंत्र तैयार किया जाएगा।
- यह मिशन पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, असम सरकार, केंद्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/संगठनों के समन्वय से संचालित है।

मूगा रेशम-

- यह दुनिया का एकमात्र प्राकृतिक रूप से सुनहरा रेशम है।
- यह भारत का पहला जीआई-टैग प्राप्त रेशम माना जाता है।
- असम विश्व के मूगा रेशम उत्पादन का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा अकेले उत्पादित करता है।

लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (विनिमय) का उद्घाटन-

- हाल ही में केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 9 जून, 2026 को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (विनिमय) का उद्घाटन किया।
- लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम भारत की विशाल भू-सीमा के कुशल प्रबंधन के लिए "स्मार्ट बॉर्डर" विज़न के तहत एक आधुनिक, डिजिटल, एकीकृत और रियल-टाइम प्रबंधन प्रणाली है।
- **लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम की विशेषताएं और तकनीकी-**
  - यह कार्गो (माल), पैसेंजर और वाहनों के प्रबंधन के लिए एक सिंगल-विंडो सिस्टम उपलब्ध कराता है।
  - इसमें पूरी व्यवस्था को डिजिटल कर कागजी प्रक्रियाओं को लगभग समाप्त कर दिया गया है।
  - इसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान आधारित गेट संचालन प्रणाली शामिल है।
  - LPMSके माध्यम से विभिन्न प्रमुख प्रणालियों को एक ही मंच पर लाया गया है जिससे रियल-टाइम डेटा साझा हो सकेगा।

बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन के वर्ष 2025-26 के द्वितीय अग्रिम अनुमान जारी-

- हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन के वर्ष 2025-26 के द्वितीय अग्रिम अनुमान जारी किए हैं।

कुल बागवानी	2025-26 (द्वितीय अग्रिम अनुमान)
क्षेत्रफल	301.51 (लाख हेक्टेयर में)
उत्पादन	3777.76 (लाख टन में)

मुख्य बिन्दु-

- देश में, वर्ष 2025-26 में बागवानी फसलों का क्षेत्रफल लगभग 301.51 लाख हेक्टेयर है जो कि 2024-25 (अंतिम) की तुलना में 0.14 लाख हेक्टेयर (0.05%) अधिक है।
- देश में, वर्ष 2025-26 में, बागवानी उत्पादन लगभग 3777.76 लाख टन है, जो कि 2024-25 (अंतिम) की तुलना में 70.39 लाख टन (1.90%) ज़्यादा है।
- देश में फलों, सब्जियों, फूलों और सुगंधित एवं औषधीय पौधों के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

सात्विक इंडेक्स

- यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) द्वारा जारी किया गया इंडेक्स है, जो नैतिक (एथिकल) निवेश पर केंद्रित है। यह इंडेक्स बीएसई 500 इंडेक्स से तैयार किया गया है और निवेशकों को अपने निवेश को मूल्य-आधारित सिद्धांतों के अनुरूप रखने का अवसर प्रदान करता है।

थोक मूल्य सूचकांक (WPI)-

- हाल ही में भारत सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित कर 2022-23 कर दिया है।

बदलाव या संशोधन-

- o बास्केट का विस्तार-सूचकांक में शामिल कुल वस्तुओं की संख्या697 से बढ़ाकर 957कर दी गई है।
- o हरित ऊर्जा का समावेश- 'विद्युत' समूह के अंतर्गत अब पारंपरिक बिजली के साथ-साथहरित ऊर्जा का समावेश किया गया है।
- o कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का स्थानांतरण- इन्हें 'ईंधन और बिजली'समूह में स्थानांतरित कर दिया गया है।
- o उत्पादन और सांख्यिकी के स्तर पर डेटा की सटीकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित तीन बड़े तकनीकी बदलाव किए गए हैं-

सुधार का क्षेत्र	पुरानी श्रृंखला (2011-12)	नई श्रृंखला (2022-23)	आर्थिक महत्व/लाभ
भार निर्धारण	शुद्ध व्यापार मूल्य	सकल उत्पादन मूल्य	यह उत्पादक के दृष्टिकोण से घरेलू उत्पादन के वास्तविक आर्थिक महत्व को बेहतर ढंग से दर्शाता है।
सूचकांक गणना	दीर्घकालिक सूत्रीकरण विधि	शृंखला-आधारित अल्पकालिक सूत्रीकरण विधि	यह अल्पकालिक मूल्य परिवर्तनों और बाजार के रुझानों को अधिक सटीकता से पकड़ता है।
मिसिंग डेटा का उपचार	'कैरी-फॉरवर्ड' विधि	'लक्षित माध्य इम्पुटेशन'	यदि किसी महीने का मूल्य डेटा उपलब्ध न हो, तो यह विधि सांख्यिकीय रूप से अधिक सटीक अनुमान लगाती है और डेटा को त्रुटिहीन बनाती है।

पूर्वी रेलवे के लिए सिग्नल आधुनिकीकरण परियोजना को मंजूरी-

- हाल ही में भारतीय रेल ने 17 जून, 2026 को पूर्वी रेलवे पर 405 करोड़ रुपये की सिग्नलिंग उन्नयन परियोजना को मंजूरी दी है।
- इस परियोजना के तहत 32 स्टेशनों पर रिले-आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- यह परियोजना भारतीय रेलवे की व्यापक कार्यनीति का हिस्सा है जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण मार्गों पर सिग्नलिंग सिस्टम का आधुनिकीकरण करना और पूरे नेटवर्क में विश्वसनीयता, सुरक्षा और प्रचालनगत प्रदर्शन में सुधार करना है।

खाद्यान्न भंडारण के लिए स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम लाँच-

- हाल ही में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने 18 जून, 2026 को नई दिल्ली में खाद्यान्न भंडारण के लिए स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम लाँच किया है।
- यह सिस्टम भारत के खाद्यान्न भंडारण तंत्र के आधुनिकीकरण की दिशा के लिए महत्वपूर्ण है।
- यह प्रणाली सार्वजनिक क्षेत्र के खाद्यान्न भंडारण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) आधारित प्रौद्योगिकियों की विश्वव्यापी सबसे बड़ी तैनाती का प्रतिनिधित्व करती है।
- इस पहल को केंद्रीय भंडारण निगम के 215 बोरी आधारित खाद्यान्न गोदामों में लागू किया गया है, जबकि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) अतिरिक्त 150 गोदामों में इस प्रणाली को लगा रहा है।
- इस प्रौद्योगिकी-आधारित प्रणाली से वाहन के टर्नअराउंड समय को कम करके, पारदर्शिता बढ़ाकर, अनुपालन निगरानी को मजबूत करके, मानव संसाधन उत्पादकता में सुधार करके, खतरों का शीघ्र पता लगाने में सक्षम बनाकर और गोदाम संचालन की वास्तविक समय की दृश्यता प्रदान करके परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय सुधार किया जा सकेगा।

राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड की आधारशिला रखी-

- हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून, 2026 को लखनपुर, झारसुगुड़ा जिला (ओडिशा) में भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड की कोयला-से-अमोनियम नाइट्रेट परियोजना की आधारशिला रखी।
- इस परियोजना का लक्ष्य भारत की ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी आत्मनिर्भरता और घरेलू कोयला संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित किया जाना है।
- इस परियोजना का उद्देश्य कोयला गैसीकरण के माध्यम से लगभग 0.66 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) तकनीकी श्रेणी के अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करना है।
- इस परियोजना के निर्माण में लगभग ₹25,000 करोड़ से अधिक का निवेश किया जा रहा है।
- **भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड (बीसीजीसीएल)-**
  - यह कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (बीएचईएल) के बीच गठित एक संयुक्त उद्यम कंपनी है।
  - इसमें जिसमें सीआईएल की 51% और बीएचईएल की 49% हिस्सेदारी है।
- **कोल गैसीफिकेशन**
  - यह एक रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें कोयले को भाप और सीमित ऑक्सीजन की उपस्थिति में उच्च तापमान पर गर्म करके सिंथेटिक गैस (सिनगैस) में बदला जाता है।
  - यह प्रक्रिया कोयले को सीधे जलाने के बजाय उपयोगी ईंधन और रसायनों में परिवर्तित करती है, जिससे प्रदूषण कम होता है और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होती है।

भारत वर्ष 2025 में विश्व का अग्रणी जहाज पुनर्चक्रण राष्ट्र बना-

- संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के अनुसार, वर्ष 2025 में वैश्विक जहाज पुनर्चक्रण में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 35.4% हो गई है, जो दुनिया में सबसे अधिक है।
- भारत में जहाज पुनर्चक्रण वर्ष 2024 के 1.86 मिलियन ग्रॉस टन से लगभग 60 प्रतिशत बढ़करवर्ष 2025 में 2.99 मिलियन ग्रॉस टनतक पहुंच गया है।
- भारत नेसमुद्री भारत विजन 2030 के तहत वैश्विक स्तर पर अग्रणी जहाज पुनर्चक्रण राष्ट्र बनने का लक्ष्य निर्धारित समय से काफी पहले ही हासिल कर लिया है।

कॉपर-क्लोरीन थर्मोकेमिकल चक्र पर आधारित विश्व की पहली हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा का उद्घाटन

- भारत के आणविक ऊर्जा विभाग ने इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, कल्पक्कम में स्थितफास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा का उपयोग करकेकॉपर-क्लोरीन (Cu-Cl) थर्मोकेमिकल चक्रपर आधारितविश्व की पहली हाइड्रोजन उत्पादन सुविधाका उद्घाटन किया है।
- इस Cu-Cl ऊष्मा रासायनिक प्रक्रिया कोभाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबईद्वारा पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है।
- यह सुविधा एक 'टेक्नोलॉजी डेमोनस्ट्रेटर' के रूप में स्थापित की गई है। यह सुविधा प्रमाणित करती है कि परमाणु ऊर्जा से मिलने वाली उच्च तापमान वाली हीट को सीधे हाइड्रोजन उत्पादन के साथ एकीकृत किया जा सकता है। इससे भविष्य में कार्बन-मुक्त हाइड्रोजन का उत्पादन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

विविध

- हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 10 जून, 2026 आंध्रप्रदेश की न्यू कैपिटल सिटी, अमरावती में जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के निर्माण को स्वीकृति दे दी है। यह कैपिटल सिटीअमरावती के साथ साथ आंध्र प्रदेश राज्य में पहली जीपीआरए परियोजना है।
- ऑयलसीड्स किसान मित्र- यह आईसीएआर-आईआईओआर, हैदराबाद द्वारा विकसित वाट्सऐप-आधारित एआई परामर्श सेवा है। यह सेवा तिलहन की खेती आधारित जानकारी किसानों के मोबाइल फ़ोन पर उपलब्ध करवाती है। इस सेवा को 6 फरवरी, 2026 को शुरू किया गया था।
- हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने 11 जून, 2026 को आईएस 20201:2026 सामुदायिक बीज बैंक प्रबंधन नयी भारतीय मानक आवश्यकताएं प्रकाशित की हैं।
- हाल ही में आईआईटी गांधीनगर में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 11 जून, 2026 को डीएसटी द्वारा वित्तपोषित सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी और 3 रिसर्च क्लस्टर लॉन्च किए है।
- हाल ही में भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) और फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (एफडीडीआई) ने 12 जून, 2026 को भारत के चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र में गुणवत्ता, परीक्षण, मान्यता और कौशल तंत्र को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- हाल ही में भारत सरकार के खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने खादी उत्कृष्टता केंद्र (सीओईके) द्वारा निर्मित 'स्वधा' नाम से एक विशेष वेलनेस वियर कलेक्शन पेश किया है।
- हाल ही में ग्रामीण विकास विभाग 6 करोड़ लखपति दीदियों का लक्ष्य पूरा करने के लिए 700 शी-मार्ट और 1,000 ज़िला फुलफ़िलेमेंट सेंटर बनाने की घोषणा की है।
- हाल ही में भारत के कोयला-समृद्ध क्षेत्रों में रेलवे की क्षमता में सुधार करते हुए भारतीय रेल ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 42 किलोमीटर लंबी चांपा-कोरबा तीसरी रेल लाइन परियोजना को लगभग 755 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मंज़ूरी प्रदान की है।
- वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 1.78 लाख करोड़ रुपये रहा। यह वार्षिक रक्षा उत्पादन पिछले वित्त वर्ष के 1.54 लाख करोड़ रुपये के उत्पादन की तुलना में 15.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
- हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस ने 18 जून, 2026 ग्रामीण और कम सुविधा वाले क्षेत्रों मेंसरकारी खरीद के अवसरों तक पहुंच बढ़ाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।
- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्धारित भारतीय विमानन कंपनियों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए विमानन टरबाइन ईंधन की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने में सहायता प्रदान करने हेतु तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपये तक की एकमुश्त बजटीय सहायता को मंज़ूरी प्रदान की है।
- कोयला मंत्रालय ने 'कोल एक्सचेंज रुल्स 2026 अधिसूचित किए। इससे देश में कोल एक्सचेंज स्थापित किए जाएंगे, जहां कोयले की खरीद-बिक्री पारदर्शी तरीके से होगी।
- वित्त मंत्रालय ने E22, E25, E27 और E30 पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क पूर्ण माफ कर दिया है। इसका उद्देश्य एथेनॉल के उपयोग को बढ़ाना और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना है।
- विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष-2026-27 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.6% रह सकती है। वहीं वैश्विक विकास दर 2.5% रह सकती है।
- केंद्र सरकार ने आयात घटाने के लिए छह वर्किंग ग्रुप बनाए। ये समूह 100 प्रमुख उत्पादों की पहचान करेंगे, जिनका घरेलू उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा। इन वर्किंग ग्रुप की अध्यक्षता DPIIT के सचिव करेंगे।

Samyak
An Institute For Civil Services
PSI
PAPER 1st & 2nd
बैच प्रारम्भ
3 दिवसीय नि:शुल्क कक्षा के साथ

5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

रक्षा-प्रौद्योगिकी

नेत्र-विमानस्थ प्रारंभिक चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली

- हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने स्वदेशी नेत्र-विमानस्थ प्रारंभिक चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली काअंतिम परिचालन स्वीकृति (एफओसी) प्रमाणपत्रभारतीय वायुसेना को औपचारिक रूप से सौंप दिया है।
- यह प्रणालीडीआरडीओ, भारतीय वायुसेना और भारतीय रक्षा उद्योग जगतके त्रिपक्षीय सहयोग से विकसित की गई है।
- इसका उद्देश्यहवाई निगरानी, स्थिति संबंधी जागरूकता और युद्ध प्रबंधन क्षमताओं को सुदृढ़ करना है।
- नेत्र-
  - यहभारत का पहला स्वदेशी तौर पर विकसित विमानस्थ प्रारं-भिक चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली है।
  - इसे एम्ब्रेयर विमान के प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया गया है।
  - इसमें 240-डिग्री कवरेज वाला एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार लगा है।

दिव्यास्त्र MK-1 का सफल परीक्षण-

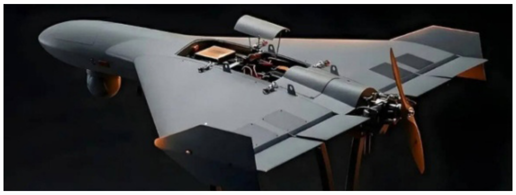

- हाल ही में भारतीय सेना ने जोधपुर में स्वदेशी टैक्टिकल लोइटरिंग म्यूनिशन 'दिव्यास्त्र MK-1' का सफल परीक्षण किया।
- यह एक स्वदेशी टैक्टिकल यूएवी है।
- इसे खुफिया जानकारी, निगरानी, टोही और सटीक हमले के मिशनों के लिए विकसित किया गया है।
- **प्रमुख विशेषता-**
  - निर्माता- Hoverit (डिफेंस स्टार्टअप) द्वारा
  - उड़ान क्षमता- 5 घंटे
  - पेलोड क्षमता- 15 किलोग्राम
  - ऑपरेशनल रेंज- 500 किलोमीटर
  - गति- 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे
  - कम लागत और AI आधारित स्वार्म अटैकक्षमता से युक्त।

रुद्र एम-II वायु-से-सतह मिसाइल

- हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय वायु सेना ने चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में स्वदेशी रुद्र एम-II मिसाइल का का सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमान से सफल उड़ान परीक्षण किया गया।
- रुद्रम-II को स्वदेशी रूप से हैदराबाद स्थित इमारत अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है, जो डीआरडीओ की नोडल प्रयोगशाला है।
- **RudraM-II मिसाइल-**
  - यह स्वदेशी एंटी-रेडिएशन मिसाइल है।
  - यह वायु-से-सतह पर मार करती है।
  - RudraM मिसाइल के तीन संस्करण है-
    1. RudraM-I
    2. RudraM-II
    3. RudraM-III
- विकास- इमारत अनुसंधान केंद्र, हैदराबाद

डीआरडीओ ने लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल (एलआरएलएसीएम) का सफल परीक्षण किया-

- हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 15 जून, 2026 को लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया।
- यह मिसाइल परीक्षण ओडिशा तट पर स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था।
- यह मिसाइल शत प्रतिशत स्वदेशी रूप से विकसित क्रूज मिसाइल है।
- इस मिसाइल की परियोजना के लिए नोडल प्रयोगशाला बेंगलुरु स्थित एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है।
- यह मिसाइल हवा में ही अपना रास्ता बदलने और दुश्मन के ठिकानों को ढूंढकर उन पर सटीक स्ट्राइक करने की क्षमता रखती है।
- इस मिसाइल की मारक क्षमता 1,000 किलोमीटर से लेकर 1,500 किलोमीटर तक है।

भारतीय तटरक्षक बल ने स्वदेशी एयर कुशन वाहन को सेवा में शामिल किया-

- हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने 18 जून, 2026 को स्वदेशी एयर कुशन व्हीकल्स (एसीवी) को भारतीय तटरक्षक बल की सेवा में शामिल किया है।
- इस एसीवी का निर्माण "चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड" द्वारा किया गया है।
- इस होवरक्राफ्ट का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में भारतीय तटरक्षक बल की संचालन क्षमता को बढ़ाना और उभरती चुनौतियों का सामना करने की उसकी क्षमता को मजबूत करना है।

Note:- भारतीय तटरक्षक बल के लिए छह एसीवी (एकल वाहन) की खरीद का अनुबंध रक्षा मंत्रालय और चोगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के बीच 24 अक्टूबर, 2026 को हस्ताक्षरित किया गया था।

भारतीय नौसेना में तीन अत्याधुनिक जहाज कमीशन हुए-

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 21 जून, 2026 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारतीय नौसेना के प्रथम पंक्ति के तीन अत्याधुनिक जहाजों को कमीशन किया।
- इनमें बहु-उद्देशीय क्षमताओं से लैस आईएनएस दूनागिरी, एक विशाल सर्वेक्षण पोत आईएनएस संशोधक और उथले पानी के पनडुब्बी-रोधी युद्धपोत आईएनएस अग्रय शामिल हैं।
- ये अत्याधुनिक जहाज देश की परिचालन क्षमताओं, भू-राजनीतिक खतरों के खिलाफ समुद्री सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में स्थितिजन्य जागरूकता को बढ़ाएंगे।

- **आईएनएस दूनागिरी-**
  - यह प्रोजेक्ट 17ए के तहत नीलगिरी श्रेणी का पांचवां युद्धपोत है।
  - यह गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित है।
  - यह युद्धपोत सुपरसोनिक सतह-से-सतह मिसाइलों, उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों, मीडियम-रेंज गन, क्लोज-इन वेपन सिस्टम तथा अत्याधुनिक पनडुब्बी-रोधी युद्धक क्षमताओं से लैस है।
  - इसे उच्च-स्तरीय समुद्री अभियानों और बहुआयामी युद्धक भूमिकाओं के लिए तैयार किया गया है।

- **आईएनएस संशोधक-**
  - यह विशाल सर्वेक्षण पोत श्रेणी का चौथा जहाज है।
  - यह भारत के 'मैरीटाइम विजन 2030' को सशक्त बनाता है।
  - यह पोत अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक और समुद्र-विज्ञान प्रणालियों के साथ-साथ चार सर्वे मोटर बोट्स (एसएमबी) से सुसज्जित है।

- **आईएनएस अग्रय-**
  - यह उथले पानी के पनडुब्बी-रोधी युद्धपोत श्रृंखला का पांचवां पोत है।
  - यह भारतीय नौसेना की उथले जल क्षेत्रों में पनडुब्बी-रोधी व माइन वॉरफेयर क्षमताओं को और सुदृढ़ करता है।
  - इस पर अत्याधुनिक सोनार, टॉरपीडो, पनडुब्बी-रोधी रॉकेट तथा उन्नत कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है।

X-59 विमान

- यह नासाऔर लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित सुपरसोनिक विमान है।
- इस विमान की गति लगभग 1,489-1,510 किमी/घंटा है।
- यह विमान उड़ान के दौरान उत्पन्न होने वाले सोनिक बूम को सोनिक थंप में बदल देता है।

एयरबस सी-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की पहली टेस्ट फ्लाइट-

- 11 जून, 2026 को देश के पहले 'मेड इन इंडिया' एयरबस सी-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने वडोदरा से पहली टेस्ट फ्लाइट सफलतापूर्वक पूरी की। इसे टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और एयरबस की वडोदरा स्थित फाइनल असेंबली लाइन में बनाया गया है।
- यह वायुसेना के लिए देश में बनने वाले 40 सी-295 विमानों की श्रृंखला का पहला विमान है। यह भारत में निजी क्षेत्र द्वारा सैन्य विमान निर्माण का पहला बड़ा प्रोजेक्ट है। इन विमानों में 85% से अधिक स्ट्रक्चरल निर्माण भारत में हो रहा है।

रूस से एस-400 की चौथी स्क्वाड्रन प्राप्त हुई-

- हाल ही में रूस से एयर डिफेंस सिस्टम एस-400 (सुदर्शन चक्र) की चौथी स्क्वाड्रन प्राप्त हुई है।
- भारत ने रूस से एस-400 एयरडिफेंस सिस्टम की पांच स्क्वाड्रन की खरीद का समझौता अक्टूबर, 2018 में किया था।
- भारत और रूस के बीच 5 स्क्वाड्रन के लिएअंतर-सरकारी समझौता हुआ था।

एस-400

- विकसित- रूस द्वारा
- यह लंबी दूरी की, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालीहै।
- यह सिस्टम एक साथ चार अलग-अलग श्रेणियों की मिसाइलों को दागने में सक्षम है, जिससे यह एक अभेद्य सुरक्षा कवच बनाता है।
- इसका रडार 600 किमी. दूरी तकके हवाई खतरों का पता लगा सकता है और एक साथएकाधिक लक्ष्यों को ट्रैककर सकता है।
- यह पूरी तरह से सड़क-आधारित वाहनों पर तैनात है।

इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक-ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन-

- हाल ही में हैदराबाद के स्टार्टअप ब्लूजे एयरोस्पेस ने दूसरी जेनरेशन का इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक-ऑफ एंड लैंडिंग (eVTOL) ड्रोन विमान पेश किया है।
- यह ड्रोन हेलीकॉप्टर की तरह बिना रनवे टेकऑफ और लैंडिंग कर सकेगा।
- इसे भारी सामान की तेज ढुलाई के लिए बनाया गया है।
- विशेषता-
  - भार वहन क्षमता- 200 किलो
  - अधिकतम रफ्तार- 200 किमी प्रति घंटा
  - रेंज- बैटरी मॉडल की रेंज 50-70 किमी जबकि हाइड्रोजन-इलेक्ट्रिक मॉडल की रेंज 250-300 किमी

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन-

- 29 जून, 2026 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन (डीएफपी-2026)' जारी कियाहै।
- यह डीएफपी-2026 रणनीतिक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के समय पर निष्पादन, दक्षता और जवाबदेही को बढ़ाने के सुधार के रूप में है।

अंतरिक्ष-प्रौद्योगिकी

आर्टेमिस-III मिशन के चालक दल की घोषणा-

- नासा ने चंद्रमा के मिशन आर्टेमिस-III के चालक दल की घोषणा की।
- **क्रू सदस्य और जिम्मेदारियां-**
    - रैंडी ब्रेस्निक- नासा के अंतरिक्ष यात्री, कमांडर
    - लुका परमिटानो- ईएसए (यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी) के अंतरिक्ष यात्री, पायलट
    - आंद्रे डगलस- नासा के अंतरिक्ष यात्री, मिशन विशेषज्ञ
    - फ्रैंक रुबियो- नासा के अंतरिक्ष यात्री, मिशन विशेषज्ञ
- आर्टेमिस-III मिशन वर्ष 2028 में चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने के प्रयास से पहले नियोजित अंतिम मिशन है।

सेमी क्रायोजेनिक इंजन का हॉट टेस्ट

- इसरो नेसेमी क्रायोजेनिक इंजन का आठवां हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक किया है। यह इंजन अत्याधुनिक प्रक्षेपणयान एलवीएम-3 की पे-लोड क्षमता बढ़ाएगा।
- इसका परीक्षण महेंद्रगिरि स्थित प्रणोदन परिसर में किया गया।

सूचना-प्रौद्योगिकी व अन्य प्रौद्योगिकी-

कैंसर कारकों को निष्क्रिय करने के लिए अगली पीढ़ी की नैनोमेडिसिन की खोज-

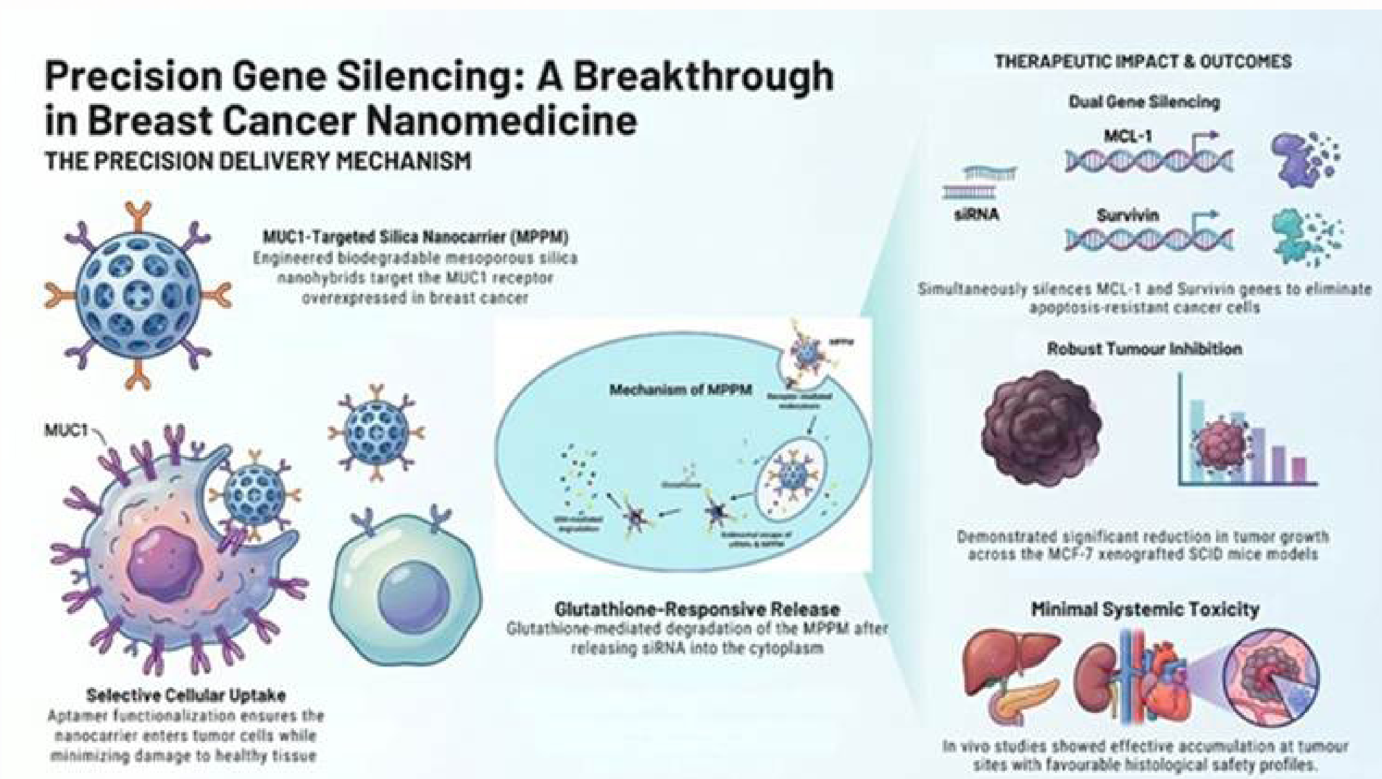

- हाल ही में पुणे स्थित अगरकर अनुसंधान संस्थान के नैनोबायोसाइंस समूह के वैज्ञानिकों ने जीन साइलेंसिंग की रणनीति विकसित की है जो स्तन कैंसर में ट्यूमर को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है।
- वैज्ञानिकों नेस्तन कैंसर के इलाज में लक्षित जीन थेरेपी के लिए एक नवीनजैव-अपघटनीय नैनोकैरियर प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
- यह प्रणालीजैव-अपघटनीय मेसोपोरस सिलिका नैनोकणों पर आधारित है। ये नैनोकण अपनी उच्च लोडिंग क्षमता या ज्यादा दवा ले जाने की क्षमता और बेहतर सतह रसायन के गुण दर्शाते है।
- यह तकनीक पारंपरिक कीमोथेरेपी की तुलना में बेहतर है क्योंकि-

पारंपरिक कीमोथेरेपी	नैनोमेडिसिन आधारित थेरेपी
कैंसर कोशिकाओं के साथ-साथ शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को भी मार देती है। इससे बाल झड़ना, कमजोरी जैसे साइड-इफेक्ट्स होते हैं।	एप्टामर-निर्देशित होने के कारण यह केवल ट्यूमर कोशिकाओं पर हमला करती है। इससे स्वस्थ कोशिकाओं को कोई नुकसान नहीं होता (कम साइड-इफेक्ट्स)।
ट्यूमर के अंदर तक पूरी दवा सटीक मात्रा में नहीं पहुंच पाती।	नैनोकणों के कारण दवा सीधे ट्यूमर के कोर तक पहुंचती है और रिसेप्टर्स के जरिए कोशिकीय अवशोषण बढ़ जाता है।

- अगरकर अनुसंधान संस्थान, भारत सरकार केविज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्तसंस्थान है।

आधुनिक कंप्यूटिंग में ऊर्जा खपत को कम करने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग-

- हाल ही में शोधकर्ताओं ने ध्वनि तरंगों का उपयोग करके मैग्नॉन-आधारित स्पिन धाराओं को उत्पन्न और नियंत्रित करने की एक नई प्रणाली खोजी है।
- यह खोज नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली के शोधकर्ताओं ने की है।
- वर्तमान के कंप्यूटर और मोबाइल विद्युत आवेशपर काम करते हैं। इसकी कमी यह है कि इलेक्ट्रॉनों के टकराने सेऊष्माउत्पन्न होती है और ऊर्जा की भारी हानिहोती है।इसके विपरीत स्पिनट्रॉनिक्स अगली पीढ़ी की तकनीक हैजिसमें सूचना का प्रसारण विद्युत आवेश के बजाय इलेक्ट्रॉनों केस्पिनद्वारा किया जाता है।
- मैग्नॉन- पदार्थों के भीतर चुंबकीय विक्षोभ की तरंगों को मैग्नॉन कहा जाता है जो सूचना के बहुत कुशल वाहक हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों की तुलना मेंबहुत कम ऊर्जा हानिके साथ काम करते हैं।
- **अनुप्रयोग और लाभ-**
  - इसके प्रयोग से कंप्यूटिंग उपकरणों में होने वाली ऊर्जा की खपत और थर्मल हीटिंगकी समस्या को बहुत हद तक कम किया जा सकेगा।
  - यह खोज अधिक स्थिर और कुशल क्वांटम प्रोसेसर और मेमोरी डिवाइस बनाने में मदद कर सकती है।
  - 6Gऔर उससे आगे की हाई-स्पीड, अल्ट्रा-लो लेटेंसी संचार प्रणालियों के विकास में यह तकनीक गेम-चेंजर साबित हो सकती है।
  - इससे अधिक छोटे, तेज और टिकाऊ प्रोसेसर बनाए जा सकेंगे।

एमएनआईटी जयपुर में स्थापित होगी एडवांस क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस प्रयोगशालाएं-

- हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 11 जून, 2026 को मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर में उन्नत क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम संचार प्रयोगशाला स्थापित किए जाने की घोषणा की।
- ये प्रयोगशालाएं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इलेक्ट्रॉनिकी और आईसीटी अकादमिक परियोजना के तहत स्थापित की जाएंगी। इनका उद्देश्य सुरक्षित संचार विकसित करने के तंत्र क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, क्वांटम कंप्यूटिंग सिमुलेशन और क्वांटम सेंसिंग हार्डवेयर घटकों में स्वदेशी क्षमता निर्मित करना होगा।

लैम रिसर्च का सेमीवर्स प्लेटफॉर्म-

- एमएनआईटी जयपुर में लैम रिसर्च के सेमीवर्स प्लेटफॉर्म की सुविधा मिलेगी, जो डिजिटल ट्विन आधारित सेमीकंडक्टर निर्माण और प्रशिक्षण पारितंत्र है।

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस लैब-

- इस लैब में अनुसंधान और नवाचार के लिए उन्नत कंप्यूटिंग और उपकरणों सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसका मुख्य उद्देश्य इसे इंडियाएआई मिशन नेटवर्क से जोड़ना है।

मेकर्स लैब उद्घाटन-

- एमएनआईटी जयपुर में मेकर्स लैब का उद्घाटन किया।
- मेकर्स लैब विद्यार्थियों को सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों तकनीकों में प्रायोगिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करेगी।
- इसमें सेंसर, एम्बेडेड सिस्टम, कंप्यूटर उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली शामिल होंगे।

जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट आकाशवाणी एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन-

- हाल ही में केन्द्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आकाशवाणी के जयपुर परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के आकाशवाणी एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया।
- इस ट्रांसमीटर का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में अखिल भारतीय रेडियो और दूरदर्शन की पहुंच को मजबूत करना है।
- इस ट्रांसमीटर के उद्घाटन के साथ ही राजस्थान में एफएम ट्रांसमीटरों की संख्या 39 हो गई।
- रामगढ़ ट्रांसमीटर से सीमावर्ती क्षेत्र में 80 कि.मी. के दायरे में रेडियो कवरेज सुनिश्चित होगा जो जैसलमेर जिले के लगभग 20 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगा।

'वार्या' एआई मॉडल का शुभारंभ-

- हाल ही में एआई-नेटिव ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी अवतार ने 12 जून, 2026 को डिस्टिल्ड वीडियो मॉडल 'वार्या' के लॉन्च की घोषणा की।
- यह एआई मॉडल भारत के अगली पीढ़ी के उपयोगकर्ताओं के लिए फ्रंटियर वीडियो एआई को किफायती, सुलभ और प्रासंगिक बनाने के लिए लाँच किया गया है।
- वार्या एआई मॉडल इंडिया एआई मिशन के सहयोग से विकसित किया गया है।
- यह एआई मॉडल वीडियो निर्माण को 50 चरणों को घटाकर 4 चरणों तक सीमित कर देता है और 0.48 रुपये प्रति सेकंड की लागत पर वीडियो बना सकता है।
- वार्याको भारत के विविध सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है, न कि भारत की किसी सामान्यीकृत अवधारणा के आधार पर।
- इस मॉडल का उद्देश्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों, त्योहारों, समुदायों, खान-पान, पहनावे, सार्वजनिक स्थानों और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े सांस्कृतिक रूप से समृद्ध दृश्य प्रस्तुतियां तैयार करना और उन्हें समझना है।
- **अवतार कंपनी-** यह एआई-नेटिव ट्रान्सफॉर्मेशन कंपनी है, जो डोमेन-विशिष्ट एआई उत्पाद बनाती है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 16 एफडीसी पर प्रतिबंध लगाया-

- हाल ही में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 20 जून, 2026 को 16 निश्चित खुराक संयोजनों (एफडीसी) के निर्माण, बिक्री और उनके मानवीय उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
- स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह प्रतिबंध औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 की धारा 26ए के तहत लगाये है।
- इस प्रतिबंध का लक्ष्य जनस्वास्थ्य की रक्षा करने और केवल वैज्ञानिक रूप से उचित दवा संयोजनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
- **प्रतिबंधित एफडीसी-**

क्र.सं.	एफडीसी की संरचना
1	एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड + एथोहेप्टाज़ीन
2	एलोवेरा का अर्क + एलेंटोइन + अल्फाटोकोफेरोल एसीटेट + डी-पेंथेनॉल + विटामिन ए
3	एलोवेरा का अर्क + विटामिन ई + डाइमेथिकोन + ग्लिसरीन
4	एलो वेरा + जोजोबा तेल + विटामिन ई
5	एलोवेरा + ऑरेंज ऑयल
6	एलोवेरा + जोजोबा तेल + व्हीट जर्म ऑयल + टी ट्री तेल
7	एलोवेरा + विटामिन ई + हर्बल
8	डाइसाइक्लोमाइन + पैरासिटामोल + क्लिडिनियम ब्रोमाइड
9	डाइसाइक्लोमाइन + पैरासिटामोल + क्लिडिनियम ब्रोमाइड + क्लोर्डियाज़ेपॉक्साइड
10	ग्लिक्लाजाइड + क्रोमियम पिकोलीनेट
11	पैरासिटामोल + लिग्नोकेन
12	एमोक्सिसिलिन + सेराटियोपेप्टिडेज़ + लैक्टोबैसिलस स्पोरोजेन्स
13	एमोक्सिसिलिन + क्लोक्सासिलिन + लैक्टिक एसिड बैसिलस + सेराटियोपेप्टिडेज़
14	एमोक्सिसिलिन + सेराटियोपेप्टिडेज़
15	सेफैड्रोक्सिल + प्रोबेनेसिड
16	सेफ्यूरोक्सिम + सेराटियोपेप्टिडेज़

निश्चित खुराक संयोजन (एफडीसी)- इसे निश्चित खुराक वाली दवा संयोजन (एफडीसी) के रूप में भी जाना जाता है।यह एक ही खुराक रूप में दो या दो से अधिक सक्रिय दवाओं का संयोजन होते हैं।

जेनरेटिव एआई अपनाने में भारत की पांचवीं रैंक-

- भारत जेनरेटिव एआई अपनाने में दुनिया के शीर्ष-5 देशों में सम्मिलित हो गया है। इस सूची में भारत से आगे शीर्ष स्थानों पर क्रमश: अमेरिका, चीन, सिंगापुर और ब्रिटेन हैं।
- भारत ने इस सूची में जर्मनी को पीछे छोड़ है।
- भारत डिजिटलीकरण रैंकिंग में भी आठवें से पांचवें स्थान पर पहुंच गया है।

हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स-फ्यूल मोटरसाइकिलों के लॉन्च-

- हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प ने 3 जून, 2026 को नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स-फ्यूल मोटरसाइकील लॉन्च की है।

फ्लेक्स-फ्यूल मोटर साइकील

- एक फ्लेक्स-फ्यूल मोटरसाइकील वह है जिसका इंजन पेट्रोल और एथेनॉल के किसी भी मिश्रण पर चल सकता है।
- साधारण मोटर साइकीलें केवल पेट्रोल पर चलने के लिए डिज़ाइन की जाती हैं।
- इसके विपरीत फ्लेक्स-फ्यूल मोटरसाइकील का इंजन इस तरह बनाया जाता है कि वह 0% से लेकर 85% तक एथेनॉल-पेट्रोल मिश्रण पर चल सकता है।

रेटैट्रुटाइड/रेटाट्रूटाइड दवा

- यह वजन घटाने वाली और डायबिटीज-रोधी दवा है जो अभी प्रायोगिक स्तर पर है। इसे अमेरिकी दवा कंपनी एली लिली (Eli Lilly) द्वारा विकसित किया जा रहा है।
- यह दवा शरीर में तीन अलग-अलग हार्मोन (जीएलपी-1, जीआईपी और ग्लूकागॉन) की तरह काम करती है। इससे भूख कम लगती है। शरीर अधिक ऊर्जा खर्च करता है और ब्लड शुगर नियंत्रित रहती है।

आर्सेनसेफ उपकरण-

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भुवनेश्वर के शोधकर्ताओं ने पीने के पानी में आर्सेनिक की तेजी से पहचान के लिए 'आर्सेनसेफ' नामक एक पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है।
- यह कम लागत वाला आसानी से इस्तेमाल किया जा सकने वाला समाधान है।
- यह उपकरण पानी में आर्सेनिक की मौजूदगी का त्वरित पता लगाने में सक्षम है।
- इसे आईआईटी भुवनेश्वर के अनुसंधान एवं उद्यमिता पार्क में स्थापित एक नवाचार उद्यम के माध्यम से विकसित किया गया है।

ट्रूनेट एचपीवी-एचआर प्लस-

- यह मोल्बियो डायग्नोस्टिक्स द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी पॉइंट-ऑफ-केयर मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक परीक्षण किट है। इसे हाल ही में एम्स और आईसीएमआर के शोधकर्ताओं ने सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रमाणित किया है।
- यह 8 उच्च जोखिम वाले HPV प्रकारों की पहचान कर सकता है।

रिवर्स एजिंग की दवा का इंसानों पर पहला ट्रायल प्रारम्भ-

- अमेरिका के बोस्टन स्थित बायोटेक स्टार्टअप 'लाइफ बायोसाइंसेज' ने रिवर्स एजिंग के लिए एक व्यक्ति को सेल्यूलर रीप्रोग्रामिंग का इंजेक्शन दिया है।
- यह इंजेक्शन ग्लूकोमा (काला मोतिया) से पीड़ित एक मरीज की एक आंख की पुतली में लगाया गया है। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य उम्र बढ़ने के कारण कमजोर हो चुकी कोशिकाओं को फिर से युवा और सक्रिय बनाना है।

आईआईटी-मद्रास नेदुनिया का सबसे विस्तृत थ्री-डी ब्रेन_ स्टेम एटलस जारी किया-

- आईआईटी मद्रास के सुधा गोपालकृष्णन ब्रेन सेंटर ने मानव ब्रेनस्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत थ्री-डी एटलस जारी किया है। इस विस्तृत थ्री-डी एटलस का नाम 'एंकर' रखा गया है। इस एटलस में ब्रेनस्टेम के 200 से ज्यादा न्यूरल केंद्रों और तंत्रिका मार्गों की विस्तृत मैपिंग की गई है।
- **ब्रेनस्टेम-**

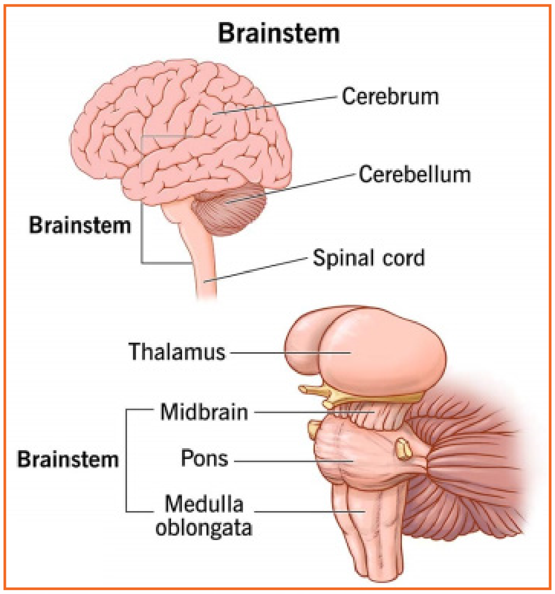

  - यह मानव मस्तिष्क का हिस्सा है।
  - यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बीच का मुख्य जोड़ है।
  - यह सांस लेने, दिल की धड़कन और शरीर की कई जरूरी गतिक्र विधियों को नियंत्रित करता है।

भारत का पहला एआई डेटा सेंटर बनाएगी रिलायंस-मेटा-

- रिलायंस इंडस्ट्रीज और मेटा ने जामनगर (गुजरात) में डेटा सेंटर के निर्माण के लिए समझौता किया।

- यह देश में मेटा का पहला 'बिल्ट-टू-सूट' डेटा सेंटर होगा। इसकी डेटा सेंटर की क्षमता 168 मेगावाट होगी। इस साझेदारी के तहत रिलायंस इस डेटा सेंटर को पूरी तरह से विकसित करेगी।
- रिलायंस इस प्रोजेक्ट के लिए डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, यूटिलिटी मैनेजमेंट, रिन्यूएबल पावर, नेटवर्क कनेक्टिविटी और मैनेज्ड सर्विसेज सहित एंड-टू-एंड सर्विसेज देगी।

हाइड्रोजेल-आधारित सुपर स्पंज-

- हाल ही में आइआइटी-गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने उन्नत हाइड्रोजेल-आधारित सामग्री विकसित की है जो सुपर स्पंज की तरह काम करेगा।
- यह सुपर स्पंज औद्योगिक अपशिष्ट जल में मौजूद जहरीले या विषैले रंगों को प्रभावी ढंग से सोखने में सक्षम है।
- आइआइटी-गांधीनगर के सुपर स्पंज का यह शोध 'एसीएस एप्लाइड पॉलिमर मैटेरियल्स' पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

शिगेला संक्रमण-

- केरल में शिगेला संक्रमण के सौ से अधिक मामले सामने आये है।
- **शिगेला-**
  - यह संक्रामक बैक्टीरियल संक्रमण है।
  - यह आंतों को प्रभावित करता है।
  - यह मुख्यत: दूषित भोजन या पानी के जरिए फैलता है।

कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण तकनीक-

- जापान की ओसाका मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने बैटरी-रहित कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण प्रणाली विकसित की है।
- यह प्रणाली केवल सूर्य की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके तरल ईंधन बना सकती है।

तमिलनाडु तट पर लगेंगे 3डी प्रिंटेड कृत्रिम रीफ

- भारत के पहले 3डी प्रिंटेड कृत्रिम रीफ मॉड्यूल्स को तमिलनाडु के रामनाथपुरम तट के पास समुद्र में स्थापित किया जाएगा।
- यह परियोजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के दूसरे चरण के तहत समुद्री आवास पुनर्स्थापन की महत्वाकांक्षी पहल है।
- इस पायलट परियोजना में छह नए रीफ डिजाइन का मूल्यांकन होगा, जिन्हें अत्याधुनिक 3डी प्रिंटिंग तकनीक से विकसित किया गया है।
- इन 3डी प्रिंटेड कृत्रिम रीफ को आइआइटी मद्रास की स्टार्टअप ट्वस्ता ने केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के सहयोग से विकसित किया है।

रीफ- रीफ समुद्र के अंदर बनने वाली जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है, जो मछलियों को भोजन, आश्रय और प्रजनन स्थल प्रदान करता है।

- हाल ही में बेंगलुरू में आयोजित ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों (एचओएसए) की बैठक के समापन सत्र में केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने "ब्रिक्स अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था" का प्रस्ताव रखा है।
- हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 20 उन्नत क्षमता वाले वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली जैमर की खरीद के लिए बेंगलुरु स्थित अकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ 449 करोड़ रुपये की कुल लागत के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।
- हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 12 जून, 2026 को तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी (डीआरडीएल) में अत्याधुनिक हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया।
- हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 19 जून, 2026 को नौसेना के लिए 1.25 मेगावाट के लगभग 425 करोड़ रुपये की कुल लागत के 12 मरीन गैस टर्बाइन जनरेटर सेट की खरीद के लिए पुणे स्थित भारत फोर्ज लिमिटेड के साथ पर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए है।
- हंगोर पनडुब्बी- यह पाकिस्तान की नौसेना में शामिल की गयी पनडुब्बी है। यह उन आठ हंगोर श्रेणी की पनडुब्बियों में पहली है, जिन्हें 2028 तक पाकिस्तानी नौसेना में शामिल किया जाना है।
- भारतीय वायुसेना ने घरेलू कंपनियों के सहयोग से स्वदेशी कामीकाजे ड्रोन परियोजना शुरू की। तमिलनाडु के सुलूर स्थित '5 बेस रिपेयर डिपो' इसकी नोडल एजेंसी है।
- भारत की पहली स्वदेशी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का वारहेड महाराष्ट्र के नागपुर से सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड पहुंचाएगी।
- 'वाक्विटा' जो विलुप्ति के कगार पर पहुंचा दुर्लभसमुद्री स्तनधारी को वैज्ञानिकों ने डिजिटल रूप में संरक्षित किया है।
- आंध्र प्रदेश की अमरावती क्वांटम वैली ने स्वदेशी तकनीक से विकसित डायल्यूशन रेफ्रिजरेटर से माइनस 269 डिग्री सेल्सियस तापमान हासिल किया है।

- तमिलनाडु के इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर की गर्मी से हाइड्रोजन बनाने वाला प्लांट शुरू हुआ। इसमें BARC की स्वदेशी कॉपर-क्लोरीन तकनीक का इस्तेमाल होगा।
- हाल ही में नेशनल जूलॉजिकल पार्क (एनजेडपी), नई दिल्ली में स्मार्ट डिजिटल ज़ू गाइड "एनजेडपी साथी ऐप" लॉन्च किया गया है। इस एप का उद्देश्य स्मार्ट नेविगेशन के माध्यम से आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाना और ऑनलाइन टिकट बुकिंग को आसान बनाना है।
- हाल ही में आईआईटीएम ने हिमालयी क्षेत्र में भारत जलवायु अवलोकन नेटवर्क के दीर्घकालिक निगरानी केंद्र की स्थापना के लिए आर्यभट्ट अनु-संधान विज्ञान संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है।
- हाल ही में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 23 जून 2026 को नई दिल्ली स्थित अटल अक्षय ऊर्जा भवन में NAFEDके ऑक्शन पोर्टल **NAFEX.in** का शुभारंभ किया।
- हाल हीमें सी-डॉट ने 24 जून, 2026 को अगली पीढ़ी की संचार प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी-हैदराबाद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस रणनीतिक सहयोग के अंतर्गत सी-डॉट आईआईटी हैदराबाद में एक उत्कृष्टता केंद्र

6. खेल परिदृश्य

क्रिकेट

आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप-2026

ICC
WOMEN'S T20
WORLD CUP
ENGLAND & WALES 2026

- संस्करण- 10वां
- आयोजन तिथि- 12 जून-5 जुलाई, 2026
- आयोजक- अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद
- आयोजन स्थल- इंग्लैंड और वेल्स
- **प्रतिभागी टीम- 12 टीम**

1.	इंग्लैंड	**2.**	भारत
3.	ऑस्ट्रेलिया	**4.**	श्रीलंका
5.	न्यूजीलैंड	**6.**	पाकिस्तान
7.	साउथ अफ्रीका	**8.**	वेस्टइंडीज
9.	बांग्लादेश	**10.**	नीदरलैंड्स
11.	आयरलैंड	**12.**	स्कॉटलैंड

- नीदरलैंड्स की टीम पहली बार (डेब्यू) महिला टी20 वर्ल्ड कप खेल रही है।

कोहली देश की सबसे मूल्यवान हस्ती-

- फॉर्च्यून इंडिया और वैश्विक ब्रांड परामर्श फर्म इंटरब्रांड द्वारा जारी भारत की सबसे मूल्यवान हस्तियों की सूची में विराटकोहलीशीर्ष स्थान पर हैं।
- विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू 3,542 करोड़ रुपए है।
- **क्रमशः शीर्ष 10 मूल्यवान हस्ती-**

1. विराट कोहली	-	क्रिकेटर
2. शाहरुख खान	-	अभिनेता
3. प्रियंका चोपड़ा	-	अभिनेत्री
4. महेंद्र सिंह धोनी	-	क्रिकेटर
5. रणवीर सिंह	-	अभिनेता
6. अक्षय कुमार	-	अभिनेता
7. अमिताभ बच्चन	-	अभिनेता
8. सचिन तेंदुलकर	-	क्रिकेटर
9. आलिया भट्ट	-	अभिनेत्री
10. अल्लू अर्जुन	-	अभिनेता

वनडे वर्ल्ड कप - 2027

- आयोजन तिथि- 4 अक्टूबर से 21 नवंबर, 2027
- आयोजन स्थल- दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी
- इस टूर्नामेंट में कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी और कुल 54 मुकाबले खेले जाएंगे।

निखिल चौधरी-

- यह भारत में जन्मे ऑलराउंडर क्रिकेटर है। इनको पहली बार ऑस्ट्रेलिया की टी-20 टीम में शामिल किया गया है। इन्हें बांग्लादेश दौरे के लिए ट्रेविस हेड की जगह टीम में चुना गया है।
- निखिल ने वर्ष 2017 से 2019 के मध्य पंजाब के लिए घरेलू मैच खेले थे।

केन विलियमसन-

- यह न्यूजीलैंड के बल्लेबाज और पूर्व कप्तान है। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है।

साईराज बहुतुले-

- यह पूर्व भारतीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और घरेलू क्रिकेटर है। इनको **बीसीसीआई द्वारा भारत का स्पिन गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है।**

हॉकी

पुरुष हॉकी अंडर-18 एशिया कप 2026

- आयोजन तिथि- 29 मई से 6 जून, 2026
- आयोजन स्थल- काकामिगाहारा, जापान
- संस्करण- 6वां संस्करण
- प्रतिभागी टीम- 9 टीम
- विजेता-भारत (भारत ने फाइनल मैच में जापान को हराकरयह खिताब अपने नाम किया।)
- **फाइनल मुकाबला- 6 जून, 2026**
  - भारत ने जापान को 4–1 से शिकस्त दी।
  - भारत ने तीसरी बारइस महाद्वीपीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है।
- **स्टार खिलाड़ी-**
  - भारतीय फॉरवर्ड आशीष तानी पूर्ति

Note- हॉकी अंडर-18 एशिया कप-2026 के महिला वर्ग में भारतीय अंडर-18 महिला हॉकी टीम ने कोरिया को 3-0 से हराकर कांस्य पदक हासिल किया है।

FIH हॉकी विमेंस नेशंस कप-2025-26

- आयोजन तिथि- 15-21 जून, 2026
- मेजबान देश-ऑकलैंड, न्यूजीलैंड
- विजेता-भारत (फाइनल में मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराया)
- उपविजेता-न्यूजीलैंड
- भारतीय कप्तान-सलीमा टेटे
- प्लेयर ऑफ द मैच (फाइनल)-लालरेम्सियामी
- यह भारत की दूसरी नेशंस कप जीत है। इससे पहले साल 2022 में भारत ने इस खिताब पर अपना कब्जा जमाया था।

मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट-2026

- संस्करण- 7वां संस्करण
- आयोजन तिथि- 23 जून से 03 जुलाई, 2026
- आयोजन स्थल- जलाहल्ली एयर फोर्स स्टेशन, बेंगलुरु में
- इस टूर्नामेंट का आयोजन एयर फोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड (एएफएससीबी) साल 2018 से कर रहा है।
- इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में देशभर की कुल 16 टीमों ने भाग लिया।
- **टूर्नामेंट के लिए पुरस्कार-**
  - विजेता- 10,00,000/- रूपये
  - उपविजेता- 8,00,000/- रूपये

एथलेटिक्स

एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप

- संस्करण- 22वां
- आयोजन तिथि- 28 मई से 31 मई, 2026
- आयोजन स्थल- हांगकांग, चीन
- आयोजक- एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा
- भारत का प्रदर्शन- भारतीय एथलीटों ने कुल 19 पदक अपने नाम किये।
- **स्वर्ण पदक- 10**

1. वेंकटराम रेड्डी मोगाली
2. निखिल चंद्रशेखर

3. नितिन गुप्ता
4. बसंत
5. शाहनवाज खान
6. राहुल जाखड़
7. मुस्कान
8. पूजा सिंह
9. अमानत कंबोज
10. भारतीय महिला रिले टीम

- **रजत पदक- 5**
- **कांस्य पदक- 4**
- भारत ने पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया (चीन ने 25 पदक जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया)
- इस चैंपियनशिप में कुल 48 भारतीय एथलीटों ने भाग लिया, जिनमें 30 पुरुष और 18 महिलाएं शामिल थीं।
- घरेलू मैदान से बाहर आयोजित महाद्वीपीय ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

राष्ट्रीय अंतरराज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप-2026

- संस्करण- 65वां
- आयोजन तिथि-24 जून से 28 जून, 2026
- आयोजन स्थल- भुवनेश्वर, ओड़िशा
- यह चैम्पियनशिप जापान में आयोजित होने वाले आगामी2026 एशियाई खेलों के लिए मुख्य राष्ट्रीय क्वालिफिकेशन और चयन ट्रायल इवेंट थी।

जैकोब थार्प-

- यह अमरीकी एथलीट है जिन्होंने नेशनल कॉलेजिएट एथलेटिक एसोसिएशन की आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ के सेमीफाइनल में 12.75 सेकंड का समय निकाला। इन्होंने 14 साल पुराने एरीज मेरिट के 12.80 सेकंड समय के विश्व रेकॉर्ड को तोड़ा है।

फुटबॉल

फीफा वर्ल्ड कप-2026

- संस्करण- 23वां
- आयोजन तिथि- 11 जून व 19 जुलाई, 2026
- आयोजन दिसव- 39 दिन
- आयोजन स्थल- अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको
- प्रतिभागी टीम- 48 टीम
- मैच-104 मैच
- यह फीफा के सदस्य संघों की राष्ट्रीय टीमों द्वारा खेला जाने वाला चतुर्वार्षिक अंतरराष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैम्पियनशिप है।
- इसकी संयुक्त मेजबानी 16 शहर कर रहे हैं- 11 संयुक्त राज्य अमेरिका में, 3 मेक्सिको में और 2 कनाडा में।
- **प्रतिभागी टीम सारणी-**

एएफसी (9)	*कॉन्काकैफ (6)*	*यूईएफए (16)*
1. ऑस्ट्रेलिया	**1.** कनाडा	**1.** ऑस्ट्रिया
2. ईरान	**2.** कुराकाओ	**2.** बेल्जियम
3. इराक	**3.** हैती	**3.** बोस्निया और हर्ज़ेगोविना
4. जापान	**4.** मेक्सिको	**4.** क्रोएशिया
5. जॉर्डन	**5.** पनामा	**5.** चेक गणराज्य
6. कतर	**6.** अमेरिका	**6.** इंग्लैंड
7. सऊदी अरब	*कॉनमेबोल (6)*	**7.** फ्रांस
8. दक्षिण कोरिया	**1.** अर्जेंटीना	**8.** जर्मनी
9. उज़्बेकिस्तान	**2.** ब्राजील	**9.** नीदरलैंड
सीएएफ (10)	**3.** कोलंबिया	**10.** नॉर्वे
1. अल्जीरिया	**4.** इक्वाडोर	**11.** पुर्तगाल
2. केप वर्डे	**5.** पैराग्वे	**12.** स्कॉटलैंड
3. डीआर कांगो	**6.** उरुग्वे	**13.** स्पेन
4. मिस्र	*ओएफसी (1)*	**14.** स्वीडन
5. घाना	**1.** न्यूजीलैंड	**15.** स्विट्जरलैंड
6. आइवरी कोस्ट		**16.** तुर्की
7. मोरक्को		
8. सेनेगल		
9. दक्षिण अफ्रीका		
10. ट्यूनीशिया		

भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने जीती एसएएफएफ महिला चैंपियनशिप 2026-

- संस्करण- 8वां संस्करण
- आयोजन तिथि- 25 मई 2026 से 6 जून 2026

- आयोजक-साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन
- मेजबान- भारत
- प्रतिभागी टीमें- भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका
- पहला संस्करण- वर्ष 2010

फाइनल मुकाबल-

- भारत बनाम बांग्लादेश
- आयोजन स्थल- पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम (फातोर्डा स्टेडियम), मडगांव (मार्गाओ), गोवा
- विजेता- भारत(भारत ने बांग्लादेश को हराया)
- उपविजेता- बांग्लादेश
- यह भारत का छठा एसएएफएफ महिला चैंपियनशिप खिताब है।

तहसीन मोहम्मद जमशेद-

- यह भारतीय मूल के कतर के पेशेवर फुटबॉलर हैं।
- यह फीफा में कतर की ओर से खेलेंगे।
- इससे पहले वर्ष 2006 के फीफा वर्ल्डकप में आंध्र प्रदेश मूल के विकास धोरासू ने फ्रांस की टीम की तरफ से फीफा में खेला था।

ग्रेस दांगमेई-

- यह भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान है जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है।
- यह मणिपुर की रोंगमेई जनजाति से संबंध रखती हैं।

शतरंज

नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2026-

- आयोजन तिथि- 25 मई से 5 जून 2026
- आयोजन- ओस्लो, नार्वे
- विजेता- ग्रैंडमास्टरआर. प्रग्नानंद
- टूर्नामेंट के फाइनल राउंड में प्रगनानंद ने जर्मनी के विसेंट केमार को हराया। इस टूर्नामेंट में अमेरिकी ग्रैंडमास्टर वेस्ले सो दूसरे स्थान पर जबकि अलीरेजा फिरोजा तीसरे स्थानपर रहे।
- Note- आर. प्रग्नानंद इस प्रतिष्ठित वैश्विक टूर्नामेंट को जीतने वाले_ पहले भारतीय बने हैं।

टेनिस/टेबल टेनिस

फ्रेंच ओपन-2026

- आयोजन तिथि- 18 मई से 7 जून, 2026
- आयोजन स्थल- पेरिस , फ्रांस
- एक ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट था।
- विजेता-

कैटेगरी	विजेता	उपविजेता
पुरुष एकल	अलेक्जेंडर ज्वेरेव	फ्लेवियो कोबोली
महिला एकल	मीरा एंड्रीवा	माजा चवलिंस्का
पुरुष युगल	मार्सेल ग्रानोलर्स - होरासियो जेबालोस	हैरी हेलियोवारा - हेनरी पैटन
महिला युगल	कैटरीना सिनियाकोवा - टेलर टाउनसेंड	अन्ना दानिलिना - अलेक्जेंड्रा क्रुनिच
मिश्रित युगल	सारा एरानी - एंड्रिया वावासोरी	—

दिव्यांशी भौमिक-

- यह भारत की 15 वर्षीय टेबल टेनिस खिलाड़ी है। इन्होंने डब्ल्यूटीटी फीडर महिला एकल खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय बनीं है। दिव्यांशी ने फाइनल में चीनी ताइपे की ये यी-तियान को 3-2 से शिकस्त दी।

कुश्ती

उलानबतोर ओपन-2026 कुश्ती टूर्नामेंट-

- आयोजन तिथि- 4 से 7 जून, 2026
- आयोजन स्थल- उलानबतोर, मंगोलिया
- यह यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग सीज़न कीतीसरी रैंकिंग सीरीज़ थी।
- भारत का प्रदर्शन-
- भारत ने कुल 16 पदकअपने नाम किये
- स्वर्ण पदक विजेता-

पहलवान का नाम	*भार वर्ग*	*कुश्ती की शैली*
सुनील कुमार	87 किग्रा	ग्रीको-रोमन
नितेश कुमार	97 किग्रा	ग्रीको-रोमन
सागर जगलान	74 किग्रा	पुरुष फ्रीस्टाइल
दिनेश धनखड़	125 किग्रा	पुरुष फ्रीस्टाइल
दीपक	61 किग्रा	पुरुष फ्रीस्टाइल
मनीषा भानवाला	57 किग्रा	महिला फ्रीस्टाइल
नेहा सांगवान	59 किग्रा	महिला फ्रीस्टाइल
काजल धोचक	76 किग्रा	महिला फ्रीस्टाइल

अन्य

विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026-

- संस्करण- प्रथम संस्करण
- मैस्कॉट- वीर द लॉयन (Veer the Lion)
- आयोजन तिथि- 4 से 8 जून , 2026
- आयोजन स्थल- अहमदाबाद, गुजरात
- भागीदारी- 79 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया
- **पदक तालिका-**
  - भारत ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। भारत ने 114 पदक (102 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदक) जीते हैं।
  - जापान पदक तालिका में 11 पदकों (3 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य) के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि अर्जेंटीना ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।

15वीं एशियन सीनियर कुराश चैंपियनशिप 2026-

- आयोजन तिथि- 11 से 15 जून, 2026
- आयोजन स्थल- दुशांबे, ताजिकिस्तान
- आयोजक- इंटरनेशनल कुराश एसोसिएशन
- कुराश- मध्य एशिया की पारंपरिक कुश्ती है जो अब एक प्रमुख वैश्विक खेल है।

ग्लोबल स्किल्स चैलेंज 2026-

- आयोजन तिथि- 23 से 29 जून 2026
- आयोजन स्थल- ऑस्ट्रेलिया
- आयोजक- वर्ल्डस्किल्स ऑस्ट्रेलिया
- यह वर्ल्डस्किल्स कॉम्पिटिशन का ही एक बड़े स्तर का अंतरराष्ट्रीय सिमुलेशन है।
- भारतीय दल ने 15 प्रतियोगियों और 15 विशेषज्ञों सहित 30 सदस्यीय उन्नत विनिर्माण, डिजिटल प्रौद्योगिकी, निर्माण व्यवसाय, रचनात्मक उद्योग और सेवा क्षेत्र कौशल सहित 15 कौशल श्रेणियों में देश का प्रतिनिधित्व किया। इस प्रतियोगिता में टीम इंडिया ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए 5 पदक जीते हैं-
- **स्वर्ण पदक- 3**
  - पवन भद्रावती सुरेश (कर्नाटक)-एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में
  - मौसम कुमार गिरि (बिहार)- क्लाउड कंप्यूटिंग में
  - विष्णुप्रिया सुनील (दिल्ली)- स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल में
- **रजत पदक- 1**
  - हर्ष रमेश पवार (महाराष्ट्र)- 3डी डिजिटल गेम आर्ट में
- **कांस्य पदक- 1**
  - मुस्कान (हरियाणा)- चित्रकला और साज-सज्जा में

जैस्मिन लंबोरिया

- वर्ल्ड चैम्पियन जैस्मिन लंबोरिया महिला 57 किग्रा वर्ग में दुनिया की नंबर-1 मुक्केबाज बन गई हैं।
- वर्ल्ड बॉक्सिंग रैंकिंग में भारत ने महिलाओं की 10 में से 9 और पुरुषों की 10 में से 8 वेट कैटेगरी में टॉप-10 में जगह बनाई है।

रुमेश पथिरागे

- यह श्रीलंका के जैवलिन थ्रोअर है।
- इन्होंने रोम डायमंड लीग में 92.62 मीटर का थ्रो किया है।
- यह 90 मीटर से अधिक भाला फेंकने वाले एशिया के चौथे खिलाड़ी बने। उनसे पहले, पाक के अरशद नदीम (92.97), चीन के चेंग चाओ सुन (91.36), भारत के नीरज चोपड़ा (90.23) ऐसा कर चुके हैं।

खेल जगत के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची-

- जारीकर्ता- टाइम मैगजीन
- कवर पेज पर स्थान- लेब्रन जेम्स (एनबीए चैम्पियन) को
- टाइम मैगजीन ने पहली बार खेल जगत की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची जारी की है।

स्मृति मंधाना-

- यह भारतीय क्रिकेटर है। इन्होंने इस सूची में जगह बनाई है।
- वे इस सूची में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं।
- इनको टाइटन्स श्रेणी में स्थान दिया गया है।

रोहित राजपाल-

- इनको हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल-2026 का शेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। यह भारतीय ओलंपिक संघ की कार्यकारी समिति के सदस्य, भारतीय डेविस कप टीम के कप्तान तथा ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष है।

- शेफ डी मिशन के रूप में रोहित भारतीय दल के संचालन व समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

राष्ट्रमंडल खेल-

- आयोजन तिथि- 23 जुलाई से 2 अगस्त, 2026
- आयोजन स्थल- ग्लास्गो में
- इसमें राष्ट्रमंडल के 74 देशों और क्षेत्रों के लगभग 3,000 खिलाड़ी भाग लेंगे।

निहारिका सिंघानिया-

- यह मुंबई की 19 वर्षीय युवा घुड़सवार है। इन्होंने एशियन गेम्स-2026 के लिए भारतीय शो जंपिंग टीम में जगह बनाई है।
- वह भारतीय टीम की सबसे युवा घुड़सवार हैं।

विविध

- **शोर्ट-** भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यू चंडीगढ़ में खेले गए एकमात्र टेस्ट में अफगानिस्तान को एक पारी और 300 रन से हराया। यह भारत की टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी जीत है।
- **शोर्ट-** हाल ही में विंबलडन टूर्नामेंट की इनामी राशि में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है। इस स्पर्धा में पुरुष व महिला सिंगल्स विजेता को 36 लाख पाउंड (करीब 47 करोड़ रुपए) मिलेंगे।
- **शोर्ट-** हाल ही में जारी आईसीसी की सालाना वनडे रैंकिंग में भारतीय टीम लगातार 33 महीने से शीर्ष स्थान पर काबिज है।
- **शोर्ट-** क्रिकेट की आईपीएल की तर्ज पर 'योगासन सुपर लीग' लॉन्च किया जायेगा। इसे योगासन भारत फेडरेशन द्वारा लाँच किया जायेगा।
- **शोर्ट-** भारत की युवा मुक्केबाज प्राची ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप-2026 में विश्व चैंपियन चीनी ताइपे की वू शिह-यी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है।
- **शोर्ट-** भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना टी-20 क्रिकेट में 600 चौके लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई हैं।
- **शोर्ट-** वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में अर्धशतक लगाया। वे लिस्ट-ए (वनडे) क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले क्रिकेटर बने है।
- **शोर्ट-** हरमनप्रीत कौर 200 इंटरनेशनल टी-20 खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई। पुरुष क्रिकेट में भी यह मुकाम किसी ने नहीं छुआ है।
- **शोर्ट-** फ्रांस पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जयपुर के पैराशटलर कृष्णा नागर ने सिंगल्स में स्वर्ण पदक जीता। सिंगल्स में कृष्णा ने पेरिस पैरालंपिक के स्वर्ण विजेता चार्ल्स नोक्स को दो सैटों में 21-19, 21-11 से हराया।
- **शोर्ट-** भारतीय क्रिकेटर रवि बिश्नोई को इंडियन हेल्थकेयर लीग (आइएचएल) का आधिकारिक ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है।
- **शोर्ट-** एशियाई रिले चैंपियनशिप में भारत की 4 गुणा 100 मीटर महिला रिले टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। यह पदक श्राबणी नंदा, एसएस स्नेहा, सुदेश्ना शिवंकर और तमन्ना की चौकड़ी ने 43.85 सेकंड का सीजन का सर्वश्रेष्ठ समय निकालकर जीता है।
- **शोर्ट-** भारत के युवा निशानेबाज प्रीतम केंद्रे ने आइएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है।
- **शोर्ट-** अमरीका के पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी विंडहम क्लार्क ने यूएस ओपन खिताब जीता है।
- **शोर्ट-** राष्ट्रमंडल खेलों के नए मेजबानी मॉडल के तहत अहमदाबाद में होने वाले 2030 राष्ट्रमंडल खेलों में 17 खेल शामिल होंगे।
- **शोर्ट-** भारत की बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरणी पहली बार आइसीसी महिला टी-20 गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई है। इस रैंकिंग में श्री चरणी ने इंग्लैंड की लिंसी स्मिथ को पीछे छोड़ा है।
- **शोर्ट-** पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो **छह** अलग-अलग विश्व कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने।
- **शोर्ट-** केरल की लंबी कूद की एथलीट एंसी सोजन ने राष्ट्रीय अंतर-राज्यीय चैंपियनशिप में 6.88 मीटर की लम्बी कूद लगाकर अंजू बॉबी जॉर्ज का 22 साल पुराना रिकॉर्ड (6.83 मीटर) तोड़ दिया।

7. पुरस्कार एवं सम्मान

29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार (NAe-G) - 2026

- हाल ही में ई-गवर्नेंस पहलों के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता को मान्यता और प्रोत्साहन देने के लिए 7 श्रेणियों में कुल 17 परियोजनाओं/पहलोंका चयन किया गया है। यह पुरस्कार चयनित पहलों/परियोजनाओं को जयपुर (राजस्थान)में आयोजित होने वाले ई-गवर्नेंस पर 29वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रदान किये जायेंगे।
- **पुरस्कारों का वर्गीकरण-** 10 स्वर्ण, 6 रजत, 1 जूरी पुरस्कार।
- **पुरस्कार राशि-**
  - स्वर्ण पुरस्कार- 10 लाखरुपये, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र।
  - रजत पुरस्कार- 5 लाख रुपये, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र।
  - पुरस्कार विजेता और संबंधित संगठन-

क्र.सं.	परियोजना/पहल का नाम	संबंधित मंत्रालय/संगठन/राज्य
1.	एग्री स्टैक	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
2.	ई-जागृति	उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय
3.	महाकुंभ-2025	प्रयागराज मेला प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश
4.	ब्लड बैग ट्रेसिबिलिटी और नागरिक संपर्क पोर्टल	केरल विकास और नवाचार रणनीतिक परिषद
5.	ई-संजीवनी में AI-सक्षम नैदानिक निर्णय सहायता प्रणाली	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
6.	जिला न्यायालय केस प्रबंधन प्रणाली	केरल उच्च न्यायालय
7.	ICMR-MINDS (मानसिक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग अनुसंधान)	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद
8.	खतरे की जानकारी/DNS फ़िल्टरिंग सुरक्षा उत्पाद	अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र - इसरो, अहमदाबाद
9.	ई नगर पालिका में साइबर सुरक्षा	शहरी विकास एवं आवास विभाग, मध्य प्रदेश
10.	एकीकृत साइबर सुरक्षा ढांचा	बैंक ऑफ बड़ौदा
11.	ई-आरोग्य धामनी	स्वास्थ्य विभाग, जिला परिषद नंदुरबार, महाराष्ट्र
12.	पुणे 360	पुणे नगर निगम, महाराष्ट्र
13.	काडेपुर ग्राम पंचायत	सांगली जिला, महाराष्ट्र
14.	बिजय नगर ग्राम पंचायत	पश्चिम त्रिपुरा जिला, त्रिपुरा
15.	त्रिनेत्र (महाकाल मंदिर के लिए AI आधारित वीडियो निगरानी)	महाकालेश्वर मंदिर ट्रस्ट, उज्जैन
16.	पंचायत उन्नति सूचकांक	पंचायती राज मंत्रालय
17	CORSनेटवर्क के माध्यम से सटीक स्थिति निर्धारण (जूरी पुरस्कार)	सर्वे ऑफ इंडिया

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 की 7 श्रेणियां-

1. डिजिटल परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा सरकारी प्रक्रिया पुनर्गठन।

2. नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए एआई और अन्य नई युग की प्रौद्योगिकियों के उपयोग द्वारा नवाचार।
3. साइबर सुरक्षा में सर्वश्रेष्ठ ई-गवर्नेंस तौर-तरीके/नवाचार।
4. ई-गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल।
5. सेवा वितरण को गहरा/विस्तारित करने के लिए ग्राम पंचायतों या समकक्ष पारंपरिक स्थानीय निकायों द्वारा जमीनी स्तर की पहल।
6. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/जिलों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत और मिशन-मोड ई-गवर्नेंस परियोजनाओं का दोहराव और विस्तार।
7. केंद्रीय मंत्रालयों/राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा डिजिटल प्लेट-फार्मों में डेटा एनालिटिक्स के उपयोग द्वारा डिजिटल परिवर्तन।

यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार-

- हाल ही में भारतीय सेना में अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के लिए यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- वर्तमान में मेजर मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (यूएनआईएफआईएल) में एक एंगेजमेंट टीम कमांडर और जेंडर फोकल प्वाइंट के रूप में कार्यरत है।
- इस सम्मान के साथमेजर बराक यह सम्मान पाने वाले तीसरे भारतीय शांति रक्षक बन गयी हैं। इससे सुमन गवानी को 2019 में और राधिका सेन को 2023 में यह पुरस्कार मिला था।
- मेजर अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेली-कॉप्टर पायलट भी हैं।

यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार-

- स्थापना- वर्ष 2016
- संबंधित विभाग- सैन्य मामलों का कार्यालय (संयुक्त राष्ट्र का शांति अभियान विभाग)
- यह पुरस्कार ऐसे सैन्य शांतिरक्षकों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए असाधारण प्रतिबद्धता दिखाई है।

राष्ट्रपति ने प्रदान किए 'वीरता पुरस्कार'-

- हाल ही में भारत की राष्ट्रपतिश्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने 8 जून, 2026 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह-2026 (चरण-I) में वीरता पुरस्कार प्रदान किए।
- यह पुरस्कार उन कर्मियों को दिए गए जिन्होंने कर्तव्य पालन के दौरान अदम्य साहस, अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया है।
- रक्षा अलंकरण समारोह-2026 के चरण-I के दौरान कुल51 वीरता पुरस्कारप्रदान किए गए, जिनका विवरण निम्नानुसार है-
  - **कीर्ति चक्र-7 (2 मरणोपरांत)**
  - **वीर चक्र- 15 (3 मरणोपरांत)**
  - **शौर्य चक्र-29 (1 मरणोपरांत)**
- **कीर्ति चक्र-7 (2 मरणोपरांत)-**

क्र.सं.	नाम	सेवा
1	लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम	सेना
2	नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा	सेना
3	मेजर अर्शदीप सिंह	सेना
4	एयर कमोडोर प्रशांत बालकृष्णन नायर	वायु सेना
5	कैप्टन लालरीनावमा सैलो	सेना
6	सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर, महार रेजिमेंट (मरणोपरांत)	सेना
7	लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी, सेना सेवा कोर (मरणोपरांत)	सेना

- **वीर चक्र- 15 (3 मरणोपरांत)-**

क्र.सं.	नाम	सेवा
1	कर्नल कोशांक लांबा	सेना
2	ग्रुप कैप्टन रणजीत सिंह सिद्धू	वायु सेना
3	ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा	वायु सेना
4	ग्रुप कैप्टन अनिमेष पटनी	वायु सेना

5	ग्रुप कैप्टन कुणाल कालरा	वायु सेना
6	विंग कमांडर (अब ग्रुप कैप्टन) जॉय चंद्र	वायु सेना
7	लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट	सेना
8	स्क्वाड्रन लीडर सार्थक कुमार	वायु सेना
9	स्क्वाड्रन लीडर सिद्धांत सिंह	वायु सेना
10	स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक	वायु सेना
11	फ्लाइट लेफ्टिनेंट आरश्वीर सिंह ठाकुर	वायु सेना
12	नायब सूबेदार सतीश कुमार	सेना
13	सब इंस्पेक्टर (जीडी), मोहम्मद इम्ते-याज ***(मरणोपरांत)***	गृह मंत्रालय
14	राइफलमैन सुनील कुमार, 4 जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री ***(मरणोपरांत)***	सेना
15	सीटी/जीडी दीपक चिंगखम (***मरणो-परांत***	गृह मंत्रालय

- **शौर्य चक्र-29 (1 मरणोपरांत)-**

क्र.सं.	नाम	सेवा
1	निरीक्षक, श्री लक्ष्मण केवट	गृह मंत्रालय
2	लेफ्टिनेंट कर्नल नीतेश भारती शुक्ला	सेना
3	मेजर आदित्य प्रताप सिंह	सेना
4	मेजर आशीष कुमार	सेना
5	कांस्टेबल/जीडी संजय तिवारी	गृह मंत्रालय
6	सहायक कमांडेंट मोहम्मद शफीक	सेना
7	लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर	नौसेना
8	राम गोयल	नौसेना
9	कांस्टेबल/जीडी सद्दाम हुसैन	गृह मंत्रालय
10	सहायक कमांडेंट विपिन विल्सन	गृह मंत्रालय
11	राइफलमैन भोज राम साहू	सेना
12	विंग कमांडरअभिमन्यु सिंह	वायु सेना
13	मेजर भार्गव कलिता	सेना
14	मेजर लीशंगथेम दीपक सिंह	सेना
15	मेजर अंशुल बाल्टू	सेना
16	मेजर शिवकांत यादव	सेना
17	सूबेदार पीएच मोसेस	सेना
18	मेजर विवेक	सेना
19	राइफलमैन मंगलेम संग वेईफेई	सेना
20	लेफ्टिनेंट कर्नल घाटगे आदित्य श्रीकुमार	सेना
21	कप्तान योगेंद्र सिंह ठाकुर	सेना
22	सूबेदार शमशेर सिंह	सेना
23	लांस नायक (अब नायक) राहुल सिंह	सेना
24	राइफलमैन धुरबा ज्योति दत्ता	सेना
25	लेफ्टिनेंट कमांडर दिल्ना के	नौसेना
26	लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए	नौसेना
27	निरीक्षक, श्री रामेश्वर प्रसाद देशमुख	गृह मंत्रालय
28	कांस्टेबल/जीडी फेदा हुसैन दार	गृह मंत्रालय
29	बलदेव चंद ***(मरणोपरांत)***	सेना

भारत की राष्ट्रपति ने नागरिक अलंकरण समारोह-II में पद्म पुरस्कार-2026 प्रदान किए-

- हाल ही में भारत की राष्ट्रपति ने 23 जून, 2026 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह-II में वर्ष 2026 के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए।
- पुरस्कार प्राप्तकर्ता-
- पद्म विभूषण- समारोह-II में दो लोगों को सम्मान प्रदान किया गया है-

क्र. सं.	नाम	क्षेत्र	राज्य
1	श्री के. टी. थॉमस	सार्वजनिक मामले	केरल
2	श्री पी. नारायणन	साहित्य एवं शिक्षा	केरल

पद्म भूषण- समारोह- II में सात लोगों को सम्मान प्रदान किया गया है

क्र. सं.	नाम	क्षेत्र	राज्य / देश
1	श्री विजय अमृतराज	खेल	संयुक्त राज्य अमेरिका
2	श्री एस. के. एम. मैइलानंदन	सामाजिक कार्य	तमिलनाडु
3	श्री ममूटी	कला	केरल
4	श्री वेल्लापल्ली नटेसन	सार्वजनिक मामले	केरल
5	डॉ. नोरी दत्तात्रेयुडु	चिकित्सा	संयुक्त राज्य अमेरिका
6	श्री शिबू सोरेन (मरणोपरांत)	सार्वजनिक मामले	झारखंड
7	सुश्री अलका याग्निक	कला	महाराष्ट्र

- पद्मश्री पुरस्कार- समारोह-II में सतावन लोगों को सम्मान प्रदान किया गया है।

पद्म पुरस्कार 2026

- राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं।

पद्म पुरस्कार

- पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं।
- ये 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं:
    1. पद्म विभूषण
    2. पद्म भूषण
    3. पद्म श्री
- ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, व्यापार व उद्योग, चिकित्सा, साहित्य व शिक्षा, खेल और सिविल सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं।
- पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए तथा पद्म श्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है।
- पद्म पुरस्कारों की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी।
- इनके लिए नामांकन गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं।
- पद्म पुरस्कारों के साथ कोई नकद राशि या पेंशन नहीं दी जाती।
- पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है।
- ये सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोहों में प्रदान किए जाते हैं।

वुल्फ प्राइज-

- हाल ही में अमरीकी-भारतीय मूल के सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी प्रो. जैनेंद्र के. जैन को मिश्रित फर्मियन की खोज के लिए वुल्फ प्राइज से सम्मानित किया गया है।
- प्रोफेसर प्रो. जैनेंद्र के. जैन वुल्फ प्राइज पाने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति है।
- यह पुरस्कार 'वुल्फ फाउंडेशन' की ओर से दिया जाता है जो नोबेल पुरस्कार के बाद दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है।
- **राजस्थान से संबंध-** इनकी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय की शिक्षा राजस्थान से हुई। इन्होंने महाराजा कॉलेज, जयपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी।

इंडियन एथलेटिक्स अवॉर्ड्स 2025-

- अवॉर्ड्स वितरण तिथि- 20 जून, 2026
- अवॉर्ड्स वितरण स्थल- नई दिल्ली
- **इंडियन एथलेटिक्स अवॉर्ड्स 2025 विजेताओं की सूची**
    - वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट-नीरज चोपड़ा
    - वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट-पारुल चौधरी
    - वर्ष के उभरते हुए पुरुष एथलीट-शहनवाज खान
    - वर्ष की उभरती हुई महिला एथलीट-पूजा
    - वर्ष के सर्वश्रेष्ठ कोच-परवीर सिंह

- **लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड-पीटी उषा, गुरबचन सिंह रंधावा, बहादुर सिंह चौहान, अंजू बॉबी जॉर्ज**
- **वर्ष का सर्वश्रेष्ठ राज्य फेडरेशन- तमिलनाडु एथलेटिक्स एसोसिएशन**
- **एथलेटिक्स को सर्वश्रेष्ठ समर्थन देने वाला राज्य-ओडिशा राज्य सरकार**
- **वर्ष के सर्वश्रेष्ठ तकनीकी अधिकारी-डॉ. कुलदीप सिंह**

केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता-2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह-

- हाल ही में केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता-2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह 25 जून, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।
- संसदीय कार्य मंत्रालय पिछले 38 वर्षों से केंद्रीय विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है।
- युवा संसद योजना का उद्देश्य युवा पीढ़ी में आत्म-अनुशासन, विभिन्न मतों के प्रति सहिष्णुता, विचारों की निष्पक्ष अभिव्यक्ति और लोकतांत्रिक जीवन शैली के अन्य गुणों को विकसित करना है।
- राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए "सरदार वल्लभभाई पटेल रनिंग पार्लियामेंट्री शील्ड और ट्रॉफी" डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय, प्रेसिडेंट एस्टेट, नई दिल्ली (दिल्ली क्षेत्र, उत्तर जोन) को प्रदान की गयी
- क्षेत्रीय विजेता-

क्रम सं.	केंद्रीय विद्यालय का नाम	क्षेत्र
1.	केन्द्रीय विद्यालय, मथुरा कैंट, मथुरा, उत्तर प्रदेश (एफक्यूए क्षेत्र)	पश्चिम
2.	पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय नंबर 1, मदुरै, तमिलनाडु (चेन्नई क्षेत्र)	दक्षिण
3.	पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय नंबर 2, शिवाजी नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश (भोपाल क्षेत्र)	मध्य
4.	पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय, वायु सेना स्टेशन, बोरझार गुवाहाटी, असम (गुवाहाटी क्षेत्र)	पूर्व

- क्षेत्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 20 केंद्रीय विद्यालयों को भी विजेता ट्राफियां प्रदान की गयी।
- Note- पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय नंबर 1, वायु सेना स्टेशन, सूरतगढ़, राजस्थान (क्षेत्र-जयपुर) को भी विजेता ट्राफियां प्रदान की गयी।

ज्योति महाजन

- यह ब्राइट बिगिनिंग्स न्यू डॉन वेलफेयर फाउंडेशन की संस्थापक है।
- इनकों शिक्षा व सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 'हीरोज ऑफ इंडिया अवॉर्ड्स 2026' में 'वूमन अचीवर ऑफ द ईयर' सम्मान से नवाजा गया।
- ज्योति महाजन वंचित बच्चों के उत्थान व कौशल विकास के लिए संस्था के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम चलाती हैं।

सॉयल फार्मर हीरो सम्मान-

- हाल ही में तमिलनाडु के 58 वर्षीय किसान वल्लुवन को यूएन के खाद्य एवं कृषि संगठन ने 'सॉयल फार्मर हीरो' सम्मान से नवाजा है।
- वल्लुवन ने नारियल के खेत को बहुफसली खेती में तब्दील करके पानी की बचत और मिटटी की गुणवता में सुधार किया है।

प्रतिभा एम. सिंह-

- इनको इंटरनेशनल आइपी हॉल ऑफ फेम-2026 में शामिल किया गया है। यह इसमें शामिल होने वाली पहली भारतीय न्यायाधीक्ष बन गई हैं। वर्तमान में यह दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीक्ष हैं।

मेजरप्रभात मिश्रा-

- यह भारतीय सेना की 22 कुमाऊं रेजीमेंट में मेजर हैं। इन्होंने अमेरिकी सेना कमांड और जनरल स्टाफ कॉलेज में दो शीर्ष शैक्षणिक अवॉर्ड जीते हैं।
- इनको उत्कृष्ट मास्टर ऑफ मिलिट्री आर्ट्स एंड साइंस थीसिस के लिए बिरर-ब्रूक्स अवॉर्ड और जनरल डगलस मैकआर्थर मिलिट्री लीडरशिप राइटिंग अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है।
- यह वर्ष 1948 के बाद से पहले भारतीय अधिकारी हैं, जिन्होंने बिरर-ब्रूक्स अवॉर्ड जीता है।

भैरूसिंह चौहान

- यह मालवा के निर्गुण भजनों को देशभर में पहचान दिलाने वाले व्यक्ति है। संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष 2024-25 के पुरस्कारों की निर्गुणी श्रेणी में इनका चयन किया है। उन्हें 2025 में पद्मश्री से भी नवाजा गया था।

- **शोर्ट-** जस्टिस मीनाक्षी मदन राय पटना हाईकोर्ट की नई मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं। इससे पहले वे सिक्किम हाईकोर्ट में न्यायाधीश थी और सिक्किम से हाईकोर्ट जज बनने वाली पहली महिला हैं।
- **शोर्ट-** हाल ही में 3 जून 2026 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 वितरित किये गये। वर्ष 2025 के लिए देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए गये है। (पुरस्कार श्रेणी के लिए जून माह का अंक देखे)

निर्वाचन और नियुक्ति

राष्ट्रीय

विवेक अग्रवाल को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उपाध्यक्ष चुना गया-

- हाल ही में भारत के वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के 2026-27 कार्यकाल के लिए अगला उपाध्यक्ष चुना गया है। उनके उपाध्यक्ष चुने जाने का निर्णय 17-19 जून, 2026 को आयोजित एफएटीएफ की पूर्ण बैठक के दौरान लिया गया।
- इनका कार्यकाल जुलाई, 2026 से जून, 2027 तक होगा।
- एफएटीएफ की इस पूर्ण बैठक में गाइल्स थॉमसन को एफएटीएफ का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
- विवेक अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। विवेक अग्रवाल इससे पहले भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)-

- स्थापना- 1989
- मुख्यालय- पेरिस में
- यह एक अंतर-सरकारी संस्था है।
- यह मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और प्रसार के लिए फ़ंडिंग को रोकने के लिए वैश्विक मानक तय करती है।
- एफएटीएफ की प्रेसिडेंसी का कार्यकाल दो साल का होता है और वाइस प्रेसिडेंट, संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने में प्रेसिडेंट की मदद करते हैं।

श्री डी.के. शिवकुमार-

- हाल ही में कर्नाटक के वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी.के. शिवकुमार ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है।
- उन्हें कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
- डॉ. जी. परमेश्वर ने भी कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली है।

नीलकंठ मिश्रा-

- यह भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य है। इनको वाशिंगटन स्थित विश्व बैंक मुख्यालय में भारत का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है।
- इनका कार्यकाल तीन साल का होगा। वे परमेश्वरन अय्यर की जगह लेंगे।

धीरज सेठ-

- हाल ही में भारत सरकार ने वर्तमान सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को 30 जून, 2026 से अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया है।
- धीरज सेठ मौजूदा सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे हैं।
- यह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला के पूर्व छात्र हैं और इन्होंने दिसंबर, 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन प्राप्त किया था।

डॉ. पी.एल. गौतम-

- यह भारत प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक है। इनको हाल ही में कृषि जैव विविधता विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
- डॉ. पी.एल. गौतम को हाल ही में कृषि विज्ञान में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था।
- कृषि जैव विविधता विशेषज्ञ समिति- यह समिति राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) की एक महत्वपूर्ण सलाहकार संस्था के रूप में कार्य करती है।

आशुतोष दीक्षित-

- यह भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी और एयर मार्शल है। इन्हें भारत सरकार ने अगला वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ नियुक्त किया है। यह 1 जुलाई, 2026 को कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- वर्तमान में आशुतोष दीक्षित एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय में एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख (सीआइएससी) के पद पर कार्यरत हैं।

डॉ. सैबल चट्टोपाध्याय

- यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कोलकाता के पूर्व निदेशक हैं। इनको हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इनके साथ ही इस आयोग में निम्न व्यक्तियों को सदस्य नियुक्त किया गया है-

1. प्रो. शुभब्रता दास
2. श्री सत्येन्द्र बहादुर सिंह
3. डॉ. माधवन मुकुंद

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग-

- स्थापना- वर्ष 2005 में, यह आयोग देश की सभी प्रमुख सांख्यिकी गतिविधियों के लिए एक नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है।

पंकज शर्मा

- हाल ही में अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने इन्हें उत्तर पश्चिम रेलवे का जीएम नियुक्त किया है। यह इंडियन रेलवे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्विस के 1989 बैच के अधिकारी है।

एयर मार्शल तरुण चौधरी-

- इनकों वायु सेना की सेंट्रल एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के पद पर नियुक्त किया गया है। इन्होंने एयर मार्शल बालकृष्णन मणिकंतन की जगह ली हैं।

राजीव घई एनएससीएस के नए सैन्य सलाहकार नियुक्त-

- लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) का नया मिलिट्री एडवाइजर नियुक्त किया गया है।
- वे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डीजीएमओ रहे।
- राजीव घई एनएससीएस के पद पर नियुक्त होने वाले पहले कार्यरत अधिकारी होंगे।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस)-**
  - स्थापना- वर्ष 1998
  - मुख्यालय- नई दिल्ली
  - यह राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों के मामलों पर प्रधानमंत्री कार्यालय को सलाह देने वाला सर्वोच्च निकाय है।

रुद्र गौरव श्रेष्ठ-

- यह 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी है।
- इनको विदेश मंत्रालय ने तुर्किये में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। वह वर्तमान में ईरान में भारत के राजदूत हैं।

डॉ. अलका राव-

- इनको चंडीगढ़ स्थित सीएसआईआर-इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी की निदेशक नियुक्त किया गया है।
- वर्ष 1984 में इस संस्थान की स्थापना के बाद यह पद संभालने वाली वे पहली महिला वैज्ञानिक हैं। इससे पहले वे भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण में सलाहकार रह चुकी हैं।

विपुल-

- यह 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी है।
- इनको विदेश मंत्रालय ने सऊदी अरब में अगला भारतीय राजदूत नियुक्त किया है। वे सऊदी अरब में इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले गैर-मुस्लिम भारतीय राजनयिक होंगे।
- वर्तमान में कतर में भारत के राजदूत विपुल, सुहेल एजाज खान का स्थान लेंगे।

अलख एन. शर्मा-

- इनको लेबर स्टेटिस्टिक्स पर गठित तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है।
- यह समिति देश के श्रम बाजार में हो रहे बदलावों का आकलन करेगी तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सटीक आंकड़े तैयार करने पर काम करेगी।
- प्रोफेसर अलख एन. शर्मा वर्तमान में इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के निदेशक हैं।

हर्ष पति सिंघानिया-

- यह भारतीय बिजनेस लीडर है। इनको इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी), पेरिस का नया चेयरमैन चुना गया है।

तुषार मेहता

- केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को तीन साल के एक और कार्यकाल के लिए पुन: नियुक्ति को मंजूरी दी है।
- इसके अलावा विक्रमजीत बनर्जी, के.एम. नटराज, एस.वी. राजू, एश्वर्या भाटी, एन. वेंटरमणन को भी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुनः नियुक्ति दी गयी है।

विश्वास विदु सपकाल-

- इनको स्लोवाकिया में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यह भारतीय विदेश सेवा के 1998 बैच के अधिकारी है।
- इससे पहले वे फिजी में भारत के उच्चायुक्त रह चुके हैं।

महेश दीक्षित-

- भारत सरकार ने महेश दीक्षित को इंटेलिजेंसब्यूरो का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने तपन डेका का स्थान लिया है जिनका कार्यकाल 30 जून, 2026 को समाप्त हो गया।
- यह 1993 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी है।

अंतराष्ट्रीय

मेटे फ्रेडरिक्सन-

- इन्होंने हाल ही में डेनमार्क की प्रधानमंत्री के रूप में अपना लगातार तीसरा कार्यकाल संभाला है। इन्होंने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, लिबरल पार्टी और मॉडरेट्स के साथ गठबंधन सरकार बनाई है।
- वह इस पद पर आसीन होने वाली दूसरी महिला और डेनमार्क के इतिहास में सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री हैं।

अबेलार्डो डे ला एस्प्रीएला-

- इन्होंने कोलंबियाई राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। यह कोलंबिया में "द टाइगर" उपनाम से भी जाने जाते है।
- यह कोलंबिया के इतिहास में सबसे अधिक वोट (2.9 मिलियन वोट) पाने वाले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन गए हैं।

बिल पुल्टे-

- इनकों हाल ही में अमेरिकी सरकार ने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक (कार्यवाहक) नियुक्त किया है। यह भारतीय मूल की तुलसी गबार्ड का स्थान लेंगे। बिल पुल्टे वर्तमान में आवास वित्त एजेंसी के प्रमुख है।

हान सियोंग-सुक-

- इन्होंने दक्षिण कोरिया की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है।
- वह बीते दो दशकों में दक्षिण कोरिया की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी।

एड्रियन वेस्टिया-

- यह रोमानियाई राजनीतिज्ञ है। इनको रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन ने देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है।

बिमल एन. पटेल-

- यह भारत के विधिवेत्ता, अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। इनको अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून ट्रिब्यूनल (आईटीएलओएस) का जज चुना गया है। आईटीएलओएस समुद्री कानूनों से जुड़े विवादों का समाधान करता है।

विविध

- शोर्ट- हाल ही में वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थी ने 1 जून, 2026 को श्री विजयपुरम में अंडमान और निकोबार कमान के 20वें कमांडर-इन-चीफ के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।
- शोर्ट- हाल ही में मेजर जनरल राहेल थॉमस ने 1 जून, 2026 को सैन्य नर्सिंग सेवा के अपर महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। इन्होंने मेजर जनरल लिसाम्मा पीवी का स्थान लिया है।
- शोर्ट- भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ कैडर के 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी सुंदरराज पी. को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिरीक्षक नियुक्त किया।
- शोर्ट- कुणाल शाह- भारतीय फिनटेक कंपनी क्रेड के फाउंडर है जिनको वॉट्सऐप के ग्लोबल सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है।
- शोर्ट- प्रभजीत सिंह- इनकों ओपनएआई (इंडिया) के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है।

निधन

डॉ. सुभाष कश्यप-

- यह भारत के सुप्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ, प्रख्यात लेखक और लोकसभा के पूर्व महासचिवथे जिनका 4 जून, 2026 को निधन हो गया।
- **संवैधानिक एवं प्रशासनिक भूमिका-**
  - संसदीय सेवा- 1953 से 1990 तक भारतीय संसद की सेवा की औरलोकसभा के महासचिव।
  - संविधान समीक्षा आयोग- 'संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग' कीप्रारूपण एवं संपादन समिति के अध्यक्ष।
  - वर्ष 1990 से 2023 तक CPR में मानद अनुसंधान प्रोफेसर रहे और उन्होंने 'अकादमी ऑफ ग्रासरूट स्टडीज एंड रिसर्च ऑफ इंडिया' संस्थान की स्थापना में भूमिका निभाई।
- सम्मान- पद्म भूषण- वर्ष 2015 में उन्हें पद्म भूषणसे सम्मानित किया गया।
- लेखन-
  - Our Constitution (हमारा संविधान)
  - Our Parliament (हमारी संसद)

सलीम कुमार-

- यह राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और दिग्गज मलयालम अभिनेता थे।
- इनका हाल ही में कोच्चि में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। उन्होंने तीन दशक के करियर में करीब 350 फिल्मों में काम किया। उन्हें फिल्म 'अदामिन्ते मकान अबू' में अभिनय के लिए वर्ष 2010 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था।

भारती राजा-

- यह तमिल सिनेमा के फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। इनका हाल ही में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें प्यार से 'इयक्कुनर इमयम' कहा जाता था। इनको तमिल सिनेमा में यथार्थवादी ग्रामीण कहानियों को बड़े पर्दे पर लाने का श्रेय जाता है।

कृष्णास्वामी भाग्यराज

- यह तमिल फिल्म उद्योग के अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे, जिनका 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- उन्हें 'किंग ऑफ स्क्रीनप्ले' कहा जाता था। उन्होंने 75 से अधिक फिल्मों में अभिनय और 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया।

जसपाल राणा-

- यह भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता थे। हाल ही में इनका नई दिल्ली में 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- यह भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। इन्होनें ही मनु भाकर को निशानेबाजी में प्रशिक्षित किया था।
- उन्हें फरवरी 2025 में 25 मीटर पिस्टल के लिए भारतीय जूनियर टीम का हाई परफार्मेंस कोच बनाया गया था।
- **मेडल विजय- 23 मेडल**
  - ➢ **एशियन गेम्स में- 8 मेडल**
    - गोल्ड - 4 मेडल
    - सिल्वर - 2 मेडल
    - ब्रॉन्ज - 2 मेडल
  - ➢ **कॉमनवेल्थ गेम्स में - 15 मेडल**
    - गोल्ड - 9 मेडल
    - सिल्वर - 4 मेडल
    - ब्रॉन्ज - 2 मेडल
  - ➢ **सम्मान-**
    - वर्ष 1994 में अर्जुन पुरस्कार
    - वर्ष 1997 में पद्म श्री पुरस्कार
    - वर्ष 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार

पहलाज निहलानी

- यह दिग्गज फिल्म प्रोड्यूसर और सेंसर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष थे।
- इनका 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्होंने वर्ष 1982 में फिल्म 'हथकड़ी' निर्माता के रूप में करियर शुरू किया था।
- अन्य फिल्म- इल्जाम, गुनाहों का फैसला, शोला और शबनम, आंखें तथा तलाश।
- जनवरी, 2015 से अगस्त, 2017 तक वे सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष रहे।

दिनयार तीरंदाज-

- यह दिग्गज एक्टर थे जिनका 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया है।
- उन्होंने नुक्कड़, ब्योमकेश बख्शी और जुबान संभाल के जैसे सीरियलों में काम किया।

रॉबर्ट ए.एफ. थर्मन-

- यह बौद्ध धर्म के एक प्रख्यात विद्वान, प्रतिष्ठित शिक्षक और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति थे। इनका हाल ही में 84 वर्ष की आयु में वुडस्टॉक, न्यूयॉर्क में निधन हो गया।
- **इनेक द्वारा रचित कृतियाँ-**
  1. व्हाई द दलाई लामा मैटर्स
  2. विजडम इज ब्लिस

विलियम आर. बर्कले-

- यह अमरीकी उद्यमी और वैश्विक बीमा कंपनी डब्ल्यू.आर.बर्कले के संस्थापक एवं कार्यकारी अध्यक्ष थे।
- इनका 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

- दक्षिण अफ्रीका के पियानोवादक अब्दुल्ला इब्राहिम का 91 वर्ष की आयु में जर्मनी में निधन हो गया। उनकी चर्चित रचना 'मैननबर्ग' 1974 में रिकॉर्ड हुई थी। इस रचना ने नेल्सन मंडेला को भी प्रेरित किया था।
- बज्र कीति आभा नरेंद्र देब्यावती- यह थाईलैंड की राजकुमारी थी जिनका 47 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।

■■■■

सम्मेलन/बैठक /मेला/महोत्सव/प्रदर्शनी

ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह (सीडब्ल्यूजी) की बैठक-

- बैठक- द्वितीय
- आयोजन तिथि- 4-5 जून, 2026 को
- आयोजन स्थल- वाराणसी, उत्तर प्रदेश में
- यह बैठक भारत के ब्रिक्स 2026 के विषय "लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण" के अनुरूप सांस्कृतिक सहयोग पर व्यवस्थित बहुपक्षीय संवाद को बढ़ावा देगी।

भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की संवाद बैठक

- बैठक संस्करण- द्वितीय
- आयोजन तिथि- 1 जून, 2026
- आयोजन स्थल- मानेकशॉ सेंटर, नई दिल्ली
- अध्यक्षता- भारत के रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री श्री रिचर्ड मार्ल्स ने सह-अध्यक्षता की।
- **उद्देश्य-**
  - o दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना।
  - o रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा को नवीनीकृत और सुदृढ़ करना।
- **Note-** भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की संवाद बैठक का प्रथम संस्करण 9 अक्टूबर, 2025 को हुआ था।

ब्रिक्स में उन्नत पशुपालन प्रौद्योगिकी एवं चारा प्रणाली (एएलटी एंड एफएस) पर संवाद-

- आयोजन तिथि- 1 जून, 2026
- आयोजन स्थल- नई दिल्ली
- उद्देश्य- ब्रिक्स सदस्य देशों में लचीले पशुधन क्षेत्रों को मजबूत करना।

13वां ब्रिक्स शहरीकरण मंच-

- आयोजन तिथि- 11-12 जून, 2026
- आयोजन स्थल- नई दिल्ली में
- विषय- 'जनता के लिए शहर: समावेशी और सुदृढ़ शहरी भविष्य के लिए ब्रिक्स सहयोग'
- **उद्देश्य- सदस्य देशों के बीच समावेशी, टिकाऊ, लचीले और जन-केंद्रित शहरों के निर्माण को बढ़ावा देना।**
- यह मंच 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत एक महत्वपूर्ण मंत्रिस्तरीय कार्यक्रम है।

एमएसएमई सहयोग पर भारत-दक्षिण अफ्रीका बैठक-

- आयोजन तिथि- 1 जून, 2026 को
- आयोजन स्थल- नई दिल्ली
- अध्यक्षता- श्री जीतन राम मांझी, एमएसएमई मंत्री
- उद्देश्य- एमएसएमई क्षेत्र में सहयोग एवं साझेदारी को सुदृढ़ करने के अवसरों का पता लगाना।

निर्वाचन प्रक्रियाओं और अभियानों में मीडिया के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रणालियों और नवाचारों पर सम्मेलन-

- आयोजन तिथि- 3-4 जून, 2026
- आयोजन स्थल- इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईआईडीईएम), नई दिल्ली में
- आयोजक- भारत निर्वाचन आयोग
- उद्देश्य- निर्वाचन प्रबंधन के विभिन्न आयामों में अंतरराष्ट्रीय अनुभवों, आदर्श मानकों और सर्वोत्तम प्रणालियों को प्रलेखित करने वाले **अभ्यासकर्ता-उन्मुख वैश्विक ज्ञान संसाधनों** को विकसित करना।

निवेशक शिविर-

- आयोजन तिथि- 5 जून, 2026
- आयोजन स्थल- भोपाल में
- आयोजक- निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)
- उद्देश्य- निवेशकों को सशक्त बनाना और उनकी शिकायतों के निवारण तथा बिना दावे वाले लाभांश प्रक्रिया को सरल बनाना।

उत्तर पूर्वी परिषद के 73वां पूर्ण सत्र आयोजन-

- हाल ही में उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) का 73वां पूर्ण सत्र 4 जून, 2026 को मेघालय के शिलांग आयोजित हुआ।
- इस सत्र की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। इस सत्र में उत्तर पूर्वी क्षेत्र को आर्थिक विकास, कनेक्टिविटी, नवाचार, स्थिरता और सांस्कृतिक समृद्धि के समग्र उन्नयन पर विचार किया गया।
- **उत्तर पूर्वी परिषद-** यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नोडल एजेंसी है।
- इस परिषद का गठन 1971 में संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था।
- इसमें आठ राज्य (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा) शामिल हैं।

समुद्री खाद्य निर्यात विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला-

- आयोजन तिथि- 5-6 जून, 2026
- आयोजन स्थल- विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में
- आयोजक- मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य विभाग द्वारा
- सहयोगी संस्थान- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार के समर्थन से
- उद्देश्य- भारत के समुद्री खाद्य निर्यात इकोसिस्टम को राज्यों और हितधारकों के बीच सुदृढ़ करना।

ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026

- आयोजन तिथि- 4 जून, 2026
- आयोजन स्थल- भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) में
- विषय- वैश्विक उथल-पुथल के बीच व्यापार प्रबंधन
- उद्देश्य- वैश्विक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक उथल-पुथल के दौर में व्यापार प्रबंधन की चुनौतियों पर विचार-विमर्श करना।

भारत-इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक-

- संस्करण- 8वीं
- आयोजन तिथि- 7 जून, 2026
- आयोजन स्थल- नई दिल्ली में
- अध्यक्षता- डॉ. एस. जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगिओनो (सह-अध्यक्षता)
- इस बैठक में राजनीति, रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, क्रिटिकल मिं-नरल्स, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा में सहयोग बढ़ाने पर सहमती बनी।

सिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2026

- आयोजन तिथि- 3-4 जून, 2026
- आयोजन स्थल- जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, मुंबई में
- उद्देश्य- भारत के आर्थिक विकास के लिए वैश्विक निवेशकों, कॉर्पोरेट लीडर्स, नीति निर्माताओं और उद्यमियों को एक मंच पर लाना।

युवा विकसित भारत- एमवाई भारत युवा सम्मेलन

- आयोजन तिथि- **6 जून, 2026**
- आयोजन स्थल- **त्यागराज स्टेडियम, नई दिल्ली**
- आयोजक- **केन्द्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय**
- इस सम्मेलन में देश भर से **6,000** से अधिक युवाओं ने भाग लिया।

राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) भारत क्षेत्र जोन-II उत्तर जोन सम्मेलन-

- आयोजन तिथि- 8- 9 जून, 2026
- आयोजन स्थल- हरियाणा विधान सभा, चंडीगढ़
- संस्करण- द्वितीय
- विषय- विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में जागरूक समाज और विधि-निर्माताओं की भूमिका'
- उद्देश्य-संसदीय सहयोग को मजबूत करना, श्रेष्ठ विधायी और संसदीय पद्धतियों के आदान-प्रदान को सुगम बनाना और क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देना।

समुद्री खाद्य निर्यात पर राष्ट्रीय कार्यशाला

- आयोजन तिथि- 5-6 जून, 2026
- आयोजन स्थल- विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश
- आयोजक- मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग द्वारा
- सहयोगी संस्थान/विभाग- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार
- उद्देश्य- वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी समुद्री खाद्य निर्यातक राष्ट्र के रूप में स्थापित करना।

अन्लॉकिंग वैल्यू- उन्नत पोषण और विकास के लिए दक्षिण एशियाई नीति नेतृत्व संवाद-2026-

- आयोजन तिथि- 9-10 जून, 2026
- आयोजन स्थल- अहमदाबाद
- आयोजक- केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
- उद्देश्य- दक्षिण एशिया में रोजगार सृजन और सतत विकास के लिए खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना।

'लघु पनबिजली विकास योजना' पर राष्ट्रीय कार्यशाला-

- आयोजन तिथि- 9 जून, 2026
- आयोजक- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
- उद्देश्य- समूचे भारत में लघु पनबिजली विकास को गति देना।

ब्रिक्स विज्ञान अकादमी फोरम 2026 की बैठक-

- संस्करण-प्रथम
- आयोजन तिथि- 9 जून, 2026
- आयोजक- भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आईएनएसए), नई दिल्ली
- विषय- "सतत विकास के लिए एआई का उपयोग और वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना"
- उद्देश्य- सतत विकास के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग और वैश्विक दक्षिणसहयोग को मजबूत करना।
- इस फोरम में 10 देशों (ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशि-या, रूस, दक्षिण अफ्रीका, बेलारूस, नाइजीरिया और वियतनाम) की विज्ञान अकादमियों ने जिम्मेदार और न्यायसंगत एआई विकास पर एक साझा घोषणा को आगे बढ़ाने के लिए भाग लिया।
- ब्रिक्स विज्ञान अकादमियों के मंच की दूसरी ऑनसाइट बैठक 22-23 जुलाई, 2026 को आईआईटी हैदराबाद में आयोजित की जाएगी।

भारत-ताजिकिस्तान संयुक्त आयोग की बैठक-

- बैठक- 12वीं
- आयोजन तिथि- 10 जून, 2026
- आयोजन- वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से
- उद्देश्य- दोनों देशो के मध्य व्यापार, निवेश, दवा, कृषि, सेवा क्षेत्र, ऊर्जा, परिवहन-संपर्क और क्षमता निर्माण में सहयोग को मजबूत करना।

ब्रिक्स शहरीकरण फोरम-

- संस्करण- 13वां संस्करण
- आयोजन तिथि- 11-12 जून, 2026
- आयोजन स्थल- सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली
- आयोजक- केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
- विषय- जन-केंद्रित शहर: समावेशी एवं लचीले शहरी भविष्य के लिए ब्रिक्स सहयोग
- **उद्देश्य-** शहरी विकास के एजेंडे को वैश्विक विकास विमर्श में और अधिक सशक्त रूप से स्थान देने का अवसर प्रदान करना।
- इस फोरम में ब्राज़ील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान तथा संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञों ने भाग लिया।
- भारत चौथी बार ब्रिक्स शहरीकरण फोरम की मेजबानी कर रहा है।

इससे पहले-

1. वर्ष 2013 - नई दिल्ली में
2. वर्ष 2016 - विशाखापत्तनम में
3. वर्ष 2021 - वर्चुअल माध्यम से

सारथी (रणनीतिक सलाहकार एवं सुधार कार्य बल) बैठक-

- बैठक- प्रथम बैठक
- आयोजन तिथि- 12 जून, 2026
- आयोजन स्थल- विज्ञान भवन, नई दिल्ली में
- आयोजक- कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
- उद्देश्य- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करना और यह सुनिश्चित करना कि व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणालियां उद्योग की बदलती आवश्यकताओं और भविष्य की कार्यबल की जरूरतों के अनुरूप बनी रहें।
- इस बैठक की अध्यक्षता भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और जयंत चौधरी ने की।

नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक-

- बैठक- 11वीं बैठक
- आयोजन तिथि- 11 जून, 2026
- आयोजन स्थल- नई दिल्ली
- आयोजक- नीति आयोग
- बैठक का विषय- विकसित भारत@2047 के लिए समावेशी मानव विकास
- इस बैठक में 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों ने भाग लिया।

नीति आयोग

- गठन- 1 जनवरी, 2015
- यह भारत सरकार का सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है।
- उद्देश्य- सहकारी संघवाद के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देना।

नीति आयोग की शासी परिषद-

- गठन-16 फरवरी, 2015
- पुनर्गठन- फरवरी, 2021
- **सदस्यगत संरचना-**
  - अध्यक्ष- भारत का प्रधानमंत्री
  - सभी राज्यों के मुख्यमंत्री
  - विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री
  - अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल
  - पदेन सदस्य
  - नीति आयोग का उपाध्यक्ष
  - नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल
- कार्य- राष्ट्रीय विकास की रूपरेखा तैयार करने में राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और कार्यनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना।
- शासी परिषद सहकारी संघवाद के उद्देश्यों का प्रतीक है।

रक्षा खरीद और नवाचार इकोसिस्टम सेमिनार

- आयोजन तिथि- 11 और 12 जून, 2026
- आयोजन स्थल- नई दिल्ली में
- आयोजक- मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ और संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से
- विषय- एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए रक्षा खरीद, आईडेक्स, टीपीसीआर और परीक्षण प्रक्रियाओं को समझना
- उद्देश्य- रक्षा अधिग्रहण और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में उद्योग की भागीदारी को मजबूत करना।

राइज़ कॉन्क्लेव-2026

- आयोजन तिथि- 13-14 जून, 2026
- आयोजन स्थल- बेंगलुरु
- आयोजक- वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)
- विषय- विकसित भारत 2047 के लिए इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से प्रेरित विकास
- उद्देश्य- अनुसंधान संस्थानों, उद्योग जगत, स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों को एक साझा मंच पर लाना।
- RISE- Research, Industry, Start-up, Entrepreneurship

ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों की बैठक-

- बैठक क्रम- 16वीं
- आयोजन तिथि- 12-13 जून, 2026
- आयोजन स्थल- इन्दौर, मध्यप्रदेश
- इस बैठक में 4 प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श किया गया-
  - प्राथमिकता 1- खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका।
  - प्राथमिकता 2- कृषि व्यापार और सहयोग।
  - प्राथमिकता 3- नवीकरणीय खेती, जलवायु के अनुकूल और संवहनीय कृषि।
  - प्राथमिकता 4- नवोन्मेष के उद्देश्य से सहयोग का सुदृढ़ीकरण तथा कृषि और खाद्य प्रणाली को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए निवेश।

विकसित भारत युवा संसद-2026

- आयोजन तिथि- 15 से 17 जून, 2026
- आयोजन स्थल- नई दिल्ली में
- आयोजक- केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
- इस युवा संसद का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने 16 जून, 2026 को किया। इस आयोजन से युवा नागरिकों को शासन, नीतिगत विचार-विमर्श और संसदीय कार्यप्रणाली की व्यावहारिक समझ प्राप्त हुई।

नशा मुक्त भारत सप्ताह

- आयोजन तिथि-17 जून से 26 जून, 2026
- आयोजक- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
- उद्देश्य- मादक द्रव्यों के सेवन को रोकने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना।

अध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तीकरणमहासम्मेलन-

- आयोजन तिथि-18 जून, 2026
- आयोजन स्थल- बैतूल, मध्य प्रदेश में
- आयोजक- प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय
- उद्देश्य- जनजातीय समुदायों को उनकी सांस्कृतिक जड़ों और प्राकृतिक जीवन-मूल्यों से जोड़ते हुए उनका समग्र विकास सुनिश्चित करना।
- इस सम्मेलन में भारत की राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने भी भाग लिया था।

ब्रिक्स इंदौर डिक्लेरेशन-

- हाल ही में 12-13 जून, 2026 को इन्दौरमें आयोजित ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों की बैठक में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक में सर्वसम्मति से 'ब्रिक्स इंदौर डिक्लेरेशन' को अपनाया गया।
- ब्रिक्स इंदौर डिक्लेरेशन का मूल केंद्र किसान है।
- इस डिक्लेरेशन में खाद्य सुरक्षा, पोषण, कृषि व्यापार, नवाचार, निवेश, जलवायु-सहनीय खेती और सतत कृषि विकास को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता दर्शाई गई है।
- इसी बैठक में चार संस्थागत पहलों का भी प्रस्ताव रखा गया है जो निम्न है-
  1. BRICS Network of Centres of Excellence on Agro-Ecology and Regenerative Agriculture की स्थापना की जायेगी। यह नेटवर्क प्राकृतिक, जैविक और पुनर्य योंजी कृषि पद्धतियों पर संयुक्त रिसर्च, अनुभव-साझेदारी और क्षमता निर्माण का प्लेटफॉर्म बनेगा।
  2. BRICS Network on Digital Agriculture की स्थापना की जायेगी है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भू-स्थानिक तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा आधारित कृषि समाधानों के क्षेत्र में सहयोग को नई दिशा देगा।
  3. Global Forum on Farmers' Rights in Seed Systems की स्थापना की जायेगी। इसका उद्देश्य किसानों के बीज संबंधी अधिकारों, देशी बीजों की विविधता और पारंपरिक ज्ञान की रक्षा करना है।
  4. BRICS AgriN (Agro Inputs, Genetic Resources and Information Network की स्थापना की जायेगी जो सदस्य देशों के बीच कृषि आदानों, बीजों और अनुवांशिक संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करेगा।

मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (एमआईएफएफ) 2026

- संस्करण- 19वां संस्करण
- आयोजन तिथि- 15 से 21 जून, 2026
- आयोजन स्थल- मुंबई, महाराष्ट्र
- आयोजक- राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) द्वारा
- इस सालमहोत्सव के प्रतिस्पर्धा भाग में भारत समेत 47 देशों से 1,459 फिल्में आई।
- **गोल्डन कोंच पुरस्कार-**
  - **सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फिल्म-** पोलिश वृत्तचित्र 'सिल्वर' को इस महोत्सव का सर्वोच्च सम्मान मिला।
  - **निर्देशक व निर्माता-** इसका निर्देशन नतालिया कोनियार्ज़द्वारा और निर्माण मैसीज कुबिकी द्वारा किया गया है।
- **सिल्वर कोंच पुरस्कार-**
  - सर्वश्रेष्ठ भारतीय वृत्तचित्र फिल्म-यह पुरस्कार साईनाथ एस. को उनकी फिल्म के लिए प्रदान किया गया।
  - सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म-जर्मनी की फिल्म 'मायाज़ सॉन्ग' (Maya's Song) को यह पुरस्कार मिला, जिसका निर्देशन और निर्माण फ्रांज़िस्का शोनेनबर्गर और जयकृष्णन सुब्रमणियन ने किया है।

मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव-

- यह वर्ष 1990 में शुरू हुआ था।
- यह दक्षिण एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा गैर-फीचर फिल्म महोत्सव है।
- भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा आयोजित हुआ।

प्रथम ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एसएमई कार्य समूह की बैठक-

- आयोजन तिथि- 19 जून, 2026
- आयोजन स्थल- आगरा, उत्तर प्रदेश
- विषय- लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण।
- आयोजक- केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन-2026-

- संस्करण- 26वां संस्करण
- आयोजन तिथि- 19-20 जून, 2026
- आयोजन स्थल- नई दिल्ली
- उद्घाटन- केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वार
- उद्देश्य-आपराधिक न्याय प्रणाली में अत्याधुनिक तकनीक और फिंगरप्रिंट डेटाबेस का अधिकतम उपयोग करके दोषसिद्धि दर को बढ़ाना और नागरिकों को त्वरित न्याय सुनिश्चित करना।
- **Note-** इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा चार महत्वपूर्ण एप्लीकेशन को भी लाँच किया गया-

1. **NCRB-अभिज्ञान-**
   - यह एक मोबाइल एप्लिकेशन है जो ऑन-फील्ड पुलिस को सर्टिफाइड फिंगरप्रिंट स्कैनर की सहायता से किसी भी स्थान से संदिग्ध व्यक्ति के फिंगरप्रिंट को नेशनल डेटाबेस में सर्च करने की सुविधा देता है।
   - यह फील्ड पुलिसिंग को अधिक सक्षम और त्वरित बनाता है।
2. **CrPIएप्लीकेशन-**
   - इस सिस्टम में फेस, आइरिस और DNA मैचिंग का एकीकरण किया जा रहा है।
   - यह मल्टी-मोडल बायोमेट्रिक तकनीक पहचान की विश्वसनीयता बढ़ाती है, मैनुअल एरर घटाती है और प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाती है।
3. **ई-फ़ॉरेंसिक्स 2.0-**
   - यह देश की फोरेंसिक प्रयोगशालाओं और जांच एजेंसियों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है।
4. **ई-प्रॉसिक्यूशन 2.0-**
   - यह प्लेटफॉर्म पुलिस, अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया के बीच डिजिटल समन्वय स्थापित करता है, ताकि अपराधी की पहचान के बाद उसे समयबद्ध सजा भी सुनिश्चित हो सके।

सिंधु कुम्भ-

- आयोजन तिथि- 22 से 27 जून, 2026 (पांच दिवसीय)
- आयोजन स्थल- लेह-लद्दाख में
- **उद्देश्य-**
  1. देश की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करना।
  2. राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना व सिंधु नदी के प्रति सम्मान व्यक्त करना।
- यह प्रथम सिंधु कुम्भ है। इसे सिंधु दर्शन यात्रा के 30 वर्ष पूर्ण (वर्ष 1997) होने के रूप में मनाया जा रहा है।

निर्भय चेतना अभियान/कार्यक्रम

- आयोजन तिथि- 7 से 19 जून 2026
- आयोजन स्थल- नई दिल्ली
- आयोजक- पंचायती राज मंत्रालय
- उद्देश्य- जमीनी स्तर पर लैंगिक रूप से संवेदनशील शासन को मजबूत करना।
- इस कार्यक्रम में ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया द्वारा विकसित निर्भय चेतना प्रशिक्षण मॉड्यूल का भी शुभारंभ किया गया।
- इस पहल का उद्देश्य मुख्य प्रशिक्षकों का एक समूह तैयार करना है जो पंचायती राज संस्थाओं के भीतर लैंगिक समानता, महिलाओं की सुरक्षा, अधिकारों और नेतृत्व पर पुरुष निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करेंगे।

निर्भय चेतना-

- यह 11 मार्च, 2026 को शुरू निर्भय रहो पहल के अंतर्गत शुरू की गयी पहल है।
- उद्देश्य- निर्वाचित पुरुष प्रतिनिधियों को लैंगिक समानता और महिलाओं की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाना।

ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक-2026

- संस्करण/बैठक क्रम- 11वां
- आयोजन तिथि- 25-26 जून, 2026
- आयोजन स्थल- गुरुग्राम, हरियाणा
- आयोजक- भारत
- विषय- सर्वेषां ऊर्जम (सभी के लिए ऊर्जा)
- उद्देश्य- ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और नवाचार पर सहयोग को बढ़ावा देना।
- यह बैठक तीन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर केंद्रित रही जो निम्न है-
  - प्राथमिकता 1: ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता
  - प्राथमिकता 2: ऊर्जा पहुंच और समानता
  - प्राथमिकता 3: प्रौद्योगिकी और नवाचार

रक्षा सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार समिति की बैठक

- बैठक क्रम या संस्करण- 15वां
- आयोजन तिथि- 23 जून, 2026
- आयोजन स्थल- नई दिल्ली
- आयोजक- एकीकृत रक्षा स्टाफ (एचक्यू आईडीएस)
- लक्ष्य- सूचना प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता और अत्याधुनिक उपकरणों को समयबद्ध तरीके से अपना।

"वैश्विक बाजारों के लिए वस्त्र" पर शिखर सम्मेलन

- आयोजन तिथि- 23 जून, 2026
- आयोजन स्थल- नई दिल्ली
- आयोजक- वस्त्र मंत्रालय
- विषय- वैश्विक बाजारों के लिए वस्त्र: 2030 तक 100 अरब अमेरि की डॉलर के निर्यात का लक्ष्य हासिल करने की रणनीति
- उद्देश्य-समन्वित कार्ययोजना तैयार करना और 2030 तक वस्त्र एवं परिधान निर्यात को लगभग 37 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना।

वंदे मातरम शिविर-

- संस्करण/क्रम- प्रथम
- आयोजन तिथि- 24 से 30 जून, 2026
- आयोजन स्थल- कोलकाता, पश्चिम बंगाल
- आयोजक- युवा मामलों का विभाग (युवा मामले एवं खेल मंत्रालय)
- उद्देश्य- राष्ट्रीय एकता, संवैधानिक मूल्यों और युवा नेतृत्व को मजबूत करना।
- यह शिविर 'माई भारत' अभियान अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के अंतर्गत चिन्हित जिलों में 20 शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक में 15 से 29 वर्ष की आयु के 150 युवा प्रतिभागी शामिल होंगे।
- प्रत्येक शिविर में छह राज्यों के प्रतिनिधि होंगे, पूर्वोत्तर से अनिवार्य प्रतिनिधित्व होगा। महिलाओं तथा सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की कम से कम 50 प्रतिशत भागीदारी होगी।

आईपी-2026 के माध्यम ले रक्त एवं रक्त के घटकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन-

- आयोजन तिथि- 24 जून, 2026
- आयोजन स्थल- गाज़ियाबाद
- आयोजक- इंडियन फार्माकोपिया आयोग
- उद्देश्य- इंडियन फार्माकोपिया 2026 में हाल ही में शामिल हुए रक्त एवं रक्त के घटकों से जुड़े मोनोग्राफ़ के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उन्हें लागू करने में मदद करना।

समर फैंसी फूड शो 2026-

- आयोजन तिथि- 28 जून, 2026
- आयोजन स्थान-न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका
- उद्घाटनकर्ता- श्री बिनय श्रीकांत प्रधान और विकास खन्ना (शेफ)
- यह यह उत्तरी अमेरिका की सबसे विशिष्ट और प्रतिष्ठित खाद्य प्रदर्शनी है। इस शो के इंडिया पवेलियन में भारतीय आम की छह उच्च गुणवत्ता वाली निर्यात किस्मों का प्रदर्शन किया गया।
- समर फैंसी फूड-2026 में बासमती चावल से बने व्यंजनों ने भारतीय चावल की विविधता को भी प्रदर्शित किया।

नार्को-कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) की 10वीं शीर्ष-स्तरीय बैठक

- संस्करण/बैठक -10वीं
- आयोजन तिथि- 26 जून 2026
- आयोजन स्थल-विज्ञान भवन, नई दिल्ली
- आयोजक- नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो
- यह बैठक हाइब्रिड मोड में 44 केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के प्रमुख हितधारकों के साथ-साथ राज्य सरकारों और ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के 108 प्रतिनिधियों को एक साथ लाती है।
- इस बैठक में केन्द्रीय गृह मंत्री ने "मादक पदार्थ नियंत्रण पर विज़न डॉक्यूमेंट (2026-2029)" जारी किया। यह विज़न डॉक्यूमेंट, ड्रग की समस्या से निपटने के लिए मांग कम करने, आपूर्ति कम करने और नुकसान कम करने के पहलुओं पर एक साझा रोडमैप प्रदान करता है।

"ग्रामीण विकास में एआई से मिलने वाले लाभ" पर राष्ट्रीय कार्यशाला-

- आयोजन तिथि- 25 जून,2026
- आयोजन स्थल- भारत मंडपम, नई दिल्ली
- आयोजक- ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
- विषय- ग्रामीण विकास में एआई से मिलने वाले लाभ
- **उद्देश्य-**
  - ग्रामीण विकास के अनुकूल बड़े पैमाने पर लागू होने वाले और उच्च प्रभाव वाले एआई उपयोग मामलों की पहचान करना।
  - उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों से कार्यान्वयन के अनुभवों एवं संस्थागत सीख को प्रदर्शित करना।
  - देश भर में तकनीक को अपनाने के लिए आवश्यक डेटा इकोसिस्टम और संस्थागत ढांचे की तैयारी का आकलन करना।

वस्त्र शिखर सम्मेलन-2026

- आयोजन तिथि- 23 से 24 जून,2026, आयोजन स्थल-नई दिल्ली
- आयोजक- वस्त्र मंत्रालय
- उद्देश्य- वस्त्र व्यापार के लिए सतत विकास, निर्यात और वैश्विक बाजार विस्तार को सुनिश्चित किया जाना।

राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन

- संस्करण- 8वां
- आयोजन का शुभारम्भ- 25 जून, 2026
- आयोजन स्थल-श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर
- विषय- 'सहकार से समृद्धि- विजन से जमीनी वास्तविकता तक'
- उद्देश्य- सहकारिताके क्षेत्र में की गई पहलों की समीक्षा करना, जमीनी स्तर की चुनौतियों की पहचान करना और भविष्य का रोडमैप तैयार करना।

सुजल ग्राम संवाद-

- संस्करण- आठवें संस्करण
- आयोजन तिथि- 25 जून, 2026
- आयोजन स्थल- नई दिल्ली
- आयोजक- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय
- उद्देश्य- जल जीवन मिशन 2.0 के तहत समुदाय-नेतृत्व वाले जल शासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन-2026

- आयोजन तिथि- 28 और 29 जून, 2026
- आयोजन स्थल- नई दिल्ली
- आयोजक-ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
- अध्यक्षता- केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान
- उद्देश्य- गांवों के समग्र विकास को सुनिश्चित किया जाना।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केंद्रीय परिषद का सम्मेलन-2026

- संस्करण-16वां सम्मेलन
- आयोजन तिथि- 29 जून 2026
- आयोजन स्थल- विज्ञान भवन, नई दिल्ली
- आयोजक- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
- उद्देश्य- स्वास्थ्य के क्षेत्र में संचालित वर्तमान पहलों की समीक्षा करना, स्वास्थ्य की सर्वोत्तम विधियों को साझा करना, स्वास्थ्य के क्षेत्र उभरती चुनौतियों की पहचान करना और देश भर में स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करना।
- अध्यक्षता- श्री जेपी नड्डा (केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री)
- **केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद**
  - गठन- संविधान के अनुच्छेद-263 के तहत
  - यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सर्वोच्च सलाहकार संस्था है।
  - यह परिषद चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रों से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझेदारी में उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाती है।

भारत-फिलीपींस व्यापार एवं निवेश संयुक्त कार्य समूह बैठक-

- बैठक संस्करण- 14वां
- आयोजन तिथि- 5 जून, 2026
- आयोजन स्थल- मनीला, फिलीपींस
- अध्यक्षता- वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव अमित वर्मा और फिलीपींस के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समूह के व्यापार एवं उद्योग विभाग के अवर सचिव एलन बी. गेप्टी ने की द्वारा
- इस बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश रुझान, प्राथमिकता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान तथा विभिन्न क्षेत्रों में संवर्धन गति-विधियों और सहयोग पर चर्चा हुई।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन-

- संस्करण- 114वां
- आयोजन तिथि- 1-12 जून, 2026
- आयोजन स्थल- जिनेवा, स्वीटजरलैंड
- आयोजक- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
- उद्देश्य- वैश्विक स्तर पर श्रम मानकों और नीतियों का निर्माण करना, श्रमिकों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य, उचित वेतन, और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- इस सम्मेलन में केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)-

- स्थापना- वर्ष 1919 में
- मुख्यालय- जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड
- उद्देश्य- उद्देश्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त मानव व श्रम अधिकारों की रक्षा करना।

अंतर्राष्ट्रीय हर्बल फार्माकोपियापर डब्ल्यूएचओ विशेषज्ञ बैठक-

- बैठक क्रम- 5वीं बैठक , आयोजन तिथि- 16 से 18 जून, 2026
- आयोजन स्थल- हांगकांग, चीन
- आयोजक- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)
- उद्देश्य- वैश्विक स्तर पर औषधियों के मानकों पर विचार-विमर्श करना।

भारत-थाईलैंड रक्षा सम्मेलन-

- संस्करण-10वां संस्करण, आयोजन तिथि- 16 जून, 2026
- आयोजन स्थल- बैंकॉक, थाईलैंड
- अध्यक्षता- थाईलैंड के रक्षा उप स्थायी सचिव और भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने।
- इस सम्मेलन में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया।

विश्व औषध संहिता की अंतर्राष्ट्रीय बैठक (आईएमडब्ल्यूपी)-2026

- संस्करण/बैठक क्रम- 16वीं, आयोजन तिथि- 15 से 17 जून, 2026
- आयोजन स्थल- ब्रासीलिया, ब्राजील
- उद्देश्य- सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए समन्वित प्रयासों हेतु सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के तरीके खोजना।
- Note- 15वां आईएमडब्ल्यूपी भारतीय औषधसंधि आयोग और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त रूप से 6-7 फरवरी, 2025 को नई दिल्ली आयोजित किया गया था।

भारत-उज्बेकिस्तान अंतर-सरकारी आयोग का सत्र

- संस्करण/सत्र क्रम- 14वां , आयोजन तिथि- 19 जून, 20
- आयोजन स्थल- ताशकंद, उज्बेकिस्तान
- उद्देश्य- दोनों देशों के मध्य व्यापार विस्तार, नियामकीय सहयोग, क्षेत्रीय विविधीकरण, संपर्क-सुविधा और प्रभावी क्रियान्वयन को बढ़ावा देना।
- भारत-उज्बेकिस्तान अंतर-सरकारी आयोग की 15वीं बैठक भारत में आयोजित की जाएगी।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) महिला मंच-2026-

- आयोजन तिथि- 26 जून, 2026
- आयोजन स्थल- बिश्केक, किर्गिज़ गणराज्य
- भारतीय प्रतिनिधित्व-केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी
- विषय- 'आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका'

विविध

- शोर्ट- हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 जून, 2026 को सेवा तीर्थ में 'प्रगति' की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। आईसीटी आधारित यह बहु-माध्यम मंच केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों को निर्बाध रूप से एकीकृत कर सक्रिय शासन और समयबद्ध क्रियान्वयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।
- शोर्ट- हाल ही में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने 16 जून, 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 9वें जिला कलेक्टर पेयजल संवाद का आयोजन किया।
- शोर्ट- बिरसा लिव्स इन न्यू भारत वीक- यह वीक या सप्ताह 25 मई से 2 जून, 2026 तक भगवान बिरसा मुंडा की प्रेरणादायक विरासत की स्मृति में मनाया गया है।
- शोर्ट- जनजातीय गरिमा उत्सव 10 मई से 9 जून, 2026 तक मनाया गया है।
- शोर्ट- हाल ही में पहली ब्रिक्स भ्रष्टाचार-रोधी कार्य समूह की बैठक 2–3 जून 2026 को भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के नेतृत्व मेंवर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई।
- शोर्ट- हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने 3 जून, 2026 को राजस्थान क्लस्टर के लिए पीएम-एसईटीयू (उन्नत आईटी-आई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता) पर उद्योग संवाद का आयोजन किया।
- शोर्ट- हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में 3 जून, 2026 को नई दिल्ली में ट्रांस_जेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई।
- शोर्ट- हाल ही में केंद्रीय कॉर्पोरेट मंत्रालय ने 13 जून, 2026 को नई दिल्ली में "भारत के पुनर्गठन पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्परिभाषित करने: सीखने के एक दशक- भविष्य के लिए दिशाएं" विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया।
- शोर्ट- भारत ने विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) के अवसर पर जेनेवा में डब्ल्यूटीओ व्यापार और पर्यावरण सप्ताह-2026 के दौरान एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जिसका शीर्षक 'भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना का शोकेस और नवीकरणीय ऊर्जा में मानकीकरण' था।
- शोर्ट- हाल ही में राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय स्तरीय नीति कार्यान्वयन एवं निगरानी समिति की 9 जून, 2026 को नई दिल्ली में पहली बैठक आयोजित हुई।

अभियान/ऑपरेशन/युद्धअभ्यास

बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास 'खान क्वेस्ट'-

- संस्करण- 23वां
- आयोजन तिथि- 20 जून से 3 जुलाई, 2026
- आयोजन स्थल- फाइव हिल्स ट्रेनिंग एरिया, मंगोलिया
- भागीदार- यह बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसमें एक से अधिक देश भाग लेते है।
- उद्देश्य- रक्षा बलों के दल को बहुपक्षीय वातावरण में शांतिरक्षा अभियानों के लिए तैयार करना।
- इस अभ्यास में दुनिया भर की सैन्य ताकतें संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत शांति समर्थन अभियानों में सहयोग और अंतर-संचालनीयता बढ़ाने के लिए एकजुट हुई।
- इस अभ्यास का पिछला संस्करण 14-28 जून 2025 तक मंगोलिया में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास की शुरुआत सबसे पहले 2003 में अमेरिका और मंगोलियाई रक्षा बलों के बीच एक द्विपक्षीय कार्यक्रम के रूप में हुई थी। इसके बाद, 2006 से यह अभ्यास एक बहुपक्षीय शांतिरक्षा अभ्यास में परिवर्तित हो गया।

ऑपरेशन दृष्टि-

- यह भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की एक विशेष नेत्र चिकित्सा टीम द्वारा चलाया गया 9वां मेगा नेत्र शल्य चिकित्सा शिविर था।
- यह शिविर 15 से 19 जून, 2026 के बीच रांची के नामकुम स्थित सैन्य अस्पताल में आयोजित किया गया।
- दिसंबर, 2024 में देहरादून में पहले शिविर के बाद से 'ऑपरेशन दृष्टि' का विस्तार जयपुर, बागडोगरा, उधमपुर, लक्षद्वीप, भुज, गोरखपुर और लेह-लद्दाख में हुआ है।

महत्वपूर्ण दिवस

तेलंगाना स्थापना दिवस-

- आयोजन तिथि- प्रतिवर्ष 2 जून
- यह दिवस तेलंगाना राज्य के गठन की स्मृति में मनाया जाता है।
- 2 जून, 2014 को आंध्र प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी हिस्से को विभाजित करके भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का आधिकारिक गठन किया गया था।

विश्व साइकिल दिवस-

- आयोजन तिथि- प्रतिवर्ष 3 जून
- विषय- 'हरित भविष्य के लिए साइक्लिंग (Cycling for a Greener Future)'
- उद्देश्य- साइकिल को किफायती, टिकाऊ, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन साधन के रूप में मान्यता देना।

विश्व साइकिल दिवस-2026

- आयोजन तिथि- प्रतिवर्ष 3 जून
- विषय- हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना।
- उद्देश्य- साइकिल को एक सरल, किफायती, विश्वसनीय और पर्यावरण के अनुकूल स्थायी परिवहन साधन के रूप में मान्यता देना।
- अप्रैल 2018 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया था।

विश्व पर्यावरण दिवस 2026

- आयोजन तिथि- प्रतिवर्ष 5 जून
- विषय- प्रकृति से प्रेरित। जलवायु के लिये। हमारे भविष्य के लिये।
- इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक समारोह की मेजबानी अजरबैजान ने की है।
- उद्देश्य- वैश्विक सत्र पर लोगों को पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के प्रति जागरूक करना।

वैश्विक पवन दिवस

- आयोजन तिथि- प्रतिवर्ष 15 जून
- विषय- **पवन ऊर्जा:- महत्वाकांक्षा से विकास की ओर**
- उद्देश्य- पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में इसकी भूमिका को उजागर करना।
- Note- हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 15 जून, 2026 को गोवा में वैश्विक पवन दिवस 2026 सम्मेलन आयोजित किया।

भारत का पवन ऊर्जा परिदृश्य-

- भारत की अनुमानित कुल पवन ऊर्जा क्षमता जमीन से 120 मीटर की ऊंचाई पर 695.5 गीगावाट और 150 मीटर की ऊंचाई पर 1,163.9 गीगावाट है।
- 150 मीटर की ऊंचाई पर मूल्यांकित पवन ऊर्जा क्षमता का अधिकांश हिस्सा आठ उच्च संसाधन वाले राज्यों में केंद्रित है-

  1. राजस्थान- 284.2 गीगावाट
  2. गुजरात- 180.8 गीगावाट
  3. महाराष्ट्र- 173.9 गीगावाट
  4. कर्नाटक- 169.3 गीगावाट
  5. आंध्र प्रदेश- 123.3 गीगावाट
  6. तमिलनाडु- 95.1 गीगावाट
  7. मध्य प्रदेश- 55.4 गीगावाट
  8. तेलंगाना- 54.7 गीगावाट

- पवन संसाधनों का मानचित्रण करने और पवन ऊर्जा विकास के लिए उच्च क्षमता वाले स्थलों की पहचान करने के लिए देशभर में 900 से अधिक पवन निगरानी स्टेशन स्थापित किए गए हैं।
- गुजरात और तमिलनाडु के तटों से दूर स्थित 500 मेगावाट की 1,000 मेगावाट की अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए ₹ 6,853 करोड़ की व्यवहार्यता अंतर निधि (VGF) को मंजूरी दी गई है।

विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस-2026

- आयोजन तिथि- प्रतिवर्ष 17 जून
- विषय- चारागाह: पहचानें, सम्मान करें, पुनर्स्थापित करें।
- यह दिवस संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण निवारण सम्मेलन (यूएनसीसीडी) के अंतर्गत मनाया जाता है।
- उद्देश्य- मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने और कार्रवाई को बढ़ावा देना।

अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस 2026-

- आयोजन तिथि- प्रतिवर्ष 19 जून
- विषय- क्लोजिंग द सर्वाइवल गैप: इक्विटी इन सिकल सेल डिज़ीज़
- उद्देश्य- सिकल सेल रोग के प्रति जागरूकता, निदान, उपचार एवं रोकथाम को प्रोत्साहित करना।
- **विविध तथ्य-**
  - इस दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर, 2008 को प्रस्ताव पारित कर मान्यता प्रदान की।
  - सिकल सेल रोग-
    - यह आनुवंशिक रक्त विकार है।
    - इसमें मानव की लाल रक्त कोशिकाएं सामान्य गोल आकार की बजाय हँसिये के आकार की बन जाती हैं।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस-2026

- संस्करण/क्रम-12वां
- आयोजन तिथि- प्रतिवर्ष 21 जून
- विषय- स्वस्थ आयु के लिए योग
- इस बार भारत में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस-2026 का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित किया गया है।
- **विविध तथ्य-**
  - पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस **21 जून, 2015** को मनाया गया।
  - संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2014 में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए **प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी** ने संयुक्त राष्ट्र के **69वें अधिवेशन** में प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव का **175 सदस्य देशों** ने समर्थन किया।
  - यूनेस्को ने वर्ष 2016 में योग को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की अपनी प्रतिनिधि सूची में शामिल किया था।

अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी विरोधी दिवस-

- आयोजन- प्रतिवर्ष 26 जून
- उद्देश्य- मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक और आर्थिक नुकसान के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना।

विश्व संगीत दिवस-

- आयोजन तिथि- प्रतिवर्ष 21 जून
- उद्देश्य- संगीत को बढ़ावा देना, निःशुल्क संगीत उपलब्धता और संगीत के माध्यम से सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।
- इस दिवस की शुरुआत मूल रूप से फ्रांस में वर्ष 1982 में हुई थी, जिसे वहां 'फेते डी ला म्यूजिक' कहा जाता है। इसकी कल्पना फ्रांस के तत्कालीन संस्कृति मंत्री जैक लैंग ने की थी।

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस-

- आयोजन तिथि- प्रतिवर्ष 23 जून
- उद्देश्य- शारीरिक सक्रियता को बढ़ावा देना और दैनिक जीवन में खेल और शारीरिक गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- 23 जून, 1894 को पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी, जिसकी याद में वर्ष 1948 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई।

संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस

- आयोजन तिथि- प्रतिवर्ष 23 जून
- विषय- Transforming Public Institutions: Advancing Innovation, Participation, and Inclusion
- उद्देश्य- विकास की प्रक्रिया में लोक सेवा और सार्वजनिक सेवा के योगदान व भूमिका को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर, 2002 को अपने प्रस्ताव (A/RES/57/277) के जरिए आधिकारिक तौर पर 23 जून को 'संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस' के रूप में घोषित किया था।
- यह पहली बार वर्ष 2003 में मनाया गया था।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस-2026

- आयोजन तिथि- प्रतिवर्ष 27 जून
- विषय- नवाचार और सतत औद्योगिक विकास के माध्यम से एमएसएमई का सशक्तिकरण।
- उद्देश्य- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को सुदृढ़ता प्रदान करना।
- **विश्व में एमएसएमई का प्रतिनिधित्व-**
  - व्यवसायों में हिस्सा- 90 प्रतिशत
  - जीडीपी का हिस्सा- 50 प्रतिशत
  - रोजगार में योगदान- 60 से 70 प्रतिशत रोजगार
- **भारत में एमएसएमई का प्रतिनिधित्व-**
  - जीडीपी- लगभग 31.1 प्रतिशत
  - विनिर्माण उत्पादन-लगभग 35.4 प्रतिशत
  - निर्यात- लगभग 48.58 प्रतिशत
  - रोजगार- लगभग 38.9 करोड़ (कृषि के बाद भारत में रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत)
- **एमएसएमई मुख्यत:** गरीब कामगारों, महिलाओं, युवाओं और कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले समूहों की आजीविका को बनाए रखने में सहायक होते हैं।
- **भारत सरकार द्वारा एमएसएमई का वर्गीकरण-**
  - भारत सरकार ने 1 अप्रैल, 2025 से एमएसएमई की परिभाषा/वर्गीकरण को संशोधित किया था। निवेश और वार्षिक टर्नओवर पर आधारित नई परिभाषा उद्यमों को वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है-

○ एमएसएमई (MSMEs) का वर्गीकरण

श्रेणी	संयंत्र/मशीनरी/ उपकरण में निवेश	वार्षिक टर्नओवर (कुल बिक्री)
सूक्ष्म उद्यम	₹ 2.5 करोड़ तक	₹ 10 करोड़ तक
लघु उद्यम	₹ 25 करोड़ तक	₹ 100 करोड़ तक
मध्यम उद्यम	₹ 125 करोड़ तक	₹ 500 करोड़ तक

- Note- जून 2026 में, भारत ने अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत प्रथम ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एसएमइ वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की।

राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस-2026

- संस्करण- 20वां
- आयोजन तिथि- प्रतिवर्ष 29 जून
- प्रथम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस- वर्ष 2007
- विषय- प्रशासनिक आँकड़ों की क्षमता का दोहन।
- आयोजक- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
- उद्देश्य- राष्ट्रीय विकास के लिए सामाजिक-आर्थिक नियोजन और नीति-निर्माण में सांख्यिकी के महत्व के प्रति जन-जागरूकता, विशेषकर युवा पीढ़ी में, बढ़ाना।
- यह दिवस सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन के क्षेत्र के अग्रणी प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है।

विविध

"संस्कृति रत्न भंडार: भौवैयार इतिब्रिटो" (भवाइया: ए कल्चरल ट्रेजर एंड इट्स हिस्टोरिकल जर्नी)-

- इस पुस्तक को संसद सदस्य (लोकसभा) डॉ. जयंत कुमार रॉय और सुश्री संगीता रॉय द्वारा लिखा गया है।
- इस पुस्तक का विमोचन 25 जून, 2026 को नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने किया।

वीआईपी कल्चर इन इंडिया: पावर, प्रिविलेज एंड द डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी-

- इस पुस्तक को अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यसभा सांसद श्री नबम रेबिया और सह-लेखक श्री संदीप कुमार द्वारा लिखा गया है।
- इस पुस्तक का विमोचन 24 जून, 2026 को नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने किया।
- यह पुस्तक भारत में लोकतांत्रिक शासन और सार्वजनिक जीवन के मूल उजागर करती है।

गाइनाकैंथा खासियाका-

- इस ड्रैगनफ्लाई प्रजाति को हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के नामदफा नेशनल पार्क में देखा गया। इसे आखिरी बार वर्ष 1914 में तत्कालीन एबोर हिल्स क्षेत्र में देखा किया गया था। यह ड्रैगनफ्लाई अपनी तेज उड़ान और बड़ी आंखों के लिए जानी जाती है।

यून सुक योल-

- यह दक्षिण कोरिया पूर्व राष्ट्रपति थे जिनको सिओल अदालत ने 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने और दिसंबर, 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने का दोषी पाया है।

विपिन कुमार-

- यह रोमानिया में कार्यरत भारतीय निर्माण श्रमिक है। इनकों रोमानिया के क्राओवा शहर ने 'मानद नागरिकता' से सम्मानित किया। इन्होंने रोमानिया में जनवरी माह में जमी हुई झील में गिरी 5 वर्षीय बच्ची की जान बचाई थी।

जोनाथन कछुआ (सेशेल्स) -

- यह दुनिया का सबसे बुजुर्ग जमीनी जानवर है जिसने अपने जीवन के 194 वर्ष पूरे किए हैं। इसे 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' ने उसे अपना आधिकारिक आइकन चुना है।

व्हेन ऑडिट मैटर्स: सीएजी इंटरवेंशन्स दैट मेड ए डिफरेंस-

- यह में भारत के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री विनोद राय द्वारा संपादित पुस्तक है। इस पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने किया। यह पुस्तक इस धारणा को चुनौती देती है कि ऑडिट केवल गलतियां निकालने या अनुपालन तक सीमित है।

शिपोकोसा पॉलस माशातिले-

- यह दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति है।
- इन्होंने हाल ही में भारत की आधिकारिक यात्रा की है।

- शोर्ट- हाल ही में आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2026 से पहले 14 जून, 2026 को यूट्यूब पर सीधे योग प्रसारण के सबसे अधिक दर्शकों (4,35,831 दर्शक) का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।
- शोर्ट- हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारत के ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन पोर्टल (जीएचसीआई) का शुभारंभ किया है। मंत्रालय द्वारा विकसित यह पोर्टल भारत की ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना के अंतर्गत पारदर्शी प्रमाणन तथा नियामकीय आवश्यकताओं के अनुपालन को सुगम बनाएगा।

डॉ॰ हेमेन्द्र कुमार सिंह

राजस्थान में वन्यजीव और जैव विविधता

"सामान्यतः देश और दुनिया की नजरों में राजस्थान की छवि भले ही एक शुष्क भू-भाग की हो लेकिन थार के विशिष्ट जीवों से लेकर केवलादेव और रणथंभौर तक यहाँ एक अद्भुत और समृद्ध जैव-विविधता दिखाई देती है। कठोर जलवायु में भी जीवित यह विरासत हमारी पारिस्थितिक सुरक्षा और राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वर्तमान में विकास की अंधी दौड़ के कारण इसके अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है जिसे बचाने के लिए सरकारी नीतियों और पारंपरिक सामुदायिक संरक्षण को फिर से मजबूत करना समय की सबसे बड़ी मांग है।"

भारत विश्व के 12 मेगा जैव विविधता सम्पन्न देशों में शामिल है। भारत एक विशाल भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश है। इसकी अवस्थिति, जलवायु, विविधता और विविध पारिस्थितिकी प्रणाली के कारण वन्य जीव जन्तुओं का यह एक विशेष आवास है। वन्य जीवों में प्राकृतिक परिवेश में रहने वाले प्राणी, जलीय और भू-वनस्पतीय जीवों को सम्मिलित किया जाता है। भारत विश्व में जैव विविधता की दृष्टि से अपना एक विशेष स्थान रखता है।

राजस्थान में वन्यजीव-

वनों में निवास करने वाले वन्य जीव प्राकृतिक पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं और जैव विविधता के प्रतीक हैं। राजस्थान के भौगोलिक पर्यावरण की विविधता अर्थात् जलवायु, उच्चावच, वनस्पति, मृदा, जल राशियों की भिन्नता के कारण यहाँ अनेक प्रकार के वन्य जीवों का आवास है। वनीकरण की दृष्टि से कमजोर होने के बावजूद राजस्थान वन्यजीव जन्तुओं के मामले में एक विशेष स्थान रखता है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ माँसाहारी और शाकाहारी पशुओं, रेंगने वाले जीवों, विभिन्न प्रकार के पक्षियों आदि का निवास पाया जाता वर्तमान में वन्य जीवों को संकट का सामना करना पड़ रहा है यहाँ तक की वन्य जीवों के अस्तित्व को भी खतरा हो गया है।

वन्य जीव संरक्षण:-

वन्य जीवों में होने वाली निरन्तर कमी विश्वव्यापी समस्या है, हमारे देश भारत में भी यह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वन्य जीवों में होने वाली यह कमी राजस्थान राज्य में देखी जा सकती है, यहाँ के जीव-जन्तुओं की काफी प्रजातियाँ विलुप्ति के कगार पर पहुँच चुकी हैं। वन्यजीवों और जन्तुओं की कमी होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं-

1. वनों के विस्तार में होने वाली निरन्तर कमी
2. जलवायु में होने वाले लगातार बदलाव
3. वन भूमि का कृषि, उद्योग और आवासीय भूमि में बदलना
4. वन्य जीव जन्तुओं का शिकार, अवैध तस्करी एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु
5. लगातार सूखा पड़ने और जल स्रोतों के सूखने से वन्य जीव जन्तुओं की अकाल मृत्यु हो रही है।

वन्य जीवों की रक्षा के लिए प्रयास प्राचीनकाल से ही हो रहे हैं यहाँ रहने वाला विश्नोई समाज वन्य जीवों की रक्षा करता आया है। इसके अतिरिक्त राजस्थान ने 1951 में वन्य जीव और पक्षी संरक्षण की दिशा में प्रथम सराहनीय कदम उठाया।

1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तथा 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द्वारा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कानून बनाये गये।

- राजस्थान में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु प्रयास 1955 में हुआ जब सरिस्का (अलवर), केवलादेव घना (भरतपुर), दर्रा (कोटा), वन विहार (धौलपुर), जयसमंद (सलूम्बर) और कैलादेवी (करौली) को आरक्षित स्थल घोषित कर दिया जो पूर्व राजा-महाराजाओं के आखेट स्थल थे और यहाँ वन्य

जीव-जन्तुओं के शिकार पर रोक लगा दी गयी।

- राजस्थान में जयपुर (1876), उदयपुर (1878), बीकानेर (1922), जोधपुर (1936), कोटा (1954) में कुल 5 जन्तुआलय हैं।
- राजस्थान में हिरणों की सुरक्षा और संवर्द्धन के लिए मृगवन बनाये गए हैं।
- राजस्थान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत अनेक जीव-जन्तुओं को पूर्णतः संरक्षित जीव घोषित कर उनके शिकार करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन में से प्रमुख हैं- हिरण, चीता, बिल्ली, चिंकारा, भेड़िया, लोमड़ी, गीदड़, मोर, सारस, बाघ, तेंदुआ, घड़ियाल, गिलहरी, बाज, कस्तूरी, कछुआ आदि।
- अप्रैल 1973 में बाघ संरक्षण हेतु देश में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया जिसके अंतर्गत 1973-74 में रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य को जबकि 1978-79 में सरिस्का को जोड़ा गया और इनमें बाघ संरक्षण हेतु परियोजना को लागू किया गया।
- राजस्थान राज्य में वन्य जीव-जन्तुओं के प्रति जागरुकता लाने के लिए राजस्थान सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय मार्च, 2016 में सभी जिलों के लिए वन्य जीव शुभंकर की घोषणा की जो उस जिले के लिए विशेष पहचान होगा।

राजस्थान के जिला वन्यजीव शुभंकर

क्र.सं.	जिला	वन्यजीव शुभंकर
1.	अलवर	सांभर
2.	अजमेर	खरमोर पक्षी
3.	भरतपुर	सारस
4.	बाड़मेर	मरू लोमड़ी लॉकी)
5.	भीलवाड़ा	मोर
6.	बांसवाड़ा	जल पीपी
7.	बूंदी	सुर्खाब
8.	बारां	मगरमच्छ
9.	चुरू	कृष्ण मृग
10.	दौसा	खरगोश
11.	धौलपुर	पंचीरा (इंडियन स्क्रीमर)
12.	जालौर	भालू/रीछ
13.	जैसलमेर	गोडावन
14.	डूंगरपुर	जांघिल
15.	झुंझुनूँ	काला तीतर
16.	सिरोही	जंगली मुर्गी
17.	जयपुर	चीतल

क्र.सं.	जिला	वन्यजीव शुभंकर
18.	जोधपुर	कुरजां
19.	हनुमानगढ़	छोटा किलकिला
20.	करौली	घड़ियाल
21.	झालावाड़	गागरोनी तोता
22.	नागौर	राजहंस
23.	कोटा	ऊदबिलाव
24.	प्रतापगढ़	उड़न गिलहरी
25.	श्रीगंगानगर	चिंकारा
26.	सवाई माधोपुर	बाघ (Royal Bangal Tiger)
27.	सीकर	शाहीन
28.	पाली	तेंदुआ
29.	टोंक	हंस
30.	उदयपुर	कब्रबिज्जू
31.	राजसमंद	भेड़िया
32.	बीकानेर	भट्ट तीतर
33.	चित्तौड़गढ़	चौसिंघा

वन्य जीवों का महत्त्वः-

- मानव और वन्य जीवों का प्राचीन काल से ही घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है।
- वन्य जीवों से मानव समाज को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं जो निम्नलिखित हैं-
- आर्थिक लाभ- वन्य जीवों से हमें खाल, सींग, पंख जैसे विभिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं जो वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग में लिये जाते हैं।
- पर्यटन- वन्य जीवों के संरक्षण हेतु बनाए गए राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, जन्तुआलयों को देखने के लिए पर्यटक आते हैं। जिससे आय प्राप्त होने के साथ-साथ अन्य लोगों को रोजगार मिलता है।
- भूमि के उपजाऊपन में बढ़ोतरी- वन्य जीवों के अपशिष्ट से भूमि को उपजाऊ खाद प्राप्त होती है।
- वन्य जीव, प्राकृतिक वनस्पति के प्रकीर्णन में सहायक होते हैं।
- वन्य जीवों की शारीरिक संरचना मनुष्य से मिलती जुलती होने के कारण विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोग, शोध और अनुसंधान वन्य जीवों पर किये जाते हैं।
- प्रकृति के संतुलन को बनाये रखने में वन्य जीवों का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। वन्य जीव अपने क्रियाकलापों के द्वारा किसी न किसी रूप में प्राकृतिक वनस्पति (जंगलों) के पनपने में प्रकृति का सहयोग करते हैं।
- वन्य जीवों की अधिक संख्या, जंगलों को सघन बनाती है और वर्षा को आकर्षित करती है। इससे पर्यावरणीय संतुलन बना रहता है।

राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण और उनके प्रबंधन हेतु प्रयासः-

- राजस्थान में स्थित टाइगर रिजर्वों में और वन्य जीव अभयारण्यों के लिए वित्त पोषण केन्द्रीय प्रवर्तित योजना Integrated Development

of Wildlife Habitat और Project Tiger के तहत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रलय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। रणथम्भौर, सरिस्का बाघ परियोजना संरक्षण सोसायटी में जमा राशि से अतिरिक्त विकास कार्य करवाया जा रहा है।

- इनके अलावा वन्य जीव संरक्षण कार्य राज्य योजना, स्टैट कैंपा, RFBP-2, नाबार्ड के द्वारा भी करवाया जा रहा है।
- राजस्थान में 5 जन्तुआलय है जिनका प्रबंधन केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है।
- भारत सरकार के केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा अनुमोदित कांसेप्ट प्लान के अनुसार जयपुर जन्तुआलय का सैटेलाइट केन्द्र नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जोधपुर जंतुआलय को सैटेलाइट केन्द्र माचिया सफारी पार्क और उदयपुर जन्तुआलय का सैटेलाइट केन्द्र सज्जनगढ़ जैविक उद्यान विकसित किये गये हैं।
- इसी प्रकार कोटा और बीकानेर में क्रमशः अभेडा बायोलॉजिकल पार्क एवं मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क विकसित किये गए हैं।
- रणथम्भौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघ संरक्षण फाउण्डेशन बाघ रिजर्व क्षेत्रें के लिए पारिस्थितिकीय पर्यटन, पारिस्थितिकीय विकास कार्यक्रम एवं टाइगर जैवविविधता के संरक्षण के लिए तथा उनके प्रबंधन को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए बाघ संरक्षण फाउण्डेशन की स्थापना की गयी है। जिसका प्रमुख उद्देश्य बाघ संरक्षण के लिए बाघ रिजर्व प्रबंधन को आसान बनाना और सहायता प्रदान करना है।
- राजस्थान सरकार द्वारा 2013 में मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व तथा 2023 में धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व घोषित किया।

प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्डः- 5 जून 2013 को गोडावण के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट बस्टर्ड लांच करने वाला राजस्थान पहला राज्य है यह प्रोजेक्ट राष्ट्रीय मरू उद्यान में लांच किया गया।

प्रथम कृत्रिम प्रजनन सेंटरः- गोंडावन के संरक्षण हेतु भारत सरकार, भारतीय वन्य जीव संस्थान व राज्यसरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है जिसके तहत जैसलमेर के सम क्षेत्र में गोडावण कृत्रिम प्रजनन सेंटर बनाया गया है। जहाँ मार्च, 2025 में दो चूजों का जन्म हुआ।

द्वितीय कृत्रिम प्रजनन सेंटरः- रामदेवरा (जैसलमेर) में ''ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एग कलेक्शन एण्ड हैंचिंग सेंटर'' बनाया गया हैं। बारां के सोरसन में भी एक केप्टिव ब्रिडिंग सेंटर की स्थापना किए जाने का प्रावधान है।

बटरफ्रलाई वैली और बोगनवेलिया पार्कः- राज्य सरकार द्वारा स्मृति वन में बटरफ्रलाई वैली प्रोजेक्ट एवं आगरा रोड़, जयपुर स्थित सिल्वन पार्क में बोगनवेलिया पार्क विकसित किया गया है।

वनधन योजनाः- वन क्षेत्र के समीप रहने वाले लोगों के विकास, उनकी वनों पर निर्भरता कम करने के लिए, रोजगार उपलब्ध कराने हेतु वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वनधन योजना प्रारम्भ की। यह योजना पायलट आधार पर रणथम्भौर टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय मरुउद्यान, जैसलमेर, माउण्ट आबू, कुम्भलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य व जवाई कंजर्वेशन रिजर्व में लागू की गई।

खरमौर कृत्रिम प्रजनन केन्द्रः ब्यावर जिले के सथाना गाँव में, दूसरा सोसन (अंता, बारां)

कायलाना बायोडाइवर्सिटी पार्कः- जोधपुर की कायलाना झील के पास स्थित वन खण्ड, बड़ा भाकर क्षेत्र को औषधीय पौधों के संरक्षण व विकास के उद्देश्य से कायलाना बायोडाइवर्सिटी पार्क के रूप में विकसित किया गया है।

राजीव गाँधी बायोस्फीयर रिजर्वः- रणथम्भौर बाघ परियोजना क्षेत्रें से बाहर विचरण करने वाले बाघों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए रणथम्भौर और मुकंदरा हिल्स के बीच कोरिडोर का विकास किया जाना है।

राजस्थान में जैव विविधता-

- जैव विविधता शब्द पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जैविक प्रजातियों के अपने में समाहित की हुई है इनमें समस्त प्रकार के स्तनधारी, पक्षी प्रव जातियाँ, सरीसृप, उभयचर, मछली प्रजातियाँ, कीड़े-मकोड़े, पेड़-पौधे, शैवाल, कवक तथा प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस आदि सूक्ष्म जीव शामिल है। यह विविधता आनुवांशिक जाति और पारिस्थितिकी तंत्र प्रकार की होती है जो पर्यावरण संतुलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ 60 प्रतिशत भू-भाग पर शुष्क और अर्द्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, तो मध्य में अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार है। दक्षिणी-पूर्वी भाग पठारी है तो पूर्वी मैदानी प्रदेश नदियों द्वारा निर्मित है। यही भौगोलिक विविधता राजस्थान की जैव विविधता को आधार प्रदान करती है। इसी कारण से राजस्थान एक जैव विविधता समद्ध प्रदेश है।
- राजस्थान में लगभग 2500 प्रजातियों के पेड़ पौधे, 450 प्रजातियों के पक्षी, 50 प्रजातियों के स्तनपायी, 58 प्रकार के सरीसृप, 12 प्रजातियों के उभयचर पाये जाते हैं।
- जैव विविधता के अध्ययन की दृष्टि से राजस्थान को चार विशिष्ट जैव विविधता क्षेत्रें में विभक्त किया जा सकता है-

1. पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेशः

- राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र में शुष्क तथा अर्द्धशुष्क मरुस्थल का विस्तार है। यहाँ की प्रमुख विशेषता कम वर्षा, उच्च तापमान तथा शुष्कता है। इसी कारण ही यहाँ के जीव-जन्तुओं एवं वनस्पतियों में भी विभिन्नता देखी जाती है।
- यहाँ पेड़-पौधों में काँटेदार वनस्पति, कंटीली झाड़ियाँ, घास तथा ऐसे जीव अधिक पाए जाते हैं जिन्हें पानी की कम जरूरत होती है। यहाँ पाए जाने वाले जन्तुओं में प्रमुख जन्तु चिंकारा, काला हिरण, मरु बिल्ली, लोमड़ी, भेड़िया, खरगोश और नेवला है।
- 22 प्रकार के स्तनधारी जीव एवं पक्षियों की यहाँ लगभग 120 प्रजातियाँ पायी जाती है। जिनमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोडावन) प्रमुख हैं जो वर्तमान में संकटापन्न है और राजस्थान का राजकीय पक्षी है। इसके अलावा तीतर, मोर, कुरजां, स्पेन गौरिया आदि पक्षी पाए जाते हैं।

2. मध्य अरावली पर्वत प्रदेशः

- राज्य के मध्य में दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है जो कि जैवविविधता से सम्पन्न है। अरावली पर्वतमाला के दक्षिणी भाग में आज भी वनों का पर्याप्त विस्तार है। जहाँ सालर, धौक, महुआ, आम, बाँस, चुरैल आदि की वनस्पति प्रजातियाँ तथा बघेरा, रीछ, जरख, चीतल, सांभर, चौसिंगा, जंगली सुअर, भेड़िया, लोमड़ी, उड़न गिलहरी आदि वन्यजीव पाये जाते हैं।
- अरावली पर्वतमाला के मध्य तथा उत्तरी-पूर्वी भाग अर्थात् सवाई माधोपुर, अलवर, अजमेर, सीकर जिलों में पतझड़ वन व अनेक वन्य जीव पाये जाते हैं।

3. पूर्वी मैदानी प्रदेशः

- यह अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है एवं गंगा-यमुना के मैदान भाग का हिस्सा है। इस क्षेत्र में मुख्यतः राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर जिले आते हैं। इस क्षेत्र में नहर, तालाब, पोखर आदि जल स्रोत बड़ी संख्या में है जिस कारण यहाँ पक्षियों और प्रवासी पक्षियों की संख्या अधिक पायी जाती है।

4. दक्षिणी-पूर्वी पठारी प्रदेशः

- इस प्रदेश को हाड़ौती के पठार के नाम से भी जाना जाता है। हाड़ौती के पठार के एक ओर मुकंदरा की पहाड़ियाँ तो दूसरी ओर चम्बल नदी क्षेत्र है, इस कारण से यहाँ जैव विविधता अधिक देखने को मिलती है।
- चम्बल नदी में मगरमच्छ, घड़ियाल, डाल्फिन, कछुए, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, केंकड़े आदि मिलते हैं।
- मुकंदरा हिल्स को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है, इसमें दर्रा वन्यजीव अभयारण्य, जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय चम्बल वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं। मुकंदरा राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों के अतिरिक्त अनेक पादप विविधताएँ हैं।
- इस क्षेत्र में जैव विविधता संरक्षण के लिए रामगढ़ अभयारण्य, बस्सी अभयारण्य, शेरगढ़ अभयारण्य और राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य बनाये गये हैं।

राजस्थान की ईको-टूरिज्म साइट्स-

जैव विविधता संरक्षण

- जैव विविधता के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे- जैव विविधता वाले क्षेत्रें को राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य तथा आरक्षित एवं संरक्षित क्षेत्र घोषित करना आदि।
- जैव विविधता संरक्षण सामान्यतः दो प्रकार से किया जाता है-

राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्यः–

- ऐसा प्राकृतिक स्थान जहाँ जीव-जन्तुओं को प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली नेशनल पार्क (1936) था। जिसे वर्तमान में जिम कार्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। जिसे रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है।

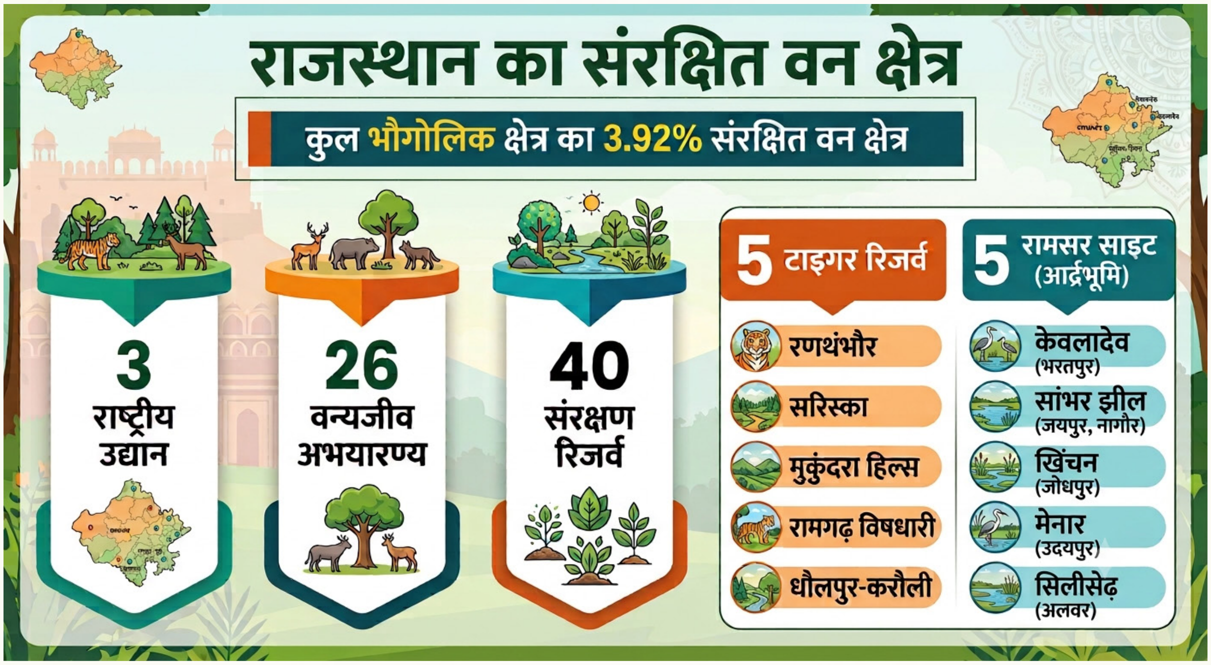

वर्तमान में राज्य में 3 नेशनल पार्क हैं-

1. रणथम्भौर नेशनल पार्क (सवाई माधोपुर):-

- राजस्थान का प्रथम अभयारण्य है जिसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है।
- राजस्थान का प्रथम वन्यजीव अभयारण्य है जिसे वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा 1955 में दिया गया था और 1 नवंबर, 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। सवाई माधोपुर के पास रणथम्भौर के चारों तरफ फैला यह राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण स्थल है। इसका विस्तार 282.03 वर्ग किलोमीटर में है।
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना का क्रियान्वयन 1973 से किया जा रहा है इसे 'Land of Tiger' भी कहते हैं।
- यहाँ सीताफल व धौंक वन की प्रचुरता है। यहाँ लाल सिर वाले तोते व दुर्लभ प्रजाति के काले गरूड़ यहीं मिलते हैं।
- यहाँ का मुख्य आकर्षण केन्द्र बाघ है, इसके अतिरिक्त यहाँ गीदड़, बघेरा, जंगली सूअर, बिज्जू, भेड़िया, सांभर, लंगूर, चीतल, हिरण व नीलगाय भी पाये जाते हैं। जबकि दूसरा मुख्य आकर्षण मगरमच्छ हैं।
- इसके दक्षिण में चम्बल एवं उत्तर में बनास नदी है।
- यहाँ बाघों की सुरक्षा के लिए 'विशेष बाघ संरक्षण बल का गठन किया गया है।

2. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यानः-

- यहाँ वनस्पतियाँ काफी घनी होने के कारण इस घना अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है।
- यह भरतपुर जिले में स्थित है। इसे 1956 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। 27 अगस्त, 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। 1985 में यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसे 1981 में रामसर साइट घोषित किया गया।
- इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है।
- यह एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल 28.73 वर्ग किमी है, जिसमें से 11 वर्ग किमी में झील है।
- यहाँ राज्य की प्रथम वन्यजीव प्रयोगशाला स्थापित है।
- यहाँ प्रतिवर्ष 500 से भी अधिक प्रवासी पक्षियों की प्रजातियों को देखा जा सकता है। जिसमें स्थानीय और विदेशी प्रवासी शामिल हैं।

- शीत ऋतु में यह हंसों, मेलार्ड, गेड़ वाला, पोचार्ड टिल्स, पिनटेल्स आदि प्रजातियों और उनकी उपप्रजातियों से भर जाता है।
- सफेद साइबेरियाई क्रेन यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। यह यहाँ अक्टूबर-नवंबर में आता है और फरवरी-मार्च में वापस चला जाता है।
- कदम्ब के वृक्ष यहाँ बहुतायत में पाये जाते हैं। इसे पानी अजान बांध से मिलता है और यहाँ बाणगंगा और गम्भीरी नदी बहती है।
- इसमें पायथन प्वाइंट है जहाँ सर्दियों में अजगर धूप सेकते नजर आते हैं।
- यह गोल्डन ट्राइएंगल (स्वर्णिम त्रिकोण)(जयपुर-आगरा- दिल्ली) पर अवस्थित होने के कारण पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है।
- यह अभयारण्य डॉ. सलीम अली की कर्मस्थली है।
- वन्यजीवों में यहाँ काले हिरण, चीतल, सांभर, लोमड़ी, गीदड़, नेवला, जंगली बिल्ली और सूअर आदि पाये जाते हैं।
- यहाँ ऑस्ट्रियन सॉरोस्कि के आर्थिक सहयोग व WWf के निर्देशन में सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर वर्ष 2006 में खोला है।
- केवलादेव उद्यान को WBHCC के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए जनवरी 2022 में वर्ल्ड वाइल्ड फण्ड के साथ एमओयू हुआ है।

3. मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यानः (पुराना नाम दर्रा अभयारण्य)

- इसे 1 नवंबर, 1955 को अभयारण्य घोषित किया गया।
- इस राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार 199.55 वर्ग किमी है जिसमें दर्रा वन्य जीव अभयारण्य, जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य तथा राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य शामिल है।
- मुकंदरा की पहाड़ियाँ सघन वनों से युक्त हैं यहाँ आदिमानव के शैलाश्रय तथा उनके द्वारा बनाये गये शैलचित्र देखने को मिलते हैं।
- यह कोटा एवं चित्तौड़गढ़ जिले में विस्तृत है।
- यहाँ वन्य जीवों में चीता, तेंदुआ, रीछ, हिरण, सांभर, जंगली सूअर, चीतल और नीलगाय आदि पाये जाते हैं।
- यह गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है जिसका वैज्ञानिक नाम 'सिटाकुला यूपेट्रिया/एलेक्जेण्ड्रिया पेराकीट' है। यह तोता हूबहू मानव की आवाज की नकल के लिए प्रसिद्ध है। इसे हीरामन तोता और हिन्दुओं का आकाश लोचन नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में इसके अस्तित्व पर संकट है।

राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्यः

1. राष्ट्रीय मरुउद्यान, जैसलमेरः

- राजस्थान के पश्चिमी शुष्क भाग में स्थित राष्ट्रीय मरुउद्यान की स्थापना 1981 में की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति और लाखों-करोड़ों वर्षों से जमीन में दबे जीवाश्मों को संरक्षण प्रदान करना। इसलिए इसे जीवाश्म उद्यान भी कहते हैं।
- राष्ट्रीय मरुउद्यान का विस्तार राजस्थान के जैसलमेर (1900 किमी.) और बाड़मेर (1262 किमी.) जिलों में 3162 वर्ग किमी. में विस्तृत है।
- इसे राष्ट्रीय आकलवुड फोसिल पार्क भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में बालुका स्तूपों की प्रधानता है और यहाँ जीवाश्म और वनस्पति के संरक्षण के अतिरिक्त यहाँ चिंकारा, चौसिंगा, गोडावण और काले हिरण को भी संरक्षण दिया जाता है। यह राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है।

2. सरिस्का वन्य जीव अभयारण्यः

- यह वन्य जीव अभयारण्य अलवर में स्थित है एवं 544.22 वर्ग किमी- में विस्तृत है। इसकी स्थापना आजादी से पहले ही कर दी गयी। जिसे राज्य सरकार ने 1955 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया। यहाँ केन्द्र सरकार द्वारा बाघ परियोजना चालू की गयी है।
- यहाँ मुख्य रूप से बाघ, हरे कबूतर (हरियल) सांभर, चीतल, नीलगाय, काला खरगोश, जंगली सूअर, लंगूर और अनेक पक्षी निवास करते हैं।
- यहाँ क्रासका व कांकवाड़ी पठार स्थित हैं।
- बाघों की संख्या नगण्य हो जाने के कारण यहाँ अब रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान से बाघ स्थानान्तरित किए गये हैं।
- यह रीसस बंदर के लिए प्रसिद्ध है। 9 जनवरी, 2012 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया।
- इसमें धार्मिक स्थल पांडुपोल, भर्तृहरि, नीलकंठ महादेव, तालवृक्ष गरठी कायोद तथा विरासत सम्पदा थानागाजी कुशलगढ़, बाला किला, अजबगढ़, भानगढ़ स्थित हैं।

3. नाहरगढ़ अभयारण्यः

- यह राजस्थान के आमेर दुर्ग, नाहरगढ़ तथा जयगढ़ के चारों ओर फैला हुआ है, जिसे 1980 में अभयारण्य बनाया गया है। यह अभयारण्य 52.40 वर्ग किमी में विस्तृत है। इस अभयारण्य में लंगूर, सेही और पाटागोह की प्रधानता है। यहाँ जैविक उद्यान स्थित है। यहाँ देश का तीसरा बीयर रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया गया है।

4. जमवारामगढ़ अभयारण्यः

- राजस्थान की राजधानी जयपुर में प्रसिद्ध शिकारगाह रामगढ़ को 1982 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया। यह अभयारण्य लगभग 300 किमी. में फैला हुआ है। यहाँ पर बघेरा, जंगली सूअर, जंगली बिल्ली, भेड़िया, नीलगाय और सांभर आदि वन्य जीव मिलते हैं।

5. जयसमंद अभयारण्य (1955):

- सलूम्बर में 52.34 वर्ग किमी- में विस्तृत, जससमंद झील के किनारे पहाड़ियों पर स्थित अभयारण्य है। यहाँ मुख्य रूप से रीछ, जंगली सूअर, नीलगाय, तेंदुआ आदि वन्य जीवों की संरक्षण स्थली है।

6. तालछापर कृष्ण मृग अभयारण्य (1962):

- सुजानगढ़ (चुरू), तालछापर अभयारण्य में काले हिरण व कुरंजा देखने को मिलते हैं। यह 7.19 वर्ग किमी. में फैला हुआ है। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा कृष्ण मृग है।
- यहाँ मकड़ी की दुर्लभ प्रजाति ''ग्रीन लिंक्स'' पायी जाती है। यह एशिया की सबसे बड़ी कृष्ण मृग अभयारण्य है यहाँ मोथिया नामक गर्म घास (मोचिया साइप्रस रोटेण्डस) पाई जाती है जो कृष्णमृग को प्रिय है।

7. बस्सी अभयारण्य (1988)-

- यह अभयारण्य चित्तौड़ में स्थित, 138.69 वर्ग किमी- में फैला है।
- इसे वर्ष 1988 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है।
- यह अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं के मिलन स्थल पर स्थित है यहाँ चौसिंघा, बघेरे, सैण्डग्राउज, जंगली बिल्ली और मगरमच्छ देखने को मिलते हैं। इस अभयारण्य से औराई और ब्राह्मणी नदियाँ निकलती है।

8. फुलवारी की नालः

- वर्ष 1983 में स्थापित उदयपुर के पिछड़े और शांत क्षेत्र फुलवारी की नाल अरावली पर्वतमाला के मध्य में स्थित, वन्य जीव अभयारण्य है। 511.41 वर्ग किमी. में विस्तृत।
- यहाँ से सोम, मानसी और वाकल आदि नदियाँ निकलती हैं।
- यहाँ पाये जाने वाले सघन वनों में बाघ, बघेरा, सांभर चीतल वन्य जीवों के साथ अनेक प्रजातियों के पक्षी देखे जा सकते हैं।
- यह अभयारण्य टीक (सागवान) वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है।
- यहाँ देश का पहला ह्यूमन एनोटॉमी पार्क विकसित किया जा रहा है।

9. भैंसरोड़गढ़ अभयारण्यः

- चित्तौड़गढ़ के पर्वतीय क्षेत्र में 273.54 वर्ग किमी- में फैला हुआ है जिसे 1983 में अभयारण्य घोषित किया गया था।
- जलीय अभयारण्य जो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है।
- यहाँ सैकड़ों प्रकार के पक्षियों के अतिरिक्त लकडबग्घा, बघेरा, नीलगाय, जंगली सूअर, चीतल, लंगूर, चिंकारा, लोमड़ी व गीदड़ पाये जाते हैं।

10. सज्जनगढ़ अभयारण्यः

- उदयपुर जिले की अरावली पर्वत श्रंखला के सघन क्षेत्र में यह अभयारण्य स्थित है। यह राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य है। जिसे 1987 में अभयारण्य दर्जा मिला। लगभग 5.19 वर्ग किमी में विस्तृत इस अभयारण्य में शेर, नीलगाय, चीतल, लंगूर, जंगली सूअर, चिंकारा, कृष्णमृग, सांभर आदि वन्य जीव देखे जा सकते हैं।

11. बन्ध बरेठा अभयारण्यः

- वर्ष 1985 को अभयारण्य बना जो लगभग 170-65 वर्ग किमी- में विस्तृत है। यह कुकुंद नदी पर बारेठा नामक स्थान पर एक बांध बनाया गया। और यहाँ अनेक प्रजातियों के वन्य जीव व पक्षी सुरक्षित है। यह अभयारण्य परिंदों के घर उपनाम से प्रसिद्ध, जरखों के लिए प्रसिद्ध है।

12. राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्यः

- वर्ष 1979 में अभयारण्य घोषित। यह अभयारण्य 564.03 वर्ग किमी- के जलीय क्षेत्र में विस्तृत है। चम्बल नदी पर राणा प्रतापसागर में नदी के जल बहाव तक इसका फैलाव है। इस एकत्रित हुए पानी में घड़ियाल और मगरमच्छ अपना जीवनयापन करते हैं। यह घड़ियालों का संसार/जलीय जीवों की प्रजनन स्थली है। इस अभयारण्य में गांगेय सूस (नेत्रहीन डॉल्फिन) नामक स्तनपायी पायी जाती है।

- इसका प्रमुख उद्देश्य घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करना तथा उनकी संख्या में वृद्धि करना है।
- यह अभयारण्य कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में विस्तृत है। पालीघाट (सवाई माधोपुर)-राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य में घड़ियालं के संरक्षण के लिए रियरिंग सेंटर के निर्माण की घोषणा बजट 2024-25 में की गई है।

13. टाडगढ़ रावली अभयारण्यः

- यह अभयारण्य राजस्थान के तीन जिलों ब्यावर, पाली और राजसमंद में विस्तृत है। 495.27 वर्ग किमी- में विस्तृत। जिसे 1983 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। यहाँ मुख्य रूप से जरख, रीछ, गीदड़, बंदर तथा नीलगाय आदि वन्य जीव निवास करते हैं।
- यह अभयारण्य राज्य के तीन संभागों (अजमेर, जोधपुर, उदयपुर) में विस्तृत है। इसमें कामली घाट और गोरमघाट दर्रे है।

14. रामगढ़ विषधारी अभयारण्यः

- बूंदी जिले में स्थित इसे 1982 में अभयारण्य घोषित किया गया है। यह अभयारण्य 303.05 वर्ग किमी- के क्षेत्रफल में विस्तृत है। इसे प्राचीष्नकाल से ही बाघ-बघेरों का घर माना जाता है। इसके अलावा यहाँ जरख, रीछ, गीदड़, नीलगाय, चीतल, चिंकारा, भेड़िया, लोमड़ी, नेवला, जंगली सूअर आदि देखे जा सकते हैं। राजस्थान का चौथा और देश का 52वाँ टाईगर रिजर्व बनाया गया है। इसे रणथम्भौर के बांधों का जच्चाघर भी कहा जाता है।

15. रामसागर वन विहार अभयारण्यः

- धौलपुर में स्थित, इसे 1955 में अभयारण्य घोषित किया गया जो कि 34-40 वर्ग किमी. में विस्तृत है। झील के किनारे पर स्थित होने के कारण पानी के पास पाये जाने वाले पक्षी भी मिलते हैं। प्रमुख वन्य जीव- जंगली सूअर, सांभर, नीलगाय, चीतल, सांभर, तीतर और मोर पाये जाते हैं।

राजस्थान के अन्य वन्य जीव अभयारण्य

क्रम सं.	अभयारण्य	वर्ग किमी	स्थान और क्षेत्रफल	प्रमुख विशेषताएँ	स्थापना वर्ष
1.	दर्रा वन्य जीव अभयारण्य	239.76	कोटा, झालावाड़	गागरोनी तोते व धोकड़ा वन, अबली मीणी का महल, गागरोन का किला	1955
2.	सवाई मानसिंह	113.07	सवाई माधोपुर	---	1984
3.	कैलादेवी	676.82	करौली, स. माधोपुर	धौंक वन क्षेत्र, डांग भूमि	जुलाई 1983
4.	कुंभलगढ़	610.53	उदयपुर, पाली, राजसमंद	भेड़िये, जैन मंदिर (रणकपुर), बनास व साबरमती नदियाँ	जुलाई 1971
5.	सीतामाता	422.94	चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर	चीतल, उड़न गिलहरी, चौसिंगा (स्थानीय भाषा में भडेल/घटेल), जाखम बाँध, सागवान वन	जनवरी 1979
6.	माउंट आबू	326.10	सिरोही	जंगली मुर्गा, गुरुशिखर, दुर्लभ वनस्पति (डिकिलपटेरा आबू एंसिस)	अप्रैल 2008
7.	जवाहर सागर	220.09	बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़	गैपरनाथ का मंदिर, गरड़िया महादेव का मंदिर	अक्टूबर 1975
8.	शेरगढ़	81.67	शेरगढ़ (बायाँ)	साँपों का शरण स्थल, परवन नदी	जुलाई 1983
9.	वनविहार	25.60	धौलपुर (बाड़ी)	---	1955
10.	केसरबाग	14.76	धौलपुर	---	1955
11.					
11.	सवाई माधोपुर संपुरी	131.30	सवाई माधोपुर	---	

राजस्थान के मृगवन

नाम	स्थापना	जिला	विशेषता
चित्तौड़ मृगवन	1969	चित्तौड़	चित्तौड़ दुर्ग के दक्षिणी छोर पर स्थित, राजस्थान का सबसे प्राचीन मृगवन यहाँ काला हिरण, नीलगाय, चीतल व चिंकारा पाए जाते हैं।
सज्जनगढ़ मृगवन	1984	उदयपुर	सज्जनगढ़ दुर्ग की तलहटी में स्थित है।
माचिया सफारी पार्क	1985	जोधपुर	कायलाना झील के किनारे स्थित, यहाँ भेड़िया, लंगूर, सेही, मरुबिल्ली, नीलगाय, काला हिरण, चिंकारा आदि मिलते हैं।
पुष्कर मृगवन	1985	अजमेर	पुष्कर में प्राचीन पंचकुण्ड के पास स्थित।
अशोक विहार मृगवन	1986	जयपुर	12 हैक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत, हिरण एवं चिंकारा हेतु।
संजय उद्यान मृगवन/अटल वन	1986	शाहपुरा (जयपुर)	10 हैक्टेयर में विस्तृत, यहाँ चिंकारा, नीलगाय, चीतल आदि रहते हैं।
अमृता देवी मृगवन	1994	खेजड़ली (जोधपुर)	काले हिरणों, चिंकारा, मरु लोमड़ी हेतु प्रसिद्ध।

लेपर्ड सफारी

- राजस्थान में पैंथर/तेंदुआ/लेपर्ड संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट लेपर्ड 4 अक्टूबर, 2018 को प्रारंभ किया गया।
- प्रोजेक्ट लेपर्ड जहाँ संचालित हैं - झालाना (जयपुर), आमागढ़ (जयपुर), कुम्भलगढ़, रावली टॉडगढ, जयसमंद (सलूम्बर), शेरगढ़ (बारां), खेतड़ी बांसियाल (झुंझनूं), माउन्ट आबू (सिरोही), जवाई बाँध (पाली), बस्सी (चित्तौडगढ़) व सीतामाता अभयारण्य (प्रतापगढ़)
- झालाना लेपर्ड सफारी (जयपुर) - देश का पहला लेपर्ड प्रोजेक्ट
- आमागढ़ लेपर्ड सफारी पार्क - 22 मई 2022 को लोकापर्ण, जयपुर जिले में स्थित
- जयपुर देश का अकेला शहर जहाँ तीन लेपर्ड/पैंथर सफारी है।
  (1) झालाना पैंथर सफारी (2) आमागढ़ पैंथर सफारी
  (3) बीड पापड़ पैंथर सफारी/मैला बाग (नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य में) शुरुआत 5 जून, 2025
- **लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर:-** सज्जनगढ़ अभयारण्य (उदयपुर) में राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा।
- राजस्थान के वे जिले जिनमें कोई राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, आखेट निषिद्ध क्षेत्र, मृगवन व जंतुआलय नहीं हैं- सीकर, झुंझुन, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डीडवाना-कुचामन, बालोतरा, हनुमानगढ़, गंगानगर (8)
- जोड़बीड़ (बीकानेर) राजस्थान का पहला व भारत का तीसरा गिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व।
- राजस्थान में प्रथम गदर्भ अभयारण्य - डुंडलोद (झुन्झुनूं)
- **मत्स्य अभयारण्य -** बड़ी तालाब (उदयपुर), **हाइटेक वर्चुअल वर्ल्ड फिश एक्वेरियम** - उदयपुर , **रेपटाइल पार्क -** उदयपुर
- राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क उदयपुर में स्थापित। यहाँ राज्य में पाई जाने वाली बटरफ्लाइस की 189 प्रजातियों में से 80 प्रजातियाँ पाई जाती है।

जैव विविधता संरक्षण के अंतरराष्ट्रीय प्रयास-

- सन् 1948 में जैव विविधता संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र के अधीन IUCN की स्थापना की गयी।
- IUCN ने सन् 1972 में रेड डेटा बुक का प्रकाशन किया जिसमें विलुप्त हो रही प्रजातियों, उनके आवास तथा उनकी वर्तमान संख्या को सूचीबद्ध किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रजातियों के 5 संवर्ग हैं-
    1. विलुप्त प्रजातियाँ- जो प्रजातियाँ अब मौजूद नहीं हैं, जैसे डोडो पक्षी डायनासोर आदि।
    2. संकटग्रस्त प्रजातियाँ- जो विलुप्ति के कगार पर हैं और संरक्षण के अभाव में विलुप्त होने वाली हों, जैसे- चीता, बाघ, गैंडा आदि।
    3. अतिसंवेदनशील प्रजातियाँ- जिन प्रजातियों की संख्या तेजी से कम हो रही है और शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका है।
    4. दुर्लभ प्रजातियाँ- जो प्रजातियाँ बहुत ही सीमित क्षेत्र में ही अस्तित्व में रह गयी हैं या जिनकी संख्या बहुत विरल है।
    5. अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियाँ-जिनके बारे में पर्याप्त जनकारी नहीं है।
- रेड डेटा बुक में लाल, पीले, सफेद, हरे एवं भूरे रंग के पृष्ठों पर क्रमशः कम संकटग्रस्त प्रजातियों को दर्ज किया जाता है।

राजस्थान में संरक्षण रिजर्व (कंजर्वेशन रिजर्व)			
क्र.	संरक्षण रिजर्व नाम	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)	जिला
1.	शाहबाद	189.03	बारां
2.	शाकम्बरी	131	सीकर, झुन्झुनू
3.	सुंधा माता	117.49	जालौर, सिरोही
4.	मनसा माता	102.31	झुन्झुनू
5.	रणखार	72.88	जालौर
6.	बंसियाल खेतड़ी	70.18	झुन्झुनू
7.	जवाई बांध लैपर्ड II	61.98	पाली
8.	जोहड़बीड गाढ़वाल	56.47	बीकानेर
9.	बीसलपुर	48.31	टोंक (पहला संरक्षित क्षेत्र)
10.	बंसियाल खेतड़ी बागोर	39.66	झुन्झुनू
11.	जवाई बांध लैपर्ड	19.79	पाली
12.	बीड़ झुन्झुनूं	10.47	झुन्झुनू
13.	गोगेलाव	3.58	नागौर
14.	उम्मेद गंज	2.72	कोटा
15.	गुढ़ा विश्नोईयान	2.32	जोधपुर
16.	रोटू	0.729	नागौर
17.	वाडाखेड़ा	43.31	सिरोही
18.	बाघदर्रा क्रोकोडाइल	3.69	उदयपुर
19.	बीड़ घास फूलियाखुर्द	0.857	भीलवाड़ा
20.	शाहबाद तलहटी	178.84	बारां
21.	झालाना-आमागढ़	35.07	जयपुर
22.	बांझ अमली कंजर्वेशन रिजर्व	14.62	बारां
23.	हमीरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व	5.66	भीलवाड़ा
24.	खरमोर कंजर्वेशन रिजर्व	9.31	अजमेर
25.	कुरजा कंजर्वेशन रिजर्व	2.92	फलोदी
26.	रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व	38.08	बारां
27.	सोरसेन कंजर्वेशन-I रिजर्व	16.10	बारां
28.	सोरसेन-II कंजर्वेशन रिजर्व	4.27	बारां
29.	सोरसेन-III कंजर्वेशन रिजर्व	0.75	बारां
30.	बीड़ फतेहपुर कंजर्वेशन रिजर्व	30.03	सीकर
31.	गंगा भेरव घाटी कंजर्वेशन रिजर्व	39.51	अजमेर
32.	बीड़ मुहाना कंजर्वेशन रिजर्व-ए	2.06	जयपुर
33.	बीड़ मुहाना कंजर्वेशन रिजर्व-बी (सबसे छोटा)	0.10	जयपुर
34.	बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व (सबसे बड़ा)	221.69	सीकर
35.	महासीर कंजर्वेशन रिजर्व	2.06	उदयपुर
36.	अमरख महादेव तेंदुआ कंजर्वेशन रिजर्व	71.47	उदयपुर
37.	आसोप कंजर्वेशन (राजस्थान का नवीनतम कंवर्जेशन रिजर्व)-	118.45	भीलवाड़ा
38.	मोखला पारेवर कंजर्वेशन रिजर्व	43.122	जैसलमेर
39.	बुचारा मेन कन्जर्वेशन रिजर्व	44.37	कोटपूतली-बहरोड
40.	खेजड़ली कलां कन्जर्वेशन रिजर्व (17 दिसंबर, 2025) नवीनतम	1.5085	जोधपुर

- राजस्थान में 10 अप्रैल, 2018 को राजस्थान वैटलैण्ड अथॉरिटी का गठन हुआ। राजस्थान में आर्द्रभूमि का क्षेत्रफल 7,82,314 हैक्टेयर है।
- सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व वाला जिला-बारां (7) है।
- राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम आर्द्रभूमि क्रमशः भीलवाड़ा (6.94%) व चुरू (0.08%) है।

राजस्थान के आखेट निषिद्ध क्षेत्र

1.	जोधपुर	1. डोली 2. गुढ़ा विश्नोई 3. फीटकाश्नी 4. जम्मेश्वर 5. साथीन
2.	फलौदी	1. लोहावट 2. डेंचू
3.	बाडमेर	1. धोरीमन्ना
4.	जैसलमेर	1. रामदेवरा 2. उज्जला
5.	बीकानेर	1. देशनोक 2. जोड़वीड़ 3. बज्जू 4. दियात्रा 5. मुकाम 6 संवत्सर कोटसर
6.	दौसा	1. सैंथल सागर
7.	जयपुर	1. महलां
8.	कोटपूतली बहरोड़	1. बरदोद
9.	खैरथल तिजारा	1. जोड़िया

10.	टोंक	रानीपुरा
11.	सवाई माधोपुर	कंवाल जी
12.	बूंदी	1. कनक सागर
13.	बारां	1. सोरसन
14.	उदयपुर	1. बागदड़ा
15.	अजमेर	1.सौंखलिया 2. गंगावाना 3. तिलोरा
16.	चित्तौड़गढ़	1. मेनाल
17.	नागौर	1. रोटू 2. जरोदा
18.	जालौर	1. सांचोर
19.	पाली	1. जवाई बांध

- राज्य में कुल 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र है जिनमें सबसे बड़ा संवत्सर कोटसर (बीकानेर) तथा सबसे छोटा कनक सागर (बूंदी) आखेट निषिद्ध क्षेत्र है।
- सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्रों वाला जिला- बीकानेर है।

जिला अधिसूचित वैटलैण्ड

जिला		अधिसूचित वैटलैंड
अजमेर	1	बड़ा तालाब
बांसवाड़ा	2	कुडा वेटलैण्ड, टेमरान
बारां	13	नाहरगढ़, नियाना, बैथली, इकलेरा सागर, गरदा तालाब, हिंगलोत, कोटरापर, ल्हासी, पुष्कर तालाब, रामगढ़ क्रेटर, सहरोल, तेजाजी की तलाई, उतावली
डीग	1	समाई खेडा
भीलवाड़ा	1	चावंडिया
बीकानेर	4	देवीकुंड, लाखोलाई (दियातरा), लूणकरणसर, सूरसागर
बूंदी	6	अभयपुरा बांध, बर्धाबांध, जैतसागर, रामसागर, रत्नसागर, नवलसागर
चित्तौड़गढ़	9	बड़वई, भवर पीपला बांध, दोराई बांध, गम्भीरी, किसन करेरी, मंगलवाड, ओराई बांध, पारसोली बांध, राजगढ़ तालाब
चुरू	1	चरवास
डूंगरपुर	1	सबेला
जालौर	1	रणखार
झालावाड़	4	बडवेला, देहलनपुर तालाब, कडेला तालाब, मुंडिया खेरी तालाब
जोधपुर	2	कायलाना, सुरपुरा
करौली	2	कालीसिंल बाँध, मामाचेरी बाँध
कोटा	3	हनुतिया, कनवास पक्षी विहार, किशोरसागर
डीडवाना कुचामन	1	डीडवाना
पाली	2	लखोटिया, लोर्डिया
प्रतापगढ़	1	केसरियावाड
राजसमंद	2	राघवसागर, राज्यवास
सीकर	1	रेवासा
सिरोही	1	लखेराव
टोंक	6	बुधसागर, चंदलाई, गलवानिया, मोती सागर, टोरडीसागर, बीसलपुर
उदयपुर	9	बारापाल-खजुरी, बसदिया, भंडा, झाड़ोल, किटबोरी, माद्री बांध, (दंढ़तालाब व ब्रह्म तालाब) मेनार, नागमाला, नगरिया
सलूंबर	2	चावंड, डिगरी

पर्यावरण स्थिरता और जलवायु अनुकूलन हेतु राज्य सरकार की नीतियाँ:-

1. राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति - 2023

- यह नीति 5 जून 2023 (विश्व पर्यावरण दिवस) को जारी की गई।
- उद्देश्यः राज्य को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सुरक्षित करने और सतत विकास को बढ़ावा देना।
- यह तापमान वृद्धि, लू, सूखा, जल संकट और मरुस्थलीकरण जैसी चुनौतियों से निपटने पर केंद्रित है।

प्रमुख विशेषताएँ-

- सभी विभागों की योजनाओं और निर्णय प्रक्रियाओं में जलवायु परिवर्तन को शामिल करना।
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाना।

- समुदायों, अवसंरचना और पारिस्थितिक तंत्रें की अनुकूलन क्षमता बढ़ाना।
- जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकी, नवाचार और ग्रीन फाइनेंस को प्रोत्साहित करना।
- प्रभावी क्लाइमेट गवर्नेंस के लिए संस्थागत व्यवस्था, डेटा प्रणाली और मॉनिटरिंग को मजबूत करना।

2. राजस्थान वन नीति-2023

- इसका उद्देश्य वैज्ञानिक, पारंपरिक और अनुभवजन्य ज्ञान के आधार पर वनों, वन्यजीवों और जैव विविधता का सतत प्रबंधन करना है।
- नीति का लक्ष्य अगले 20 वर्षों में राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के 20% तक वनस्पति आवरण बढ़ाना है।
- यह नीति प्राकृतिक वनों, वन्यजीवों और जैव विविधता के संरक्षण, पुनर्स्थापन और प्रबंधन पर आधारित है।

प्रमुख विशेषताएँ-

- पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा तथा उसकी उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक वनों और जैव विविधता का संरक्षण।
- पुनर्वनीकरण, वनीकरण, कृषि-वानिकी और वृक्षारोपण के माध्यम से वन एवं वृक्षावरण का विस्तार।
- वन एवं चारागाह आधारित संसाधनों के सतत उपयोग के लिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना।
- मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण को रोकना तथा भूमि की उत्पादकता में सुधार करना।
- दुर्लभ और संकटग्रस्त वनस्पति एवं जीव-जंतुओं की प्रजातियों का संरक्षण।

3. राजस्थान ई-वेस्ट प्रबंधन नीति - 2023

- ई-वेस्ट से जुड़ी समस्याओं के समाधान और उसके प्रभावी प्रबंधन के लिए यह नीति जारी की गई है।
- नीति का उद्देश्य ई-वेस्ट के सुरक्षित संग्रहण, पुनर्चक्रण और वैज्ञानिक निस्तारण को सुनिश्चित करना है।
- यह नीति अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक क्षेत्र से जोड़कर सर्क्युलर इकोनॉमी को बढ़ावा देती है।

प्रमुख विशेषताएँ-

- पर्यावरण-अनुकूल ई-वेस्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना।
- ई-वेस्ट के संग्रहण, पृथक्करण, पुनर्चक्रण और वैज्ञानिक निस्तारण को प्रोत्साहित करना।
- ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग उद्योग को बढ़ावा देना।
- संसाधनों की पुनर्प्राप्ति और सर्क्युलर इकोनॉमी को समर्थन देना।
- ई-वेस्ट प्रबंधन नियमों और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) का पालन सुनिश्चित करना।

अशोक कुमार शर्मा
डिप्टी कमिश्नर (जीएसटी)

राजस्थान सरकार की प्रमुख नीतियाँ

कृषि क्षेत्र - यह प्रमुख क्षेत्र है इसके चार उपक्षेत्र है

(1) फसलें (2) पशुपालन
(3) वानिकी (4) मत्स्यपालन

(क) कृषि नीति - राजस्थान सरकार की **पहली कृषि नीति** 2013 में घोषित की गई।

(1) फसलें (कृषि) क्षेत्र की नीतियाँ

मुख्य उद्देश्य

(i) शुष्क क्षेत्र में कृषि - विकास
(ii) सिचाई (जल) के उपयोग में दक्षता (कम पानी से अधिक सिंचाई अर्थात् बिना बर्बादी के जल का उपयोग) में सुधार
(iii) जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने की रणनीति
(iv) फसल उत्पादकता (प्रति हेक्टेयर उत्पादन) को बढ़ाना।
(v) खाद्य व पोषण सुरक्षा सभी के लिए संतुलित आहार सुनिश्चित करना, सामाजिक न्याय तथा पशुओं के लिए चारे की मांग को पूरा करना।

यह केवल साक्षात्कार हेतु बिंदु सहित याद करना। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सन याद रखनी है।

(ख) पहली जैविक कृषि नीति - 2017

- कोटा में सम्पन्न GRAM (ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट) में यह नीति मई 2017 में घोषित की गई थी।
- सिक्किम राज्य की तर्ज पर यह नीति तैयार की गई।
- इसमें वृहद, मध्यम, लघु तीन भागों में लक्ष्य तैयार किए गया।

मुख्य बिंदु: -

1. जैविक बीज व पौध सामग्री तैयार करना।
2. रासायनिक उर्वरक - कीटनाशक - पीडकनाशको के उपयोग को नियन्त्रित करना।
3. जैविक उत्पादो के उत्पादन हेतु प्रशिक्षण, इन उत्पादो को प्रोत्साहन देना।
4. जैविक उत्पादो के उत्पादन हेतु आधारभूत ढाँचा, भण्डार प्रदर्शन, पैकिजिग व प्रोद्योगिकी व विपणन की युनिटस की स्थान करना।
5. इस हेतु विभागो - कृषि – उद्यानिकी — पशुपालन, कृषि विपणन — वन विभागों तथा कृषि विश्वविद्यालयों को एकीकृत बनाना।

(ग) राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात संवर्धन नीति 2019- यह 17 दिसम्बर 2019 को जारी की गई।

बाद में 26 मई 2022 की इसमें संशोधन किए गए।

उद्देश्य :- राजस्थान को प्रसंस्कृत (Processed) कृषि उत्पादो का उत्पादन व आपूर्ति केन्द्र बनाना तथा निवेशको, प्रसंस्करण कर्ताओ और निर्यातको हेतु प्रथम वरीयता केन्द्र बनाना।

(1) समूह आधारित कार्य प्रणाली द्वारा फसल कटाई के बाद होने वाली हानि को कम करना।
(2) किसान व उनके संगठनों की सहभागिता बढ़ाना।
(3) मूल्य संवर्धन और आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार करके किसानो की आय बढ़ाना।
(4) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रशिक्षण देकर कौशल विकास कर रोजगार सृजन
(5) मांग आधारित उत्पादन को बढ़ाना।
(6) राज्य की उत्पादन बहुलता वाली फसलो (जैसे- जीरा, धनियाँ, सौंफ अजवायन, ज्वार, इसबगोल, दलहन, तिलहन, मेहंदी आदि के मूल्य संवर्धन एवं निर्यात को प्रोत्साहन देना।

वित्तीय प्रावधान:-

- SC/ST के 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली परियोजनाओं / SC, ST किसानो उनके संगठनो का 75 प्रतिशत अनुदान व अन्य को 50 प्रतिशत अनुदान जो अधिकतम 150 लाख (पूंजीगत लागत का)
- केन्द्र सरकार द्वारा लागत का 10% जो 50 लाख तक का अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान

- टर्म लोन पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान
- राज्य के बागवानी उत्पादो को अन्य राज्यों के बाजारो में ले जाने पर 300 km से अधिक परिवहन पर 3 साल की अवधि तक 10 लाख रुपए / प्रतिवर्ष अनुदान जैविक उत्पादो के लिए 15 लाख रूपए / वर्ष अनुदान 5 साल की अवधि के लिए।
- प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद निर्यात पर 3 वर्ष के लिए 15 लाख प्रसंस्कृत जैविक उत्पाद निर्यात पर 5 वर्ष के लिए 20 लाख तक अनुदान देय है।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना नीति 2024 (RIPS 2024) -

- 8 अक्टूबर 2024 को लॉन्च।
- उद्देश्य: राज्य में सतत आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देना।
- योजना विनिर्माण, सेवाएँ, MSME, स्टार्ट-अप, R&D, GCC, औद्योगिक अवसंरचना और निर्यात संवर्द्धन पर केंद्रित
- औद्योगिक विकास में नवाचार, पर्यावरणीय स्थिरता और हरित विकास को प्रोत्साहन |
- दिसम्बर 2024 तक 410 इकाइयों को पात्रता जारी।
- निवेश प्रोत्साहन: विनिर्माण में ₹50 करोड़ + और सेवा क्षेत्र में ₹25 करोड़ + (पर्यटन ₹10 करोड़ +) निवेश पर 7 वर्षों तक राज्य करों पर 75% निवेश सब्सिडी।
- वैकल्पिक रूप से वाणिज्यिक उत्पादन के बाद पूंजीगत सब्सिडी या टर्नओवर आधारित प्रोत्साहन
- अतिरिक्त प्रोत्साहन: नियोक्ता बूस्टर (10–15%), थ्रस्ट बूस्टर (10%), एंकर बूस्टर (20%)।
- मुख्य छूटें: 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट, मंडी / बाजार शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति, स्टाम्प व रूपांतरण शुल्क में 75% छूट तथा 25% प्रतिपूर्ति।
- पहली बार निवेश संवर्द्धन नीति 2003 में राज्य में लागू की गई।
- 2024 से पहले 2022 में नीति लागू की गई थी।
- RIPS 2024-31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी।

राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति, 2025

- जारी 31 मार्च 2025 जो 31 मार्च 2029 तक जारी रहेगी।
- उद्देश्य: लॉजिस्टिक्स अवसंरचना सुदृढ़ करना, लागत कम करना और निजी निवेश आकर्षित करना।
- साइलो, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, कंटेनर फ्रेट स्टेशन आदि परियोजनाओं हेतु पात्र स्थिर पूंजी निवेश का 25% पूंजी अनुदान (10 वर्षों में; अधिकतम ₹5-50 करोड़ प्रति वर्ष)।
- परियोजनाओं के लिए 7 वर्षों तक 7% ब्याज अनुदान (अधिकतम ₹50 लाख प्रति वर्ष)।
- श्रमिक प्रशिक्षण हेतु 6 माह तक प्रशिक्षण लागत का 50% (अधिकतम ₹4,000 प्रति माह प्रति श्रमिक) प्रतिपूर्ति।
- स्टाम्प ड्यूटी व भूमि रूपांतरण शुल्क में 75% छूट तथा 25% प्रतिपूर्ति, साथ ही 7 वर्षों तक विद्युत व मण्डी शुल्क में 100% छूट।
- प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु ट्रैकिंग उपकरण, लॉजिस्टिक्स सॉफ्टवेयर, फायर डिटेक्शन सिस्टम और पर्यावरणीय परियोजनाओं पर विभिन्न प्रतिपूर्ति / ग्रीन प्रोत्साहन।
- सभी प्रोत्साहन RIPS-2024 के प्रावधानों के अनुरूप।

राजस्थान डेटा सेंटर नीति, 2025

- 19 फरवरी 2025 को अधिसूचित; उद्देश्य राजस्थान को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय डेटा सेंटर निवेश का प्रमुख केंद्र बनाना।
- क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ई-गवर्नेस, AI, बिग डेटा और डेटा लोकलाइजेशन को बढ़ावा।
- उद्यमों को निवेश अनुदान, पूंजी अनुदान या टर्नओवर आधारित प्रोत्साहन में से विकल्प; प्रथम तीन मेगा/ अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को विशेष सनराइज प्रोत्साहन।
- भवन मानदंडों में लचीलापन —— उच्च FAR, फ्लेक्सिबल ग्राउंड कवरेज, मॉड्यूलर डेटा सेंटर इकाइयाँ, मल्टी-लेवल DG स्टैकिंग व आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र।
- डेटा सेंटर को ESMA के अंतर्गत आवश्यक सेवा घोषित; 24x7 संचालन व सुरक्षा नियमों के तहत सभी पारियों में महिलाओं के नियोजन की अनुमति; श्रम कानूनों हेतु Self-Certification सुविधा।
- नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण व ग्रीन बिल्डिंग को प्रोत्साहन तथा टियर-2 और टियर - 3 शहरों में डेटा सेंटर विकास को प्राथमिकता।
- यह 31 मार्च 2029 तक जारी रहेगी।

राजस्थान एम. एस. एम. ई. नीति 2024

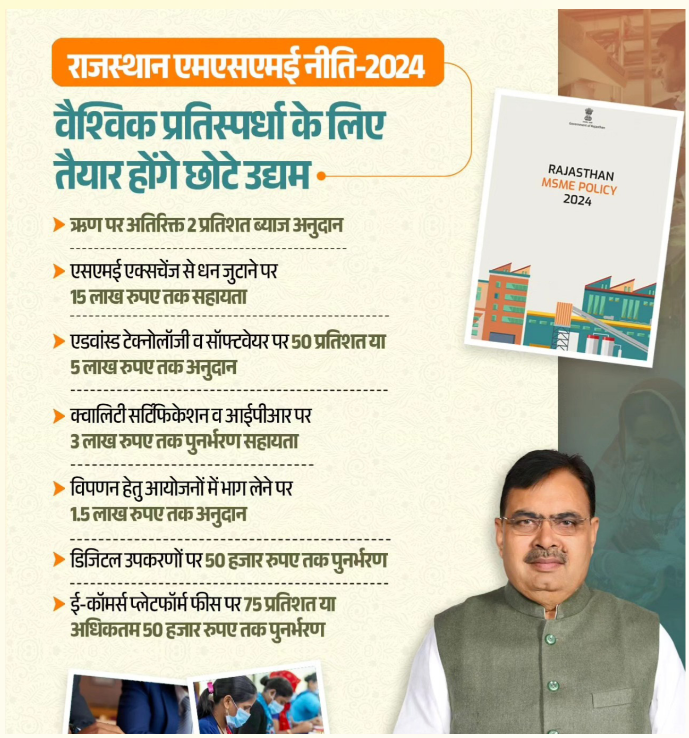

- यह नीति 8 दिसंबर 2024 से लागू हुई और 31 मार्च, 2029 तक प्रभावी रहेगी।
- उद्देश्य : MSME क्षेत्र के संतुलित और समावेशी विकास के माध्यम से राजस्थान में आर्थिक और सामाजिक सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देना।
- इसका लक्ष्य वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और स्थानीय रूप से प्रासंगिक MSME पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में सहयोग करना है। इसे राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त समस्त प्रोत्साहनों हेतु एक "वन स्टॉप शॉप" समाधान के रूप में तैयार किया गया है।
- पहली MSME पॉलिसी 2015 में लागू हुई थी।

मुख्य प्रावधान

- नई MSME की स्थापना और मौजूदा MSME इकाइयों के विस्तार के लिए, RIPS-2024 के तहत ₹50 करोड़ तक की ऋण राशि पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- चयनित इकाइयों के लिए 2% तक की अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी भी दी जाएगी।
- लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों द्वारा NSE /BSE एक्सचेंज प्लेट फॉर्म के माध्यम से इक्विटी पूंजी जुटाने हेतु 15 लाख रुपये तक की एकमुश्त सहायता।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए, सरकार द्वारा स्थापित प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों से उन्नत प्रौद्योगिकी / सॉफ्टवेयर प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय का 50% (5 लाख रुपये तक) राशि सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रमाणन और बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय का 50% (अधिकतम 3 लाख रुपये) की सहायता प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाएगी।
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेकर MSME उत्पादों के विपणन के लिए, स्टॉल किराए और दो व्यक्तियों के यात्रा व्यय हेतु 75% सहायता (अधिकतम 1.5 लाख रुपये) प्रदान की जाएगी।
- उद्यमों के डिजिटलीकरण के लिए किए गए व्यय का 75% (अधिकतम 50,000 रुपये) प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।
- ई-कॉमर्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म शुल्क का 75% प्रतिपूर्ति (अधिकतम 50,000 रुपये) प्रदान किया जाएगा।

राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन - नीति 2024

- उद्देश्य: सतत व समावेशी निर्यात वृद्धि को बढ़ावा; विशेष ध्यान SME, स्थानीय हस्तशिल्प और निर्यात विविधीकरण पर।
- निर्यात दस्तावेजीकरण सहायता: वार्षिक लागत का 50% (अधिकतम ₹5 लाख)।
- विपणन सहायता: अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में व्यय का 75% प्रतिपूर्ति व अधिकतम ₹3 लाख यात्रा सहायता (दो वर्ष में एक बार)।
- उत्पाद परीक्षण प्रोत्साहन: व्यय का 75% प्रतिपूर्ति (अधिकतम ₹20,000 प्रति शिपमेंट, ₹3 लाख प्रति वर्ष) ।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन: आधुनिक तकनीक पर व्यय का 75% प्रतिपूर्ति (अधिकतम ₹50 लाख)। ई-कॉमर्स सहायता: प्लेटफॉर्म शुल्क का 75% प्रतिपूर्ति (अधिकतम ₹2 लाख)।
- निर्यात ऋण बीमा: ECGC प्रीमियम का 50% प्रतिपूर्ति (अधिकतम ₹2 लाख प्रति वर्ष)।
- अतिरिक्त प्रोत्साहन: पहली बार निर्यात करने वाली इकाइयों को RIPS-2024 के तहत माल भाड़ा लागत पर 25% सब्सिडी (अधिकतम ₹25 लाख)।

राजस्थान एक जिला एक उत्पाद (ODOP) नीति 2024

- 8 दिसंबर 2024 को घोषित।
- उद्देश्य: प्रत्येक जिले के निर्यात क्षमता वाले उत्पादों / सेवाओं की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित करना और जिलों को संभावित निर्यात केंद्र बनाना।
- मुख्य उपाय: नए उद्यमों को वित्तीय सहायता, तकनीकी अपनाने, गुणवत्ता प्रमाणन, नवीकरणीय ऊर्जा पहल, अवसंरचना विकास, विपणन सहायता और ई-कॉमर्स को बढ़ावा।
- ODOP में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
- **लक्ष्य:** मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना।
- यह 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी।

क्र.	जिला	ODOP उत्पाद का नाम
1.	अजमेर	ग्रेनाइट एवं मार्बल उत्पाद
2.	अलवर	ऑटोमोबाइल पार्ट्स
3.	बालोतरा	वस्त्र उत्पाद
4.	बाड़मेर	कशीदाकारी
5.	बांसवाड़ा	मार्बल उत्पाद
6.	ब्यावर	क्वार्ट्ज एवं फेल्स्पार पाउडर
7.	बारां	लहसुन उत्पाद
8.	भरतपुर	कृषि आधारित उत्पाद
9.	भीलवाड़ा	वस्त्र उत्पाद
10.	जोधपुर	लकड़ी के उत्पाद
11.	टोंक	सैंडस्टोन उत्पाद
12.	उदयपुर	मार्बल एवं ग्रेनाइट उत्पाद
13.	बीकानेर	बीकानेरी नमकीन
14.	खैरथल - तिजारा	ऑटोमोबाइल पार्ट्स
15.	बूंदी	सैंडस्टोन
16.	कोटा	कोटा डोरिया
17.	चित्तौड़गढ़	ग्रेनाइट एवं मार्बल उत्पाद
18.	कोटपूतली - बहरोड़	ऑटोमोबाइल पार्ट्स
19.	चूरू	लकड़ी के फर्नीचर उत्पा
20.	नागौर	पान मेथी एवं मसाला प्रसंस्करण
21.	दोसा	पत्थर आधारित उत्पाद
22.	पाली	वस्त्र उत्पाद
23.	डीडवाना - कुचामन	मार्बल एवं ग्रेनाइट उत्पाद
24.	फलौदी	सोनामुखी उत्पाद
25.	डीग	पत्थर आधारित उत्पाद
26.	प्रतापगढ़	थेवा आभूषण
27.	धौलपुर	पत्थर आधारित उत्पाद
28.	राजसमंद	ग्रेनाइट एवं मार्बल उत्पाद
29.	डूंगरपुर	मार्बल उत्पाद
30.	सलूम्बर	क्वार्ट्ज
31.	हनुमानगढ़	कृषि आधारित उत्पाद
32.	सवाई माधोपुर	मार्बल उत्पाद
33.	जयपुर	रत्न एवं आभूषण
34.	सीकर	लकड़ी के फर्नीचर उत्पाद
35.	जैसलमेर	येलो स्टोन उत्पाद
36.	सिरोही	मार्बल उत्पाद
37.	जालोर	ग्रेनाइट उत्पाद
38.	श्रीगंगानगर	सरसों का तेल
39.	झालावाड़	कोटा स्टोन उत्पाद
40.	टोंक	स्लेट स्टोन उत्पाद
41.	झुंझुनूं	लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पाद

राजस्थान व्यापार संवर्द्धन नीति, 2025

- 7 दिसम्बर 2025 से लागू।
- उद्देश्यः सूक्ष्म व्यापार उद्यमों व छोटे व्यापारियों को संस्थागत ऋण, बाजार पहुंच और निवेश अवसर देना।
- ब्याज अनुदान: ₹1 करोड़ तक ऋण पर 6%, तथा ₹1-2 करोड़ ऋण पर 4% ब्याज अनुदान।
- क्रेडिट गारंटी सहायता: CGTMSE के तहत ₹5 करोड़ तक ऋण पर गारंटी शुल्क का 50% प्रतिपूर्ति (5 वर्ष) ।
- बीमा प्रीमियम प्रतिपूर्ति: सूक्ष्म खुदरा व्यापारियों को 50% (अधिकतम ₹1 लाख प्रति वर्ष) पाँच वर्षों तक।
- ई-कॉमर्स प्रोत्साहन : प्लेटफॉर्म शुल्क का 75% प्रतिपूर्ति (अधिकतम ₹50,000 प्रति वर्ष, 1 वर्ष)।
- विशेष श्रेणी लाभ: महिला, SC, ST और दिव्यांग स्वामित्व वाले उद्यमों को ₹1-2 करोड़ ऋण पर अतिरिक्त 1% ब्याज अनुदान।
- यह 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी।

राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति, 2025

- 13 फरवरी 2025 को अधिसूचित
- उद्देश्य: राजस्थान को वस्त्र एवं परिधान उद्योग का वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना ।
- निवेश प्रोत्साहन : 10 वर्षों तक परिसंपत्ति सृजन प्रोत्साहन (निवेश अनुदान, पूंजी अनुदान, टर्नओवर आधारित प्रोत्साहन)।
- मेगा परियोजना लाभ: मेगा / अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को फ्लेक्सिबल लैंड पेमेंट व राज्य कर / वैट प्रतिपूर्ति।
- भूमि व कर रियायतें स्टाम्प व पंजीकरण शुल्क में 75% छूट व 25% प्रतिपूर्ति; भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क में भी वही प्रावधान।
- ऊर्जा प्रोत्साहन : 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट।
- पर्यावरणीय प्रोत्साहन: पर्यावरणीय परियोजनाओं पर व्यय का 50% प्रतिपूर्ति (अधिकतम ₹12.5 करोड़)।
- फ्रेट सब्सिडी: ICD/ एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स से निर्यात पर मालभाड़ा लागत का 25% (अधिकतम ₹25 लाख) प्रतिपूर्ति।
- कौशल विकास व IPR सहायता: प्रशिक्षण व्यय और पेटेंट/कॉपीराइट पंजीकरण व्यय का 50% प्रतिपूर्ति।
- सभी वित्तीय प्रोत्साहन RIPS-2024 के अनुरूप।
- यह 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी।

प्रवासी राजस्थानी नीति, 2025

- यह नीति 10 दिसम्बर 2025 को जारी की गई।
- इसका उद्देश्य विश्वभर में बसे प्रवासी राजस्थानियों के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है।
- नीति का लक्ष्य प्रवासी राजस्थानियों को निवेश, व्यापार, नवाचार और सामाजिक विकास से जोड़कर राज्य के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है।
- नीति के पाँच प्रमुख स्तंभ: Accelerate, Bridge, Celebrate, Drive and Ensure.
- इसकी समाप्ति की तिथी निश्चित नहीं है, हॉ लक्ष्य प्राप्ति वर्ष 2030 रखा गया है।

राजस्थान खनिज नीति, 2024

- उद्देश्य: पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ और पारदर्शी खनिज विकास को बढ़ावा देना।
- पहली खनिज नीति राज्य के 1978 में घोषित की गई थी।

प्रमुख विशेषताएँ :-

- खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर निवेश आकर्षित करना और राज्य के जीएसडीपी में खनन क्षेत्र का योगदान बढ़ाना।
- शून्य - अपशिष्ट खनन, पर्यावरण अनुकूल तकनीक और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना।
- उन्नत अन्वेषण तकनीकों और एआई आधारित निगरानी के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
- जीपीएस आधारित ट्रैकिंग, जियो- फेंसिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग के जरिए अवैध खनन गतिविधियों पर नियंत्रण करना।
- मौजूदा 0.68% खनिज रियायत क्षेत्र को 2029-30 तक 1.0% और 2046-47 तक 2.0% तक विस्तारित करना
- वर्तमान में 58 प्रकार के खनिजों का खनन किया जा रहा है जिसे 2047 तक 70 करना।
- प्रदेश की जीडीपी में खनिज क्षेत्र का वर्तमान योगदान 3.4 % है जिसे बढ़ाकर 2029 – 30 तक 5 % और 2046 – 47 तक 8 % करना।
- राज्य के राजस्व को 2029 – 30 तक 3 गुना एवं 2047 तक 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना।

- 2029 – 30 तक 50 लाख एवं 2047 तक 1 करोड़ रोजगार लक्ष्य।
- खनिज संसाधनों की खोज में निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।
- निवेशकर्ताओं के लिए Post Auction Facilitation Cell की स्थापना।
- केंद्र सरकार के साथ समन्वय में बहुमूल्य, रणनीतिक और महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और नीलामी पर जोर।
- आवेदकों और रियायतग्राहियों को वन भूमि के परिवर्तन में सहायता करने के लिए क्षेत्रों को "भूमि बैंक" के रूप में नामित करना, खनिज रियायतों का समय पर संचालन सुनिश्चित करना।
- विनियामक और बुनियादी ढाँचे की चुनौतियों का समाधान करके और अनुमोदन के लिए समय कम करके व्यापार करने में आसानी बढ़ाना।
- नीलामी के लिए अधिक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल) ब्लॉक बनाने में केंद्र सरकार की सहायता करना।
- Note – इस से पहले की राज्य की खनिज नीतियाँ –

  1. 1978
  2. 1991
  3. 1994
  4. 2011 5. 04 जून 2015

राजस्थान एम- सैंड नीति 2024

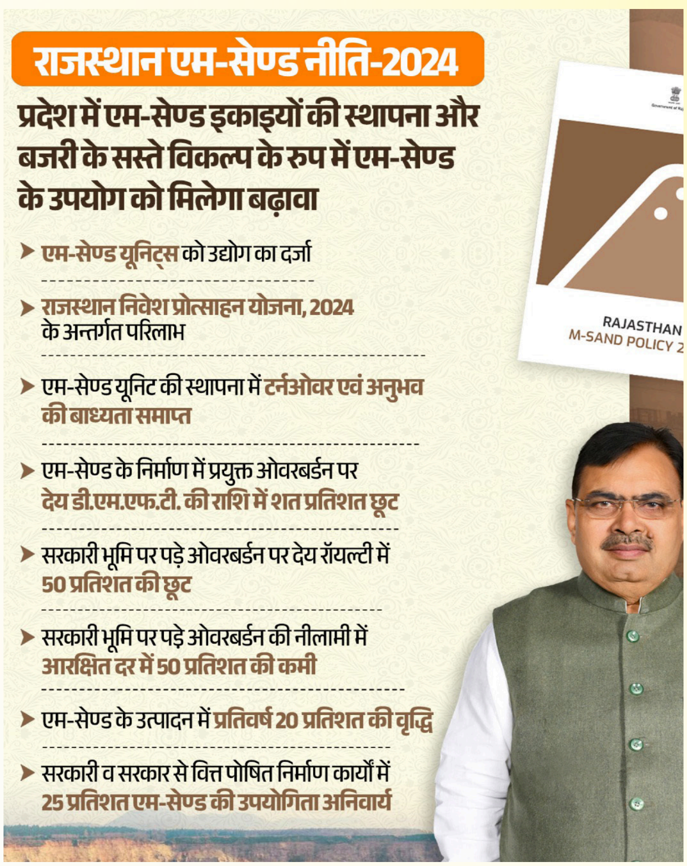

- **उद्देश्य:** निर्माण कार्यों में नदी रेत (बजरी) के स्थान पर एक स्थायी विकल्प के रूप में निर्मित रेत (M- सैंड) के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहन देना।

मुख्य विशेषताएं	M-सैंड इकाइयों के लिए प्रोत्साहन
▪ यह नीति प्रक्रियाओं को सरल बनाकर, नियमों को आसान बनाकर और वित्तीय प्रोत्साहन देकर M-सैंड इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करती है। ▪ गुणवत्ता अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु BIS प्रमाणन और समय-समय पर अनिवार्य परीक्षण का प्रावधान है। ▪ अपशिष्ट प्रबंधन और स्थिरता हेतु जल पुनः उपयोग के लिए शून्य-निर्वहन (जीरो-डिस्चार्ज) प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा। ▪ सरकारी परियोजनाओं में एम-सैंड के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाना (2028-29 तक 50% का लक्ष्य)। ▪ ऑन साइट गुणवत्ता प्रयोगशालाओं को प्रोत्साहन।	▪ **वित्तीय लाभ:** रॉयल्टी में छूट (50%) और ओवरबर्डन डंप उपयोग शुल्क में राहत। ▪ **निवेश सब्सिडी:** 10 वर्षों के लिए 75% राज्य कर प्रतिपूर्ति। ▪ **बिजली शुल्क छूट:** 7 वर्षों के लिए 100% छूट ▪ **स्टाम्प शुल्क में कमी:** स्टाम्प शुल्क पर 75% छूट। ▪ **रोजगार लाभ:** स्थानीय कर्मचारियों के लिए EPF और ESI के लिए नियोक्ता के अंशदान का 50% प्रतिपूर्ति

- प्रथम एम- सैंड नीति-2019 में आई थी।

राजस्थान सिटी गैस वितरण (CGD) नीति, 2025

- यह नीति 16 जुलाई 2025 को जारी की गई।
- उद्देश्य: गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना व स्वच्छ प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ाना।
- इसके तहत गैस पाइपलाइन अवसंरचना को मजबूत करना तथा CGD नेटवर्क का विस्तार किया होगा। इसके माध्यम से घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) और संपीडित प्राकृतिक गैस (CNG) की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है।

राजस्थान रोजगार नीति, 2026

मुख्य बिंदु

- यह 12 जून 2026 को राष्ट्रीय युवा दिवस पर घोषित
- रोजगार चुनौतियों के समाधान हेतु समग्र नीति; राज्य की श्रम बल भागीदारी दर 64.4% और बेरोजगारी दर 4.2%
- विजन: प्रत्येक युवा को सार्थक रोजगार उपलब्ध कराना और राज्य को समावेशी व सतत रोजगार का अग्रणी केंद्र बनाना
- मिशन : स्वरोजगार, वेतन रोजगार व उद्यमिता के माध्यम से मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार अवसर सृजित करना।
- रणनीतिक स्तम्भ: प्राथमिक क्षेत्र व ग्रामीण अर्थव्यवस्था पुनरुत्थान, विनिर्माण व हरित रोजगार बढ़ावा, सेवा क्षेत्र विस्तार और सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार सुदृढ़ीकरण।
- कार्यान्वयन तंत्र : EEMS 2.0 (AI आधारित रोजगार पोर्टल)- नौकरी चाहने वालों को सार्वजनिक व निजी नियोक्ताओं से जोड़ता है; ई-जॉब फेयर व अंतरराष्ट्रीय प्लेसमेंट सुविधा।
- क्षेत्रीय फोकस: जिला स्तर पर क्रियान्वयन; TSP क्षेत्रों व आकांक्षी जिलों पर विशेष ध्यान।
- डेटा आधारित शासन : रोजगार परिणाम सूचकांक (EOI) के
- माध्यम से निगरानी, उच्चस्तरीय समिति द्वारा पर्यवेक्षण।

राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) नीति, 2025

- यह नीति 27 नवम्बर 2025 को अधिसूचित की गई।
- उद्देश्य: राजस्थान को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) के प्रमुख गंतव्य के रूप में विकसित करना है।
- GCC बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए आईटी, अनुसंधान एवं विकास, वित्त, एनालिटिक्स, मानव संसाधन, जोखिम प्रबंधन और डिजिटल नवाचार जैसी उच्च मूल्य सेवाओं के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं।
- इसका लक्ष्य नीति के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार, कौशल विकास, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देना है।
- इस नीति का मूल मंत्र Connect – Collaborate-Contribute है।

राजस्थान कौशल नीति, 2025

- यह नीति 16 अप्रैल 2025 को जारी की गई।
- उद्देश्य: कौशल प्रशिक्षण व व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से युवाओं की रोजगार क्षमता, आय बढ़ाना।

प्रमुख प्रावधान

- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) का आधुनिकीकरण और विस्तार।
- मॉडल केरियर केन्द्रों की स्थापना।

- पूर्व शिक्षण की मान्यता (Recognition of Prior Learning) | Recruit-Train-Deploy कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार से जुड़ा प्रशिक्षण।
- राजस्थान राज्य व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (RCVET) को सुदृढ़ करना।
- फिनिशिंग स्कूल और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना।
- अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।

राजस्थान पर्यटन नीति 2025

- पहली पर्यटन नीति 2001 में घोषित की गई।
- राजस्थान पर्यटन नीति 2025 का शुभारम्भ 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में किया गया।
- यह नीति "विकसित राजस्थान@2047" की दीर्घकालिक विकास दृष्टि के अनुरूप तैयार की गई है।
- उद्देश्य: राज्य में आधुनिक, नवाचार आधारित एवं भविष्य उन्मुख पर्यटन विकास को बढ़ावा देना।

प्रमुख फोकस क्षेत्र

- निजी निवेश को प्रोत्साहित करते हुए होटल, रिसॉर्ट, विरासत संपत्तियों एवं होमस्टे विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।
- पर्यटन अवसंरचना को मजबूत एवं विस्तारित किया जाएगा। पारंपरिक पर्यटन के साथ पर्यावरण, ग्रामीण, आदिवासी, साहसिक एवं धार्मिक पर्यटन को शामिल किया जाएगा।
- रोजगार सृजन एवं कौशल विकास को प्रोत्साहन दिया जाएगा। निवेशकों हेतु प्रोत्साहन
- पूंजी सब्सिडी, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति तथा सावधि ऋणों पर ब्याज सब्सिडी (प्रचलित RIPS के अनुसार) उपलब्ध कराई जाएगी।
- स्टांप ड्यूटी एवं बिजली शुल्क में छूट (प्रचलित RIPS के अनुसार) प्रदान की जाएगी।

राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025

- इस प्रकार की पहली नीति 2022 में घोषित की गई।
- इस नीति का उद्देश्य राज्य को वैश्विक फिल्म निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है। फिल्म निर्माताओं की सहायता हेतु व्यापक फिल्म निर्देशिका और ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ किया गया है।

प्रमुख प्रोत्साहन एवं लाभ

- राजस्थान में फिल्माई गई फिल्मों, वेब सीरीज, टीवी सीरियल एवं डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग लागत पर 30% तक सब्सिडी दी जाएगी।
- फीचर फिल्मों के लिए अधिकतम सब्सिडी सीमा ₹3 करोड़ निर्धारित की गई है।
- वेब सीरीज एवं डॉक्यूमेंट्री के लिए अधिकतम सीमा ₹2 करोड़ है।
- टीवी सीरियल के लिए अधिकतम सब्सिडी ₹1.50 करोड़ तक है।

पात्रता शर्तें

- फीचर फिल्मों के लिए राजस्थान में न्यूनतम ₹2 करोड़ खर्च करना आवश्यक है।
- वेब सीरीज एवं टीवी सीरियल के लिए न्यूनतम ₹1 करोड़ खर्च अनिवार्य है।
- डॉक्यूमेंट्री के लिए कोई न्यूनतम खर्च सीमा निर्धारित नहीं है।
- सब्सिडी के लिए फिल्म या लघु फिल्म का कम से कम 5% स्क्रीन टाइम राजस्थान में होना चाहिए, अथवा कुल शूटिंग दिनों में से से कम 50% दिन राजस्थान में शूट किए गए हों।
- राजस्थानी भाषा की फिल्में भी इस नीति के तहत पात्र हैं।

अतिरिक्त लाभ

- राज्य या केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्थलों पर शूटिंग के लिए 5 दिनों तक 100% लोकेशन शुल्क प्रतिपूर्ति दी जाएगी।
- राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्मों के लिए ₹50 लाख का विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मों के लिए ₹1 करोड़ का विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

राजस्थान पर्यटन इकाई नीति (RTUP) – 2024

- पहली पर्यटन इकाई नीति 2007 में जारी की गई।
- इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र में नई पर्यटन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करना है।

- नीति के माध्यम से रोजगार एवं उद्यमिता के अवसरों का सृजन किया जाएगा।
- पर्यटन क्षेत्र से जुड़े निवेशकों एवं उद्यमियों को देय लाभों में वृद्धि की गई है।
- निजी क्षेत्रों में उपलब्ध विरासत संपत्तियों के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। होटल, रेस्तरां एवं अन्य पर्यटन प्रतिष्ठानों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
- पर्यटन इकाइयों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) के अंतर्गत सभी वित्तीय लाभ उपलब्ध होंगे।

राजस्थान पर्यटन इकाई नीति- 2024 के लाभ

1. संभाषण शुल्क से संबंधित लाभ
2. स्टाम्प ड्यूटी से संबंधित लाभ
3. औद्योगिक दरों पर भवन योजना अनुमोदन शुल्क
4. विकास शुल्क और भूमि शुल्क से छूट
5. औद्योगिक दरों पर बिजली शुल्क
6. "व्यावसायिक उपयोग के लिए 10 प्रतिशत प्लिथ / 1,000 वर्गमीटर क्षेत्र (जो भी कम हो) की अनुमति
7. औद्योगिक दर पर शहरी विकास (यूडी) कर
8. बेटरमेंट लेवी के बिना चार (4) का डबल बिल्ट-अप एरिया (बीएआर)
9. प्रचलित उत्पाद शुल्क नीति के अनुसार रियायती दरों / शुल्क पर समग्र बार लाइसेंस
10. फायर एनओसी - एक बार में 3 वर्ष
11. परिचालन लाइसेंस (व्यापार, होटल और रेस्तरां लाइसेंस) एक बार में 10 वर्ष
12. पहली राज्य होटल नीति 2006 में लागू की गई।

राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, 2024

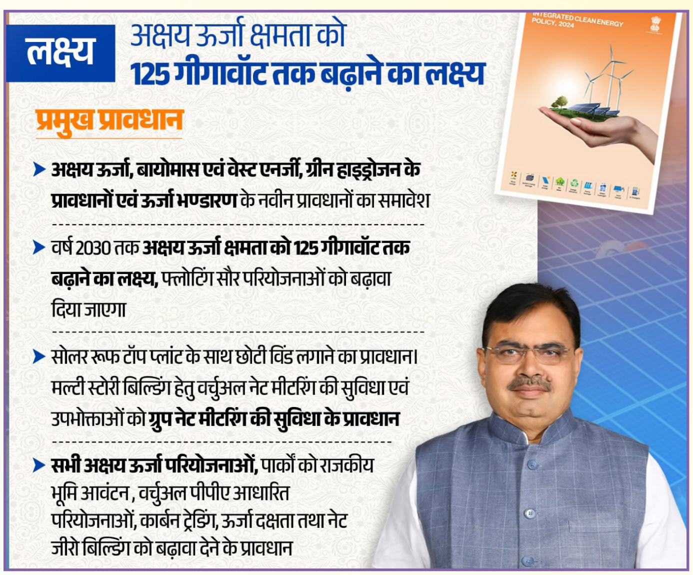

- लॉन्च: 4 दिसंबर 2024 को।
- मुख्य उद्देश्य: 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देना है।
- नीति के तहत 2029-30 तक 115 गीगावाट जिसमें 90 गीगावाट सोलर, 25 गीगावाट विंड एव हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और 10 गीगावाट ऊर्जा भंडारण क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, और ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका लक्ष्य 2030 तक 2,000 किलो टन प्रति वर्ष (KTPA) हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्राप्त करना है।
- पहले 500 केटीपीए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को ट्रांसमिशन और व्हीलिंग शुल्क पर 50% की छूट से लाभ होगा।
- **नोटः-** पहली सौर ऊर्जा नीति-2011, में आई

पहली-पवन ऊर्जा नीति - 2012 में

- पहली बायो मास (BIOMASS) नीति - 2010 में पहली राजस्थान विंड एवं हाइब्रिड एलर्जी नीति (जिसे दूसरी पवन ऊर्जा नीति भी कह सकते है) 2019 में आई
- 2019 में Biomass and Waste to energy policy आई।
- इन सभी नीतियों को मिलाकर 2023 में राजस्थान गैर परम्परागत ऊर्जा नीति नाम दिया गया। जिन्हें 2024 में 'एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति' बनाकर 4 दिसम्बर 2024 को लांच की गई।

नवीकरणीय ऊर्जा पार्क नीति

- यह निजी पार्क डेवलपर्स द्वारा सौर / पवन / हाइब्रिड पार्क के विकास को बढ़ावा देती है।
- उद्देश्य: पावर ग्रिड में बिजली को निकालने के लिए सामान्य बुनियादी ढांचे का निर्माण करना।

राजस्थान ई-वेस्ट प्रबंधन नीति- 2023

- ई-वेस्ट से जुड़ी समस्याओं के समाधान और उसके प्रभावी प्रबंधन के लिए यह नीति जारी की गई है। नीति का उद्देश्य ई-वेस्ट के सुरक्षित संग्रहण, पुनर्चक्रण और वैज्ञानिक निस्तारण को सुनिश्चित करना है।
- यह नीति अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक क्षेत्र से जोड़कर सर्क्युलर इकोनॉमी को बढ़ावा देती है।

प्रमुख विशेषताएँ

- पर्यावरण अनुकूल ई-वेस्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना।
- ई-वेस्ट के संग्रहण, पृथक्करण, पुनर्चक्रण और वैज्ञानिक निस्तारण को प्रोत्साहित करना।
- ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग उद्योग को बढ़ावा देना।
- संसाधनों की पुनर्प्राप्ति (Resource Recovery) और सर्क्युलर इकोनॉमी को समर्थन देना।
- ई-वेस्ट प्रबंधन नियमों और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) का पालन सुनिश्चित करना।

राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति - 2023

- यह नीति 5 जून 2023 (विश्व पर्यावरण दिवस) को जारी की गई।
- उद्देश्य: राज्य को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सुरक्षित करने और सतत विकास को बढ़ावा देना।
- यह तापमान वृद्धि, लू, सूखा, जल संकट और मरुस्थलीकरण जैसी चुनौतियों से निपटने पर केंद्रित है।

प्रमुख विशेषताएँ

- सभी विभागों की योजनाओं और निर्णय प्रक्रियाओं में जलवायु परिवर्तन को शामिल करना।
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाना।
- समुदायों, अवसंरचना और पारिस्थितिक तंत्रों की अनुकूलन क्षमता (Resilience) बढ़ाना।
- जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकी, नवाचार और ग्रीन फाइनेंस को प्रोत्साहित करना।
- प्रभावी क्लाइमेट गवर्नेंस के लिए संस्थागत व्यवस्था, डेटा प्रणाली और मॉनिटरिंग को मजबूत करना।

राजस्थान वन नीति-2023

- इसका उद्देश्य वैज्ञानिक, पारंपरिक और अनुभवजन्य ज्ञान के आधार पर वनों, वन्यजीवों और जैव विविधता का सतत प्रबंधन करना है।
- नीति का लक्ष्य अगले 20 वर्षों में राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के 20% तक वनस्पति आवरण बढ़ाना है।
- यह नीति प्राकृतिक वनों, वन्यजीवों और जैव विविधता के संरक्षण, पुनर्स्थापन और प्रबंधन पर आधारित है।

प्रमुख विशेषताएँ

- पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा तथा उसकी उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक वनों और जैव विविधता का संरक्षण।
- पुनर्वनीकरण, वनीकरण, कृषि-वानिकी और वृक्षारोपण के माध्यम से वन एवं वृक्षावरण का विस्तार।
- वन एवं चारागाह आधारित संसाधनों के सतत उपयोग के लिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना।
- मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण को रोकना तथा भूमि की उत्पादकता में सुधार करना।
- दुर्लभ और संकटग्रस्त वनस्पति एवं जीव-जंतुओं की प्रजातियों का संरक्षण।

राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति (REVP) 2022

- यह आगामी पाँच वर्षों के लिए सतत् परिवहन हेतु शुरू की गई है।
- उद्देश्य: वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करना तथा EV ईको सिस्टम के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना है |
- वर्ष 2025-26 के लिए SGST प्रतिपूर्ति हेतु ₹150 करोड़ का बजट प्रावधान इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाये जाने को बढावा देता है।
- रीको द्वारा डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक वाहन तथा कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पार्कों का भी विकास किया जायेगा।
- निजी और सार्वजनिक चार्जिंग आधारभूत अवसंरचना के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना को लाइसेंस मुक्त किया गया है।

प्रावधान

- **इलेक्ट्रीक व्हीकल परिदृश्य का निर्माण:** मजबूत चार्जिंग नेटवर्क का निर्माण करना, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना तथा राज्य में विनिर्माण को प्रोत्साहन देना।
- **उत्तरदायी विभाग:** विभिन्न विभागों यथा परिवहन, ऊर्जा, उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार आदि को नीति की कार्रवाई को क्रियान्वित करने तथा विभागों के मध्य सहयोग सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
- **प्रोत्साहन:** उपभोक्ताओं के लिए किफायती इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन निर्धारित किए गए हैं।
- **आईटी प्लेटफॉर्म:** सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की रियल-टाईम स्थिति की जानकारी प्रदान करने हेतु एप्लिकेशन-आधारित प्लेटफॉर्म की स्थापना की जायेगी।

राजस्थान एआई / एमएल नीति- 2026

- इसे 6 जनवरी, 2026 को जयपुर में आयोजित राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस में लॉन्च किया गया।
- उद्देश्य: शासन में एआई को अपनाना, उद्योगों के लिए एआई प्रोत्साहन और एआई कौशल एवं क्षमता निर्माण।
- यह नीति सार्वजनिक सेवा प्रदायगी के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देगी।
- यह नीति विकसित राजस्थान@2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होगी।

प्रावधान

- इसमें शासन में पारदर्शिता बढाने पर विशेष जोर दिया गया है।
- एआई के लाभों तक समान एवं समावेशी पहुँच सुनिश्चित की जाएगी।
- एआई शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विकास को गति प्रदान करेगा।
- नीति राज्य के दीर्घकालिक विकास रोडमैप के अनुरूप तैयार की गई है। भविष्य के लिए तैयार डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दिया जाएगा।

बाल एवं महिला कल्याण नीति (बजट 2026-27, राजस्थान सरकार में प्रस्तावित)

- प्रारंभिक बाल देखभाल एवं शिक्षा नीति (Early Childhood Care & Education Policy) बनाई जाएगी।
- धर्मशालाओं के निर्माण हेतु Build Operate-Transfer (BOT) आधारित नीति लाई जाएगी।
- डिजिटल अवसंरचना सुविधा नीति (Digital Infrastructure Facilitation Policy) और भौगोलिक स्थानिक नीति (Geo-Spatial Policy) लाई जाएगी।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति (Solid Waste Management Policy) लागू की जाएगी।
- एम- सैंड नीति (M-Sand Policy) के तहतनिर्माण कार्यों में उपयोग 25% से बढ़ाकर 50% किया जाएगा।
- RIPS-2024 के तहत न्यूफैक्चरिंग के साथ-साथ सेवा क्षेत्र को भी ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
- लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउस औरवैश्विक क्षमता केंद्र (GCC Sector) को विस्तार लाभ दिए जाएंगे।
- कंटेनर निर्माण (Container Manufacturing) को RIPS-2024 के अन्तर्गतप्रोत्साहित क्षेत्र में शामिल किया गया है।
- ऊर्जा परिवर्तन कौशल क्लस्टर (Energy Transition Skilling Cluster) के माध्यम सेग्रीन रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। राजस्थान ओडीओपी पॉलिसी - 2024 के तहत विस्तार हेतु 10% मार्जिन मनी सहायता दी जाएगी।
- शहरी आवास को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री जन आवास योजना में नई प्रगतिशील नीति लाई जाएगी।
- शहरी विकास के लिए नई TDR Policy लागू की जाएगी।

राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026

- 18 मार्च 2026 को लागू।
- **मुख्य उद्देश्य:** राज्य को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक चिप निर्माण का हब बनाना.
- **प्रमुख क्षेत्र:** जोधपुर, पाली और मारवाड़ क्षेत्र को 'प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर' के रूप में विकसित किया जा रहा है.
- **लाभ:** भारत सरकार की सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त पूंजी सहायता, 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% की छूट और स्टाम्प ड्यूटी में 75% की छूट

राजस्थान एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026

- 18 मार्च 2026 को लागू।
- **मुख्य उद्देश्य:** एयरोस्पेस, रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विनिर्माण को प्रोत्साहित करना।
- **लाभ:** निवेश को आकर्षित करने के लिए, लार्ज और मेगा श्रेणियों के उद्योगों को 7 वर्षों तक स्टेट टैक्स में 75% का निवेश अनुदान (Reimbursement) और एंप्लॉयमेंट बूस्टर जैसी अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएंगी।

राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026

- 18 मार्च 2026 को लागू।
- **मुख्य उद्देश्य:** औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और एकीकृत औद्योगिक (Industrial) हब का निर्माण करना।
- **सुविधा:** 'राज-निवेश' पोर्टल के माध्यम से सिंगल-विंडो सिस्टम से मंजूरी, भूमि और लीज रेंटल सब्सिडी में लाभ, तथा कम विकसित क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा।

समसामयिकी पत्रिका टेस्ट : (जुलाई- 2026)

कुल प्रश्न : 100 **अंक : 200**

1. हाल ही में हस्ताक्षरित यमुना जल परियोजना समझौता के सन्दर्भ में सत्य विकल्प का चयन कीजिए-

1. परियोजना की लागत-	₹34,102 करोड़ (अनुमानित लागत)
2. जल की मात्रा-	577 मिलियन क्यूबिक मीटर
3. जल का स्रोत-	हथिनीकुंड बैराज, राजस्थान

कूट:
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

2. टैक्सकॉन-2026 शिखर के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथन/कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन/कथनों की पहचान कीजिए।
1. यह 12 जून, 2026 को आयोजित किया गया था।
2. इसका आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर में किया गया।
3. इसके आयोजन टैक्स कंसल्टेंट एसोसिएशन द्वारा करवाया गया।
कूट:
(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

3. राज्य स्तरीय जूनियर पुरुष हॉकी के सन्दर्भ में सत्य युग्म/युग्मों की पहचान कीजिए।

1. संस्करण	-	16वां
2. आयोजन स्थल	-	पाली
3. विजेता	-	सीकर

कूट:
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

4. राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस-2026 कौनसा संस्करण और किस विषय के साथ आयोजित किया गया है-
(a) 21वां संस्करण और "प्रशासनिक आँकड़ों की क्षमता का दोहन" विषय
(b) 20वां संस्करण और "प्रशासनिक आँकड़ों की क्षमता का दोहन और विकसित भारत" विषय
(c) 20वां संस्करण और "प्रशासनिक आँकड़ों की क्षमता का दोहन" विषय
(d) 24वां संस्करण और "प्रशासनिक आँकड़ों की क्षमता का दोहन" विषय

5. विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 के सन्दर्भ सत्य विकल्प का चयन कीजिए-

1. संस्करण-	प्रथम
2. मैस्कॉट-	वीर द लॉयन
3. भागीदारी-	89 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया

कूट:
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

6. पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथन/कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन/कथनों की पहचान कीजिए।
1. इसका केन्द्रीय मंत्री अमित शाह ने 23 जून, 2026 को गांधीनगर में शुभारंभ किया।
2. यह ट्रैकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण और परिवार कल्याण को मजबूत करेगा।
कूट:
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न 2

7. हाल ही में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने 18 जून, 2026 को कहां पर खाद्यान्न भंडारण के लिए स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम लॉंच किया है-
(a) राजस्थान में (b) पश्चिम बंगाल में
(c) हरियाणा में (d) नई दिल्ली में

सम्पूर्ण टेस्ट पेपर देने के लिए SAMYAK एप डाउनलोड करे---
QR Code

Samyak
An Institute For Civil Services

RAS-2024 RESULT

सम्यक् मार्गदर्शन
सर्वश्रेष्ठ परिणाम

RANK 2
Virendra Charan

RANK 3
Navneet Sharma

RANK 4
Ravindra Singh

RANK 5
Vikash Siyag

RANK 6
Aishwarya Kanwar

RANK 7
Dinesh

RANK 9
Bhoopender Singh

07 RANKS in TOP 10 | 56 RANKS in TOP 100 | 690+ SELECTION in RAS-2024

IAS | RAS

FOUNDATION & क्लास 12th के बाद ग्रेजुएशन के साथ 2 & 3 वर्षीय कोर्स

PSI

PAPER 1st & PAPER 2nd

COURSE FEATURE

- विषय विशेषज्ञों द्वारा क्लासेज
- प्रिंटेड बुकलेट्स / ई-नोट्स*
- टेस्ट सीरीज
- पर्सनल मेंटरशिप
- लाइब्रेरी सुविधा*
- ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन कोर्स निःशुल्क

Offline & Online Separate Batches For Hindi & English Medium

HEAD OFFICE: NEAR RIDDHI - SIDDHI, JAIPUR 9875170111

सम्यक् मार्गदर्शन = सर्वश्रेष्ठ परिणाम

RAS 2024 में TOP 10 में 7, TOP 100 में 56, सहित 690+ चयन

सभी सफल प्रतिभाओं को हार्दिक बधाई!

Rank	Name
RANK 2	VIRENDRA CHARAN
RANK 3	NAVNEET SHARMA
RANK 4	RAVINDRA SINGH
RANK 5	VIKASH SIYAG
RANK 6	AISHWARYA KANWAR
RANK 7	DINESH
RANK 9	BHOOPENDER SINGH
RANK 12	KULDEEP SHARMA
RANK 13	KAILASH KUMAR
RANK 16	KAILASH RANWA
RANK 18	UMANG RAWAL
RANK 23	SAHDEV BIDADA
RANK 24	PARAMVEER SINGH
RANK 25	SWAROOP SINGH
RANK 26	AANCHAL NAGPAL
RANK 27	MAMTA LIMBA
RANK 28	ARIHANT JAIN
RANK 29	SIMRAN SHEKHAWAT
RANK 30	VINAY MOHAN
RANK 31	ANSHIKA AGARWAL
RANK 33	LOKENDRA SINGH
RANK 34	VIKAS CHOUDHARY
RANK 35	SANJU
RANK 36	KRISHANPAL SHEKHAWAT
RANK 43	JITENDRA
RANK 45	AMAR SINGH RATHORE
RANK 46	MANASVINI VERMA
RANK 48	TULSI
RANK 49	RAMAVTAR MUNDEL
RANK 50	DHARMRAJ SINGH RAO
RANK 52	BHOOMIKA TRIVEDI
RANK 55	RONAK
RANK 57	POONAM
RANK 58	SACHIN AGRAWAL
RANK 59	PARUL CHOUDHARY
RANK 61	KAMLESH KR SHARMA
RANK 65	ARIMARDAN CHAUHAN
RANK 66	UNNAT KISHOR RAJORA
RANK 70	KRITIKA GAUR
RANK 71	URMILA VISHNOI
RANK 73	JAYESH PRAJAPAT
RANK 74	MAHENDRA DAN
RANK 76	SIDDHARTH DHAKAD
RANK 77	JYOTSANA RANAWAT
RANK 78	CHOUDHARY MADHU ROOPARAM
RANK 79	NITESH GUPTA
RANK 80	VIKASH BISHNOI
RANK 82	DAMODAR PAREEK
RANK 83	KAILASH KUMAR
RANK 84	SHYAM SUNDER MEENA
RANK 85	MOHIT GODARA
RANK 86	NARASI RAM BISHNOI
RANK 87	RAM RATAN BATESAR
RANK 88	MAHENDRA CHOUDHARY
RANK 99	GHAMANDA RAM
RANK 100	VANDANA PATEL

690+...

HEAD OFFICE: NEAR RIDDHI - SIDDHI, JAIPUR 9875170111